रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)—73

REGISTERED No. D. (D.N.)-73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 36] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 4, 1982/भाद्र 13, 1904

No. 36] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 4, 1982/BHADRA 13, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं

Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 16 अगस्त, 1982

का०आ० 3054.—नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा सूचना दी जाती है कि श्री बीरेन्द्र नाथ बनर्जी, एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिए दिया है कि उसे कलकत्ता व 24 परगना व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्त किया जाए।

2. उक्त व्यक्ति की नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप में मेरे पास भेजा जाए।

[सं 5(60)/82-न्या०]

के० सी० डी० गंगवानी, सक्षम प्राधिकारी

MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS

(Department of Legal Affairs)

New Delhi, the 16th August, 1982

S.O. 3054.—Notice is hereby given by Competent Authority in pursuance of rule 6 of the Notaries Rules, 1956, that application has been made to the said Authority, under rule 4 of the said Rules, by Shri Birendra Nath Banerjee, Advocate for appointment as a Notary to practise in Calcutta & 24 Parganas

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this Notice.

[No. F. 5(60)/82-Judl.]

K. C. D GANGWANI, Competent Authority

गृह मंत्रालय

(भारत के महापंजीकार का कार्यालय)

नई दिल्ली, 17 अगस्त, 1982

का०आ० 3055.—जनगणना अधिनियम, 1948 (1948 की सं० 37) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार भारतीय प्रशासनिक सेवा (संघ राज्यक्षेत्र) के अधिकारी श्री प्रोमेश सैगल को 1981 की जनगणना के लिए तारीख 21 जुलाई, 1982 के अपराह्न से अगले आदेशों तक जनगणना कार्य निदेशालय, लक्षद्वीप में निदेशक के पद पर एतद्द्वारा नियुक्त करती है।

[सं० 11/91/79-प्रशा०-I]

पी० पद्मनाभ, भारत के महापंजीकार और पदेन जनगणना

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Office of the Registrar General India)

New Delhi, the 17th August, 198

S.O. 3055.—In exercise of the power Section (1) of Section 4 of the Census 1948), the Central Government hereby

Saigal of the Indian Administrative Service (Union Territory Cadre) as Director of Census Operations, Lakshadweep for the 1981 Census, with effect from the afternoon of the 21st July, 1982, until further orders.

[No. 11/91/79-Ad. I]
P. PADMANABHA, Registrar General and Ex-officio Census Commissioner for India.

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 1982

का० आ० 3056—तारीख 19-5-1975 के आंध्र प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण आदेश, 1975 [जी० एस० आर० 285 (ई)] के पैरा 3 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, उड़ीसा वरिष्ठ न्यायिक सेवा (वरिष्ठ शाखा) के सेवा-निवृत्त अधिकारी, श्री के० एम० मिश्र को कार्यभार संभालने की तारीख से आंध्र प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण के सदस्य के रूप में नियुक्त करते हैं।

[सं० 21013/2/81-एस० आर०]
जी० वी० आर० मूर्ति, अवर सचिव

New Delhi, the 23rd August, 1982

S.O. 3056.—In exercise of the powers conferred by paragraph 3 of the Andhra Pradesh Administrative Tribunal Order, 1975 [G.S.R. 285(E), dated the 19th May, 1975] the President is pleased to appoint Shri K. M. Mishra, retired officer of the Orissa Superior Judicial Service (Senior Branch), as Member of the Andhra Pradesh Administrative Tribunal with effect from the date he takes over charge of office.

[F. No. 21013/2/81-SR]
G. V. R. MURTHY, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 18 मई, 1982

आयकर

का० आ० 3057.—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात् भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद, ने निम्नलिखित संस्था को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (iii) के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदन किया है, अर्थात्:—

(i) यह कि श्री शारदा महाविद्यालय शैक्षणिक न्यास, सालेम द्वारा इस छूट के अधीन संग्रहीत निधि का उपयोग अनन्यतः सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान की प्रोन्नति के लिए किया जाएगा।

(ii) यह कि महाविद्यालय इस छूट के अधीन इस प्रकार संग्रहीत निधि का पृथक लेखा रखेगा और इस छूट के अधीन संग्रहीत निधि और वह रीति जिसमें निधि का उपयोग किया जाता है, नियमित रूप में दर्शित करते हुए लेखा विवरण के साथ अपने क्रिया कलापों की वार्षिक विवरणी परिषद को भेजेगा।

(iii) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 (1) (iii) के अधीन प्राप्त किए गए दान से अयुक्त किसी निधि को धारा [redacted] (1) (घ) में विहित रीति से विनिहित किया जाएगा [redacted] अन्तर्गत सरकारी बचत पत्रों में विनिधान, अनुसूचित [redacted] निक्षेप, यू०टी० आई० में विनिधान, पब्लिक सैक्टर [redacted] में निक्षेप, डाकघर और सरकारी कंपनियों आदि में

(iv) प्रत्येक वर्ष के लिए अपनी कुल आय और अपने वार्षिक संपरीक्षित लेखा की एक प्रति और अपनी आस्तियां तथा दायित्व दर्शित करते हुए तुलन पत्र की एक प्रति 30 जून तक विहित प्राधिकारी को भेजेगा और इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक प्रति सबद्ध आयकर आयुक्त को भेजेगा।

संस्था

श्री शारदा महाविद्यालय शैक्षणिक न्यास, सालेम

यह अधिसूचना इसके जारी किए जाने की तारीख से प्रभावी होगी और तीन वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगी।

[सं० 4616/फा०सं० 203/124/81-आई टी ए II]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 18th May, 1982

INCOME TAX

S.O. 3057.—It is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by the Indian Council of Social Science Research, the prescribed authority for the purposes of clause (iii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961, subject to the following conditions :—

(i) That the funds collected by Sri Sarda College Educational Trust, Salem under this exemption shall be utilized exclusively for promotion of research in Social Sciences.

(ii) That the College shall maintain a separate accounts of the funds so collected by them under this exemption and shall send to the Council an Annual Report of its activities alongwith the Statement of Accounts regularly showing specifically the funds collected under this exemption and the manner in which these funds are utilized.

(iii) Any unutilized funds, out of the donations received under section 35(1) (iii) of Income-tax Act, 1961, will be invested in the manner prescribed in Section 13(1)(d) which includes, investment in Govt. Saving Certificates, deposit in Scheduled Bank, investment in U.T.I., deposits with the Public Sector Companies, deposits in Post Office and Govt. Companies etc.

(iv) That the College shall submit to the Prescribed Authority by 30th June, each year a copy each of their audited annual accounts showing their total income and expenditure and balance-sheet showing its assets and liabilities with a copy of each of these documents to the concerned Commissioner of Income-tax.

INSTITUTION

Sri Sarda College Educational Trust, Salem.

This notification takes effect from the date of its issue and is valid for a period of three years.

[No. 4616/F. No. 203/124/81-ITA.II]

नई दिल्ली, 22 मई, 1982

आयकर

का० आ० 3058.—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात् भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद नई दिल्ली ने निम्नलिखित संस्था को आय-कर नियम, 1962 के नियम 6 (ii) के साथ पठित, आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के प्रयोजनों के लिए चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में "वैज्ञानिक अनुसंधान संगम" प्रवर्ग के अधीन, निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है, अर्थात्:—

(i) यह कि प्रतिष्ठान चिकित्सा अनुसंधान के लिए प्राप्त राशियों का पृथक लेखा रखेगा।

(ii) यह कि प्रतिष्ठान अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रियाकलापों की वार्षिक विवरणी परिषद को प्रति वर्ष 31 मई तक ऐसे रूप में प्रस्तुत करेगा जो इस प्रयोजन के लिए अधिकथित किया जाए और उसे सूचित किया जाए

(iii) यह कि प्रतिष्ठान कुल आस्तियों और दायित्वों सहित लेखा का वार्षिक संपरीक्षित विवरण परिषद को प्रति वर्ष 31 मई तक भेजेगा और इसके अतिरिक्त इसकी एक प्रति सम्बद्ध आय-कर आयुक्त को भेजेगा

संस्था

डा० अगासे चिकित्सा प्रतिष्ठान, अहमदनगर, महाराष्ट्र

यह अधिसूचना 31-3-1982 से 30-3-1984 तक दो वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी है।

[सं० 4647 (फा० सं० 203/87/82-आईटी ए० II

New Delhi, the 22nd May, 1982

INCOMES TAX

S.O. 3058.—It is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by Indian Council of Medical Research New Delhi, the prescribed authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961 read with Rule 6(ii) of the Income-tax Rules, 1962 under the category of "Scientific Research Association" in the field of Medical Research subject to the following conditions :—

(i) That the Foundation will maintain a separate account of the sums received by it for medical research.

(ii) That the Foundation will furnish annual returns of its scientific research activities to the Council by 31st May each year at the latest in such form as may be laid down and intimated to them for this purpose.

(iii) That the Foundation will furnish a copy of the annual audited statement of accounts along with total assets and liabilities to the Council by 31st May, each year and in addition send a copy of it to the concerned Income-tax Commissioner.

INSTITUTION

Dr. Agashe Medical Foundation, Ahmedanager, Maharashtra.

The notification is effective for a period of two years from 31-3-1982 to 30-3-1984.

[No. 4627/F. No. 203/87/82-ITA.II]

नई दिल्ली 24 मई, 1982

आयकर

का०आ० 3049.—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी अर्थात भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद ने निम्नलिखित संस्था को आयकर, अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (iii) के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है,

अर्थात.—

(i) यह कि कृत्रिम टैक्सटाइल्स प्रतिष्ठान, मुम्बई, द्वारा इस छूट के अधीन संग्रहीत निधि का उपयोग अनन्यतः सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान की प्रोन्नति के लिए किया जाएगा।

(ii) यह कि प्रतिष्ठान इस छूट के अधीन संग्रहीत निधि का पृथक लेखा रखेगा।

(iii) यह कि प्रतिष्ठान प्रत्येक वर्ष के लिए इस छूट के अधीन संग्रहीत निधि और वह रीति जिसमें निधि का उपयोग किया जाता है दर्शित करते हुए अपने वार्षिक संपरीक्षित लेखा की एक प्रति और वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति परिषद को भेजेगा।

(iv) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(i) (ii) के अधीन प्राप्त किए गए दान से अनुप्रयुक्त किसी निधि को धारा 13(1) (घ) में विहित रीति से विनिहित किया जायगा जिसके अन्तर्गत सरकारी बचत पत्रों में विनिधान, अनुसूचित बैंक मे निक्षेप यू० टी० आई० में विनिधान पब्लिक सैक्टर कंपनियों में निक्षेप, डाक घर और सरकारी कंपनियों आदि मे निक्षेप भी है।

संस्था

कृत्रिम टेक्सटाइल्स अनुसंधान प्रतिष्ठान, मुम्बई

यह अधिसूचना 1-4-1982 से प्रभावी है और एक वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगी।

[सं० 4632 फा० सं० 203/210/81-आईटी एII]

New Delhi, the 24th May, 1982

INCOME TAX

S.O. 3059.—It is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by the Indian Council of Social Science Research, the prescribed authority for the purposes of clause (iii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961 subject to the following conditions :—

(i) That the funds collected by the Manmade Textiles Foundation, Bombay under this exemption shall be utilized exclusively for promotion of research in Social Sciences.

(ii) That the Foundation shall maintain a separate account of the funds collected by them under this exemption.

(iii) That the Foundation shall sent to the Council an Annual Report and Audited Statement of Accounts regularly showing the funds collected under this exemption and the manner in which these funds are utilized.

(iv) Any unutilized funds, out of the donations received under Section 35(1)(iii) of Income-tax Act, 1961,

will be invested in the manner prescribed in Section 13(1)(d) which includes investment in Govt. Saving Certificates, desposit in Scheduled Bank, investment in U.T.I., deposits with the Public Sector Companies, deposits in Post Office and Govt. Companies etc.

INSTITUTION

Man Made Textiles Research Foundation, Bombay.

This notification takes effect from 1-4-82 and is valid for one year.

[No. 4683/F. No. 203/210/81-ITA. II]

आयकर

का० आ० 3060.—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात् भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद ने निम्नलिखित संस्था को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा

35 की उपधारा (1) के खण्ड (iii) के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है, अर्थात्:—

(i) यह कि मनिपाल प्रबंध संस्थान, मनिपाल द्वारा इस छूट के अधीन संग्रहीत निधि का उपयोग अनन्यत सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान की प्रोन्नति के लिए किया जाएगा।

(ii) यह कि संस्थान इस छूट के अधीन इस प्रकार संग्रहत निधि का पृथक लेखा रखेगा और इस छूट के अधीन संग्रहित निधि और वह रीति जिसमें निधि का उपयोग किया जाता है, नियमित रूप से दर्शित करते हुए लेखा विवरण के साथ अपने क्रिय. कलापों की वार्षिक विवरणी परिषद को भेजेगा।

(iii) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 (i) (iii) के अधीन प्राप्त किए गए दान में अनुप्रयुक्त किसी निधि को धारा 13 (1) (घ) में विहित रीति से विनिहित किया जाएगा जिसके अन्तर्गत सरकारी बचत पत्रों में विनिधान, अनुसूचित बैंक में निक्षेप, यू० टी० आई० में विनिधान पब्लिक सैक्टर कंपनियों में निक्षेप, डाकघर और सरकारी कंपनियों आदि में निक्षेप आदि भी है।

(iv) यह कि संस्थान प्रत्येक वर्ष के लिए अपनी कुल आय और व्यय को दर्शित करते हुए अपने वार्षिक संपरीक्षित लेखा की एक प्रति और अपनी आस्तियां तथा दायित्व दर्शित करते हुए तुलन पत्र की एक प्रति 30 जून तक विहित अधिकारी को भेजेगा और इन दस्तावेजों की प्रत्येक की एक प्रति सबद्ध आयकर आयुक्त को भेजेगा ;

संस्था

मनिपाल प्रबंध, संस्थान, मनिपाल

यह अधिसूचना इसके जारी किए जाने की तारीख से प्रभावी होगी और तीन वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगी।

[सं० 4633/फा० सं० 203/153/81-आई० टी० ए० II]
एम० जी० सी० गोयल, अवर सचिव

INCOME TAX

S.O. 3060.—It is hereby notified for general infromation that the institution mentioned below has been approved by the Indian Council of Social Science Research, the prescribed authority for the purposes of clause (iii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961, subject to the following conditions :—

(i) That the funds collected by the Manipal Institute of Management, Manipal under this exemption shall be utilized exclusively for promotion of research in Social Sciences.

(ii) That the Institute shall maintain a separate account of the funds so collected by them under this exemption and shall send to the Council an Annual Report of its activities along with the Statement of Accounts regularly showing specifically the funds collected under this exemption and the manner in which these funds are utilized.

(iii) Any unutilized funds, out of the donations received under section 35(1)(iii) of Income-tax Act, 1961, will be invested in the manner prescribed in Section 13(1)(d) which includes investment in Govt. Saving Certificate, deposit in scheduled Bank, investment in U.T.I., deposits with the Public Sector Companies, deposits in Post Office and Govt. Companies etc.

(iv) That the Institute shall submit to the Prescribed authority by 30th June each year a copy each of their audited annual accounts showing their total income and expenditure and balance sheet showing its assets and liabilities with a copy of each of these documents to the concerned Commissioner of Income-tax.

INSTITUTION

Manipal Institute of Management, Manipal.

This notification takes effect from the date of its issue and is valid for a period of three years.

[No. 4633/F. No. 203/153/81-ITA.II]
M. G. C. GOYAL, Under Secy.

नई दिल्ली, 23 जून, 1982

आय-कर

का०आ० 3061—केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23-ग) के खण्ड (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए "हरिजन सेवक संघ" को निर्धारण वर्ष 1982-83 से 1984-85 के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए उक्त धारा के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है।

[सं० 4757/फा०सं० 197/12/82 आ.क.(ए 1)]

New Delhi, the 23rd June, 1982

INCOME-TAX

S.O. 3061.—In exercise of the powers conferred by clause (iv) of sub-section (23C) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Harijan Sevak Sangh" for the purposes of the said section for the period covered by the assessment years 1982-83 to 1984-85.

[No. 4757/F. No. 197/12/82-IT(AI)]

का०आ० 3062—केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23-ग) के खण्ड (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए "दि डिवाइन लाइफ सोसाइटी" को निर्धारण वर्ष 1982-83 के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए उक्त धारा के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है।

[सं० 4758 /फा० सं० 197/55/82 आ० क(ए 1)]

S.O. 3062.—In exercise of the powers conferred by clause (iv) of sub-section (23C) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "The Divine Life Society" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment year 1982-83.

[No. 4758/F. No. 197/55/82-IT(AI)]

का. आ. 3063—केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23-ग) के खण्ड (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए "केन्द्रीय राहत निधि" को निर्धारण वर्ष 1978-79 से 1981-82 के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए उक्त धारा के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है।

[सं. 4759/फा.सं. 197/109/79-आ.क. (ए1)]

S.O. 3063.—In exercise of the powers conferred by clause (iv) of sub-section (23C) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "The Divine Lift Society" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1978-79 to 1981-82.

[No. 4759/F. No. 197/109/79-IT(AI)]

का. आ. 3064—केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23-ग) के खण्ड (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए "विकलांग व्यक्ति संगम" को निर्धारण वर्ष 1979-80 से 1982-83 के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए उक्त धारा के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है।

[सं. 4760/फा.सं. 197/122/80-आ.क. (ए1)]

S.O. 3064.—In exercise of the powers conferred by clause (iv) of sub-section (23C) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "The Association of the Physically Handicapped" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1979-80 to 1982-83.

[No. 4760/F. No. 197/122/80-IT(AI)]

का०आ० 3065.—केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23ग) के खण्ड (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए "मिल स्वामी संगम राहत निधि सोसाइटी" को निर्धारण वर्ष 1977-78 के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए उक्त धारा के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है।

[सं० 4761/फा० सं० 197/128/81-आ०का०(ए० 1)]

S.O. 3065.—In exercise of the powers conferred by caluse (iv) of sub-section (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "The Millowners' Association Relief Fund Society" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment year 1977-78.

[No. 4761/F. No. 197/128/81-IT(AI)]

नई दिल्ली, 28 जून, 1982

आय-कर

का०आ० 3066.—केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23-ग) के खण्ड (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए "स्लम एण्ड रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी" को निर्धारण वर्ष 1978-79 से 1981-82 के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए उक्त धारा के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है।

[सं० 4773/फा०सं० 197/69/81 आ०क०(ए० 1)]

New Delhi, the 28th June, 1982

INCOME-TAX

S.O. 3066.—In exercise of the powers conferred by clause (iv) of sub-section (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Slum & Rural Development Society" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1978-79 to 1981-82.

[No. 4773/F. No. 197/69/81-IT(AI)]

नई दिल्ली, 6 जुलाई, 1982

का०आ० 3067.—केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23ग) के खण्ड (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, "पिरोजशा गोदरेज फाउंडेशन" को उक्त धारा के प्रयोजनार्थ निर्धारण वर्ष 1982-83 के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए अधिसूचित करती है।

[सं० 4784/फा०सं० 197/57/82-आ०क०(ए० 1)]

मिलाप जैन, अवर सचिव

New Delhi, the 6th July, 1982

S.O. 3067.—In exercise of the powers conferred by clause (iv) of sub-section (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Pirojsha Godrej Foundation" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment year 1982-83.

[No. 4784/F. No. 197/57/82-IT(AI)]

MILAP JAIN, Under Secy.

नई दिल्ली, 17 जुलाई, 1982

आय-कर

का०आ० 3068.—केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23-ग) के खण्ड (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, "चिल्ड्रन्स फिल्म सोसाइटी, इंडिया" को निर्धारण वर्ष 1976-77, 1977-78, 1980-81, 1981-82 और 1982-83 के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए उक्त धारा के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है।

[सं० 4815/फा० सं० 197/108/78-आ०क० (ए०1)]

New Delhi, the 17th July, 1982

INCOME-TAX

S.O. 3068.—In exercise of the powers conferred by clause (iv) of sub-section (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereb notifies "Children's Film Society, India" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1976-77, 1977-78, 1980-81, 1981-82 and 1982-83.

[No. 4815/F. No. 197/108/78-IT(AI)]

का०आ० 3069.—केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23-ग) के खण्ड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, "श्री सप्तश्रृंग निवासिनी देवी न्यास, नासिक" को निर्धारण 1976-77 से 1982-83 के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए उक्त धारा के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है।

[सं० 4816/फा० सं० 197/49/81 आ० क०(ए० 1)

बी० बी० श्रीनिवासन, उप सचिव

S.O. 3069.—In exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Shree Saptashrung Niwasini Devi Trust, Nasik" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1976-77 to 1982-83.

[No. 4816/F. No. 197/49/81-IT(AI)]

V. B. SRINIVASAN, Dy. Secy.

(केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा-शुल्क बोर्ड)

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 1982

सं. 204/82-सीमा-शुल्क

का. आ. 3070.—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा-शुल्क बोर्ड, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केरल राज्य राज्य के, जिला त्रिवेन्द्रम के, सेलम ताल्लुक में कल्लर भाण्डागार स्टेशन के रूप में घोषित करता है।

[फा. सं. 473/124/82-सीमा-शुल्क-7]

एन. के. कपूर, अवर सचिव,

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और सीमा-शुल्क बोर्ड

CENTRAL BOARD OF EXCISES AND CUSTOMS

New Delhi, the 4th September, 1982

NO. 204/82-CUSTOMS

S.O. 3070.—In exercise of the powers conferred by section 9 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs hereby declares Kallar in Nedumangad Taluk of Trivandrum District in the State of Kerala, to be a warehousing station.

[F. No. 473/124/82-CUS-VII]

N. K. KAPUR, Under Secy.

Central Board of Excise and Customs

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

नई दिल्ली, 15 जून, 1982

आयकर

का०आ० 3071,—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 126 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, समय-समय पर अपनी अधिसूचना सं० 1 (फा० सं० 55/233/63-आई टी०) तारीख 18 मई, 1964 से उपाबद्ध अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है।

अनुसूची में, क्रम संख्यांक 42 च (v) के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाएगा।

1	2	3	4
"(VI)	केन्द्रीय सरकार के सेवकों भिन्न ऐसे वैतनिक कर्मचारियों के सभी मामले जो भारतीय नागरिक हैं और सिक्किम में तैनात है	आ० का० अधि० सी० वार्ड, सिलीगुड़ी	वह सहायक आयुक्त (निरीक्षण) आई०ए०सी० कृत्यों के पालन के लिए नियुक्त किया गया है।

5	6
अपील सहायक आयकर आयुक्त/ आयकर आयुक्त (अपील), जिसमें स्तंभ 3 में निर्दिष्ट आ० कर अधि० के विनिश्चय के विरुद्ध अपील सुनने की शक्ति विहित की गई है।	आयकर आयुक्त, पश्चिमी बंगाल-13, कलकत्ता"

यह आदेश 1 जुलाई, 1982 से प्रभावी होगा।

[सं० 4678 (फा० सं० 188/1/82-आई टी (ए आई)]

मिलाप जैन, अवर सचिव

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

New Delhi, the 15th June, 1982

INCOME-TAX

S. O. 3071.—In exercise of the powers conferred by section 126 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes, hereby makes the following amendments in the schedule annexed to its Notification No. 1 (F. No. 55/233/63-IT) dated the 18th May, 1964 from time to time.

In the schedule after Sl. No. 42F (V) the following shall be added :—

1	2	3	4	5	6
"(VI)	All cases of salaried employees other than Central Government Servants, who are Indian Citizens and posted in Sikkim.	I.T.O., C-Ward, Siliguri.	I.A.C. who has been appointed to perform the functions of an I.A.C. in respect of C-Ward, Siliguri, West Bengal.	Appellate Assistant Commissioner of Income-tax/Commissioner of Income-tax (Appeals) who has been invested with power to hear appeals against the decision of the I.T.O., referred to in Col. 3.	C.I.T., West Bengal-XIII Calcutta.

This order shall take effect from 1st July, 1982.

[No. 4678 (F. No. 188/1/82-IT(AI)]
MILAP JAIN, Under Secy.

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बैंकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली, 20 अगस्त, 1982

का० आ० 3072.—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर एतद्द्वारा घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 10ख की उपधारा (1) और (2) के उपबंध बनारस स्टेट बैंक लिमिटेड, वाराणसी पर 30 नवम्बर, 1982 तक अथवा उसके अगले पूर्णकालिक अध्यक्ष तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, तब तक लागू नहीं होंगे।

[संख्या 15/5/82-बी० ओ० III]

एन०डी० बत्रा, अवर सचिव

(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

New Delhi, the 20th August, 1982

S.O. 3072.—In exercise of the powers conferred by section 53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government, on the recommendation of Reserve Bank of India, declares that the provisions of sub-sections (1) and (2) of section 10B of the said Act, shall not apply to the Benaras State Bank Ltd. Varanasi, till 30th November, 1982 or till the appointment of the next whole-time Chairman and Chief Executive Officer, whichever is earlier.

[No. 15/5/82-B.O.III]

N. D. BATRA, Under Secy.

(व्यय विभाग)

नई दिल्ली, 7 मई, 1982

का० आ० 3073—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (3) के अनुसरण में वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियम, 1978 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन (प्रथम संशोधन) नियम, 1982 है।

2. वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियम, 1978 की अनुसूची 1 के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची 1 रखी जाएगी, अर्थात्:—

"अनुसूची

(नियम 3 (च) देखिए)

विभागाध्यक्षों की सूची

कृषि मंत्रालय

(क) कृषि और सहकारिता विभाग

1. लेखा नियंत्रक, नई दिल्ली
2. परियोजना अधिकारी, अखिल भारतीय मृदा और भूमि उपयोग सर्वेक्षण संगठन, नई दिल्ली।
3. निदेशक, मात्स्यकी अन्वेषण परियोजना, बम्बई
4. निदेशक, केन्द्रीय मात्स्यकी, समुद्री और इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान कोचीन।
5. निदेशक, समेकित मात्स्यकी परियोजना, कोचीन।
6. निदेशक, मात्स्यकी बंदरगाहों का विकास-पूर्व सर्वेक्षण, बंगलौर
7. अध्यक्ष, वन-अनुसन्धान और महाविद्यालय, देहरादून।
8. निदेशक, ट्रैक्टर प्रशिक्षण तथा परख स्टेशन बुदनी
9. निदेशक, ट्रैक्टर प्रशिक्षण केन्द्र, हिसार।
10. निदेशक लोक विकास निदेशालय, रांची
11. निदेशक, दिल्ली-चिड़ियाघर।
12. महा प्रबंधक, दिल्ली दुग्ध योजना, नई दिल्ली।
13. निदेशक, भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून।
14. मुख्य कार्यपालिक अधिकारी, सागिंग प्रशिक्षण केन्द्र परियोजना, देहरादून
15. निदेशक, केन्द्रीय भेड़-प्रजनन फार्म, हिसार
16. निदेशक, केन्द्रीय कुक्कट उत्पादन और प्रजातंत्र प्रशिक्षण संस्थान, हेसर घट्टा बंगलौर
17. निदेशक, काजू विकास निदेशालय, कोचीन।
18. निदेशक, कपास विकास निदेशालय, मुम्बई।
19. निदेशक, जूट विकास निदेशालय, कलकत्ता।
20. निदेशक, तिलहन विकास निदेशालय, हैदराबाद।
21. निदेशक, गन्ना विकास निदेशालय, साहिबाबाद गाजियाबाद।
22. निदेशक, तम्बाकू विकास निदेशालय, मद्रास।
23. निदेशक, मिलेट, (ज्वार, बाजरा आदि) विकास निदेशालय, मद्रास।
24. निदेशक, दाल विकास निदेशालय, लखनऊ।
25. निदेशक, चावल विकास निदेशालय, पटना।
26. नारियल विकास निदेशालय, एर्नाकुलम, कोचीन, कोको, आर्कनिट और मसाला विकास निदेशालय कालीकट की बाबत उपसचिव (फसल) कृषि और सहकारिता विभाग।
27. पादप संरक्षण सलाहकार, पादप संरक्षण, संगरोध और भण्डार-करण निदेशालय, फरीदाबाद।
28. निदेशक, कृषि विमानन निदेशालय, सफदरजंग, एयरपोर्ट नई दिल्ली।
29. निदेशक, (प्रशासनिक), विस्तार निदेशालय, नई दिल्ली।
30. आयुक्त, उर्वरक विकास, फरीदाबाद।
31. आर्थिक और सांख्यिकी सलाहकार, आर्थिक और सांख्यिकी सलाहकार निदेशालय, नई दिल्ली।
32. अध्यक्ष, कृषि कीमत आयोग, नई दिल्ली।

(ख) खाद्य विभाग:

1. मुख्य निदेशक, चीनी निदेशालय, नई दिल्ली।
2. निदेशक, राष्ट्रीय चीनी संस्थान, कानपुर।

सिविल पूर्ति मंत्रालय

1. अध्यक्ष, भावी विपणन आयोग, बम्बई।
2. मुख्य निदेशक, वनस्पति, वनस्पति तेल और वसा निदेशालय, नई दिल्ली।

वाणिज्य मंत्रालय

(क) **वाणिज्य विभाग**

1. मुख्य नियंत्रक आयात और निर्यात, नई दिल्ली।
2. महानिदेशक, वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी, कलकत्ता।
3. पशु सम्पत्ति का अभिरक्षक, मुम्बई।
4. लेखा-नियंत्रक, वाणिज्य मंत्रालय।
5. विकास आयुक्त, सांताक्रुज निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र, बम्बई।
6. विकास आयुक्त, कांडला मुक्त व्यापार क्षेत्र, गांधीधाम।

(ख) वस्त्र विभाग

1. विकास आयुक्त अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड, नई दिल्ली।
2. हथकरघा विकास आयुक्त, नई दिल्ली।
3. वस्त्र आयुक्त, बम्बई।
4. पटसन आयुक्त, कलकत्ता।
5. संदाय आयुक्त, नई दिल्ली।

संचार मंत्रालय

1. महानिदेशक, समुद्र पार संचार सेवा।
2. निदेशक, मानीटर संगठन।

शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय

(क) शिक्षा विभाग।

1. निदेशक, केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, नई दिल्ली।
2. अध्यक्ष, वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग, नई दिल्ली।
3. निदेशक, प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय, नई दिल्ली।
4. लेखा-नियंत्रक, शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय, नई दिल्ली।
5. निदेशक, भारतीय भाषा केन्द्रीय संस्थान, मैसूर।
6. निदेशक, उर्दू प्रोन्नति ब्यूरो, नई दिल्ली।

(ख) संस्कृति विभाग:

1. महानिदेशालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, नई दिल्ली।
2. निदेशक, राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता।
3. निदेशक, राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली।
4. निदेशक, भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण, कलकत्ता।
5. निदेशक, भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली।
6. परियोजना अधिकारी, राष्ट्रीय सांस्कृतिक सम्पत्ति संरक्षण अनुसंधान प्रयोगशाला, लखनऊ।
7. विशेष कार्य अधिकारी, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल।
8. निदेशक, राष्ट्रीय नव कला संग्रहालय, नई दिल्ली।

ऊर्जा मंत्रालय

(क) विद्युत विभाग :

1. सदस्य-सचिव, उत्तर क्षेत्रीय विद्युत बोर्ड, नई दिल्ली।
2. सदस्य-सचिव दक्षिण क्षेत्रीय विद्युत बोर्ड, बंगलौर।
3. सदस्य-सचिव पश्चिम क्षेत्रीय विद्युत बोर्ड, मुम्बई।
4. सदस्य-सचिव, पूर्व क्षेत्रीय विद्युत बोर्ड, पटना।
5. अध्यक्ष, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण।
6. निदेशक, विद्युत पद्धति प्रशिक्षण संस्थान, बंगलौर।
7. अधीक्षक इंजीनियर, क्षेत्रीय विद्युत-धारा विश्लेषण केन्द्र, पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विद्युत बोर्ड, शिलांग।

(ख) कोयला विभाग :

1. कोयला नियंत्रक, कलकत्ता।
2. संयुक्त आयुक्त, धनबाद और कलकत्ता।

इलैक्ट्रानिक विभाग :

1. निदेशक (तकनीकी) सूचना आयोजना और समूह इलैक्ट्रानिक आयोग।

विदेश मंत्रालय

1. मुख्य पारपत्र अधिकारी।

वित्त मंत्रालय

(क) आर्थिक कार्य विभाग :

1. लेखा नियंत्रक, आर्थिक कार्य और व्यय विभाग।
2. प्रशासक, पुनर्वास वित्तीय प्रशासन यूनिट, नई दिल्ली।
3. महाप्रबन्धक, करेंसी नोट प्रेस, नासिक रोड।
4. निदेशक, आपात जोखिम बीमा योजना, नई दिल्ली।
5. बीमा-नियंत्रक शिमला।
6. भारत का राष्ट्रीय बचत आयुक्त।
7. महाप्रबंधक, भारत सरकार टकसाल, अलीपुर रोड, कलकत्ता।
8. इंचार्ज सिल्वर रिफाइनरी, कलकत्ता।
9. महाप्रबन्धक, भारत सरकार टकसाल मुम्बई।
10. मास्टर, भारत सरकार टकसाल, हैदराबाद।
11. महाप्रबंधक तथा पदेन स्टाम्प नियंत्रक, इण्डिया सिक्योरिटी प्रेस, नासिक रोड।
12. महाप्रबंधक, सिक्योरिटी पेपर मिल, होशंगाबाद।
13. महाप्रबंधक, बैंक नोट प्रेस, देवास।
14. महाप्रबन्धक, इण्डिया सिक्योरिटी प्रेस, नासिक।

(ख) व्यय विभाग

1. लेखा महानियंत्रक
2. महानियंत्रक, रक्षा लेखा

(ग) राजस्व विभाग

1. अध्यक्ष, समपहृत सम्पत्ति अपील अधिकरण, नई दिल्ली
2. आयकर आयुक्त (जिसके अन्तर्गत अपील आयुक्त है)
3. निरीक्षण निदेशक (अन्वेषण)।
4. निरीक्षण निदेशक (अनुसंधान, सांख्यिकी और प्रकाशन)
5. निरीक्षण निदेशक (प्रकाशन और जन सम्पर्क)
6. निरीक्षण निदेशक (आयकर और लेखा परीक्षा)
7. निदेशक, संगठन और पद्धति सेवाएं (आयकर) नई दिल्ली।
8. निदेशक (प्रशिक्षण), भारतीय राजस्व सेवा (प्रत्यक्ष कर) स्टाफ कालेज, नागपुर
9. तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (सम्पत्ति समपहरण) अधिनियम 1976 के अधीन कृत्यों के निर्वहन के लिए नियुक्त निरीक्षणकार्य अधिकारी, नई दिल्ली/मुम्बई/मद्रास/कलकत्ता/अहमदाबाद।
10. मुख्य लेखा नियंत्रक, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नई दिल्ली।
11. निदेशक, रत्न और आभूषण संग्रहालय, नई दिल्ली।
12. अध्यक्ष, निपटान आयोग (आयकर और धनकर)
13. निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय।
14. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क कलक्टर, अहमदाबाद, इलाहाबाद, बंगलौर, बड़ौदा, मुम्बई-1 और 2, भुवनेश्वर, कलकत्ता, चण्डीगढ़, गुण्टूर, दिल्ली, हैदराबाद, इंदौर, जयपुर, कानपुर, मद्रास, मदुरै, मेरठ, नागपुर, पटना पूणे, शिलांग और पश्चिमी बंगाल।
15. सीमा-शुल्क कलक्टर, मुम्बई, कलकत्ता, कोचीन, और मद्रास।
16. निरीक्षण निदेशक (सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क)।
17. प्रशिक्षण निदेशक (सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क)।
18. निदेशक, सांख्यिकी और आसूचना।
19. निदेशक, संगठन और पद्धति सेवाएं।
20. मुख्य रसायनज्ञ, केन्द्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला, नई दिल्ली।
21. भारकोष्टिक आयुक्त, ग्वालियर।
22. मुख्य कारखाना नियंत्रक।
23. मुख्य लेखा नियंत्रक, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा-शुल्क बोर्ड।
24. निदेशक, राजस्व और आसूचना।
25. प्रकाशन निदेशक।
26. निदेशक निवारक सतर्कताएं।
27. रजिस्ट्रार, सीमाशुल्क, उत्पादशुल्क और स्वर्ण (नियंत्रण) अपील अधिकरण।
28. निरीक्षण निदेशक (अन्वेषण) नई दिल्ली।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य विभाग :

1. निदेशक, साधारण स्वास्थ्य सेवाएं।

गृह मंत्रालय

1. निदेशक, आसूचना ब्यूरो।
2. निदेशक, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद।
3. महारजिस्ट्रार और भारत का पदेन जनगणना आयुक्त
4. महानिदेशक, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल।
5. भापायी अल्पसंख्यक आयुक्त, इलाहाबाद।
6. समन्वय निदेशक (पुलिस बे-तार)
7. महानिदेशक, सिविल सुरक्षा।
8. पुलिस महानिरीक्षक, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस।
9. महानिदेशक, असम राइफल्स
10. महानिदेशक, सीमा सुरक्षा बल।
11. महानिरीक्षक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, सैक्टर 1,2,3 और 4।
12. निदेशक, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो

13. महानिदेशक, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल।
14. महानिदेशक, पिछड़े वर्ग कल्याण ब्यूरो।
15. आयुक्त, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति।
16. सचिव, उत्तर-पूर्वीय परिषद।
17. निदेशक, अपराध विज्ञान और न्याय-विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली।
18. महा प्रबन्धक, अक्षधूम एकक।
19. समन्वय निदेशक (पुलिस कम्प्यूटर)
20. मुख्य नियंत्रक।
21. निदेशक केन्द्रीय न्याय-विज्ञान प्रयोगशाला, नई दिल्ली
22. सदाय संभव, जेल सुधार समिति, नई दिल्ली।
23. महानिदेशक, सीमा सुरक्षा बल,
    (i) पूर्वी सीमान्त, कलकत्ता।
    (ii) पश्चिमी सीमान्त, जालंधर छावनी।
    (iii) उत्तर-पश्चिमी सीमान्त, श्रीनगर।

संघ राज्य क्षेत्र

(क) अन्डमान और निकोबार द्वीप :
1. मुख्य वन नियंत्रक
2. मुख्य सचिव
3. विकास आयुक्त
4. उप-आयुक्त, पोर्ट ब्लेयर
5. मुख्य इंजीनियर, लोक निर्माण विभाग अन्डमान
6. वित्तीय सचिव व मुख्य वेतन और लेखा अधिकारी
7. उप-आयुक्त, निकोबार द्वीप।

(ख) गोवा, दमन और दीव :
1. मुख्य सचिव
2. लेखा निदेशक
4. कलक्टर, दमन
4. विकास आयुक्त
5. कलक्टर, गोवा
6. सचिव, उद्योग और श्रम
7. न्यायिक आयुक्त
8. उप-राज्यपाल का सचिव
9. मुख्य विद्युत इंजीनियर
10. मुख्य इंजीनियर, लोक निर्माण विभाग
11. शिक्षा निदेशक
12. राजस्व सचिव

(ग) दादरा और नागर हवेली
1. कलक्टर, दादरा और नागर हवेली

(घ) चण्डीगढ़
1. मुख्य इंजीनियर, राजधानी परियोजना
2. निदेशक, स्नातकोत्तर संस्थान
3. आयुक्त पंजाब, इंजीनियरिंग महाविद्यालय और पदेन निदेशक, तकनीकी शिक्षा
4. नियंत्रण, मुद्रण और लेखन सामग्री
5. पुलिस महानिरीक्षक

(ङ) दिल्ली :
1. पुलिस आयुक्त
2. मुख्य सचिव

(च) पाण्डिचेरी
1. मुख्य सचिव

(छ) अरुणाचल प्रदेश
1. मुख्य सचिव।

(ज) मिजोरम
1. मुख्य सचिव

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग
1. निदेशक, लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी, मंसूरी
2. निदेशक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो
3. निदेशक, सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान
4. अध्यक्ष, कर्मचारी चयन आयोग
5. केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त

उद्योग मंत्रालय

(क) औद्योगिक विकास विभाग।
1. सचिव (तकनीकी विकास) और महानिदेशक, तकनीकी विकास, नई दिल्ली।
2. विकास आयुक्त, लघु उद्योग, नई दिल्ली।
3. अध्यक्ष, औद्योगिक लागत और कीमत ब्यूरो, नई दिल्ली।
4. वित्तीय सलाहकार, नई दिल्ली।
5. महानिदेशक, औद्योगिक आकास्मिकताएं, नई दिल्ली
6. पेटेन्ट, डिजाइन और व्यापार चिन्ह महानियंत्रक, मुम्बई।
7. सीमेन्ट नियंत्रक, नई दिल्ली।
8. मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, नागपुर
9. नमक आयुक्त, जयपुर।
10. मुख्य लेखा नियंत्रक, उद्योग मंत्रालय।

(ख) भारी उद्योग विभाग :
1. संदाय आयुक्त, कलकत्ता।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

1. महानिदेशक, आकाशवाणी।
2. मुख्य सूचना अधिकारी।
3. मुख्य निर्माता, फिल्म प्रभाग, मुम्बई।
4. निदेशक, प्रकाशन प्रभाग।
5. निदेशक, विज्ञापन और दृश्य प्रचार।
6. निदेशक, क्षेत्रीय प्रचार।
7. भारत के समाचार पत्रों का रजिस्ट्रार।
8. निदेशक, गीत और नाटक प्रभाग।
9. अध्यक्ष, केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड, मुम्बई।
10. निदेशक, अनुसंधान और निवेश प्रभाग।
11. मुख्य लेखा अधिकारी (लेखा नियंत्रक)।
12. महा निदेशक, दूरदर्शन।

सिंचाई मंत्रालय

1. अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग।
2. निदेशक, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान स्टेशन।
3. अध्यक्ष, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग।
4. महा प्रबंधक, फरक्का बराज परियोजना।
5. वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी, फरक्का बराज परियोजना।
6. सचिव, गोदावरी जल विवाद अधिकरण।
7. सचिव, माही नियंत्रण बोर्ड।
8. वित्तीय सलाहकार, माही नियंत्रण बोर्ड।
9. सचिव, बाणसागर नियंत्रण परियोजना।
10. सचिव, फरक्का बराज नियंत्रण बोर्ड।
11. निदेशक, राष्ट्रीय बाढ़ आयोग, नई दिल्ली।
12. निदेशक, मृदा और धातु अनुसंधान केन्द्र।

श्रम मंत्रालय

1. निदेशक, श्रम ब्यूरो, चण्डीगढ़ ।
2. महा निदेशक, खान सुरक्षा, धनबाद ।
3. लौह अयस्क खान, बीड़ी, चूना पत्थर और डोलामाइट खान, कल्याण निधि कल्याण आयुक्त, जबलपुर ।
4. अभ्रक, चूना पत्थर और डोलामाइट खान, बीड़ी कल्याण निधि, कल्याण आयुक्त, इलाहाबाद ।
5. लौह अयस्क खान, चूना पत्थर और डोलामाइट खान, बीड़ी, कल्याण निधि कल्याण आयुक्त, भुवनेश्वर
6. अभ्रक, चूना पत्थर और डोलामाइट खान, बीड़ी, कल्याण निधि कल्याण आयुक्त, भीलवाड़ा ।
7. लौह अयस्क खान कल्याण निधि, कल्याण आयुक्त, पणजी गोवा।
8. लौह अयस्क खान, अभ्रक, चूना पत्थर और डोलामाइट खान, बीड़ी कल्याण निधि, कल्याण आयुक्त बंगलौर ।
9. महानिदेशक, कारखाना सेवा सलाह, मुम्बई ।
10. अध्यक्ष, माध्यस्थम बोर्ड (संयुक्त परामर्शीतंत्र), नई दिल्ली ।
11. प्रशिक्षण निदेशक, रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय मुख्यालय, नई दिल्ली ।
12. निदेशक, रोजगार कार्यालय, रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय मुख्यालय, नई दिल्ली ।
13. निदेशक, साधारण कर्मचारिवृन्द प्रशिक्षण और अनुसंधान, संस्थान कलकत्ता ।
14. निदेशक, उच्च प्रशिक्षण संस्थान, हैदराबाद और मद्रास ।
15. निदेशक, फारमेन प्रशिक्षण संस्थान, बंगलौर ।
16. क्षेत्रीय निदेशक, शिक्षुता प्रशिक्षण, कलकत्ता, मुम्बई, मद्रास और कानपुर ।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(क) विधायी विभाग :

1. मुख्य निर्वाचन आयुक्त

(ख) कम्पनी कार्य विभाग :

1. सचिव, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग ।
2. क्षेत्रीय निदेशक, कम्पनी विधि बोर्ड, मुम्बई, मद्रास, कानपुर और कलकत्ता ।
3. सदस्य सचिव, उच्च शक्ति-प्राप्त विशेषज्ञ समिति ।
4. अन्वेषण निदेशक, एकाधिकार और अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग, नई दिल्ली ।
5. रजिस्ट्रार एकाधिकार और अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग नई दिल्ली ।

(ग) विधि-कार्य विभाग :

1. अध्यक्ष, आयकर अपील अधिकरण ।

योजना मंत्रालय

सांख्यिकी विभाग :

1. निदेशक, केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, नई दिल्ली ।
2. निदेशक, संगणक केन्द्र, नई दिल्ली ।
3. निदेशक, क्षेत्र सक्रिया प्रभाग, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, नई दिल्ली ।
4. निदेशक, सर्वेक्षण, डिजाइन और अनुसंधान प्रभाग ।

ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय

1. कृषि विपणन सलाहकार, विपणन और निरीक्षण निदेशालय, नागपुर ।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

1. महासर्वेक्षक, भारतीय सर्वेक्षण, देहरादून ।
2. निदेशक, नेशनल एटलस एण्ड थेमेटिक मैपिंग संगठन, कलकत्ता ।
3. लेखा-नियंत्रक ।

पर्यावरण विभाग

1. निदेशक, भारतीय प्राणि विज्ञान सर्वेक्षण, कलकत्ता ।
2. निदेशक, भारतीय वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण, कलकत्ता ।
3. योजना अधिकारी, राष्ट्रीय प्राकृति इतिहास संग्रहालय नई दिल्ली।

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

1. महानिदेशक, नौवहन, मुम्बई ।
2. महानिदेशक, प्रकाश गृह एवं प्रकाश पोत ।
3. अध्यक्ष, अन्तर्राज्यीय परिवहन आयोग ।
4. अध्यक्ष, वाणिज्यिक समुद्रीय विभाग, मुम्बई, कलकत्ता और मद्रास।
5. मुख्य इंजीनियर और प्रशासक, अन्डमान, लक्षद्वीप बन्दरगाह संकर्म ।
6. मुख्य इंजीनियर और प्रशासक, अन्तर्देशीय जल परिवहन निदेशालय।
7. लेखा-नियंत्रक ।

समाज कल्याण मंत्रालय

1. निदेशक, राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान, नई दिल्ली ।
2. निदेशक, राष्ट्रीय दृष्टि-विकलांग संस्थान, देहरादून ।

इस्पात और खान मंत्रालय

(क) खान विभाग :

1. महानिदेशक, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, कलकत्ता ।
2. निदेशक भारसाधक, एयर बोर्न मिनरल सर्वे एक्सप्लोरेशन विंग भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, बंगलौर ।
3. नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर ।
4. लेखा-नियंत्रक, इस्पात और खान मंत्रालय, नई दिल्ली ।
5. लेखा नियंत्रक, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ।
6. उप महानिदेशक, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण केन्द्रीय मुख्यालय (कलकत्ता) पश्चिमी क्षेत्र (जयपुर), उत्तरी क्षेत्र (लखनऊ) मध्य क्षेत्र (नागपुर), दक्षिणी-क्षेत्र (हैदराबाद), पूर्वी क्षेत्र, (कलकत्ता), पूर्वोत्तर क्षेत्र (शिलांग) भारसाधक, आफ शोर मिनरल एक्सप्लोरेशन एण्ड मैरीन जियोलाजी डिवीजन ।

(ख) इस्पात विभाग .

1. लौह और इस्पात नियंत्रक, कलकत्ता ।

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय

(क) पुनर्वास विभाग :

1. मुख्य प्रशासक, दण्डकारण्य, विकास प्राधिकरण, कोरापुट ।
2. वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी, दण्डकारण्य परियोजना, जयपुर ।
3. मुख्य महालेखक, माना समूह, पारगमन केन्द्र, रक्षक मध्य प्रदेश ।
4. मुख्य कार्यपालक, मुख्य विस्थापित व्यक्ति पुनर्वास प्राधिकरण, जम्मू ।
5. मुख्य यांत्रिक इंजीनियर, पुनर्वास पुनरुद्धार संगठन, माना, मध्य प्रदेश ।

(ख) पूर्ति विभाग :

1. महा निदेशक, पूर्ति और व्ययन ।
2. मुख्य लेखा नियंत्रक ।
3. निदेशक, राष्ट्रीय परीक्षण गृह, कलकत्ता ।

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय

1. महानिदेशक पर्यटन ।
2. महा निदेशक, नागर विमानन ।
3. महानिदेशक, मौसम विज्ञान ।
4. मुख्य आयुक्त, रेल सुरक्षा, लखनऊ ।
5. आयुक्त, रेल सुरक्षा :—
(i) दक्षिण-पूर्वी सर्किल, कलकत्ता ।
(ii) मुख्य सर्किल, मुम्बई ।
(iii) पूर्वोत्तर सर्किल, गोरखपुर ।
(iv) पश्चिमी सर्किल, मुम्बई ।
(v) पूर्वी सर्किल, कलकत्ता ।
(vi) उत्तरी सर्किल, लखनऊ ।
(vii) दक्षिणी सर्किल, बंगलौर ।

निर्माण और आवास मंत्रालय

1. सतर्कता, केन्द्रीय डिजाइन संगठन और विद्युत मुख्य इंजीनियरी को छोड़कर केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के सभी मुख्य इंजीनियर ।
2. महानिदेशक (निर्माण) केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग ।
3. मुद्रण निदेशक ।
4. लेखन-सामग्री नियंत्रक ।
5. प्रकाशन नियंत्रक ।
6. सम्पदा निदेशक ।
7. निदेशक, राष्ट्रीय निर्माण संगठन ।
8. अध्यक्ष, नगर और ग्रामीण संगठन ।
9. सलाहकार लोक स्वास्थ्य और वातावरणीय इंजीनियरी संगठन

[सं० का० 1(1)-इ-2(ए)/80]
वी० सी० तिवारी अवर सचिव,

टिप्पण —वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियम, 1978 का अधिसूचना सं० का० आ० 2131 द्वारा भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित किया गया । तत्पश्चात निम्नलिखित द्वारा संशोधन किया गया :—

(i) अधिसूचना सं० का० आ० 1887 तारीख 9-6-1978
(ii) अधिसूचना सं० का० आ० 2947 तारीख 1-9-1979
(iii) अधिसूचना सं० का० आ० 2611 तारीख 4-10-1980
(iv) अधिसूचना सं० का० आ० 2164 तारीख 15-8-1981
(v) अधिसूचना सं० का० आ० 2304 तारीख 5-4-1981

(Department of Expenditure)

New Delhi, the 27th May, 1982

S.O. 3073.—In pursuance of clause (3) of article 77 of the Constitution of India, the President hereby makes the following rules further to amend the Delegation of Financial Powers Rules, 1978, namely :—

1. These rules may be called the Delegation of Financial Powers (First Amendment) Rules, 1982.

2. In the Delegation of Financial Powers Rules, 1978, for Schedule I, the following Schedule I shall be substituted namely :—

"SCHEDULE I

[See rule 3(f)]

LIST OF HEADS OF DEPARTMENTS

MINISTRY OF AGRICULTURE

(A) Department of Agriculture and Cooperation :

1. Controller of Accounts, New Delhi.
2. Project Officer, All India Soil and Land and Use Survey Organisation, New Delhi.
3. Director, Exploratory Fisheries Project, Bombay.
4. Director, Central Institute of Fisheries Project, Nautical Bombay and Engineering Training, Cochin.
5. Director, Integrated Fisheries Project, Cochin.
6. Director, Pre-investment Survey of Fishing Harbours, Bangalore.
7. President, Forest Research Institute and College, Dehradun.
8. Director, Tractor Training and Testing Station, Budni.
9. Director, Tractor Training Centre, Hissar.
10. Director, Directorate of Lac Development, Ranchi.
11. Director, Delhi Zoological Park, New Delhi.
12. General Manager, Delhi Milk Scheme, New Delhi.
13. Director, Forest Survey of India, Dehradun.
14. Chief Executive Officer, Logging Training Centre Project, Dehradun.
15. Director, Central Sheep Breeding Farm, Hissar.
16. Director, Central Training Institute for Poultry Production and Management, Hessarghatta, Bangalore.
17. Director, Directorate of Cashewnut Development, Cochin.
18. Director, Directorate of Cotton Development, Bombay.
19. Director, Directorate of Jute Development, Calcutta.
20. Director, Directorate of Oilseeds Development, Hyderabad.
21. Director, Directorate of Sugarcane Development, Sahibabad. Ghaziabad.
22. Director, Directorate of Tobacco Development, Madras.
23. Director, Directorate of Millets Development, Madras.
24. Director, Directorate of Pulses Development, Lucknow.
25. Director, Directorate of Rice Development, Patna.
26. Deputy Secretary (Crops), Department of Agriculture and Cooperation in respect of Directorate of Coconut Development, Ernakulam, Cochin, Directorate of Coco, Aracanut and Spices Development Calicut.
27. Plant Protection Adviser, Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage, Faridabad.
28. Director, Directorate of Agricultural Aviation, Safdarjung Airport, New Delhi.
29. Director (Administration), Directorate of Extension, New Delhi.
30. Commissioner, Fertilizer Promotion, Faridabad.
31. Economic and Statistical Adviser, Directorate of Economics and Statistical Adviser, New Delhi.
32. Chairman, Agricultural Prices Commission, New Delhi.

(B) Department of Food :

1. Chief Director, Directorate of Sugar, New Delhi.
2. Director, National Sugar Institute, Kanpur.

MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES

1. Chairman, Forward Marketing Commission, Bombay.
2. Chief Director, Directorate of Vanaspati, Vegetable Oils and Fats, New Delhi.

MINISTRY OF COMMERCE

(A) Department of Commerce :

1. Chief Controller of Imports and Exports, New Delhi.
2. Director General, Commercial Intelligence and Statistics, Calcutta.
3. Custodian of Enemy Property, Bombay.
4. Controller of Accounts, Ministry of Commerce.
5. Development Commissioner, Santa Cruz Export Processing Zone, Bombay.
6. Development Commissioner, Kandla Free Trade Zone, Gandhidham.

(B) Department of Textiles :

1. Development of Commissioner, All India Handicrafts Board, New Delhi.
2. Development Commissioner for Handlooms, New Delhi.
3. Taxtile Commissioner, Bombay.
4. Jute Commissioner, Calcutta.
5. Commissioner of Payments, Calcutta.

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

1. Director General Overseas Communications Commissions Service.
2. Director, Monitoring Organisation.

MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE

(A) Department of Education :

1. Director, Central Hindi Directorate, New Delhi.
2. Chairman, Commission for Scientific and Technical Terminology, New Delhi.
3. Director, Directorate of Adult Education, New Delhi.
4. Controller of Accounts, Ministry of Education and Culture, New Delhi.
5. Director, Central Institute of Indian Languages, Mysore.
6. Director, Bureau for Promotion of Urdu, New Delhi.

(B) Department of Culture.

1. Director, General Archeological Survey of India, New Delhi.
2. Director, National Library, Calcutta.
3. Director, National Museum, New Delhi.
4. Director, Anthropological Survey of India, Calcutta.
5. Director, National Archives of India, New Delhi.
6. Project Officer, National Research Laboratory for Conservation of Cultural Property, Lucknow.
7. Officer on Special Duty, National Museum of Man, Bhopal.
8. Director, National Gallery of Modern Art, New Delhi.

MINISTRY OF ENERGY

(A) Department of Power :

1. Member Secretary, Northern Regional Electricity Board, New Delhi.
2. Member Secretary, Southern Regional Electricity Board, Bangalore.
3. Member Secretary, Western Regional Electricity Board, Bombay.
4. Member Secretary, Eastern Regional Electricity Board, Patna.
5. Chairman, Central Electricity Authority.
6. Director, Power Systems Training Institute, Bangalore.
7. Superintendent Engineer, Regional Load Despatch Centre, North-Eastern Regional Electricity Board, Shillong.

(B) Department of Coal.

1. Coal Controller, Calcutta.
2. Commissioners of Payments, Dhanbad and Calcutta.

DEPARTMENT OF ELECTRONICS

1. Director (Technical), Information Planning and Group Electronics Commission.

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

1. Chief Passport Officer.

MINISTRY OF FINANCE

(A) Department of Economic Affairs :

1. Controller of Accounts for Department of Economic Affairs and Expenditure.
2. Administrator, Rehabilitation Finance Administration Unit, New Delhi.
3. General Manager, Currency Note Press, Nasik Road.
4. Director, Emergency Risks Insurance Scheme, New Delhi.
5. Controller of Insurance, Simla.
6. National Savings Commissioner for India.
7. General Manager, Government of India Mint, Alipore Road, Calcutta, Incharge Silver Refinery, Calcutta.
8. General Manager, Government of India Mint, Bombay
9. Master, Government of India, Mint, Hyderabad.
10. General Manager and Ex-Officio Controller of Stamp., India Security Press, Nasik Road.
11. General Manager, Security Paper Mill, Hoshangabad.
12. General Manager, Bank Note Press, Dewas.
13. General Manager, India Security Press, Nasik.

(B) Department of Expenditure :

1. Controller General of Accounts.
2. Controller General of Defence Accounts.

(C) Department of Revenue :

1. Chairman, Appellate Tribunal for Forefeited Property, New Delhi.
2. Commissioners of Income Tax (including Commissioners Appeals).
3. Director of Inspection (Investigation).
4. Director of Inspection (Research, Statistics and Publication).
5. Director of Inspection (Publication and Public Relations).
6. Director of Inspection (Income-Tax and Audit).
7. Director of Organisation and Methods Services (Income-Tax), New Delhi.
8. Director (Training), Indian Revenue Services (Direct Taxes) Staff College, Nagpur.
9. Officers on Special Duty, Competent Authorities appointed to perform functions under the Smugglers and Foreign Exchange, Manipulators (Forefeiture of Property) Act, 1976, New Delhi/Bombay/Madras/Calcutta/Ahmedabad.
10. Chief Controller of Accounts, Central Board of Direct Taxes, New Delhi.
11. Director of Gems and Jewellery Museum, New Delhi.
12. Chairman, Settlement Commission (Income Tax and Wealth Tax).
13. Director, Enforcement Directorate.
14. Collectors of Central Excise, Ahmedabad, Allahabad, Bangalore, Baroda, Bombay-I and II, Bhubaneshwar, Calcutta, Chandigarh, Delhi, Gantur, Hyderabad, Indore, Jaipur, Kanpur, Madras, Madurai, Meerut, Nagpur, Patna, Poona, Shillong and West Bengal.
15. Collectors of Customs, Bombay, Calcutta, Cochin and Madras.
16. Director of Inspection (Customs and Central Excise).
17. Director of Training (Customs and Central Excise).
18. Director of Statistics and Intelligence.
19. Director of Organisation and Methods Services.
20. Chief Chemist, Central Revenue Control Laboratory, New Delhi.
21. Narcotics Commissioner, Gwalior.
22. Chief Controller of Factories.
23. Chief Controller of Accounts, Central Board of Excise and Customs.
24. Director of Revenue and Intelligence.

25. Director of Publication.
26. Director of Preventive Operations.
27. Registrar, Customs, Excise and Gold (Control) Appellate Tribunal.
28. The Director of Inspection (Special Investigation), New Delhi.

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

Department of Health :

1. Director General Health Services.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

1. Director, Intelligence Bureau.
2. Director, Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Hyderabad.
3. Registrar General and Ex-Officio Census Commissioner for India.
4. Director General, Central Reserve Police Force.
5. Commissioner for Linguistic Minorities, Allahabad.
6. Director of Coordination (Police Wireless).
7. Director General Civil Defence.
8. Inspector General of Police, Indo-Tibetan Border Police.
9. Director General, Assam Rifles.
10. Director General, Border Security Force.
11. Inspector General, Central Reserve Police Force, Sectors I, II, III and IV.
12. Director, Bureau of Police Research and Development.
13. Director General, Central Industrial Security Force.
14. Director General, Backward Classes Welfare.
15. Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes.
16. Secretary, Northern Eastern Council.
17. Director, Institute of Criminology and Forensic Science, New Delhi.
18. General Manager, Tear Smoke Unit.
19. Chief Controller of Accounts.
20. Director, Coordination (Police Computers).
21. Director, Central Forensic Science Laboratory New Delhi.
22. Member Secretary, Committee on Jail Reforms, New Delhi.
23. Inspectors General, Border Security Force :
    (i) Eastern Frontier, Calcutta.
    (ii) Western Frontier, Jullundur Cantonment.
    (iii) North-Western Frontier, Srinagar.

UNION TERRITORIES

(a) Andaman and Nicobar Islands :

1. Chief Conservator of Forests.
2. Chief Secretary.
3. Development Commissioner,
4. Deputy Commissioner, Port Blair.
5. Principal Engineer, Andaman Public Works Department.
6. Finance Secretary-cum-Chief Pay and Accounts Officer.
7. Deputy Commissioner, Nicobar Islands.

(b) Goa, Daman and Diu :

1. Chief Secretary.
2. Director of Accounts.
3. Collector of Daman.
4. Development Commissioner,
5. Collector of Goa.
6. Secretary, Industries and Labour.
7. Judicial Commissioner.
8. Secretary to the Lt. Governor.
9. Chief Electrical Engineer.
10. Chief Engineer, Public Works Department.
11. Director of Education.
12. Revenue Secretary.

(c) Dadra and Nagar Haveli :

1. Collector, Dadra and Nagar Haveli.

(d) Chandigarh :

1. Chief Engineer, Capital Project.
2. Director, Post Graduate Institute.
3. The Professor, Punjab Engineering College and Ex-Officio Director of Technical Education.
4. Controller of Printing and Stationery.
5. Inspector General of Police.

(e) Delhi :

1. Commissioner of Police.
2. Chief Secretary.

(f) Pondicherry :

1. Chief Secretary.

(g) Arunachal Pradesh :

1. Chief Secretary.

(h) Mizoram :

1. Chief Secretary.

Department of Personnel and Administrative Reforms.

1. Director, Lal Bahadur Shastri Academy of Administration, Mussoorie.
2. Director, Central Bureau of Investigation.
3. Director, Institute of Secretariat Training and Management.
4. Chairman, Staff Selection Commission.
5. Central Vigilance Commissioner.

MINISTRY OF INDUSTRY

(A) Department of Industrial Development :

1. Secretary (Technical Development) and Director General of Technical Development, New Delhi.
2. Development Commissioner for Small Scale Industries, New Delhi.
3. Chairman, Bureau of Industrial Costs and Prices New Delhi.
4. Economic Adviser, New Delhi.
5. Director General of Industrial Contingencies, New Delhi.
6. Controller General of Patents, Designs and Trade Marks, Bombay.
7. Cement Controller, New Delhi.
8. Chief Controller of Explosives, Nagpur.
9. Salt Commissioner, Jaipur.
10. Chief Controller of Accounts, Ministry of Industry.

(B) Department of Heavy Industry.

1. Commissioner of Payments, Calcutta.

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

1. Director General, All India Radio.
2. Principal, Information Officer.
3. Chief Producer, Films Division, Bombay.
4. Director, Publications Division.
5. Director, Advertising and Visual Publicity.
6. Director of Field Publicity.
7. Registrar of News papers for India.
8. Director, Song and Drama Division.

9. Chairman, Central Board of Films Censors, Bombay.
10. Director, Research and Reference Division.
11. Principal Account Officer (Controller of Accounts).
12. Director General, Doordarshan.

MINISTRY OF IRRIGATION

1. Chairman, Central Water Commission.
2. Director, Central Water and Power Research Station.
3. Chairman, Ganga Flood Control Commission.
4. General Manager, Farrakka Barrage Project.
5. Financial Adviser and Chief Accounts Officer, Farrakka Barrage Project.
6. Secretary, Godawari Water Dispute Tribunal.
7. Secretary, Mahi Control Board.
8. Financial Adviser, Mahi Control Board.
9. Secretary, Bansagar Control Project.
10. Secretary, Farrakka Barrage Control Board.
11. Director, Rashtriya Barh Ayog, New Delhi.
12. Director, Soil and Material Research Station.

MINISTRY OF LABOUR

1. The Director, Labour Bureau, Chandigarh.
2. Director General, Mines Safety, Dhanbad.
3. Welfare Commissioner Iron Ore Mines, Beedi, Limestone and Dolomite Mines, Welfare, Funds, Jabalpur.
4. Welfare Commissioner, Mica, Limestone and Dolomite Mines, Beedi, Welfare Fund, Allahabad.
5. Welfare Commissioner, Iron Ore Mines, Limestone and Dolomite Mines, Beedi, Welfare Fund, Bhubaneshwar.
6. Welfare Commissioner, Mica, Limestone and Dolomite Mines, Beedi, Welfare Fund, Bhilwara.
7. Welfare Commissioner, Iron Ore Mines Welfare Fund, Panaji Goa.
8. Welfare Commissioner, Iron Ore Mines, Mica, Limestone and Dolomite Mines, Beedi, Welfare Fund, Bangalore.
9. Director General, Factory Advice Service, Bombay.
10. Chairman, Board of Arbitration (Joint Consultative Machinery), New Delhi.
11. Director of Training, Directorate General of Employment and Training Headquarters, New Delhi.
12. Director of Employment Exchanges, Directorate General of Employment and Training Headquarters, New Delhi.
13. Director, General Staff Training and Research Institute, Calcutta.
14. Director, Advanced Training Institute, Hyderabad and Madras.
15. Director, Foreman Training Institute, Bangalore.
16. Regional Directors of Apprenticeship Training, Calcutta, Bombay, Madras and Kanpur.

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(A) Legislative Department :

1. Chief Election Commissioner.

(B) Department of Company Affairs :

1. Secretary, Monopolies, Restrictive Trade Practices Commission.
2. Regional Directors, Company Law Board, Bombay, Madras, Kanpur and Calcutta.
3. Member Secretary, High Powered Expert Committee.
4. Director of Investigation, Monopolies, Restrictive Trade Practices Commission, New Delhi.
5. Registrar of Restrictive Trade Agreements, Monopolies, Restrictive Trade Practices Commission, New Delhi.

(C) Department of Legal Affairs :

1. President, Income Tax Appellate Tribunal.

MINISTRY OF PLANNING

Department of Statistics :

1. Director, Central Statistical Organisation, New Delhi.
2. Director, Computor Centre, New Delhi
3. Director, Field Operations Division, National Sample Survey Organisation, New Delhi.
4. Director, Survey Design and Research Division.

MINISTRY OF RURAL RECONSTRUCTION

1. Agricultural Marketing Adviser, Directorate of Marketing and Inspection, Nagpur.

Department of Science and Technology

1. Surveyor General Survey of India, Dehradun.
2. Director of National Atlas and Thematic Mapping Organisation, Calcutta.
3. Controller of Accounts.

Department of Environment

1. Director, Zoological Survey of India, Calcutta.
2. Director, Botanical Survey of India, Calcutta.
3. Planning Officer, National Museum of Natural History, New Delhi.

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

1. Director General of Shipping, Bombay.
2. Director General of Light Houses and Light Ships.
3. Chairman, Inter-State Transport Commission.
4. Principal, Mercantile Marine Department, Bombay, Calcutta and Madras.
5. Chief Engineer and Administrator, Andaman, Lakshdweep Harbour Works.
6. Chief Engineer and Administrator, Directorate of Inland Water Transport.
7. Controller of Accounts.

MINISTRY OF SOCIAL WELFARE

1. The Director, National Institute of Social Defence, New Delhi.
2. The Director, National Institute for the Visually Handicapped, Dehradun.

MINISTRY OF STEEL AND MINES

(A) Department of Mines :

1. Director General, Geological Survey of India, Calcutta.
2. Director-in-Charge, Air Borne Mineral Survey Exploration Wing, Geological Survey of India, Bangalore.
3. Controller, Indian Bureau of Mines, Nagpur.
4. Controller of Accounts, Ministry of Steel and Mines, New Delhi.
5. Controller of Accounts, Geological Survey of India.
6. Deputy Directors General, Geological Survey of India, Central Headquarters (Calcutta), Western Region (Jaipur), Northern Region (Lucknow), Central Regional, (Nagpur), Southern Region (Hyderabad), Eastern Region (Calcutta), North-Eastern Region (Shillong), Incharge of Off-Shore Mineral Exploration and Marine Geology Division.

(B) Department of Steel

1.Iron and Steel Controller, Calcutta.

MINISTRY OF SUPPLY AND REHABILITATION

(A) Department of Rehabilitation :

1. Chief Administrator, Dandakaranya Development Authority, Koraput.
2. Financial Adviser and Chief Accounts Officer, Dandakaranya Project, Jagdalpur.
3. Chief Commandant, Mana Group of Transit Centres, Mana, Madhya Pradesh.
4. Chief Executive, Chhamb Displaced Persons Rehabilitation Authority, Jammu.
5. Chief Mechanical Engineer, Rehabilitation Reclamation Organisation, Mana, Madhya Pradesh.

(B) Department of Supply :

1. Director General Supplies and Disposals.
2. Chief Controller of Accounts.
3. Director General, National Test House, Calcutta.

MINISTRY OF TOURISM AND CIVIL AVIATION

1. Director General of Tourism.
2. Director General of Civil Aviation.
3. Director General of Meteorology.
4. Chief Commissioner of Railway Safety, Lucknow.
5. Commissioner of Railway Safety:—
   (i) South Eastern Circle, Calcutta.
   (ii) Central Circle,. Bombay
   (iii) North Eastern Circle, Gorakhpur.
   (iv) Western Circle, Bombay
   (v) Eastern Circle, Calcutta.
   (vi) Northern Circle, Lucknow.
   (vii) Southern Circle, Bangalore.

MINISTRY OF WORKS AND HOUSING

1. All Chief Engineers in Central Public Works Department except Chief Engineers, Vigilance, Central Design Organisation and Electrical.
2. Director General (Works), Central Public Works Department.
3. Director of Printing.
4. Controller of Stationery.
5. Controller of Publications.
6. Director of Estates.
7. Director National Building Organisation.
8. Chairman, Town and Country Planning Organisation.
9. Adviser, Public Health and Environmental Engineering Organisation.

[No. F. 1(1)-EII(A)/80]

V. C. TEWARI, Under Secy.

NOTE : The Delegation of Financial Powers Rules, 1978 published vide Notification No. S.O. 2131 appearing in Part II, Section (3), Sub-Section (ii) of the Gazette of India dated July 22, 1978 Subsequently amended by :

(i) Notification No. S.O. 1887 dated 9-6-1979
(ii) Notification No. S.O. 2942 dated 4-9-1979
(iii) Notification No. S.O. 2611 dated 4-10-1980
(iv) Notification No. S.O. 2164 dated 15-8-1981
(v) Notification No. S.O. 2304 dated 5-9-1981.

समाहर्तालय : केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, इन्दौर

अधिसूचना सं० 10/82

इन्दौर, 24 जुलाई, 1982

का०आ० 3074.—मध्यप्रदेश समाहर्तालय इंदौर के सर्वश्री एच० पी० सांघी, अधीक्षक, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समूह 'ख' निवर्तन की आयु प्राप्त करने पर 31-5-82 के अपराह्न से शामिल सेवा से निवृत्त हुए।

मध्यप्रदेश समाहर्तालय इंदौर के सर्वश्री के० वी० प्रधान, अधीक्षक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समूह 'ख' निवर्तन की आयु प्राप्त करने पर 30-6-82 के अपराह्न से शासकीय सेवा से निवृत्त हुए।

[प० स० 11(3) 9-गोप/82/3958]

(Central Ecise Collectorate, Indore)

NOTIFICATION NO. 10/82

Indore, the 24th July, 1982

S.O. 3074.—Shri H. P. Sanghi, Superintendent, Central Excise, Group 'B' of M.P. Collectorate, Indore having attained the age of superannuation has retired from Govt service in the after-noon of 31st May, 1982.

2. Shri K. V. Pradhan, Superintendent, Central Excise, Group 'B' of M.P. Collectorate, Indore having attained the age of superannuation has retired from Govt. service in the after-noon of 30th June, 1982.

[C. No. II(3)9-Con.|82|3958]

अधिसूचना सं० 11/82

इन्दौर, 16 अगस्त, 1982

का०आ० 3075—मध्यप्रदेश समाहर्तालय, इन्दौर के सर्व श्री एम० रशीद तथा बी० वी० द्विवेदी, अधीक्षक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समूह 'ख' निर्वतन की आयु प्राप्त करने पर 31-7-82 के उपरान्ह से शासकीय सेवा से निवृत्त हुए।

[प० सं० 11(3) 9-गोप/82/140]

एस०के० धर, समाहर्ता

NOTIFICATION NO. 11/82

Indore, the 16th August, 1982

S.O. 3075.—S/Shri M. Rashid and B. V. Dwivedi, Superintendent, Central Excise, Group 'B' of MP. Collectorate, Indore, having attained the age of superannuation have retired from Govt. service in the afternoon of 31st July, 1982.

[C. No. II(3)9-Con|82|4582]

S. K. DHAR, Collector.

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समाहर्तालय : कलकत्ता

अधिसूचना सं० 3-के० उ०/1982

कलकत्ता, 14 जुलाई, 1982

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

का०आ० 3076—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 1944 के नियम 5 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए मैं इसके द्वारा समाहर्तालय की अधिसूचना सं० 1-के०उ०/1981 दिनांक 27-2-81 में निम्नलिखित संशोधन करता हूं।

उपरोक्त अधिसूचना में संलग्न विवरण के कालम 1 के नियम "173(1ए)" के स्थान "173-जी(1ए)" पढ़ें।

[सी०सं० IV (8) 1/के०उ०/82]

बी०एन० रंगवानी, समाहर्ता

COLLECTORATE OF CENTRAL EXCISE

NOTIFICATION NO. 3-CE/1982

Calcutta, the 14th July, 1982

CENTRAL EXCISE

S.O. 3076.—In exercise of the powers conferred upon me by rule 5 of the Central Excise Rules, 1944, I hereby make the following amendment in this Collectorate Notification No. 1/CE/1981 dated 27-2-81 namely :—

In the statement annexed to the said Notification against column 1 for rule "173(IA)" read "173-G(IA)".

[C. No. IV(8)/1-CE/82]

B. N. RANGWANI, Collector.

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 1982

का०आ० 3077—राजनयिक तथा कौंसली अधिकारी (शपथ एवं शुल्क) अधिनियम, 1948 (1948 का 41) के खंड 2 की धारा (क) के अनुपालन में केन्द्र सरकार, इसके द्वारा भारत के राजदूतावास, वियनतियाना (लाओस) में सहायक श्री रणवीर सिंह बाटा को तत्काल से कौंसली एजेन्ट का कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

[फाइल सं० टी०-4330/2/82]

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

New Delhi, the 10th August, 1982

S.O. 3077.—In pursuance of the clause (a) of Section 2 of the Diplomatic and Consular Officers (Oaths and Fees) Act, 1948 (41 of 1948) the Central Government hereby authorise Shri Ranvir Singh Batta, Assistant in the Embassy of India, Vientiane (Laos) to perform the duties of a Consular Agent with immediate effect.

[File No. T-4330/2/82]

नई दिल्ली, 11 अगस्त, 1982

का० आ० 3078—राजनयिक तथा कौंसली अधिकारी (शपथ एवं शुल्क) अधिनियम, 1948 (1948 का 41) के खंड 2 की धारा (क) के अनुपालन में केन्द्र सरकार, इसके द्वारा भारत के राजदूतावास, अदन में सहायक, श्री जे० एस० भट्टी को तत्काल से कौंसली एजेन्ट का कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

[फाइल सं० टी०-4330/2/82]
बी० एस० निद्दार, अवर सचिव।

New Delhi, the 11th August, 1982

S.O. 3078.—In pursuance of clause (a) of Section 2 of the Diplomatic and Consular Officers (Oaths and Fees) Act, 1948 (41 of 1948) the Central Government hereby authorise Shri J. S. Bhatti, Assistant in the Embassy of India, Aden to perform the duties of a Consular Agent with immediate effect.

[File No. T-4330/2/82]
B. S. NIDDAR, Under Secy.

वाणिज्य मंत्रालय

(मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात का कार्यालय)

आदेश

नई दिल्ली, 11 अगस्त, 1982

का०आ० 3079.—श्री नन्देश्वर प्रसाद श्रीवास्तव, 259, धौला कुआं फ्लैट, रिज रोड़, नई दिल्ली को एयर कन्डिशनर के साथ होन्डा सिविक 4, डोर सेडन ए/एम, 1982 माडल कार के आयात के लिए 38,000 रुपये मात्र के लिए एक सीमा शुल्क निकासी संख्या पी/जे/0390830 दिनांक 18-5-82 प्रदान किया गया था।

आवेदक ने उक्त सीमा शुल्क निकासी परमिट की अनुलिपि के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल सीमा शुल्क निकासी परमिट खो गया है। आगे यह बताया गया है कि मूल सीमा शुल्क निकासी परमिट किसी भी सीमा शुल्क प्राधिकारी के पास पंजीकृत नहीं कराया गया था और इस प्रकार उसके किसी भी मूल्य का बिल्कुल ही उपयोग नहीं किया गया है।

2 अपने तर्क के समर्थन में लाइसेंसधारी ने दिल्ली के नोटरी पब्लिक के सामने विधिवत् शपथ लेकर एक शपथ पत्र दाखिल किया है। तदनुसार, सन्तुष्ट हूं कि मूल सीमा शुल्क निकासी परमिट संख्या पी/जे/0390830, एन/एमपी/83/एच/82 दिनांक 18-5-82 आवेदक से खो गया है/अस्थानस्थ हो गया है। समय-समय पर यथा संशोधित आयात नियंत्रण आदेश 1955, दिनांक 7-12-55, की उपधारा 9 (सीसी) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर श्री नन्देश्वर प्रसाद श्रीवास्तव को जारी किए गए सीमा शुल्क निकासी परमिट संख्या पी/जे/0390830/एन/एमपी/83/एच/82, दिनांक 18-5-82 को एतद् द्वारा रद्द किया जाता है

3. श्री एन०पी० श्रीवास्तव को सीमा शुल्क निकासी परमिट की अनुलिपि अलग से जारी की जा रही है।

[मि० सं०जी०ए०-17/82-83/बीएलएस/1819]

एम०ई० थामस, संयुक्त मुख्य नियंत्रक
आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

(Office of the Chief Controller of Imports & Exports)

ORDER

New Delhi, the 11th August, 1982

S.O. 3079.—Shri Nandeswar Prasad Srivastav, 259, Dhaula Kuan Flat, Ridge Road, New Delhi was granted a CCP No. P/J/0390830 dt. 18-5-82 for Rs. 38,000 only for the import of Honda Civic 4 door Sedan A/M, 1982 model car with Air-Conditioner.

The applicant has applied for issue of a Duplicate copy of the above mentioned CCP on the ground that the original CCP has been lost. It has further been stated that the original CCP was not registered with any Custom Authority and as such the value of the CCP has not been utilised at all.

2. In support of his contention, the licensee has filed an affidavit, duly sworn before the Notary Public, Delhi, I am accordingly satisfied that the original CCP No. P/J/0390830, N/MP/83/H/82 dated 18-5-82 has been lost or misplaced by the applicant. In exercise of powers conferred under sub-clause 9(cc) of the Import Control Order 1955 dated 7-12-1955 as amended from time to time, the said original CCP No. P/J/0390830/N/MP/83/H/82 dated 18-5-82 issued to Shri Nandeswar Prasad Srivastav, is hereby cancelled.

3. A duplicate copy of the CCP is being issued to Shri N. P. Srivastav separately.

[F. No. GA17/82-83/BLS/1819]
M. E. THOMAS, Jt. Chief Controller of Imports & Exports.

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(पेट्रोलियम विभाग)

नई दिल्ली, 6 अगस्त, 1982

का० आ० 3080—यत पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का० आ० स०/1272 तारीख 6 मार्च, 1982 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यत: समक्ष प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे, यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अत: उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाईन बिछाने के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने के बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

एन० के० सी० डी० से एन० के० सी० एन० तक पाइप लाईन बिछाने के लिए ।

राज्य : गुजरात जिला और तालुका : मेहसाणा

गाँव	सर्वे नं०	हेक्टेयर	एआरई	सेन्टीयर
धनपुरा	293	0	03	60

[सं० 12016/67/81-प्रोड० II]

MINISTRY OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZER

(Department of Petroleum)

New Delhi, the 6th August, 1982

S.O. 3080.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, Chemicals and Fertilizer, (Department of Petroleum), S.O. 1272 dated 6-3-82 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline ;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government :

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification.

Now, therefore, in exericse of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline ;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil and Natural Gas Commission free from encumbrances

SCHEDULE

Pipeline from D.S. No. NKCV to NKCN

State : Gujarat District & Taluka : Mehsana

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Dhanpura	293	0	03	60

[No. 12016/67/81-Prod.II]

का० आ० 3081—यत: पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का० आ० सं० 1271/तारीख 8-3-82 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यत: समक्ष प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे, यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अत: उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने के बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

कूप नं० एस० पी० डी० से एन० के० डी० जी० तक पाइप लाईन बिछाने के लिए ।

राज्य : गुजरात जिला अहमदाबाद तालुका : विरमगाम

गाँव	सर्वे नं०	हेक्टेयर	एआरई	सेन्टीयर
भटारीया	17	0	12	24

[सं० 12016/67/81-प्रोड० I]

S.O. 3081.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, Chemicals and Fertilizer, (Department of Petroleum) S.O. 1271 dated 6-3-82 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention

to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline ;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore in exercise of the power confered by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline ;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil and Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from D.S. No. SPD to NKDG.

State : Gujarat District : Ahmedabad Taluka : Viramgam

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Bhatarla	17	0	12	24

[No. 12016/67/81-Prod. I]

अनुसूची

पाईप-लाईन वाशी से सानपाडा तक

तालुका : ठाणे जिला : ठाणे राज्य : महाराष्ट्र

गांव	खसरा नम्बर	हिस्सा नम्बर	क्षेत्रफल	
			हेक्टर	एयर
वाशी	3 का भाग	--	00	70
,,	4 ,,	--	00	22
,,	6 ,,	--	00	75
,,	17 ,,	--	00	14
नुर्भे	726 ,,	--	00	05
,,	739 ,,	--	00	18
,,	740 ,,	--	00	16
,,	741 ,,	--	00	04
,,	742 ,,	--	00	02
,,	796 ,,	--	00	42
सानपाडा	29 ,,	--	00	10
,,	30 ,,	--	00	03
,,	36 ,,	--	00	13
,,	37 ,,	--	00	04
,,	38 ,,	--	00	09
,,	39 ,,	--	00	12
,,	40 ,,	--	00	15
,,	41 ,,	--	00	18
,,	42 ,,	--	00	02
,,	46 ,,	--	00	05
,,	47 ,,	--	00	09
,,	50 ,,	--	00	20
,,	58 ,,	--	00	06
,,	77 ,,	--	00	02

[क्रमांक 12016/27/82 प्रो० I]

नई दिल्ली, 13 अगस्त, 1982

का० आ० 3082.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि महाराष्ट्र राज्य में बम्बई से पुणे तक पट्रोलियम पदार्थों के परिवहन के लिए पाईप लाईन हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन द्वारा बिछाई जानी चाहिये।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाईप लाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतत्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, बम्बई पूण पाईप लाईन्स प्रोजेक्ट, फ्युअल रिफायनरीज, कारिडार रोड, बम्बई को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

New Delhi, the 13th August, 1982

S.O. 3082.—Whereas it appears to Central Government that it is necessary to lay a pipeline for transporting Petroleum Products from Bombay to Pune in the State of Maharashtra though Pipeline and that said Pipeline is to be laid through the agency of Hindustan Petroleum Corporation Limited, Bombay.

And whereas, it appears to Central Government that for laying pipeline it is necessary to acquire the Right of User in respect of the lands appended to herewith in schedule.

Now therefore, in exercise of the powers vested in them by virtue of Section 3 (i) of Pttroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) AO 1962 (50 of 1962) Central Government notify their intention to acquire the Right of user in the lands referred to above.

Any person having his interest in the lands referred to above having any objection for laying the Pipe-line through above mentioned londs may prefer an objecion within 21 days of the publication of this notification before the competent authority Hindustan Petroleum Corporation Limited, Bombay Pune Pipeline Project, Fuels Refinery, Corridor Road, Bombay-74.

All persons having any objection may also state whether they want to be heard in person either himself or through any lawyer appointed by him.

SCHEDULE

Pipeline From Vashi to Sanpada

Taluka : Thane District : Thane, Maharashtra.

Village	Survey No./ Gut No.	Hissa No.	Area H	Area R
Vashi	3 Part	—	00	70
,,	4 ,,	—	00	22
,,	6 ,,	—	00	75
,,	17 ,,	—	00	14
Turbe	726 ,,	—	00	05
,,	739 ,,	—	00	18
,,	740 ,,	—	00	16
,,	741 ,,	—	00	04
,,	742 ,,	—	00	02
,,	796 ,,	—	00	42
Sanpada	29 ,,	—	00	10
,,	30 ,,	—	00	03
,,	36 ,,	—	00	13
,,	37 ,,	—	00	04
,,	38 ,,	—	00	09
,,	40 ,,	—	00	15
,,	41 ,,	—	00	18
,,	39 ,,	—	00	12
,,	42 ,,	—	00	02
,,	46 ,,	—	00	05
,,	47 ,,	—	00	09
,,	50 ,,	—	00	20
,,	58 ,,	—	00	06
,,	77 ,,	—	00	02

[No. 12016/27/82-Prod. I]

का०आ० 3083.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि महाराष्ट्र राज्य में बंबई से पूणे तक पेट्रोलियम पदार्थों के परिवहन के लिए पाईप लाईन हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन द्वारा बिछाई जानी चाहिये।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाईप लाईन(भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, बम्बई पूणे पाईप लाईन्स प्रोजेक्ट फ्युअल रिफाय-नरीज कारिडार, रोड बम्बई को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

पाईप-लाईन कूकशेत से शिरवणे तक

तालुका : ठाणा, जिला : ठाणा, राज्य : महाराष्ट्र

गांव	खसरा नम्बर	हिस्सा नम्बर	क्षेत्रफल हेक्टर	क्षेत्रफल ऐयर
कूकशेत	169 का भाग	—	00	18
,,	170 ,,	—	00	21
,,	181 ,,	—	00	04
सोनखार	2 ,,	—	00	32
,,	3 ,,	—	00	02
,,	4	—	00	10
,,	5 ,,	—	00	16
,,	6 ,,	—	00	10
,,	10 ,,	—	00	30
,,	11 ,,	—	00	32
,,	99 ,,	—	00	14
,,	1088 ,,	—	00	06
शिरवणे	3 ,,	—	00	02
,,	4 ,,	—	00	13
,,	5 ,,	—	00	08
,,	6 ,,	—	00	13
,,	7 ,,	—	00	20
,,	8 ,,	—	00	02
,,	22 ,,	—	00	02
,,	76 ,,	—	00	05
,,	77 ,,	—	00	17
,,	78 ,,	—	00	14
,,	80 ,,	—	00	04
,,	81 ,,	—	00	16
,,	100 ,,	—	00	03
,,	179 ,,	—	00	18
,,	181 ,,	—	00	16
,,	182 ,,	—	00	19
,,	184 ,,	—	00	05
,,	185 ,,	—	00	14
,,	197 ,,	—	00	21
,,	188 ,,	—	00	11
,,	195 ,,	—	00	27
,,	196 ,,	—	00	04
,,	199 ,,	—	00	12
,,	201 ,,	—	00	08
,,	202 ,,	—	00	13
,,	209 ,,	—	00	07
,,	218 ,,	—	00	02
,,	230 ,,	—	00	50
,,	237 ,,	—	00	07
,,	239 ,,	—	00	11
,,	242 ,,	—	00	02
,,	244 ,,	—	00	03
,,	277 ,,	—	00	13
,,	289 ,,	—	00	17
,,	295 ,,	—	00	09
,,	297 ,,	—	00	05
,,	301 ,,	—	00	03
,,	317 ,,	—	00	05

[क्रमांक 12016/27/82-प्रो II]

S.O. 3083.—Whereas it appears to Central Government that it is necessary to lay a pipeline for transporting Petroleum Products from Bombay to Pune in the State of Maharashtra through Pipeline and that said Pipeline is to be laid through agency of Hindustan Petroleum Corporation Limited, Bombay.

And whereas, it appears to Central Government that for laying pipeline it is necessary to acquire the Right of User in respect of the lands appended to herewith in schedule.

Now, therefore, in exercise of the powers vested in them by virtue of Section 3(i) of Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) AO 1962 (50 of 1962) Central Government notify their intention to acquire the Right of User in the lands referred to above.

Any person having his interest in the lands referred to above having any objection for laying the Pipeline through above mentioned lands may prefer an objection within 21 days of the publication of this notification before the competent authority Hindustan Petroleum Corporation Limited. Bombay Pune Pipeline Project, Fuels Refinery, Corridor Road, Bombay-74.

All persons having any objection may also state whether they want to be heard in person either himself or through any lawyer appointed by him.

SCHEDULE

Pipeline From Kukshet to Shirvane

Tq : Thane, Dist : Thane (Maharashtra State)

Village	Survey No. G.	No.	Hissa No.	Area H	R.
Kukshet		Part	—		
,,	169	,,	—	00	18
,,	170	,,	—	00	21
,,	181	,,	—	00	04
Sonkhar	2	,,	—	00	32
,,	3	,,	—	00	02
,,	4	,,	—	00	10
,,	5	,,	—	00	16
,,	6	,,	—	00	10
,,	10	,,	—	00	30
,,	11	,,	—	00	32
,,	99	,,	—	00	14
,,	108B	,,	—	00	06
Shirvane	3	,,	—	00	02
,,	4	,,	—	00	13
,,	5	,,	—	00	08
,,	6	,,	—	00	13
,,	7	,,	—	00	20
,,	8	,,	—	00	02
,,	22	,,	—	00	02
,,	76	,,	—	00	05
,,	77	,,	—	00	17
,,	78	,,	—	00	14
,,	80	,,	—	00	04
,,	81	,,	—	00	16
,,	100	,,	—	00	03
,,	179	,,	—	00	18
,,	181	,,	—	00	16
,,	182	,,	—	00	19
,,	184	,,	—	00	05
,,	185	,,	—	00	14
,,	188	,,	—	00	11
,,	195	,,	—	00	27
,,	196	,,	—	00	40
,,	197	,,	—	00	21
Shirvane	199	Part	—	00	12
,,	201	,,	—	00	08
,,	202	,,	—	00	13
,,	209	,,	—	00	07
,,	218	,,	—	00	02
,,	230	,,	—	00	50
,,	237	,,	—	00	07
,,	239	,,	—	00	11
,,	242	,,	—	00	02
,,	244	,,	—	00	03
,,	277	,,	—	00	13
,,	289	,,	—	00	17
,,	296	,,	—	00	09
,,	297	,,	—	00	05
,,	301	,,	—	00	03
,,	317	,,	—	00	05

[No. 12016/27/82-Prod. II]

का० आ० 3084.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि महाराष्ट्र राज्य में बंबई से पूणे तक पेट्रोलियम पदार्थों के परिवहन के लिए पाईप लाईन हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन द्वारा बिछाई जानी चहिए ।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाईप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाईप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड बम्बई पूणे पाईप लाइन्स प्रोजेक्ट फ्यूअल रिफायनरीज कारिडार रोड बम्बई को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

L.A. Case No. 1/82

अनुसूची

पाइप लाईन वाक्सई से दहिअली तक

तालुका : मावल, जिला : पूणे, राज्य : महाराष्ट्र

गांव	खसरा नम्बर	हिस्सा नम्बर	क्षेत्रफल हेक्टर	ऐयर
वाक्सई	10 का भाग	—	00	11
,,	13 ,,	—	00	04
,,	14 ,,	—	00	20
,,	16 ,,	—	00	11
,,	17 ,,	—	00	15
,,	18 ,,	—	00	13
,,	20 ,,	—	00	09

1	2	3	4	5
वाकसई	34 का भाग	—	00	18
,,	159 ,,	—	00	20
,,	163 ,,	—	00	16
देवघर	43 ,,	—	00	18
,,	44 ,,	—	00	27
,,	48 ,,	—	00	29
,,	60 ,,	—	00	16
,,	64 ,,	—	00	35
,,	65 ,,	—	00	11
,,	69 ,,	—	00	42
,,	70 ,,	—	00	20
कार्ला	81 ,,	—	00	31
,,	161 ,,	—	00	24
,,	163 ,,	—	00	42
,,	165 ,,	—	00	35
,,	166 ,,	—	00	24
,,	167 ,,	—	00	33
,,	168 ,,	—	00	21
,,	206 ,,	—	00	16
दहिवली	25 ,, गट नं० (64.65)	3/4	00	32

[क्रमांक 12016/26/82/प्रो० I]

S.O. 3084.—Whereas it appears to Central Government that it is necessary to lay a pipeline for transporting Petroleum Products from Bombay to Pune in the State of Maharashtra through Pipeline and that said Pipeline is to be laid through the agency of Hindustan Petroleum Corporation Limited, Bombay.

And whereas, it appears to Central Government that for laying pipeline it is necessary to acquire the Right of User in respect of the lands appended to herewith in schedule.

Now, therefore, in exercise of the powers vested in them by virtue of Section 3(i) of Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) AO 1962 (50 of 1962) Central Government notify their intention to acquire the Right of user in the lands referred to above.

Any person having his interest in the lands referred to above having any objection for laying the Pipeline through above mentioned lands may prefer an objection within 21 days of the publication of this notification before the competent authority Hindustan Petroleum Corporation Limited, Bombay Pune Pipeline Project, Fuels Refinery, Corridor Road, Bombay-74.

All persons having any objection may also state whether they want to be heard in person either himself or through any lawyer appointed by him.

SCHEDULE

Pipline From ; Waksai To Dhahivali.

Taluka-Maval, Distt. Pune State—Maharastra.

Village	Survey No. Gut No.	Hissa No.	Area H.	R.
1	2	3	4	5
Waksai	Part			
,,	10 ,,	—	00	11
,,	13 ,,	—	00	04
,,	14 ,,	—	00	20
,,	16 ,,	—	00	11
,,	17 ,,	—	00	15
,,	18 ,,	—	00	13
,,	20 ,,	—	00	09
,,	34 ,,	—	00	18
Waksai	159 Part	—	00	20
,,	163 ,,	—	00	16
Devghar	43 ,,	—	00	18
,,	44 ,,	—	00	27
,,	48 ,,	—	00	29
,,	60 ,,	—	00	16
,,	64 ,,	—	00	35
,,	65 ,,	—	00	11
,,	69 ,,	—	00	42
,,	70 ,,	—	00	20
Karla	81 ,,	—	00	31
,,	161 ,,	—	00	24
,,	163 ,,	—	00	42
,,	165 ,,	—	00	35
,,	166 ,,	—	00	24
,,	167 ,,	—	00	33
,,	168 ,,	—	00	29
,,	206 ,,	—	00	16
Dahivali	25 G. No. 64 & 65	3/4	00	32

[No. 12016/26/82/Prod. I]

का० आ० 3085.—यत : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि महाराष्ट्र राज्य में बंबई से पूणे तक पेट्रोलियम पदार्थों के परिवहन के लिए पाइप लाइन हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन द्वारा बिछाई जानी चाहिये ।

और यत : यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अत : अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, बम्बई पूणे पाइप लाइन्स प्रोजेक्ट पयग्रेल रिफाय-नरीज कारिडार रोड़ बम्बई को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टत : यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

(तुगार्ली से वलवन तक)

गांव : तुगार्ली, तालुका : मावल जिला : पूणे राज्य : महाराष्ट्र

गांव	खसरा नम्बर	हिस्सा नम्बर	क्षेत्रफल हेक्टर	एयर
1	2	3	4	5
तुगार्ली	7 का भाग	—	00	20
,,	8 ,,	—	00	16
,,	9 ,,	—	00	09
,,	10 ,,	—	00	16
,,	11 ,,	—	00	04

1	2	3	4	5
तुगार्ली	12 ,,	—	00	22
,,	13 ,,	—	00	09
,,	79 ,,	—	00	22
,,	80 ,,	—	00	16
,,	81 ,,	—	00	13
,,	82 ,,	—	00	09
,,	83 ,,	—	00	20
,,	84 ,,	—	00	31
,,	85 ,,	—	00	07
,,	86 ,,	—	00	05
,,	116 ,,	—	00	18
,,	118 ,,	—	00	09
,,	117 ,,	—	00	16
,,	120 ,,	—	00	29
,,	120ए ,,	—	00	24
,,	121 ,,	—	00	05
,,	131 ,,	—	00	79
,,	132 ,,	—	00	35
,,	147 ,,	—	00	40
,,	148ए ,,	—	00	13
,,	149 ,,	—	00	15
,,	150 ,,	—	00	13
,,	152 ,,	—	00	11
वाक्सई	132 ,,	—	00	29
,,	133 ,,	—	00	17
,,	134 ,,	—	00	17
,,	135 ,,	—	00	04
,,	139 ,,	—	00	31
,,	140ए ,,	—	00	21
,,	141 ,,	—	00	09
,,	144 ,,	—	00	48
,,	145 ,,	—	00	13
,,	148 ,,	—	00	11
,,	149 ,,	—	00	04
,,	150 ,,	—	00	13
,,	160 ,,	—	00	13
बरसोली	23 ,,	—	00	37
,,	24 ,,	—	00	27
,,	47 ,,	—	00	59
,,	49 ,,	—	00	40
,,	60 ,,	—	00	59
,,	63 ,,	—	00	04
लोणावला	144ए ,,	—	00	24
,,	144बी ,,	—	00	05
,,	144 ,,	—	00	18
,,	145 ,,	—	00	04
,,	169 ,,	—	00	20
वलवन	14 ,,	—	00	37
,,	15 ,,	—	00	04
,,	33 ,,	—	00	20
,,	34 ,,	—	00	11
,,	35 ,,	—	00	04
,,	38 ,,	—	00	05
,,	40ए ,,	—	00	04
,,	41ए ,,	—	00	05
,,	41बी ,,	—	00	18
,,	42 ,,	—	00	05
,,	43 ,,	—	90	16
,,	44 ,,	—	00	13
,,	45 ,,	—	00	11
,,	50 ,,	—	00	20
,,	51 ,,	—	00	20
,,	52 ,,	—	00	16
,,	65 ,,	—	00	31
,,	66 ,,	—	00	13
,,	70 ,,	—	00	05
,,	80 ,,	—	00	13
,,	83 ,,	—	00	38
,,	94 ,,	—	00	18
,,	95 ,,	—	00	22
,,	189 ,,	—	00	16

[क्रमांक 12016/26/82पी० II]

S.O. 3085.—Whereas it appears to Central Government that it is necessary to lay a pipeline for transporting Petroleum Products from Bombay to Pune in the State of Maharashtra through Pipeline and that said Pipeline is to be laid through the agency of Hindustan Petroleum Corporation Limited Bombay.

And whereas it appears to Central Government that for laying pipeline it is necessary to acquire the Right of User in respect of the lands appended to herewith in schedule.

Now, therefore, in exercise of the powers vested in them by virtue of Section 3(i) of Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) AO 1962 (50 of 1962) Central Government notify their intention to acquire the Right of user in the lands referred to above.

Any person having his interest in the lands referred to above having any objection for laying the Pipeline through above mentioned lands may prefer an objection within 21 days of the publication of this notification before the competent authority Hindustan Petroleum Corporation Limited Bombay Pune Pipeline Project, Fuels Refinery, Corridor Road, Bombay-74.

All persons having any objection may also state whether they want to be heard in person either himself or through any lawyer appointed by him.

SCHEDULE

Pipeline From : Tungarli To Waksai.

Taluka-Maval, Dist : Pune, State : Maharashtra.

Village	Survey No. Gut No.	Hissa No.	Area H.	Area R.
1	2	3	4	5
Tungarli	7 Part	—	00	20
,,	8 ,,	—	00	16
,,	9 ,,	—	00	09
,,	10 ,,	—	00	16
,,	11 ,,	—	00	04
,,	12 ,,	—	00	22
,,	13 ,,	—	00	09
,,	79 ,,	—	00	22
,,	80 ,,	—	00	16
,,	81 ,,	—	00	13
,,	82 ,,	—	00	09
,,	83 ,,	—	00	20
,,	84 ,,	—	00	31

1	2	3	4	5
Tungarli	85 ,,	—	00	07
,,	86 ,,	—	00	05
,,	116 ,,	—	00	18
,,	118 ,,	—	00	09
,,	117 ,,	—	00	16
,,	120 ,,	—	00	29
,,	120A ,,	—	00	24
,,	121 ,,	—	00	05
,,	131 ,,	—	00	79
,,	132 ,,	—	00	35
,,	147 ,,	—	00	40
,,	148A ,,	—	00	13
,,	149 ,,	—	00	15
,,	150 ,,	—	00	13
Waksai	152 ,,	—	00	11
,,	132 ,,	—	00	29
,,	133 ,,	—	00	17
,,	134 ,,	—	00	17
,,	135 ,,	—	00	04
,,	139 ,,	—	00	31
,,	140A ,,	—	00	21
,,	141 ,,	—	00	09
,,	144 ,,	—	00	48
,,	145 ,,	—	00	13
,,	148 ,,	—	00	11
,,	149 ,,	—	00	04
,,	150 ,,	—	00	13
,,	160 ,,	—	00	13
Varsoli	23 ,,	—	00	37
,,	24 ,,	—	00	27
,,	47 ,,	—	00	59
,,	49 ,,	—	00	40
,,	50 ,,	—	00	59
,,	63 ,,	—	00	04
Lonavala	144A ,,	—	00	24
,,	44B ,,	—	00	05
,,	44 ,,	—	00	18
,,	45 ,,	—	00	04
,,	69 ,,	—	00	20
Valvan	14 ,,	—	00	37
,,	15 ,,	—	00	04
,,	33 ,,	—	00	20
,,	34 ,,	—	00	11
,,	35 ,,	—	00	04
,,	38 ,,	—	00	05
,,	40 A ,,	—	00	04
,,	41A ,,	—	00	05
,,	41B ,,	—	00	18
,,	42 ,,	—	00	05
,,	43 ,,	—	00	16
,,	44 ,,	—	00	13
,,	45 ,,	—	00	11
,,	50 ,,	—	00	20
,,	51 ,,	—	00	20
,,	52 ,,	—	00	16
,,	65 ,,	—	00	31
,,	66 ,,	—	00	13
,,	70 ,,	—	00	05
,,	80 ,,	—	00	13
,,	83 ,,	—	00	38
,,	94 ,,	—	00	18
,,	95 ,,	—	00	22
,,	189 ,,	—	00	16

[No. 12016/26/82 (Prod.II)]

का० आ० 3086.—यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि महाराष्ट्र राज्य में बंबई से पूणे तक पेट्रोलियम पदार्थों के परिवहन के लिए पाईप लाईन हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन द्वारा बिछाई जानी चाहिये ।

और यत: यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अत: अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद् द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, बम्बई पूणे पाइप लाइन्स प्रोजेक्ट, फयुअल रिफाय-नरीज, कॉरिडार रोड, बम्बई को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टत: यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

पाइप लाईन कसबे से आडई तक

तालुका : ठाणे, जिला: ठाणे, राज्य: महाराष्ट्र

गांव	खसरा नम्बर	हिस्सा नम्बर	क्षेत्रफल	
			हेक्टर	ऐयर
1	2	3	4	5
कसबे शहाबाज	365 का भाग	--	00	14
,,	372 ,,	--	00	14
,,	374 ,,	00	00	02
,,	375B ,,	--	--	03
,,	376 ,,	--	00	23
,,	377A ,,	--	00	02
,,	377B ,,	--	00	07
,,	377C ,,	--	00	02
,,	387 ,,	--	00	08
,,	388 ,,	--	00	02
,,	389 ,,	--	00	37
,,	390 ,,	--	00	06
,,	391A ,,	--	00	41
,,	488 ,,	--	00	12
,,	489 ,,	--	00	02
शाहबाज	29 ,,	--	00	09
,,	30A ,,	--	00	08
,,	33A ,,	--	00	23
,,	36 ,,	--	00	27
,,	37 ,,	—	00	12
,,	38 ,,	--	00	09
,,	40B ,,	—	00	05
,,	53 ,,	--	00	82
,,	162B ,,	--	00	06
,,	193 ,,	--	00	20
,,	194 ,,	--	00	38

1	2	3	4	5
शहाबाज	195A	का भाग	--	00	08
,,	195B	,,	--	00	04
,,	188	,,	--	00	02
,,	189	,,	--	00	05
,,	198	,,	--	00	27
,,	200	,,	--	00	13
,,	201	,,	--	00	32
,,	488	,,	--	00	09
,,	489	,,	--	00	04
तलोजा	308	,,	--	00	42
कामोथे	76	,,	--	00	06
,,	77	,,	--	00	06
बेलपाडा	5	,,	--	00	55
,,	6	,,	--	00	10
,,	8	,,	--	00	23
,,	17	,,	--	00	24
,,	29	,,	--	00	04
,,	30	,,	--	00	02
,,	31	,,	--	00	05
,,	32	,,	--	00	08
,,	33	,,	--	00	16
,,	37	,,	--	00	02
,,	38	,,	--	00	04
,,	39	,,	--	00	31
अदाई	129	,,	--	00	11
,,	130	,,	--	00	07
,,	131	,,	--	00	50
,,	132	,,	--	00	16

[क्रमांक 12016/28/82/प्रो० 1]

S.O. 3086.—Whereas it appears to Central Government that It is necessary to lay a pipeline for transporting Petroleum Products from Bombay to Pune in the State of Maharashtra through Pipeline and that said pipeline is to be laid through the agency of Hindustan Petroleum Corporation Limited, Bombay.

And whereas, it appears to Central Government that for laying pipeline it is necessary to acquire the Right of User in respect of the lands appended to herewith in schedule.

Now, therefore, in exercise of the powers vested in them by virtue of Section 3(i) of Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) AO 1962 (50 of 1962) Central Government notify their intention to acquire the Right of user in the lands referred to above.

Any person having his interest in the lands referred to above having any objection for laying the Pipeline through above mentioned lands may prefer an objection within 21 days of the publication of this notification before the competent authority Hindustan Petroleum Corporation Limited, Bombay Pune Pipeline Project, Fuels Refinery, Corridor Road, Bombay-74.

All persons having any objection may also state whether they want to be heard in person either himself or through any my lawyer appointed by him.

SCHEDHLE

Pipeline From Kasbe Shahabaz to Shahabaz.
Tq. Thane, Dist : Thane, Maharashtra.

Village	Survey No./Gutt No.	Hissa No.	Area H	Area R
Kasbe Shahabaz	Part	—	H	R
,,	365 ,,	—	00	14
,,	372 ,,	—	00	14
,,	374 ,,	—	00	02
,,	375B ,,	—	00	03
,,	376 ,,	—	00	23
,,	377A ,,	—	00	02
,,	377B ,,	—	00	07
,,	377K,	—	00	02
,,	387 ,,	—	0p	08
,,	388 ,,	—	00	02
,,	389 ,,	—	00	37
,,	390 ,,	—	00	06
,,	391A ,,	—	00	41
,,	488 ,,	—	00	12
,,	489 ,,	—	00	02
Shahabaz	29 ,,	—	00	09
,,	30A ,,	—	00	08
,,	33A ,,	—	00	23
,,	36 ,,	—	00	27
,,	37 ,,	—	00	12
,,	38 ,,	—	00	09
,,	40B ,,	—	00	05
,,	53 ,,	—	00	82
,,	162 ,,	—	00	06
,,	188 ,,	—	00	02
,,	189 ,,	—	00	05
,,	193 ,,	—	00	20
,,	194 ,,	—	00	38
,,	195A ,,	—	00	08
,,	195B ,,	—	00	04
,,	198 ,,	—	00	27
,,	200 ,,	—	00	13
,,	201 ,,	—	00	32
,,	488 ,,	—	00	09
,,	489 ,,	—	00	04
Taloja				
,,	308 ,,	—	00	42
Kamothe	76 ,,	—	00	06
,,	77 ,,	—	00	06
Belpada	5 ,,	—	00	55
,,	6 ,,	—	00	10
,,	8 ,,	—	00	23
,,	17 ,,	—	00	24
,,	29 ,,	—	00	04
,,	30 ,,	—	00	02
,,	31 ,,	—	00	05
,,	32 ,,	—	00	08
,,	33 ,,	—	00	16
,,	37 ,,	—	00	02
,,	38 ,,	—	00	04
,,	39 ,,	—	00	31
Aadaice	129 ,,	—	00	11
,,	130 ,,	—	00	07
,,	131 ,,	—	00	50
,,	132 ,,	—	00	16

[No. 12016/28/82-Prod. I]

का० आ० 3087—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि महाराष्ट्र राज्य में बंबई से पूणे तक पेट्रोलियम पदार्थों के परिवहन के लिए पाईप लाईन हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन द्वारा बिछाई जानी चाहिये ।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद् द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, बम्बई पुणे पाइप लाइन्स प्रोजेक्ट पयुमेल रिफायनरीज कॉरिडॉर रोड बम्बई को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

पाइप लाईन खार घर से आमूडगांव तक

तालुका : पनवेल, जिला : रायगड़, राज्य : महाराष्ट्र

गांव	खसरा नम्बर	हिस्सा नम्बर	क्षेत्रफल हेक्टर	क्षेत्रफल ऐयर
खार घर	79 का भाग	—	00	55
,,	89 ,,	—	00	06
,,	91 ,,	—	00	38
,,	92 ,,	—	00	21
,,	95 ,,	—	00	25
,,	95 ,,	—	00	31
,,	113 ,,	—	00	30
,,	117 ,,	—	00	16
,,	118 ,,	—	00	04
,,	128 ,,	—	00	07
,,	129 ,,	—	00	05
,,	130 ,,	—	00	04
,,	131 ,,	—	00	04
,,	132 ,,	—	00	33
,,	191 ,,	—	00	01
,,	133 ,,	—	00	18
,,	192 ,,	—	00	28
,,	194 ,,	—	00	06
,,	196 ,,	—	00	16
,,	199 ,,	—	00	33
,,	205 ,,	—	00	41
,,	206 ,,	—	00	29
,,	208A ,,	—	00	03
,,	208B ,,	—	00	07
,,	208B ,,	—	00	39
,,	210 ,,	—	00	04
,,	213 ,,	—	00	06
,,	214 ,,	—	00	37
खार घर	215 का भाग	—	00	04
,,	233A ,,	—	00	27
,,	234A ,,	—	00	11
,,	235 ,,	—	00	06
,,	236 ,,	—	00	04
,,	238 ,,	—	00	10
,,	256 ,,	—	00	55
कालम्बोली	1 ,,	—	00	20
,,	3 ,,	—	00	07
,,	4 ,,	—	00	31
,,	5 ,,	—	00	08
,,	12 ,,	—	00	20
,,	13 ,,	—	00	04
,,	17 ,,	—	00	15
,,	18 ,,	—	00	06
,,	20 ,,	—	00	13
,,	21 ,,	—	00	32
,,	22 ,,	—	00	37
,,	23 ,,	—	00	05
,,	25 ,,	—	00	13
,,	95 ,,	—	00	33
,,	96 ,,	—	00	12
,,	97 ,,	—	00	43
,,	98 ,,	—	00	04
,,	119 ,,	—	00	52
,,	128A ,,	—	00	06
,,	129A ,,	—	00	14
आमूडगांव	1 का भाग	—	00	35
,,	2 ,,	—	00	27
,,	7 ,,	—	00	08
,,	42 ,,	—	00	10
,,	44 ,,	—	00	05
,,	45 ,,	—	00	22
,,	46 ,,	—	00	27
,,	47 ,,	—	00	04
,,	49 ,,	—	00	17
,,	50 ,,	—	00	06
,,	52 ,,	—	00	09
,,	53 ,,	—	00	40
,,	59 ,,	—	00	80
,,	68 ,,	—	00	14
,,	78 ,,	—	00	10
,,	79 ,,	—	00	79

[क्रमांक 12016/28/82/प्रो०-II]

S.O. 3087.—Whereas it appears to Central Government that it is necessary to lay a pipeline for transporting Petroleum Products from Bombay to Pune in the State of Maharashtra through Pipeline and that said Pipeline is to be laid through the agency of Hindustan Petroleum Corporation Limited, Bombay.

And whereas, it appears to Central Government that for laying pipeline it is necessary to acquire the Right of User in respect of the lands appended to herewith in schedule.

Now, therefore, in exercise of the powers vested in them by virtue of Section 3(i) of Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) AO 1962 (50 of 1962)

Central Government notify their intention to acquire the Right of user in the lands referred to above.

Any person having his interest in the lands referred to above having any objection for laying the Pipeline through above mentioned lands may prefer an objection within 21 days of the publication of this notification before the competent authority Hindustan Petroleum Corporation Limited, Bombay Pune Pipeline Project, Fuels Refinery, Corridor Road, Bombay-74.

All persons having any objection may also state whether they want to be heard in person either himself or through any lawyer appointed by him.

SCHEDULE

Pipeline From : Kharghar to Asudgaon

Taluka Panvel, Distt. Raighad, Maharashtra.

Village	Survey No./Gut No.	Hissa No.	Area	
			H	R
Kharghar	79 Part	—	00	55
,,	89 ,,	—	00	06
,,	91 ,,	—	00	38
,,	92 ,,	—	00	21
,,	95 ,,	—	00	25
,,	95 ,,	—	00	31
,,	113 ,,	—	00	30
,,	117 ,,	—	00	16
,,	118 ,,	—	00	04
,,	128 ,,	—	00	07
,,	129 ,,	—	00	05
,,	130 ,,	—	00	04
,,	131 ,,	—	00	04
,,	132 ,,	—	00	33
,,	191 ,,	—	00	04
,,	133 ,,	—	00	18
,,	192 ,,	—	00	28
,,	194 ,,	—	00	06
,,	196 ,,	—	00	16
,,	199 ,,	—	00	33
,,	205 ,,	—	00	41
,,	206 ,,	—	00	29
,,	208A ,,	—	00	03
,,	208B ,,	—	00	07
,,	209B ,,	—	00	93
,,	210 ,,	—	00	04
,,	213 ,,	—	00	06
,,	214 ,,	—	00	37
,,	215 ,,	—	00	04
,,	233A ,,	—	00	27
,,	234A ,,	—	00	11
,,	235 ,,	—	00	06
,,	236 ,,	—	00	04
,,	238 ,,	—	00	10
,,	256 ,,	—	00	55
Kalambili	1 ,,	—	00	20
,,	3 ,,	—	00	07
,,	4 ,,	—	00	31
	5 ,,	—	00	06
,,	12 ,,	—	00	20
,,	13 ,,	—	00	04
,,	17 ,,	—	00	15
,,	18 ,,	—	00	06
,,	20 ,,	—	00	13
,,	21 ,,	—	00	32
,,	22 ,,	—	00	37
,,	23 ,,	—	00	05
,,	25 ,,	—	00	13
,,	95 ,,	—	00	33

Village	Survey No./Gut No.	Hissa No.	Area	
			H	R
Kalambili	96 Part	—	00	12
,,	97 ,,	—	00	43
,,	98 ,,	—	00	04
,,	119 ,,	—	00	52
,,	128 A ,,	—	00	06
,,	129 A ,,	—	00	14
Asudgaon	1 ,,	—	00	35
,,	2 ,,	—	00	27
,,	7 ,,	—	00	08
,,	42 ,,	—	00	10
,,	44 ,,	—	00	05
,,	45 ,,	—	00	22
,,	46 ,,	—	00	27
,,	47 ,,	—	00	04
,,	49 ,,	—	00	17
,,	50 ,,	—	00	06
,,	52 ,,	—	00	09
,,	53 ,,	—	00	40
,,	59 ,,	—	00	80
,,	68 ,,	—	00	14
,,	78 ,,	—	00	10
,,	79 ,,	—	00	24

[No. 12016/28/82-Prod.II]

का० आ० 3088.—यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोक हित में यह आवश्यक है कि महाराष्ट्र राज्य में बंबई से पूणे तक पेट्रोलियम पदार्थों के परिवहन के लिए पाईप लाईन हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन द्वारा बिछाई जानी चाहिये।

और यत: यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अत: अब पेट्रोलियम और खनिज पाईप लाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, बम्बई पूणे पाइप लाइन्स प्रोजेक्ट पयुअल्स रिफाइनरीच कारिडार रोड, बम्बई को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टत: यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

पाइप-लाईन कोल्हेखार से चिखले तक

तालुका पनवेल, जिला : रायगढ, राज्य महाराष्ट्र

गांव	सर्वे नम्बर	हिस्सा नम्बर	क्षेत्रफल	
			हैक्टर	ऐयर
कोल्हेखार	12 का भाग	--	00	06
,,	17 ,,	--	00	22
,,	18 ,,	--	00	22
,,	28 ,,	--	00	02
,,	34 ,,	--	00	37

गाव	खसरा नम्बर		हिस्सा नम्बर	क्षेत्रफल	
				हेक्टर	ऐयर
कोल्हेखार	37	का भाग	--	00	22
,,	41	,,	--	00	37
,,	75	,,	--	00	03
,,	77	,,	--	00	16
,,	78	,,	--	00	11
पनवेल	186	,,	--	00	05
,,	187	,,	--	00	29
,,	296	,,	--	00	27
,,	198	,,	--	00	37
,,	760	,,	--	00	38
पालिदेवद	1	,,	--	00	05
,,	4	,,	--	00	15
,,	9A	,,	--	00	16
,,	7	,,	--	00	01
,,	16	,,	--	00	03
,,	17	,,	--	00	09
,,	19A	,,	--	00	19
,,	21A	,,	-	00	35
,,	52	,,	--	00	09
शिवले	74	,,	--	00	01
,,	75	,,	--	00	26
,,	76	,,	--	00	04
,,	77	,,	--	00	06
,,	78	,,	--	00	20
,,	84	,,	--	00	26
,,	85	,,	--	00	18
,,	86	,,	--	00	24
,,	128	,,	--	00	04
,,	129	,,	--	00	15
,,	130	,,	--	00	07
,,	131	,,	--	00	22
,,	133	,,	--	00	12
,,	135	,,	--	00	30
बोर्ले	91	,,	--	00	23
,,	100		--	00	04
,,	101	,,	--	00	10
,,	102	,,	--	00	07
,,	115	,,	--	00	10
,,	116	,,	--	00	10
,,	132	,,	--	00	14
,,	137	,,	--	00	06
,,	139	,,	--	00	10
,,	140	,,	--	00	10
,,	141	,,	--	00	08
,,	142	,,	--	00	01
,,	144	,,	--	00	03
,,	146	,,	--	00	14
,,	153	,,	--	00	02
,,	154		--	00	12
,,	157	,,	--	00	37
,,	158	,,	--	00	12
आजिवली	51	का भाग	--	00	01
,,	52	,,	--	00	01
,,	53	,,	--	00	10
,,	60	,,	--	00	16
,,	62	,,	--	00	35
,,	68	,,	--	00	24
,,	70	,,	--	00	15
,,	71	,,	--	00	15
,,	72	,,	--	00	07
,,	74	,,	--	00	06
नावडे खार	61	,,	--	00	03
आम्बेल खार	190	,,	--	00	27
,,	287	,,	--	00	18
,,	295	,,	--	00	09
,,	296	,,	--	00	17
,,	301	,,	--	00	12
,,	302	,,	--	00	02
,,	304	,,	--	00	07

[क्रमांक 12016/29/82-प्रो०-I]

S.O. 3088.—Whereas it appears to Central Government that it is necessary to lay a pipeline for transporting Petroleum Products from Bombay to Pune in the State of Maharashtra through Pipeline and that said Pipeline is to be laid through the agency of Hindustan Petroleum Corporation Limited, Bombay.

And whereas it appears to Central Government that for laying pipeline it is necessary to acquire the Right of User in respect of the lands appended to herewith in schedule.

Now, therefore, in exercise of the powers vested in them by virtue of Section 3(i) of Petroleum and Minerals Pipeline (Acquision of Right of User in Land) AO 1962 (50 of 1962) Central Government notify their intentions to acquire the Right of User in the lands referred to aobve.

Any person having his interest in the lands referred to above having any objection for laying the Pipeline through above mentioned lands may prefer an objection within 21 days of the publication of this notification before the competent authority Hindustan Petroleum Corporation Limited, Bombay Pune Pipeline Project, Fuels Refinery, Corridor Road, Bombay-74.

All persons having any objection may also state whether they want to be heard in person either himself or through any lawyer appointed by him.

SCHEDULE

Pipe Line from Kolhekhar to Aajivali

Taluka Panvel, Distt. Raigad, Maharashtra.

Village	Survey No./Gut No	Hissa No.	Area	
			H	R.
Kolhekhar	12 Part	—	00	06
,,	17 ,,	—	00	22
,,	18 ,,	—	00	22
,,	28 ,,	—	00	02
,,	34 ,,	—	00	37
,,	37 ,,	—	00	22
,,	41 ,,	—	00	37

Village	Survey No. Gut No.	Hissa No.	Area H	Area R
Kamothe	75 Part	—	00	03
,,	77 ,,	—	00	16
,,	78 ,,	—	00	11
Panvel	186 ,,	—	00	05
,,	187 ,,	—	00	29
,,	296 ,,	—	00	27
,,	198 ,,	—	00	37
,,	760 ,,	—	00	38
Pali Devad	1 ,,	—	00	05
,,	4 ,,	—	00	15
,,	9 A ,,	—	00	16
,,	7 ,,	—	00	01
,,	16 ,,	—	00	03
,,	17 ,,	—	00	09
,,	19 A ,,	—	00	19
,,	21 A ,,	—	00	35
,,	52 ,,	—	00	09
Chikhle	74 ,,	—	00	01
,,	75 ,,	—	00	26
,,	76 ,,	—	00	04
Chikhle.				
,,	77 ,,	—	00	06
,,	78 ,,	—	00	20
,,	84 ,,	—	00	26
,,	85 ,,	—	00	18
,,	86 ,,	-	00	24
,,	128 ,,	—	00	04
,,	129 ,,	—	00	15
,,	130 ,,	—	00	07
,,	131 ,,	—	00	22
,,	133 ,,	—	00	12
,,	135 ,,	—	00	30
Borle	91 ,,	—	00	23
,,	100 ,,	—	00	04
,,	101 ,,	—	00	10
,,	102 ,,	—	00	07
,,	115 ,,	—	00	10
,,	116 ,,	—	00	10
,,	132 ,,	—	00	14
,,	137 ,,	—	00	06
,,	139 ,,	—	00	10
,,	140 ,,	—	00	10
,,	141 ,,	—	00	08
,,	142 ,,	—	00	01
,,	144 ,,	—	00	03
,,	146 ,,	—	00	14
,,	153 ,,	—	00	02
,,	154 ,,	—	00	12
,,	157 ,,	—	00	37
,,	158 ,,	—	00	12
Aajivali	51 ,,	—	00	01
,,	52 ,,	—	00	01
,,	53 ,,	—	00	10
,,	60 ,,	—	00	16
,,	62 ,,	—	00	35
,,	68 ,,	—	00	24
,,	70 ,,	—	00	15
,,	71 ,,	—	00	15
,,	72 ,,	—	00	07
,,	74 ,,	—	00	06
Navadekhar	61 ,,	—	00	03
Aambelkhar	190 ,,	—	00	27
Aabelkhar.	287 Part	—	00	18
,,	295 ,,	-	00	09
,,	276 ,,	—	00	17
,,	301 ,,	—	00	42
,,	302 ,,	—	00	02
,,	304 ,,	—	00	07

[No.12016/29/82—Prod. I]

का० आ० 3089.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि महाराष्ट्र राज्य में बम्बई से पूणे तक पेट्रोलियम पदार्थों के परिवहन के लिए पाइप लाइन हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन द्वारा बिछाई जानी चाहिये।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, बम्बई पूणे पाइप लाइन्स प्रोजेक्ट पयुमेल रिफायनरीज कारिडार रोड बम्बई को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

शेडुग से पायजे तक

तालुका पनवेल, जिला रायगढ़, राज्य महाराष्ट्र

गांव	खसरा नम्बर	हिस्सा नम्बर	क्षेत्रफल हेक्टर	क्षेत्रफल एयर
1	2	3	4	5
शेडुग	42 का भाग		00	04
,,	110 ,,	-	00	29
,,	114 ,,	--	00	18
,,	115 ,,	-	00	06
,,	116 ,,	--	00	04
,,	117 ,,	--	00	03
,,	118 ,,	--	00	04
,,	121 ,,	--	00	20
,,	128 ,,	--	00	05

गांव	खसरा नम्बर	हिस्सा नम्बर	क्षेत्रफल	
1	2	3	4	5
			हेक्टर	ऐयर
भिगार	57 का भाग	--	00	07
,,	62 ,,	--	00	16
,,	58 ,,	--	00	67
,,	66 ,,	--	00	08
,,	68 ,,	--	00	09
,,	77 ,,	--	00	01
,,	78 ,,	--	00	02
,,	79 ,,	--	00	08
,,	82 ,,	--	00	08
,,	83 ,,	--	00	03
,,	86 ,,	--	00	03
,,	87 ,,	—	00	06
,,	92 ,,	—	00	16
,,	93 ,,	--	00	01
,,	122 ,,	--	00	05
,,	125 ,,	--	00	02
,,	139 ,,	--	00	10
,,	141 ,,	--	00	12
,,	143 ,,	--	00	07
,,	144 ,,	--	00	07
,,	145 ,,	-	00	15
,,	146 ,,		00	04
,,	147 ,,	--	00	04
,,	151 ,,	--	00	10
,,	152 ,,	--	00	09
,,	155 ,,	--	00	07
,,	177	-	00	07
,,	179 ,,	--	00	05
,,	180 ,,	--	00	03
,,	181 ,,	--	00	11
,,	186 ,,	-	00	10
,,	187 ,,		00	15
मोहिपे	58 ,,		00	03
,,	59 ,,	-	00	35
,,	72 ,,	--	00	02
पायेजे	84 ,,	--	00	09
,,	85 ,,	--	00	18
,,	105 ,,	--	00	06
,,	108 ,,	---	00	27
,,	124 ,,	--	00	19
,,	125 ,,	--	00	07
,,	131 ,,	--	00	23
,,	132 ,,	--	00	10
,,	134 ,,	--	00	10
,,	136 ,,		00	14
,,	140 ,,	--	00	04
,,	141 ,,	--	00	21
,,	142 ,,	--	00	02
,,	173 ,,	-	00	07
,,	175 ,,	-	00	07
,,	178 ,,	--	00	26
,,	180 ,,	--	00	10
,,	181 ,,	--	00	05

[क्रमांक 12016/29/82 प्रो-II]

S.O. 3089.—Whereas it appears to Central Government that it is necessary to lay a pipeline for transporting Petroleum Products from Bombay to Pune in the State of Maharashtra through Pipeline and that said Pipeline is to be laid through the agency of Hindustan Petroleum Corporation Limited, Bombay.

And whereas, it appears to Central Government that for laying pipeline it is necessary to acquire the Right of User in respect of the lands appended to herewith in schedule.

Now, therefore, in exercise of the powers vested in them by virtue of Section 3 (i) of Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) AO 1962 (50 of 1962) Central Government notify their intention to acquire the Right of user in the lands referred to above.

Any person having his interest in the lands referred to above having any objection for laying the Pipeline through above mentioned lands may prefer an objection within 21 days of the publication of this notification before the competent authority Hindustan Petroleum Corporation Limited, Bombay Pune Pipeline Project, Fuels Refinery, Corridor Road, Bombay-74.

All person having any objection may also state whether they want to be heard in person either himself or through any lawyer appointed by him.

SCHEDULE

Pipeline from Shendung to Poyenje
Taluka Panvel, Dist. Raigad, Maharashtra

Village	Survey No./ Gut No.	Hissa No.	Area	
			H	R
Shendung	42 Part	—	00	04
,,	110 ,,	—	00	29
,,	114 ,,		00	18
,,	115 ,,	—	00	06
,,	116 ,,	—	00	04
,,	117 ,,	—	00	03
,,	118 ,,	-	00	04
,,	121 ,,	—	00	20
,,	128 ,,	—	00	05
Bhirgir	57 ,,	-	00	07
,,	62 ,,		00	16
,,	58 ,,	-	00	67
,,	66 ,,	-	00	08
,,	68 ,,	—	00	09
,,	77 ,,	—	00	01
,,	78 ,,	—	00	02
,,	79 ,,		00	08
,,	82 ,,	--	00	08
,,	83 ,,	—	00	03
,,	86 ,,	-	00	06
,,	87 ,,	—	00	06
,,	92 ,,	—	00	16
,,	93 ,,	—	00	01
,,	122 ,,	—	00	05
,,	125 ,,	---	00	02
,,	139 ,,		00	10
,,	141 ,,	—	00	12
,,	143 ,,	—	00	07
,,	144 ,,	---	00	07
,,	145 ,,	—	00	15
,,	146 ,,	—	00	04
,,	147 ,,	—	00	04
,,	151 ,,	—	00	10
,,	152 ,,	--	00	09
,,	155 ,,	—	00	07

Village	Survey No./ Gutt No.		Hissa No.	Area H	Area R
Bhingar	177	Part	—	C0	07
,,	179	,,	—	00	05
,,	180	,,	—	00	03
,,	181	,,	—	00	11
,,	186	,,	—	00	10
,,	187	,,	—	00	15
Mohipe.	58	,,	—	00	03
,,	59	,,	—	00	35
,,	72	,,	—	00	02
Poyenje	84	,,	—	00	09
,,	85	,,	—	00	18
,,	105	,,	—	00	06
,,	108	,,	—	00	27
,,	124	,,	—	00	19
,,	125	,,	—	00	07
,,	131	,,	—	00	23
,,	132	,,	—	00	10
,,	134	,,	—	00	10
,,	136	,,	—	00	14
,,	140	,,	—	00	04
,,	141	,,	—	00	21
,,	142	,,	—	00	02
,,	173	,,	—	00	07
,,	175	,,	—	00	07
,,	178	,,	—	00	26
,,	180	,,	—	00	10
,,	181	,,	—	00	05

[No. 12016/29/82-II]Prod

का०आ० 3090.—यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि महाराष्ट्र राज्य में बम्बई से पूणे तक पेट्रोलियम पदार्थों के परिवहन के लिए पाइप लाइन हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यत: यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अत: अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड बम्बई पूणे पाइप लाइन्स प्रोजेक्ट पशुबेल रिफायनरीज कौरिडार रोड बम्बई को इस अधिसूचना की तारीख 21 से दिनो के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टत: यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

पाइप-लाइन कसबे खालापूर से शील तक

तालुका खालापुर जिला रायगढ़ राज्य . महाराष्ट्र

गांव	खसरा नम्बर		हिस्सा नम्बर	क्षेत्रफल हेक्टर	क्षेत्रफल ऐयर
1	2		3	4	5
कसबे खालापूर	6 का भाग		—	00	16
,,	7		—	00	23
,,	8		—	00	16
,,	परड़ी		—	00	06
,,	61		—	00	11
,,	62		—	00	29
,,	64		—	00	22
,,	68		—	00	26
,,	69	,,	—	00	22
,,	74	,,	—	00	07
,,	75	,,	—	00	18
,,	77		—	00	34
,,	78	,,	—	00	03
,,	103	,,	—	00	41
,,	104	,,	—	00	31
,,	130	,,	—	00	32
,,	132	,,	—	00	25
,,	133	,,	—	00	12
,,	68	,,	—	00	06
,,	70	,,	—	00	19
,,	71	,,	—	00	20
,,	73	,,	—	00	29
,,	76	,,	—	00	09
,,	77	,,	—	00	15
,,	79	,,	—	00	08
म[illegible]	81	,,	—	00	15
,,	88	,,	—	00	09
,,	89	,,	—	00	09
,,	90	,,	—	00	10
हलखुर्द	8	,,	—	00	37
,,	16	,,	—	00	22
,,	17	,,	—	00	19
,,	18	,,	—	00	04
,,	21	,,	—	00	15
,,	22	,,	—	00	22
,,	23	,,	—	00	26
,,	25	,,	—	00	11
,,	26	,,	—	00	04
हल बुद्रुक	23	,,	—	00	23
,,	24	,,	—	00	17
,,	37	,,	—	00	15
,,	42	,,	—	00	32
,,	43	,,	—	00	23
,,	44	,,	—	00	02

गांव	खसरा नम्बर	हिस्सा नम्बर	क्षेत्रफल	
			हैक्टर	एयर
हल बुद्रुक	49 का भाग	--	00	17
,,	50 ,,	--	00	15
,,	51 ,,	--	00	36
,,	67 ,,	--	00	13
,,	71 ,,	--	00	01
,,	72 ,,	--	00	15
आजोशी	5 ,,	--	00	04
,,	8 ,,	--	00	15
,,	16 ,,	--	00	13
शील	10 ,,	--	0	08
,,	13 ,,	--	00	14
,,	14 ,,	--	00	13
,,	17 ,,	--	00	23
,,	20 ,,	--	00	23
,,	21 ,,	--	00	27
,,	22 ,,	--	00	27
,,	34 ,,	--	00	06

(संख्या 12016/31/82-प्रो० I)

S.O. 3090.—Whereas it appears to Central Government that it is necessary to lay a pipeline for transporting Petroleum Products from Bombay to Pune in the State of Maharashtra through Pipeline and that said Pipeline is to be laid through the agency of Hindustan Petroleum Corporation Limited, Bombay.

And whereas, it appears to Central Government that for laying pipeline it is necessary to acquire the Right of User in respect of the lands appended to herewith in schedule.

Now, therefore, in exercise of the powers vested in them by virtue of Section 3 (i) of Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) AO 1962 (50 of 1962) Central Government notify their intention to acquire the Right of user in the lands referred to above.

Any person having his interest in the lands referred to above having any objection for laying the Pipeline through above mentioned lands may prefer an objection within 21 days of the publication of this notification before the competent authority Hindustan Petroleum Corporation Limited, Bombay Pune Pipeline Project, Fuels Refinery, Corridor Road, Bombay-74.

All persons having any objection may also state whether they want to be heard in person either himself or through any lawyer appointed by him.

SCHEDULE

Pipe line From : Kasbe Khalapur to Sheel

Taluka : Khalopur, Dist. Raigad.

Village	Survey No./Gut No.	Hissa No.	Area	
			H =	R
1	2	3	4	5
Kasbe Khalapur.	6 Part	–	00	16
,,	7 ,,	—	00	23
,,	8 ,,	—	00	16
,,	Pardi ,,	—	00	06
,,	61 ,,	—	00	11
,,	62 ,,	—	00	29
,,	64 ,,	—	00	22
,,	68 ,,	–	00	26
Kasbe Khalapur	67 Part	–	00	22
,,	74 ,,	—	00	07
,,	75 ,,	—	00	18
,,	77 ,,	—	00	34
,,	78 ,,	,, --	00	03
,,	103 ,,	—	00	41
,,	104 ,,	—	00	31
,,	130 ,,	—	00	32
,,	132 ,,	—	00	25
,,	133 ,,	—	00	12
Madh	68 ,,	—	00	06
,,	70 ,,	—	00	19
,,	71 ,,	—	00	20
,,	73 ,,	—	00	29
,,	76 ,,	—	00	09
,,	77 ,,	—	00	15
,,	79 ,,	—	00	08
,,	81 ,,	—	00	15
,,	88 ,,	--	00	09
,,	89 ,,	—	00	09
,,	90 ,,	–	00	10
Halkhurd.	8 ,,	—	00	37
,,	16 ,,	—	00	22
,,	17 ,,	—	00	19
,,	18 ,,	—	00	04
,,	21 ,,	--	00	15
,,	22 ,,	--	00	22
,,	23 ,,	—	00	26
,,	25 ,,	—	00	11
,,	26 ,,	—	00	04
Hal Budruk	23 ,,	–	00	23
,,	24 ,,	—	00	17
,,	37 ,,	—	00	15
,,	42 ,,	—	00	32
,,	43 ,,	–	00	23
,,	44 ,,	–	00	02
,,	49 ,,	—	00	17
,,	50. ,,	—	00	15
,,	51 ,,	—	00	36
,,	67 ,,	—	00	13
,,	71 ,,	–	00	01
,,	72 ,,	–	00	15
Aajoshi	5 ,,	--	00	04
,,	8 ,,	—	00	15
,,	16 ,,	—	00	13
Sheel	10 ,,	—	00	08
,,	13 ,,	--	00	14
,,	14 ,,	--	00	13
,,	17 ,,	—	00	23
,,	20 ,,	–	00	23
,,	21 ,,	–	00	27
,,	22 ,,	—	00	27
,,	34 ,,	–	00	06

[No. 12016/31/82—Prod. I]

का० आ० 3091.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि महाराष्ट्र राज्य में बंबई से पुणे तक पेट्रोलियम पदार्थों के परिवहन के लिए पाईप लाईन हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन द्वारा बिछाई जानी चाहिये ।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ;

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ;

बशर्ते कि उक्त भूमि मे हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, बम्बई पुणे पाईप लाइन्स प्रोजेक्ट ,युग्मल रिफायनरीज, कारिडार रोड, बम्बई को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

पाइप लाईन नगडोली से नडोदे तक

तालुका : खालापुर , जिला रायगढ़, राज्य - महाराष्ट्र

गांव	खसरा नम्बर	हिस्सा नम्बर	क्षेत्रफल	
			हेक्टर	एयर
1	2	3	4	5
नगडोली	59 का भाग	—	00	06
,,	60 ,,	—	00	06
,,	61 ,,	—	00	07
,,	62 ,,	—	00	07
,,	63 ,,	—	00	22
,,	64 ,,	—	00	13
,,	83 ,,	—	00	73
,,	84 ,,	—	00	07
,,	85 ,,	—	00	22
,,	90 ,,	—	00	18
,,	91 ,,	—	00	07
,,	92 ,,	—	00	13
,,	95 ,,	—	00	09
,,	96 ,,	—	00	12
,,	107 ,,	—	00	37
,,	111 ,,	—	00	15
,,	113 ,,	—	00	22
,,	114 ,,	—	00	11
,,	118 ,,	—	00	38
,,	120 ,,	—	00	23
शिरवले	5 ,,	—	00	15
,,	5 ,,	—	00	15
,,	6	—	00	01
,,	10	—	00	07
,,	11	—	00	02
,,	12 ,,	—	00	07
,,	31	—	00	07
,,	35 ,,	—	00	04
,,	41 ,,	—	00	11
,,	42 ,,	—	00	02
शिरवली	43 का भाग	—	00	18
,,	51 ,,	—	00	04
,,	54 ,,	—	00	01
,,	55 ,,	—	00	10
,,	56 ,,	—	00	04
,,	57 ,,	—	00	15
,,	60 ,,	—	00	22
वणवे	1 ,,	—	00	09
,,	2 ,,	—	00	11
,,	3 ,,	—	00	09
,,	4 ,,	—	00	04
,,	52 ,,	—	00	05
,,	14 ,,	—	00	26
,,	25 ,,	—	00	07
,,	27 ,,	—	00	18
,,	32 ,,	—	00	07
,,	46 ,,	—	00	04
,,	47 ,,	—	00	04
,,	48 ,,	—	00	09
,,	50 ,,	—	00	05
,,	51 ,,	—	00	16
निम्बोडे	30 ,,	—	00	02
,,	34 ,,	—	00	14
,,	36 ,,	—	00	20
,,	37 ,,	—	00	23
,,	41 ,,	—	00	38
,,	56 ,,	—	00	22
,,	58 ,,	—	00	07
,,	59 ,,	—	00	10
,,	62 ,,	—	00	27
,,	63 ,,	—	00	16
,,	64 ,,	—	00	14
नडोदे	26 ,,	—	00	14
,,	28 ,,	—	00	23
,,	43 ,,	—	00	57
,,	48 ,,	—	00	18
,,	54 ,,	—	00	06
,,	68 ,,	—	00	05
,,	69 ,,	—	00	23
,,	70 ,,	—	00	05
,,	74 ,,	—	00	18
,,	75 ,,	—	00	09
,,	78 ,,	—	00	37
,,	79 ,,	—	00	32

[क्रमांक 12016/31/82-प्रो०-II]

S.O. 3091.—Whereas it appears to Central Government that it is necessary to lay a pipeline for transporting Petroleum Products from Bombay to Pune in the State of Maharashtra through Pipeline and that said Pipeline is to be laid through the agency of Hindustan Petroleum Corporation Limited, Bombay.

And whereas, it appears to Central Government that for laying pipeline it is necessary to acquire the Right of User in respect of the lands appended to herewith in schedule

Now, therefore, in exercise of the powers vested in them by virtue of Section 3 (i) of Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) AO 1962 (50 of 1962), Central Government notify their intention to acquire the Right of user in the lands referred to above

Any person having his interest in the Lands referred to above having any objection for laying the Pipeline through above mentioned lands may prefer an objection within 21 days of the publication of this notification before the competent authority Hindustan Petroleum Corporation Limited, Bombay Pune Pipeline Project, Fuels Refinery, Corridor Road Bombay-74.

All persons having any objection may also state whether they want to be heard in person either himself or through any lawyer appointed by him.

SCHEDULE

Pipeline from Nagdoli to Nadode Talnka: Kalapur, Dist Raigad, Maharashtra

Village	Survey No. G No.	Hissa No.	Area H	Area R
Nagdoli	59 Part	—	00	06
,,	60 ,,	—	00	06
,,	61 ,,	—	00	07
,,	62 ,,	—	00	07
,,	63 ,,	—	00	22
,,	64 ,,	—	00	13
,,	83 ,,	—	00	73
,,	84 ,,	—	00	07
,,	85 ,,	—	00	22
,,	90 ,,	—	00	18
,,	91 ,,	—	00	07
,,	92 ,,	—	00	13
,,	95 ,,	—	00	09
,,	96 ,,	—	00	12
,,	107 ,,	—	00	37
,,	111 ,,	—	00	15
,,	113 ,,	—	00	22
,,	114 ,,	—	00	11
,,	118 ,,	—	00	33
,,	120 ,,	—	00	23
Shikhli	4 ,,	—	00	15
,,	5 ,,	—	00	15
,,	6 ,,	—	00	01
,,	10 ,,	—	00	07
,,	11 ,,	—	00	02
,,	12 ,,	—	00	07
,,	34 ,,	—	00	07
,,	35 ,,	—	00	04
,,	41 ,,	—	00	11
,,	42 ,,	—	00	02
,,	43 ,,	—	00	18
,,	51 ,,	—	00	04
,,	54 ,,	—	00	01
,,	55 ,,	—	00	10
,,	56 ,,	—	00	04
,,	57	—	00	15
,,	600 ,,	—	00	22
Wanwe	1 Part	—	00	09
,,	2 ,,	—	00	11
,,	3 ,,	—	00	09
,,	4 ,,	—	00	04
,,	14 ,,	—	00	26
,,	15 ,,	—	00	07
,,	27 ,,	—	00	18
,,	32 ,,	—	00	07
,,	46 ,,	—	00	04
,,	47 ,,	—	00	01
,,	48 ,,	—	00	04
,,	50 ,,	—	00	09
,,	51 ,,	—	00	05
,,	52 ,,	—	00	16
Nimbode	30 ,,	—	00	05
,,	34 ,,	—	00	02
,,	36 ,,	—	00	14
,,	37 ,,	—	00	20
,,	41 ,,	—	00	23
,,	56 ,,	—	00	38
,,	58 ,,	—	00	22
,,	59 ,,	—	00	07
,,	62 ,,	—	00	10
,,	63 ,,	—	00	27
,,	64 ,,	—	00	16
Nadode	26 ,,	—	00	14
,,	28 ,,	—	00	23
,,	43 ,,	—	00	57
,,	48 ,,	—	00	18
,,	54 ,,	—	00	06
,,	68 ,,	—	00	05
,,	69 ,,	—	00	23
,,	70 ,,	—	00	05
,,	74 ,,	—	00	18
,,	75 ,,	—	00	09
,,	78 ,,	—	00	37
,,	79 ,,	—	00	32

[No. 12016/31/82-Prod. II]

का०आ० 3092—यत केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि महाराष्ट्र राज्य में बम्बई से पूणे तक पेट्रोलियम पदार्थों के परिवहन के लिए पाईप लाईन हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन द्वारा बिछाई जानी चाहिये।

और यत यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतत्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, बम्बई पूणे पाइप लाइन्स प्रोजेक्ट फ्यूअल रिफायनरीज-लाईन्स कारिडोर रोड बम्बई को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

पाइप-लाईन मुढावरे से नायगांव तक

तालुका मावल, गांव मुढावरे, जिला पूर्ण

गांव	77 खसरा नम्बर	हिस्सा नम्बर	क्षेत्रफल हेक्टर- एयर	
मुढावरे	77 का भाग	—	00	45
"	91 "	—	00	21
"	93 "	—	00	13
"	94 "	—	00	01
"	96 "	—	00	11
"	102 "	—	00	22
"	101 "	—	00	28
"	110 "	—	00	26
"	111 "	—	00	08
"	112 "	—	00	33
"	113 "	—	00	27
"	114 "	—	00	01
"	125 "	—	00	01
"	80 "	—	00	14
"	85 "	—	00	49
वलक	86 का भाग	—	00	14
"	87 "	—	00	26
वडिवले	10 का भाग	—	00	23
"	15 "	—	00	20
"	16 "	—	00	16
"	17 "	—	00	23
"	18 "	—	00	03
"	23 "	—	00	03
"	24 "	—	00	21
"	25 "	—	00	37
"	27 "	—	50	05
"	28 "	—	00	19
नायगांव	81 का भाग	—	00	06
"	86 "	—	00	54
"	87 "	—	00	12
"	88 "	—	00	16
"	89 "	—	00	26
"	135 "	—	00	43
"	136 "	—	00	08
"	148 "	—	00	22
"	149 "	—	00	21

[क्रमांक 12016/32/82-प्रो० I

S.O. 3092.—Whereas it appears to Central Government that it is necessary to lay a pipeline for transporting Petroleum Products from Bombay to Pune in the State of Maharashtra through Pipeline and that said Pipeline is to be laid through the agency of Hindustan Petroleum Corporation Limited, Bombay.

And whereas, it appears to Central Government that for laying pipeline it is necessary to acquire the Right of User in respect of the lands appended to herewith in schedule

Now, therefore, in exercise of the powers vested in them by virtue of Section 3 (i) of Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) AO 1962 (50 of 1962) Central Government notify their intention to acquire the Right of user in the lands referred to above.

Any person having his interest in the lands referred to above having any objection for laying the Pipeline through above mentioned lands may prefer an objection within 21 days of the publication of this notification before the competent authority Hindustan Petroleum Corporation Limited Bombay Pune Pipeline Project, Fuels Refinery, Corridor Road, Bombay-74.

All persons having any objection may also state whether they want to be heard in person either himself or through any lawyer appointed by him.

SCHEDULE

Village : Mundaw re to Naigaon
Tq : Mawal Dist : Pune, Maharashtra State

Village	Survey No. G. No.	Hissa No.	Area H	R
Mundaw re	77 Part	—	00	45
,,	91 ,,	—	00	21
,,	93 ,,	—	00	13
,,	94 ,,	—	00	01
,,	96 ,,	—	00	11
,,	102 ,,	—	00	22
,,	101 ,,	—	00	28
,,	110 ,,	—	00	26
,,	111 ,,	—	00	08
,,	112 ,,	—	00	33
,,	113 ,,	—	00	27
,,	114 ,,	—	00	01
,,	125 ,,	—	00	01
,,	80 ,,	—	00	14
,,	85 ,,	—	00	49
W. lak	86 ,,	—	00	14
,,	87 ,,	—	00	26
Wadivale	10 ,,	—	00	23
,,	15 ,,	—	00	20
,,	16 ,,	—	00	16
,,	17 ,,	—	00	23
,,	18 ,,	—	00	03
,,	23 ,,	—	00	03
,,	24 ,,	—	00	21
,,	25 ,,	—	00	37
,,	27 ,,	—	00	05
,,	28 ,,	—	00	19
Naig on	81 ,,	—	00	06
,,	86 ,,	—	00	54
,,	87 ,,	—	00	12
,,	88 ,,	—	00	16
,,	89 ,,	—	00	26
,,	135 ,,	—	00	43
,,	136 ,,	—	00	08
,,	148 ,,	—	00	22
,,	149 ,,	—	00	21

[No. 12016/32/82-P ol. I]

का० आ० 3093—यत केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि महाराष्ट्र राज्य में बम्बई से पूणे तक पेट्रोलियम पदार्थों के परिवहन के लिए पाईप लाईन हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन द्वारा बिछाई जानी चाहिये ।

और यत यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद् द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, बम्बई पूणे पाइप लाइन्स प्रोजेक्ट फ्यूएल रिफायनरी, कॉरिडोर रोड, बम्बई को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

गांव : शिलाटने, तालुका मावल, जिला पूणे, राज्य : महाराष्ट्र

गांव	खसरा नं०	हिस्सा नंबर	क्षेत्रफल	
			हेक्टर	एयर
शिलाटने	4 का भाग	—	00	14
"	5 "	—	00	19
"	6 "	—	00	26
"	7 "	—	00	15
"	8 "	—	00	01
"	10 "	—	00	03
"	165 "	—	00	18
"	187 "	—	00	18
"	188 "	—	00	12
"	189 "	—	00	09
"	190 "	—	00	12
"	192 "	—	00	09
"	193 "	—	00	04
	195	—	00	21
"	197 "	—	00	05
"	198	—	00	17
"	199 "	—	00	01
	200 "	—	00	07
"	201 "	—	00	16
"	205 "	—	00	01
	215 "	—	00	13
"	216 "	—	00	01
	219	—	00	24

[संख्या 12016/32/82-प्रो० II]

S.O. 3093.—Whereas it appears to Central Government that it is necessary to lay a pipeline for transporting Petroleum Products from Bombay to Pune in the State of Maharashtra though Pipeline and that said Pipeline is to be laid through the agency of Hindustan Petroleum Corporation Limited, Bombay.

And whereas, it appears to Central Government that for laying pipeline it is necessary to acquire the Right of User in respect of the lands appended to herewith in schedule.

Now, therefore, in exercise of the powers vested in them by virtue of Section 3 (i) of Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) AO 1962 (50 of 1962) Central Government notify their intention to acquire the Right of User in the lands referred to above.

Any person having his interest in the lands referred to above having any objection for laying the Pipeline through above mentioned lands may prefer an objection within 21 days of the publication of this notification before the competent authority Hindustan Petroleum Corporation Limited, Bombay Pune Pipeline Project, Fuels Refinery, Corridor Road, Bombay-74.

All persons having any objection may also state whether they want to be heard in person either himself or through any lawyer appointed by him.

SCHEDULE

Pipeline through Village Silatane
Taluka : Mawal, Dist : Pune State : Maharashtra

Village	Survey No. Gat No.	Hissa No.	Area H	R
Shilatane	4 Part	—	00	14
,,	5 ,,	—	00	19
,,	6 ,,	—	00	26
,,	7 ,,	—	00	15
,,	8 ,,	—	00	01
,,	10 ,,	—	00	03
,,	165 ,,	—	00	18
,,	187 ,,	—	00	18
,,	188 ,,	—	00	12
,,	189 ,,	—	00	09
,,	190 ,,	—	00	12
,,	192 ,,	—	00	09
,,	193 ,,	—	00	04
,,	195 ,,	—	00	21
,,	197 ,,	—	00	05
,,	198 ,,	—	00	17
,,	199 ,,	—	00	01
,,	200 ,,	—	00	07
,,	201 ,,	—	00	16
,,	205 ,,	—	00	01
,,	215 ,,	—	00	13
,,	216 ,,	—	00	04
,,	219 ,,	—	00	24

[No. 12016/32/82 Prod-II]

नई दिल्ली, 16 अगस्त, 1982

का० आ० 3094.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि महाराष्ट्र राज्य में बम्बई से पूणे तक पेट्रोलियम पदार्थों के परिवहन के लिए पाईप लाईन हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद् द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम

कारपोरेशन लिमिटेड, बम्बई पुणे पाइप लाइन्स प्रोजेक्ट फ्युअल रिफायनरीज कॉरिडोर रोड बम्बई को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टत यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

पाइप-लाईन देवद से शिवने तक—

तालुका . पनवेल जिला रायगड, राज्य महाराष्ट्र

गाँव	खसरा नम्बर	हिस्सा नम्बर	क्षेत्रफल हेक्टर	एयर
देवद	17 का भाग	—	00	15
"	21 "	—	00	37
"	25 "	—	00	18
"	26 "	—	00	22
"	41 "	—	00	11
"	71 "	—	00	07
	72 "	—	00	15
शिवने	17 का भाग	—	00	07
"	20 "	—	00	15
"	21 "	—	00	07
"	26 "	—	00	07
"	27 "	—	00	07
"	28 "	—	00	09
"	62 "	—	00	26
"	63 "	—	00	22
"	64 "	—	00	18
"	65 "	—	00	07
"	68 "	—	00	03
"	66 "	—	00	11
"	74 "	—	00	08
"	75 "	—	00	09
शिवकर	75 का भाग	—	00	09
"	79 "	—	00	05
"	80 "	—	00	09
"	81 "	—	00	11
"	87 "	—	00	10
"	89 "	—	00	14
"	90 "	—	00	14
"	129 "	—	00	07
"	149 "	—	00	09
"	150 "	—	00	08
"	151 "	—	00	05
"	168 "	—	00	46
"	192 "	—	00	03
"	193 "	—	00	23
"	195 "	—	00	03
"	206 "	—	00	02
"	207 "	—	00	27
बारवाई	3 का भाग	—	00	06
"	4 "	—	00	12
"	12/3 "	—	00	15
"	12/8 "	—	00	11
"	12/9 का भाग	—	00	09
"	13 "	—	00	01
"	23 "	—	00	29
"	26 "	—	00	11
"	27 "	—	00	13
"	34 "	—	00	11
"	35 "	—	00	15
"	36 "	—	00	29
"	37 "	—	00	20
"	55 "	—	00	02
"	57 "	—	00	15
"	60 "	—	00	04
"	66 "	—	00	11
"	68 "	—	00	29
"	69 "	—	00	16
"	70 "	—	00	04
"	79 "	—	00	45
"	92 "	—	00	04
"	99 "	—	00	04
"	102 "	—	00	68

[क्रमांक 12016/30/82/प्रो०-I]

S.O. 3094.—Whereas it appears to Central Government that it is necessary to lay a pipeline for transporting Petroleum Products from Bombay to Pune in the State of Maharashtra though Pipeline and that said Pipeline is to be laid through the agency of Hindustan Petroleum Corporation Limited, Bombay.

And whereas, it appears to Central Government that for laying pipeline it is necessary to acquire the Right of User in respect of the lands appended to herewith in schedule.

Now, therefore, in exercise of the powers vested in them by virtue of Section 3(i) of Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) AO 1962 (50 of 1962) Central Government notify their intention to acquire the Right of user in the lands referred to above.

Any person having his interest in the lands referred to above having any objection for laying the Pipeline through above mentioned lands may prefer an objection within 21 days of the publication of this notification before the competent authority Hindustan Petroleum Corporation Limited, Bombay Pune Pipeline Project, Fuels Refinery, Corridor Road, Bombay-74.

All persons having any objection may also state whether they want to be heard in person either himself or through any lawyer appointed by him.

SCHEDULE

Pipeline From : Devad to Shivkar.

Taluk : Panvel, District . Raigad. Maharashtra.

Village	Survey No. Gat No.	Hissa No.	Area H	R
Devad	17 Part	—	00	15
,,	21 ,,	—	00	37
,,	25 ,,	—	00	18
,,	26 ,,		00	22
,,	41 ,,	—	00	11

Village	Survey No./Gut No.		Hissa No.	AREA H	AREA R
Devad	71	Part	—	00	07
,,	72	,,	—	00	15
Vinchunde	17	,,	-	00	07
,,	20	,,	—	00	15
,,	21	,,	-	00	07
,,	26	,,	-	00	07
,,	27	,,		00	07
,,	28		—	00	09
,,	62	,,	—	00	26
,,	63	,,	—	00	22
,,	64	,,	—	00	18
,,	65	,,	-	00	07
,,	66	,,	-	00	11
,,	68	,,		00	03
,,	74	,,	—	00	08
,,	75	,,	—	00	09
Shivkar	75	,,		00	09
,,	79	,,	—	00	05
,,	80	,,		00	09
,,	81	,,	—	00	11
,,	87	,,	—	00	10
,,	89	,,	—	00	14
,,	90	,,	—	00	14
,,	129	,,	—	00	07
,,	149	,,	—	00	09
,,	150	,,	-	00	08
,,	151	,,	-	00	05
,,	168	,,		00	46
,,	192	,,	—	00	03
,,	193	,,	—	00	23
,,	195	,,		00	03
,,	206	,,	-	00	02
,,	207	,,	—	00	27
Barvaee	3	,,	—	00	06
,,	4	,,	—	00	12
,,	12/3	,,	—	00	15
,,	12/8	,,	—	00	11
,,	12/9	,,		00	09
,,	13	,,	-	00	01
,,	23	,,	-	00	29
,,	26	,,	-	00	11
,,	27	,,	—	00	13
,,	34	,,	—	00	11
,,	35	,,	—	00	15
,,	36	,,	-	00	29
,,	37	,,		00	20
,,	55	,,	—	00	02
,,	57	,,	—	00	15
,,	60	,,	—	00	04
,,	66	,,	—	00	11
,,	68	,,	—	00	29
,,	69	,,	—	00	16
,,	70	,,	--	00	04
,,	79	,,		00	45
,,	92	,,		00	04
,,	99	,,		00	04
,,	100	,,		00	15
,,	102	,,	—	00	68

[No. 12016/30/82-Prod. I]

का०आ० 3095.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि महाराष्ट्र राज्य में बम्बई से पुणे तक पेट्रोलियम पदार्थों के परिवहन के लिए पाईप लाईन हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन द्वारा बिछाई जानी चाहिये।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड बम्बई पुणे पाइप लाइन्स प्रोजेक्ट पयूएल रिफाइनरीज कॉरिडोर रोड बम्बई को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

पाइप-लाईन ग्राम से धारवी तक

तालुका खालापुर जिला रायगढ़ राज्य महाराष्ट्र

गांव	सर्वे नम्बर		हिस्सा नम्बर	क्षेत्रफल हेक्टर	क्षेत्रफल ऐयर
गाम	59ए का भाग		—	00	52
	102	,,	—	00	05
,,	107		—	00	29
	11	,,	—	00	11
,,	112	,,	—	00	11
,,	115		—	00	23
मोडिवली	1 का भाग		—	00	09
	4	,,	—	00	18
,,	35		—	00	01
,,	36		—	00	38
	37		—	00	01
,,	38		—	00	22
,,	41	,,	—	00	15
,,	42		—	00	07
,,	41		—	00	53
	97		—	00	18
,,	102		—	00	01
	103		—	00	26
	104	,,	—	00	18
	105		—	00	20
,,	110		—	00	15
,,	111		—	00	04
,,	112	,,	—	00	13

गांव	सर्वे नम्बर	हिस्सा नम्बर	क्षेत्रफल	
			हैक्टेयर	एयर
नाढाल	149 का भाग	—	00	33
	151	—	00	08
"	155	—	00	04
सारंग	6 का भाग	—	00	42
"	1	—	00	04
"	13	—	00	22
	19	—	00	29
"	20	—	00	11
	66	—	00	22
"	68	—	00	12
"	69	—	00	20
"	70	—	00	16
"	71	—	00	18
"	7	—	00	12
असरोती	1 का भाग	—	00	09
"	2	—	00	18
"	3	—	00	24
"	11	—	00	22
"	12	—	00	02
	13	—	00	27
"	15	—	00	07
"	30	—	00	26
"	32	—	00	29
"	34	—	00	15
"	35	—	00	11
"	44	—	00	07
	45	—	00	15
"	46	—	00	11
धारणी	2 का भाग	—	00	12
"	3	—	00	11
"	4	—	00	33
"	10	—	00	18
	11	—	00	44
	14	—	00	04
	15	—	00	[illegible]

[क्रमांक 12016/30/8-प्रो०II)]

S.O. 3095.—Whereas it appears to Central Government that it is necessary to lay a pipeline for transporting Petroleum Products from Bombay to Pune in the State of Maharashtra though Pipeline and that said Pipeline is to be laid through the agency of Hindustan Petroleum Corporation Limited, Bombay

And whereas, it appears to Central Government that for laying pipeline it is necessary to acquire the Right of User in respect of the lands appended to herewith in schedule.

Now, therefore, in exercise of the powers vested in them by virtue of Section 3 (i) of Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) AO 1962 (50 of 1962) Central Government notify their intention to acquire the Right of user in the lands referred to above

Any person having his interest in the lands referred to above having any objection for laying the Pipeline through above mentioned lands may prefer an objection within 21 days of the publication of this notification before competent authority, Hindustan Petroleum Corporation Limited, Bombay Pune Pipeline Project, Fuels Refinery, Corridor Road, Bombay-74

All persons having any objection may also state whether they want to be heard in person either himself or through any lawyer appointed by him.

SCHEDULE

Pipeline From Rees to Dharni
Taluka Khalapur Dist Raigad Maharashtra

Village	Survey No./ Gat No		Hissa No.	AREA	
				H	R
Rees	59A	Part	—	00	52
..	102	..	—	00	05
..	107	..	-	00	29
..	111	..	-	00	11
.	112	..	--	00	11
..	118	..		00	23
Lodhivali	1	.	—	00	09
..	4	..		00	18
..	35	..	-	00	01
..	36	..		00	38
..	37	..	—	00	01
..	38	..	—	00	22
..	41	..		00	15
..	42	..	—	00	07
..	44	..	—	00	53
..	97	..	—	00	18
..	102	..	—	00	01
..	103	..	—	00	26
..	104	..	—	00	18
..	105	..	—	00	20
..	110	..	—	00	15
..	111	..	—	00	04
..	112	..	—	00	13
Nadhal	149	..		00	33
..	151	..	—	00	08
..	155	..	-	00	04
Sarang	6	Part	—	00	42
..	12	..	—	00	04
..	13	..	--	00	22
..	19	..	-	00	29
..	20	..	—	00	11
..	66	..	-	00	22
..	68	..	--	00	12
..	69	..	—	00	20
..	70	..	—	00	16
..	71	..	—	00	48
.	72	..	—	00	12
Asroti	1	..	—	00	09
..	2	..	—	00	18
..	3	..	—	00	24
..	11	..	—	00	22
..	12	..	—	00	02
..	13	..	-	00	27
..	15	..	.	00	07
..	30	..	-	00	26
..	32	..	—	00	29
..	34	..	—	00	15
..	35	..		00	11
.	44	.		00	07
..	45	.		00	15
..	46	.	-	00	11

Village	Survey No. Gut No.	Hissa No.	Area H	Area R
Dharni	2 Part	—	00	42
,,	3 ,,	—	00	11
,,	4 ,,	—	00	33
,,	10 ,,	—	00	18
,,	11 ,,	—	10	44
,,	14 ,,	—	00	01
,,	15 ,,	—	00	26

[No. 12016/30/82-Prod. II]

का० आ० 3096.—यत केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि महाराष्ट्र राज्य में बंबई से पुणे तक पेट्रोलियम पदार्थों के परिवहन के लिये पाईप लाईन हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन द्वारा बिछाई जानी चाहिये।

और यत यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाईप लाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाने के लिये आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, बम्बई पुणे पाईप लाईन प्रोजेक्ट फ्यूएल रिफायनरीज कारिडोर रोड बम्बई को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

एम०पी० केस नं० 15/82

पाईपलाईन टाकवे खुर्द से खडकाले तक

तालुका : मावल जिला पुणे राज्य महाराष्ट्र

गाव	खसरा नम्बर	हिस्सा नम्बर	क्षेत्रफल हैक्टर	क्षेत्रफल एयर
1	2	3	4	5
टाकवे खुर्द	69 का भाग	—	00	01
,,	70 ,,	—	00	05
,,	76 ,,	—	00	02
,,	77 ,,	—	00	57
,,	81 ,,	—	00	31
,,	212 ,,	—	00	20
,,	219 ,,	—	00	19
,,	239 ,,	—	00	01
,,	241 का भाग	—	00	04
,,	244 ,,	—	00	10
,,	245 ,,	—	00	05
,,	246 ,,	—	00	07
,,	262 ,,	—	00	18
,,	264 ,,	—	00	25
,,	265 ,,	—	00	11
,,	266 ,,	—	00	04
,,	268 ,,	—	00	01
,,	273 ,,	—	00	01
,,	274 ,,	—	00	34
,,	276 ,,	—	00	16
,,	279 ,,	—	00	02
,,	369 ,,	—	00	20
,,	370 ,,	—	00	18
साणे	324 ,,	—	00	03
,,	325 ,,	—	00	13
,,	327 ,,	—	00	01
,,	330 ,,	—	00	42
,,	331 ,,	—	00	17
,,	332 ,,	—	00	01
,,	337 ,,	—	00	12
,,	341 ,,	—	00	25
,,	343 ,,	—	00	24
,,	361 ,,	—	00	54
,,	364 ,,	—	00	40
,,	365 ,,	—	00	03
,,	366 ,,	—	00	57
,,	367 ,,	—	00	08
,,	383 ,,	—	00	26
खडकाले	32 ,,	—	00	03
,,	33 ,,	—	00	53
,,	34 ,,	—	00	36
,,	35 ,,	—	00	46
,,	53 ,,	—	00	09
,,	55 ,,	—	00	22
,,	56 ,,	—	00	55
,,	57 ,,	—	00	09
,,	69 ,,	—	00	36
,,	70 ,,	—	00	11

[क्रमांक 12016/42/82-प्रा०-I]

एस० एम० गायल, निदेशक

S.O. 3096.—Whereas it appears to Central Government that it is necessary to lay a pipeline for transporting Petroleum Products from Bombay to Pune in the State of Maharashtra though Pipeline and that said Pipeline is to be laid through the agency of Hindustan Petroleum Corporation Limited, Bombay.

And whereas, it appears to Central Government that for laying pipeline it is necessary to acquire the right of User in respect of the lands appended to herewith in schedule.

Now, therefore, in exercise of the powers vested in them by virtue of Section 3 (i) of Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) AO 1962 (50 of 1962) Central Government notify their intention to acquire the Right of user in the lands referred to above.

Any person having his interest in the lands referred to above having any objection for laying the Pipeline through above mentioned lands may prefer an objection within 21 days of the publication of this notification before the competent authority Hindustan Petroleum Corporation Limited Bombay Pune Pipeline Project, Fuels Refinery, Corridor Road, Bombay-74.

All persons having any objection may also state whether they want to be heard in person either himself or through any lawyer appointed by him.

L.A. Case No. 15/82

SCHEDULE

Pipeline Takave Khurd to Khadkale
Tal : Maval, Dist; : Pune State : Maharashtra

Village	Gut No.	Hissa No.	AREA H	AREA R
Takave Khurd	69 Part	—	00	01
,,	70 ,,	—	00	05
,,	76 ,,	—	00	02
,,	77 ,,	—	00	57
,,	81 ,,	—	00	34
,,	212 ,,	—	00	20
,,	219 ,,	—	00	19
,,	239 ,,	—	00	01
,,	241 ,,	—	00	04
,,	244 ,,	—	00	10
,,	245 ,,	—	00	05
,,	246 ,,	—	00	07
,,	262 ,,	—	00	18
,,	264 ,,	—	00	25
,,	265 ,,	—	00	11
,,	266 ,,	—	00	04
,,	268 ,,	—	00	01
,,	273 ,,	—	00	01

Village	Survey No.	Hissa No.	Area H	Area R
Takave Khurd	274 ,,	—	00	34
,,	276 ,,	—	00	16
,,	279 ,,	—	00	02
,,	369 ,,	—	00	20
,,	370 ,,	—	00	18
,,	324 ,	—	00	03
,,	325 ,,	—	00	13
,,	327 ,,	—	00	01
,,	330 ,,	—	00	42
,,	331 ,,	—	00	17
,,	332 ,,	—	00	01
,,	337 ,,	—	00	12
,,	341 ,,	—	00	25
,,	343 ,,	—	00	24
,,	361 ,,	—	00	54
,,	364 ,,	—	00	40
,,	365 ,,	—	00	03
,,	366 ,,	—	00	57
,,	367 ,,	—	00	08
,,	383 ,,	—	00	26
Khadkale	32 Part	—	00	03
,,	33A ,,	—	00	53
,,	34 ,,	—	00	36
,,	35 ,,	—	00	46
,,	53 ,,	—	00	09
,,	55 ,,	—	00	22
,,	56 ,,	—	00	55
,,	57 ,,	—	00	09
,,	69 ,,	—	00	36
,,	70 ,,	—	00	11

[No. 12016/42/82-Prod. I]
L.M. GOYAL, Director

नागरिक पूर्ति मंत्रालय

भारतीय मानक संस्था

नई दिल्ली, 1982-08-10

का०आ० 3097.—भारत के राजपत्र भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) दिनांक 1969-10-04 में प्रकाशित तत्कालीन औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा कम्पनी मामलों का मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) (भारतीय मानक संस्था) अधिसूचना संख्या एस ओ 4005 दिनांक 1969-09-16 के आंशिक रूप में संशोधन करते हुए भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि रेड जिंक आक्साइड क्रोम का वायु शुष्क प्राइमर देने के लिए तैयार मिश्रित रंग रोगन के मानक चिह्न में कुछ संशोधन किया गया है। मानक चिह्न की यह संशोधित डिजाइन तत्संबंधी भारतीय मानक के शीर्षक और डिजाइन के शाब्दिक विवरण सहित नीचे अनुसूची में दी गई है।

भारतीय मानक संस्था प्रमाणन चिह्न (अधिनियम 1952) और उसके अधीन बने नियम और विनियम के कार्यों के लिए यह मानक चिह्न 1981-03-16 से लागू होगा।

अनुसूची

क्रम संख्या	मानक चिह्न की डिजाइन	उत्पाद/उत्पाद की श्रेणी	तत्संबंधी भारतीय मानक की पद संख्या और शीर्षक	मानक चिह्न के डिजाइन का शाब्दिक विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	IS 2074-79 ISI	रेड जिंक आक्साइड क्रोम का वायु शुष्क प्राइमर देने के लिए, तैयार मिश्रित रंग रोगन	IS 2074-1979 रेड जिंक आक्साइड क्रोम का वायु शुष्क प्राइमर देने के लिए, तयार मिश्रित रंग रोगन की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	भारतीय मानक संस्था का मोनोग्राम जिसमें ISI शब्द होते है स्तम्भ (2) में दिखाई गई शैली और अनुपात में तैयार किया गया है और जैसा डिजाइन में दिखाया गया है उस मोनोग्राम के ऊपर की ओर भारतीय मानक की संख्या और वर्ष अंकित किया गया है।

[संख्या सी एम डी/13 : 9]

MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES

INDIAN STANDARDS INSTITUTION

New Delhi 1982-08-10

S.O. 3097.—In partiel modifcation of the then Ministry of Industrial Dovelopment, Internal Trade and Company Affairs (Deptt. of Industrial Development) (Indian Standards Institution) notification number S. O. 4005 dated 1969-09-16, published in the Gazette of India, Part-II, Section-3, Sub-Section (ii) dated 1969-10-4, the Indian Standards Institution, hereby, notifies that the Standard Mark for ready mixed paint, air drying, red oxide-zinc chrome priming, has been revised. The revised design of the Standard Mark together with the title of the relevant Indian Standard and verbal description of the design are given in the following Schedule.

This Standard Mark for the purposes of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Act, 1952 and the Rules and Regulations framed thereunder, shall come into force with effect from 1981-03-16 :

SCHEDULE

Sl. No.	Design of the Standard Mark	Product/Class of Product	No. and Title of the Relevant Indian Standard	Verbal Description of the Ddesign of the Standard Mark
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	IS : 2074-79	Ready mixed paint, air drying, red oxide-zinc chrome priming.	IS : 2074—1979 Specification for ready mixed paint, air drying, re-oxide-zinc chrome priming (first revision)	The monogram of the Indian Standards Institution, consisting of letters 'ISI' drawn in the exact style and relative proportions as indicated in Col. (2); the number of the Indian Standard, alongwith its year, being superscribed on the top side of the monogram as indicated in the design.

[No. CMD/13:9]

का०आ० 3098.—भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिन्ह) के नियम 1955 के नियम 4 के उपविनियम (1) के अनुसार भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि जिन भारतीय मानक चिन्हों की डिजाइन उसके शाब्दिक विवरण तथा तत्संबंधी भारतीय मानकों के शीर्षक सहित नीचे अनुसूची में दिए गए है न भारतीय मानक संस्था द्वारा निर्धारित किए गए हैं।

भारतीय मानक संस्था प्रमाणन चिन्ह अधिनियम 1952 और उसके अधीन बने नियमो और विनियमों के निमित्त यह मानक चिह्न प्रत्येक के आगे दी गई तिथियों से लागू होंगे

अनुसूची

क्रम संख्या	मानक चिन्ह की डिजाइन	उत्पाद/उत्पाद की श्रेणी	तत्संबंधी भारतीय मानक की संख्या और शीर्षक	मानक चिह्न की डिजाइन का शाब्दिक विवरण	लागू होने की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
IS : 804—67		संपीड़ित इस्पात की आयताकार टंकियां	IS : 804—1967 संपीड़ित इस्पात की आयताकार टंकियों की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	भारतीय मानक संस्था का मोनोग्राम जिसमें ISI शब्द होते हैं स्तम्भ (2) दिखाई गई शैली और अनुपात में तैयार किया गया है और जैसे डिजाइन मे दिखाया गया है उस मोनोग्राम के ऊपर की ओर भारतीय मानक की संख्या और वर्ष दिया गया है।	1982-03-01
2 IS 1748—81		ग्रफाइट भूषाओं के माइज	IS : 1748—1981 ग्रफाइट भूषाओं के माइजों की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	भारतीय मानक संस्था का मोनोग्राम जिसमें ISI शब्द होते हैं स्तम्भ (2) में दिखाई गई शैली और अनुपात में तैयार किया गया है उस मोनोग्राम के ऊपर की ओर भारतीय मानक की संख्या और वर्ष दिया गया है।	1982-02-01
3. IS : 4704—68		दांत भरने की रजत वंग अमलगम मिश्रधातु	IS : 4704—1968 दांत भरने की रजत वंग अमलगम मिश्रधातु की विशिष्टि	-„-	1982-03-01
4. IS : 7181—74		जल, गैस, और मल निकास क्षतिज ढलाई वाले लोहे के दोहरे फ्लैजदार पाइप	IS : 7181—1974 जल, गैस और मल निकास क्षैतिज ढलाई वाले लोहे के दोहरे फ्लैजदार पाइपो की विशिष्टि	-„-	1982-03-01

[सं० सी एम डी/13 : 9]

S. O. 3098 :– In pursuance of sub-rule (1) of rule 4 of the Indi n St nd .ds Institution (Certification Marks) Rules, 1955 the Indian St nd ds Institution, hereby, notifies that the St ndard Mark(s), design(s) of which together with the verbal description of the design(s) nd the title(s) of the relevant Indian Standard(s) are given in the Schedule hereto connexed, have been specified.

These St ndard Mark(s) for the purpose of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Act, 1952 and the Rules and Regul tions f med thereunder shall come into fo.ce with effect from the dates shown against each :

SCHEDULE

Sl. No.	Design of the Standard Mark	Product/Cl ss of Product	No. and Title of the Relevant Indian Standard	Verbal description of the Design of the Standard Mark	Date of Effect
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	IS : 804—67	Rectangular pressed steel tank	IS : 804—1967 Specification for rectangular pressed steel tank (first revision)	The monogram of the Indian Standards Institution, consisting of letters 'ISI', drawn in the exact style and relative proportions as indicated in Col. (2); the number of the Indian Standard, alongwith its year, being superscribed on the top side of the monogram as indicated in the design.	1982-03-01
2.	IS : 1748—81	Sizes of graphite crucibles	IS : 1748—1981 Specification for sizes of graphite crucibles (first revision)	The monogram of the Indian Standards Institution consisting of letters 'ISI', drawn in the exact style and relative proportions as indicated in Col. (2); the number of the Indian Standard, alongwith its year, being superscribed on the top side of the monogram as indicated in the design.	1982-02-01
3.	IS : 4704—68	Silver-tin dental amalgum alloy	IS : 4704—1968 Specification for silver-tin dental amalgum alloy	-do-	1982-03-01
4.	IS : 7181—74	Horizontally cast iron double flanged pipes of water, gas and sewage	IS : 7181—1974 Specification for horizontally castiron double flanged pipes for water, gas and sewage	-do-	1982-03-01

[No. CMD/13 : 9]

का०आ० 3099.—भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) विनियम 1955 के विनियम 7 के उपविनियम 3 के अनुसार भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विभिन्न उत्पादों की प्रति इकाई मुहर लगाने की फीस नीचे अनुसूची में दिए गए ब्यौरों के अनुसार निर्धारित की गई है और ये फीस उनके सामने दिखाई गई तिथियों से लागू होंगी ।

अनुसूची

क्रम संख्या	उत्पाद/उत्पाद की श्रेणी	तत्संबंधी भारतीय मानक की पद संख्या और शीर्षक	इकाई	प्रति इकाई मुहर लगाने का शुल्क	लागू होने की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	आयताकार संपीड़ित इस्पात की टंकियां	IS : 804–1967 आयताकार संपीड़ित इस्पात की टंकियों की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	एक मीटरी टन	रु० 15.00	1982-03-01
2.	ग्रफाइट भूषाग्रों के साहज	IS : 1748–1981 ग्रफाइट भूषाग्रों के गलन क्षमता ग्रंक साहजों की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)		1. रु० 0.01 प्रति इकाई 'ए' ग्राकार वाले टोंटीदार झुके हुए और ऊपर से डालने वाली भूषाग्रों के लिए; और 2 रु० 0.03 प्रति इकाई बेसिननुमा और टोंटीदार बेसिन नमा भूषाग्रों के लिए	1982-02-01
3.	दांत भरने की रजत वंग ग्रमलगम मिश्रधातु	IS : 4704–1968 दांत भरने की रजत वंग ग्रमलगम मिश्रधातु की विशिष्टि	एक कि०ग्रा०	1. रु० 5.00 प्रति इकाई, पहली 1000 इकाइयों के लिए 2. रु० 2.00 प्रति इकाई, 1001 वीं और इससे ऊपर की इकाइयों के लिए	1982-03-01

1	2	3	4	5	6
4.	जल, गैस और मल निकास क्षैतिज ढलाई वाले लोहे के दोहरे फ्लैजदार पाइप	IS : 7181–1974 जल, गैस और मल निकास क्षैतिज ढलाई वाले लोहे के दोहरे फ्लैजदार पाइपों की विशिष्टि	एक मीटरी टन	रु० 1.00	1982-03-01

[सं० सी एम डी/13 : 10]

S.O. 3099.—In pursuance of sub-regulation (3) of regulation 7 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Regulations, 1955, the Indian Standards Institution, hereby, notifies that the marking fee(s) per unit for various products details of which are given in the Schedule hereto annexed, have been determined and the fee(s) shall come into force with effect from the dates shown against each :

SCHEDULE

Sl. No.	Product/Class of Product	No. and Title of Relevant Indian Standard	Unit	Marking Fee per Unit	Date of Effect
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Rectangular pressed steel tank	IS : 804—1967 Specification for rectangular pressed steel tank (first revision)	One Tonne	Rs. 15.00	1982-03-01
2.	Sizes of graphite crucibles	IS : 1748—1981 Specification for sizes of graphite crucibles (first revision)	Melt capacity number	(i) Re 0.01 per unit for 'A' shape, spouted tilting type and top pour type crucibles and (ii) Re 0.03 per unit for basin type and spouted basin type crucibles	1982-02-01
3.	Silver-tin dental amalgum alloy	IS : 4704–1968 Specification for silver-tin dental amalgum alloy	One kg	(i) Rs 5.00 per unit for the first 1000 units and (ii) Rs 2.00 per unit for the 1001st unit and above	1982-03-01
4.	Horizontally cast iron double flanged pipes for water, gas and sewage	IS : 7181–1974 Specification for horizontally cast iron double flanged pipes for water, gas and sewage	One Tonne	Re 1.00	1982-03-01

[No. CMD/13 : 10]

का०आ० 3100.—निम्नलिखित अनुसूची के स्तम्भ 1 से 4 में जिन अधिसूचनाओं के ब्यौरे दिए गए हैं, उनका आंशिक संशोधन स्वरूप भारतीय मानक संस्था की ओर से एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि स्तम्भ 5 और 6 में दिए गए विभिन्न उत्पादों से संबंधित मुहर लगाने का शुल्क स्तम्भ 7 और 8 में उल्लेख के अनुसार पुनरीक्षित किया गया है। मुहर लगाने का पुनरीक्षित शुल्क दिनांक 1981-10-01 से लागू होगा।

अनुसूची

क्रम संख्या	मंत्रालय का नाम	भारत के राजपत्र की संख्या का संदर्भ	अधिसूचना का संदर्भ	उत्पाद	विशिष्टि की संख्या और शीर्षक	इकाई	प्रति इकाई मुहर लगाने का शुल्क
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6.	उद्योग एवं नागरिक पूर्ति मंत्रालय	भाग II खंड 3, उपखंड (ii) दिनांक 1975-04-19	एस ओ 1231 दिनांक 1975-04-03	जस्ता फासफेट तकनीकी	IS : 1251–1973 जस्ता फासफेट तकनीकी की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	एक मीटरी टन	रु० 15.00
2.	,,	,,	,,	इथाइलीन डाइब्रोमाइड	IS : 1311–1966 इथाइलीन डाइब्रोमाइड की विशिष्टि	100 ग्राम	रु० 2.50
3.	,,	भाग II खंड 3 उपखंड (ii) दिनांक 1975-03-02	एस ओ 2452 दिनांक 1975-07-07	मिथाइल ब्रोमाइड	IS : 1312–1967 मिथाइल ब्रोमाइड की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	एक मीटरी टन	1. रु० 25.00 प्रति इकाई पहली 1000 इकाइयों के लिए, और 2. रु० 15.00 प्रति इकाई 1001वीं इकाई और इससे ऊपर की इकाइयों के लिए

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	उद्योग एवं नागरिक पूर्ति मंत्रालय	भाग II खंड 3, उपखंड (ii) दिनांक 1975-04-19	स ओ 1231 दिनांक 1975-04-03	2, 4-डी सोडियम लवण	IS : 1488-1969 2-4 डी सोडियम लवण की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	100 ग्राम	रु० 7.00
5.	,,	,,	एस ओ 1232 दिनांक 1975-04-03	मालाथियोन तकनीकी	IS : 1832-1978 मालाथियोन तकनीकी की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	100 ग्राम	रु० 4.00
6.	,,	भाग II, खंड 3, उपखंड (ii), दिनांक 1975-04-19	एस ओ 1232 दिनांक 1975-04-03	स्थिरीकृत मिथक्सी इथाइल पारा क्लोराइड सान्द्र	IS : 2127-1962 स्थिरीकृत मिथाक्सी इथाइल पारा क्लोराइड सान्द्र की विशिष्टि	100 ग्राम	रु० 5.00
7	,,	,,	,,	जिं राम, तकनीकी	IS : 3900-1975 जिं राम, तकनीकी की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	एक मीटरी टन	रु० 7.00
8	उद्योग एवं नागरिक पूर्ति मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग)	भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) दिनांक 1975-11-01	एस ओ 4702 दिनांक 1975-09-23	थिरम, तकनीकी	IS : 4320-1967 थिरम तकनीकी की विशिष्टि	एक मीटरी टन	रु० 7.00.
9.	उद्योग एवं नागरिक पूर्ति मंत्रालय	भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) दिनांक 1981-05-16	एस ओ 1497 दिनांक 1981-04-23	फैनी ट्रांथियान तकनीकी	IS : 5280-1969 फेनी ट्राथियान तकनीकी की विशिष्टि	100 ग्राम	1. रु० 20.00 प्रति इकाई पहली 500 इकाइयों के लिए, 2. रु० 10.00 प्रति इकाई 501वीं से 1000 तक की इकाइयों के लिए और 3. रु० 2.00 प्रति इकाई 1001 वीं इकाई और इससे ऊपर की इकाइयों के लिए।

[सं० सी एम डी/13 : 10]

S. O. 3100.—In partial modification of the notifications, details of which are given in Col. 1 to 4 of the following Schedule the Indian Standards Institution, hereby, notifies that the marking fees pertaining to various products referred to in Col. 5 and 6 have been revised as mentioned in Col. 7 and 8 thereof. The revised rate of marking fees shall come into force with effect from 1981-10-01 :

SCHEDULE

Sl. No.	Name of the Ministry	Reference to Govt. of India Gazette	Reference Notification No.	Product	IS : No. & Title of the Specification	Unit	Marking fee per Unit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Ministry of Industry and Civil Supplies.	Part II, Section-3, Sub-Section(ii) dated 1975-04-19	S.O. 1231 dated 1975-04-03	Zinc phosphide, technical	IS : 1251-1973 Specification for Zinc phosphide, technical (first revision)	One Tonne	Rs. 15.00
2.	-do-	-do-	-do-	Ethylene dibromide	IS : 1311-1966 Specification for Ethylene dibromide.	100 kg	Rs. 2.50
3.	-do-	Part-II, Section-3, Sub-section (ii) dated 1975-08-02	S.O. 2452 dated 1975-07-07	Methylbromide	IS : 1312-1967 Specification for Methylbromide (first revision)	One Tonne	(i) Rs. 25.00 per unit for the first 100 units; and (ii) Rs. 15.00 per unit for the 101st unit and above

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4.	Ministry of Industry and Civil Snpplies	Part-II, Section-3, Sub-section (ii) dated 1975-04-19	S.O. 1231 dated 1975 04-03	2, 4-D-Sodium salt	IS : 1488-1969 Specification for 2, 4-D-Sodium salt (first revision)	100 kg	Rs. 7.00
5.	-do-	-do-	S.O. 1232 dated 1975-04-03	Malathion, technical	IS : 1832-1978 Specification for Malathion, technical (first revision)	100 kg	Rs. 4.00
6.	-do-	-do-	-do-	Stabilized methoxy ethyl mercury chloride concentrates	IS : 2127-1962 Specification for Stabilized methoxy ethyl mercury chloride concentrates.	100 kg	Rs. 5.00
7.	-do-	-do-	-do-	Ziram, technical	IS : 3900-1975 Specification for Ziram, technical (first revision)	One Tonne	Rs. 7.00
8.	Ministry of Industry and (Deptt. of Industrial Development)	Part-II, Section-3, Sub-section (ii) dated 1975-11-01	S.O. 4702 dated 1975-09-23	Thiram, technical	IS : 4320-1967 Specification for Thiram, technical.	One Tonne	Rs. 7.00
9.	Ministry of Civil Supplies.	Part-II, section-3, Sub-section (ii) dated 1981-05-16	S.O. 1497 dated 1981-04-23	Fenitorthion, technical.	IS : 5280-1969 Specification for Fenitorthion, technical	100 kg.	(i) Rs 20.00 per unit for the first 500 units; (ii) Rs. 10.00 per unit for the 501st to 1000 units; and (iii) Rs.2.00 per unit for the 1001st unit and above.

[No. CMD/13 : 10]

का० आ० 3101.—निम्नलिखित अनुसूची के स्तम्भ 1 से 4 में जिन अधिसूचनाओं के ब्यौरे दिये गये हैं, उनके आंशिक संशोधन स्वरूप भारतीय मानक संस्था की ओर से एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि स्तम्भ 5 और 6 में दिये गये विभिन्न उत्पादों से सम्बन्धित मुहर लगाने का शुल्क का स्तम्भ 7 और 8 में उल्लेख के अनुसार पुनरीक्षण किया गया है । मुहर लगाने का पुनरीक्षित शुल्क दिनांक 19811001 से लागू होगा ।

अनुसूची

क्रम संख्या	मंत्रालय का नाम	भारत के राजपत्र की संख्या का संदर्भ	अधिसूचना का संदर्भ	उत्पाद	विशिष्टि की संख्या और शीर्षक	इकाई	प्रति इकाई लगाने का शुल्क
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	औद्योगिक विकास मंत्रालय	भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) दिनांक 1972-12-09	एस ओ 4057 दिनांक 1972-11-23	बी एच सी तकनीकी और परिष्कृत	IS : 560—1969 बी एच सी तकनीकी और परिष्कृत की विशिष्टि (दूसरा पुन०)	एक मीटरी टन	1. रु० 3.00 प्रति इकाई पहली 3000 इकाइयों के लिये, 2. रु० 1.50 प्रति इकाई 2001वीं से 4000 तक की इकाइयों के लिये, 3. रु० 1.00 प्रति इकाई 4001वीं और इससे ऊपर की इकाइयों के लिये ।
2.	-- ,, --	-- ,, --	-- ,, --	डी डी टी, तकनीकी	IS : 563—1963 डी डी टी तकनीकी की विशिष्टि (दूसरा पुनरीक्षण)	एक मीटरी टन	1. रु० 3.00 प्रति इकाई पहली 2000 इकाइयों के लिये, 2. रु० 1.00 प्रति इकाई 2001वीं और इससे ऊपर की इकाइयों के लिये ।

(1) (2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3. औद्योगिक विकास विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय	भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) दिनांक 1974-10-05	एस ओ 2581 दिनांक 1974-09-23	ताम्रआक्सी-क्लोराइड तकनीकी	IS: 1486—1969 ताम्र आक्सीक्लोराइड तकनीक की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	एक मीटरी टन	रु० 7.00
4. उद्योग तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय	भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) दिनांक 1975-05-31	एस ओ 1684 दिनांक 1975-05-21	फिनाइल पारा एसिटेट तकनीकी	IS : 2126—1973 फिनाइल पाराएसिटेट तकनीकी की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	एक कि० ग्रा०	30 पैसे
5. उद्योग एवं नागरिक पूर्ति मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग)	भाग II, खंड 3 उपखंड (ii) दिनांक 1976-07-10	एस ओ 2471 दिनांक 1976-06-21	डाइक्लोरोवास तकनीकी	IS : 4929—1978 डाइक्लोरोवास तकनीकी की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	एक कि० ग्रा०	(1) 10 पैसे प्रति इकाई पहली 500 इकाइयों के लिये, (2) 5 पैसे प्रति इकाई 501वीं और इससे ऊपर की इकाइयों के लिये।
6. वाणिज्य एवं नागरिक पूर्ति मंत्रालय (नागरिक पूर्ति विभाग)	भाग II, खंड 3 उपखंड (ii) दिनांक 1980-06-14	एस ओ 1609 दिनांक 1980-06-19	कारबेरिल तकनीकी	IS : 7539—1975 कार्बेरिल तकनीकी की विशिष्टि	100कि०ग्रा०	(1) रु० 10.00 प्रति इकाई पहली 1000 इकाइयों के लिये, (2) रु० 5.00 प्रति इकाई 1001 से 2000 तक की इकाइयों के लिये, (3) रु० 2.00 प्रति इकाई 2001वीं और इससे ऊपर की इकाइयों के लिये।

[सं० सी एम डी/13 : 10

S.O. 3101—In supersession of the notifications, details of which are given in Col. 1 to 4 of the following Schedule, the Indian Standards Institution, hereby, notifies that the marking fees pertaining to various products referred to in Col. 5 and 6 have been revised as mentioned in Col. 7 and 8 thereof. The revised rate of marking fees shall come into force with effect from 1981-01-01 :

SCHEDULE

Sl. No.	Name of the Ministry	Reference to Govt. of India Gazette	Reference to Notification No.	Product	IS : No. & Title of the Specification	Unit	Marking fee per Unit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Ministry of Industrial Development	Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated 1972-12-09	S.O. 4057 dated 1972-11-23	BHC, technical and refined	IS : 560-1969 Specification for BHC, technical and refined. (second revision)	One Tonne	(i) Rs. 3.00 per unit for the first 200 units; (ii) Rs. 1.50 per unit for the 201st to 4000 units; and (iii) Rs. 1.00 per unit for the 4001st unit and above.
2.	-do-	-do-	-do-	DDT, technical	IS : 563—1973 Specification for DDT, technical. (second revision).	One Tonne	(i) Rs 3.00 per unit for the first 2000 units; and (ii) Rs. 1.00 per unit for the 2001st unit and above.
3.	Ministry of Industrial Development, Science and Technology	Part-II, Section-3, Sub-section (ii) dated 1974-10-05	S.O. 2581 dated 1974-09-23	Copper Oxy-chloride, technical.	IS : 1486—1969 Specification for Copper Oxychoride, technical. (first revision)	One Tonne	Rs. 7.00
4.	Ministry of Industry and Civil Supplies	Part-II, Section 3, Sub-section (ii) dated 1975-05-31	S.O. 1684 dated 1975-05-21	Phenyl mercury acetate, technical.	IS : 2126—1973 Specification for Phenyl mercury acetate technical. (first revision)	One kg.	30 Paise.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5.	Ministry of Industry and Civil Supplies (Deptt. of Industrial Development)	Part-II, Section-3, Sub-section (ii) dated 1976-07-10	S.O. 2471 dated 1976-06-21	Dichlorvos, technical.	IS : 4929-1978 Specification for Dichlorvos, technical (first revision)	One kg	(i) 10 Paise per unit for the first 500 units; and (ii) 5 Paise per unit for the 501st unit and above
6.	Ministry of Commerce and Civil Supplies (Deptt. of Civil Suppies')	Part-II, Section-3, Sub-section (ii) dated 1980-06-14	S.O. 16909 dated 1980-05-19	Carbaryl, technical	IS : 7539-1975 Specification for Carbaryl, technical.	100 kg	(i) Rs 10.00 per unit for the first 1000 units; (ii) Rs. 5.00 per unit for the 1001st to 2000 units; and (iii) Rs 2.00 per unit for the 2001st unit and above

[No. CMD/13 : 10]

नई दिल्ली, दिनांक 1982-08-13

का०आ० 3102.--समय समय पर संशोधित भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिन्ह) के विनियम 1955 के विनियम 4 के उपविनियम (1) के अनुसार भारतीय मानक संस्था की ओर से अधिसूचित किया जाता है कि जिस मानक की डिजाइन और उसके शाब्दिक विवरण तथा तत्संबंधी भारतीय मानक के शीर्षक सहित नीचे अनुसूची में दी गई है, वह भारतीय मानक संस्था द्वारा निर्धारित की गई है।

भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिन्ह) अधिनियम 1952 और उसके अधीन बने नियमों और विनियमों के निमित यह मानक चिन्ह 1982-04-01 से लागू होगी ।

अनुसूची

क्रम संख्या	मानक चिन्ह की डिजाइन	उत्पाद/उत्पादन की श्रेणी	तत्संबंधी भारतीय मानक की पदसंख्या और शीर्षक	मानक चिन्ह की डिजाइन का शाब्दिक विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.		विस्कॉस रेयन के कटे धागे (काते हुए)	IS : 3566-1966 विस्कॉस रेयन के कटे धागे (काते हुए) की विशिष्टि	भारतीय मानक संस्था का मोनोग्राम जिसमें। IS1 शब्द होते हैं, स्तम्भ (2) में दिखाई गई शैली और अनुपात में तैयार किया गया है और जैसा डिजाइन में दिखाया गया है उस मोनोग्राम के ऊपर की ओर भारतीय मानक की पदसंख्या और वर्ष अंकित किया गया है ।

[सं० सी एम डी/13 : 9]

New Delhi, the 1982-08-13

S.O. 3102.—In pursuance of sub-rule (1) of rule 4 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Rules, 1955 the Indian Standards Institution, hereby, notifies that the Standard Mark, design of which together with the verbal description of the design and the title of the relevant Indian Standard is given in the Schedule hereto annexed, has been specified.

This Standard Mark for the purpose of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Act, 1952 and the Rules and Regulations framed thereunder, shall come into force with effect from 1982-04-01 :

SCHEDULE

Sl. No.	Design of the Standard Mark	Product/Class of Product	No. and Title of the Relevant Indian Standard	Verbal description of the Design of the Standard Mark
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.		Viscose rayon cut staple spun (yarn)	IS : 3566-1966 Specification for viscose rayon cut staple spun (yarn)	The monogram of the Indian Standards Institution, consisting of letters 'ISI' drawn in the exact style and relative proportions as indicated in Col. (2) the number of the Indian Standard, alongwith its year, being superscribed on the top side of the monogram as indicated in the design.

[No. CMD/13 : 9]

का० आ० 3103.—भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिन्ह) विनियम 1955 के विनियम 7 के उपविनियम (3) के अनुसार भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विस्कॉस रेयन की प्रति इकाई मुहर लगाने की फीस अनुसूची में दिये गये ब्यौरे के अनुसार निर्धारित की गई है। यह फीस दिनांक 1982-04-01 से लागू होगी।

अनुसूची

क्रम संख्या	उत्पाद/उत्पाद की श्रेणी	तत्संबंधी भारतीय मानक की पदसंख्या और शीर्षक	इकाई	प्रति इकाई मुहर लगाने की फीस
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	विस्कॉस रेयन के कटे धागे (काते हुए)	IS : 3566-1966 विस्कॉस रेयन के कटे धागे (काते हुए) की विशिष्टि	100 कि०ग्रा०	(1) रु० 1.00 प्रति इकाई पहली 3000 इकाइयों के लिये, (2) 50 पैसे प्रति इकाई 3001वीं से 6000 तक की इकाइयों के लिये; और (3) 25 पैसे प्रति इकाई 6001वीं और ऊपर की इकाइयों के लिये

[सं० सी एम डी/13 : 10]

S.O. 3103.— In pursuance of sub-regulation (3) of regulation 7 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Regulations, 1955, the Indian Standards Institution, hereby, notifies that the marking fee per unit for viscose rayon cut staple spun (yarn) details of which are given in the Schedule hereto annexed, has been determined and the fee shall come into force with effect from 1982-04-01

SCHEDULE

Sl. No.	Product/Class of Product	No. and Title of Relevant Indian Standard	Unit	Marking Fee per Unit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Viscose rayon cut staple spun (yarn)	IS : 3566-1966 Specification for viscose rayon staple spun (yarn)	100 kg	(i) Re 1.00 per unit for the first 3000 units; (ii) 50 Paise per unit for the 3001st to 6000 units; and (iii) 25 Paise per unit for the 6001st unit and above.

[No. CMD/13 : 10]

का० आ० 3104.—समय-समय पर संशोधित भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिन्ह) विनियम 1955 के विनियम 8 के उपविनियम (1) के अनुसार भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि नीचे अनुसूची में जिन 84 लाइसेंसों के ब्यौरे दिये गये हैं। लाइसेंसधारियों को मानक संबंधी मुहर लगाने का अधिकार माह जनवरी 1980 से स्वीकृत किया गया है।

अनुसूची

क्रम संख्या	सी एम/एल	वैधता की अवधि		लाइसेंसधारी का नाम और पता	लाइसेंस के अधीन वस्तु प्रक्रिया और तत्संबंधी IS : पदनाम
		से	तक		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	सी एम/एल-8281 1980-01-02	80-01-16	81-01-15	विश्व इंजीनियरिंग वर्कर्स, 62-ए हाजरा रोड, कलकत्ता-700019 (प० बंगाल)	निम्नलिखित प्रकार के ऊर्ध्व एक सिलिंडर चार स्ट्रोक वाले जलशीत डीजल इंजन आउटपुट चक्कर प्रति लागू मिनट 3.73 (5 हार्पा) 1500 वर्ग बी एस एफ सी 265 किया प्रति घंटा IS : 160 1-1960
2.	सी एम /एल-8282 1981-01-02	80-01-01	80-12-31	स्टेंडर्ड सिलिंडर्स प्रा० लि०, 15 एच एस आई डी सी इंडस्ट्रीयल एस्टेट, पालम गुड़गांव रोड, गुड़गांव-122006 (हरियाणा)	अल्प दाब द्रवणीय गैसों के लिये 33.3 लिटर पानी की समाई वाले वेल्डकृत अल्प कार्बन इस्पात के गैस सिलिंडर— IS : 3196—1974
3.	सी एम/एल-8283 1980-02-04	80-01-16	81-01-15	लाल सज., बी-139, डीडीए शेड ओखला इंडस्ट्रियल एरिया फेज-I नई दिल्ली-110020	मार्केसिक साइजवाले 15 मिमी, 20 मिमी व 25 मिमी के उच्च दाब और अल्प दाब श्रेणियों के बाल वाल्व- IS : 1703-1977

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	सीएम/एल-8284 1980-01-04	80-01-16	81-01-15	लाल मन्ज व -139 डी डी ए रोड ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-I नई दिल्ली -110020	जल वितरण के लिए एंगिल स्टाप वाल्व व फैरूल, बिब टोटिया तथा स्टाप वाल्व (साइज केवल 15 मिमी) IS 8931 1978
5	सीएम/एल-8285 1980-01-04	80-01-16	81-01-15		जलवितरण के लिए साधेनिक साइज 15 मिमी और 20 मिमी के फैरूल — IS 2692-1978
6	सीएम/एल-8286 1981-01-04	80-01-16	81-01-15		जल वितरण प्रयोजन के लिए केवल 15 मिमी साइज की पिलर टोटिया — IS 1795-1974
7	सीएम/एल-8287 1981-10-05	80-01-16	81-01-15		15 मिमी से 25 मिमी साइज की बिबटोटिया व 15 मिमी से 50 मिमी साइज के स्टापवाल्व IS 781-1977
8	सीएम/एल-8288 1981-01-04	81-03-16	81-01-15		जल वितरण के लिए केवल 15 मिमी साइज के पैम्पी पिलर टोटिया-- IS 8934-1978
9	सीएम/एल-8289 1980-01-01	80-01-16	80-01-15	न्यूक्रैम प्लास्टिक्स लिमिटेड 54 इंडस्ट्रियल एरिया फरीदाबाद (हरियाणा)	प्लाईवुड के लिए थर्मो प्लास्टिक वर्ग के संश्लिष्ट रेजिन आसजक-- IS 848-1974
10	सीएम/एल-8290 1980-01-10	80-01-16	81-01-15	दी मैसूर इलैक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड तुमकुर रोड पोस्ट बाक्स न० 2231 बंगलौर-560022	निम्नलिखित के लिए ज्वालासह खोल (1) एम एफ एस सी वर्ग के स्टार्टर कन्ट्रोल पैनल (2) एम एफ डी सी वर्ग के ड्रम कन्ट्रोलर (3) एम एफ आर बी वर्ग, श्रेणी-I के प्रतिरोधिता बाक्स IS 2148-1968
11	सीएम/एल-8291 1980-01-10	80-01-16	81-01-15	पावर कैपेसीटर्स पोस्ट बाक्स न० 44 निकट रेलवे स्टेशन, शिमोगा-577201	2 और 3 के वी आर ए, 440 वोल्ट पावर तत्र के लिए शंट कैपेसिटर-- IS 2834-1964
12	सीएम/एल-8292 1980-01-10	79-02-01	80-11-30	गौरी पुर क० लिमिटेड गरीफा-743166 जिला 24 परगना प० बंगाल इनका कार्यालय 2, फेयरली प्लेस कलकत्ता-700001	ए-टिवल जूट बोरे IS 1943-1964
13	सीएम/एल-8293 1980-01-10	79-12-01	80-11-30	हैस्टिंग्ज मि०लि०, (जूट मिल विभाग) डाक रिशरा-712348 जिला हुगली (प० बंगाल) इनका कार्यालय 14 नेताजी सुभाष रोड कलकत्ता-700001	ए-टिवल जूट बोरे IS 1943-1964
14	सीएम/एल-8294 1981-01-10	80-01-16	80-01-15	गगन निटिंग मिल्ज, 9/7 कान्गू नगर मेन रोड तिरुपुर-638602 (तमिलनाडु)	निम्नलिखित प्रकार की सादी बुनी सूती बनियान टाइप गोल गले और गोल गले बाजू वाली साइज 75 सेमी से 100 सेमी गेज 24 IS 4964 (भाग II)-1975
15	सीएम/एल-8295 1980-01-10	79-12-01	80-11-30	एम्पायर जूट क० लि०, 15 बी० टी० रोड, डाकघर तालपुकुर-743187 जिला 24 परगना (प० बंगाल) इनका कार्यालय 8, ओल्ड कोर्ट हाउस स्ट्रीट कलकत्ता-700001 में है।	ए-टिवल्ल जूट बोरे IS 1943-1964
16	सीएम/एल-8296 1980-01-10	79-12-16	80-12-15	जनरल इंडस्ट्रियल सोसाइटी लिमिटेड, (गोस्वल पाडा जूट मिल यूनिट डाक, चन्द्र नगर, पोस्ट आफिस गोन्दलपाडा-712137 जिला हुगली (प० बंगाल) इनका कार्यालय 8 इंडिया एक्सचेंज प्लेस कलकत्ता-700001 में है।	ए-टिवल्ल पटसन बोरे IS 1943-1964
17	सीएम/एल-8297 1980-01-10	79-12-01	80-11-30	फोर्ट विलियम कं० लि०, (जूट मिल्ज विभाग 47/48 राजनारायण रायचौधुरी घाट रोड, शिवपुर-711102 हावड़ा (प० बंगाल) इनका आफिस 14 नेता जी सुभाष रोड, कलकत्ता-700001 में है।	ए-टिवल्ल पटसन बोरे IS 1943-1961
18	सीएम/एल-8298 1980-01-10	79-12-01	80-11-30	एम्पायर जूट क० लिमिटेड, 15 बी०टी० रोड डाक तालपुकुर-743187 जिला 24, परगना प० बंगाल इनका कार्यालय 8 ओल्ड कोर्ट हाउस स्ट्रीट कलकत्ता-700001 में है।	हैवी सी पटसन बोरे-- IS 2874-1964

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
19.	सीएम/एल-8299 1980-01-10	79-12-01	80-11-30	गौरीपुर कं० लि०, गरुफा-743166 जिला 24 परगना (प० बंगाल) इनका कार्यालय 2 फेयरलाई प्लेस कलकत्ता-700001 में है।	हैसियन का कपड़ा व हैसियन पटसन बोरे—IS : 3751-1964 व IS : 2374-1964
20	सीएम/एल-8300 1980-01-10	79-12-01	80-11-30	,,	मक्का भरने का पटसन का बोरिया और कपड़ा IS : 2875-1964 और IS : 3750-1966
21.	सीएम/एल-8301	80-01-16	81-01-15	मोदी स्टील मोदी नगर जिला मेरठ (यू०पी०)	कवचदार केबल के लिए मृदु इस्पात के तार— IS : 3975-1967
22.	सीएम/एल-8302 1980-01-11	80-01-16	81-01-15	ठाकुर इंडस्ट्रीज प्लाट 53/4, सातवीं गली, एम आई डी सी, अन्धेरी, बम्बई-400093	तांबे के चालकों वाले 1100 वोल्ट तक की कार्यकारी वोल्टता के लिए पी० वी० सी० रोधित (भारी काम वाले) बिजली के केबल— IS : 1554(भाग-I) 1976
23.	सीएम/एल-8303 1980-01-11	79-12-01	80-11-30	कैलेडोनियन जूट एंड इंडस्ट्रीज, 18 मेहता रोड, बड़े थाला नगर डाक बज-743319 इनका आफिस 9, ब्रेबोर्न रोड, कलकत्ता-700001 में है।	ए-टिवल्ल पटसन बोरे— IS : 1943-1964
24	सीएम/एल-8304 1980-01-11	80-01-16	81-01-15	सेवोक प्लाईवुड इंडस्ट्रीज प्रा० लि०, मालुमुरहा, मिला एर्डी डाक, एकतीसैल, जिला जलपाइगुड़ी (प बंगाल) इनका कार्यालय 1 स्कूल रोड, हाल्फ कलकत्ता में है।	चाय पेटी के लिए प्लाईवुड के तख्ते— IS : 10(भाग II)-1976
25	सीएम/एल-8305 1980-01-11	80-01-16	81-01-15	ठाकुर इंडस्ट्रीज, प्लाट 53/4, सातवीं गली एम आई डी सी मरोल इंडस्ट्रीज एरिया अंधेरी (पूर्व) बम्बई-400093	खोल रहित तांबे के चालकों के 1100 वोल्ट तक की कार्यकारी वोल्टता के लिए पी० वी० सी० रोधित केबल— IS : 694-1977
26.	सीएम/एल-8306 1980-01-11	80-01-16	81-01-15	प्लाई फर्निशिंग कं० XIII/888 जेट्टी रोड, अल्लेप्पी-688001 केरल	प्लाईवुड चाय पेटी के लिए पट्टिया— IS : 10(भाग III)-1974
27.	सीएम/एल-8307 1980-01-11	80-01-16	81-01-15	स्टैंडर्ड वायर्ज एंड केबल्ज, डी-110, इंडस्ट्रियल फोकल पाइंट, खन्ना (पंजाब)	1100 वोल्ट तक की कार्यकारी वोल्टता के लिए पी वी सी रोधित भारी काम के लिए केबल— IS : 1554(भाग I)-1976
28.	सीएम/एल-8308 1980-01-14	80-01-16	81-01-15	इंडियन रोलिंग मिल्ज, 79, फजलगंज, कानपुर	संरचना इस्पात (मानक किस्म) IS : 226-1975
29	सीएम/एल-8309 1980-01-17	80-01-16	81-01-15	समथिन लैबोरेट्रीज, प्लाट नं० 313-214, जवाहर को० ओ० इंडस्ट्रियल इस्टेट, पानवेल-410206 जिला कोलाबा (महाराष्ट्र)	डायमिथोएट पायसनीय सान्द्र (री-पैकिंग)— IS : 390-1975
30	सीएम/एल-8310 1980-01-15	80-01-16	81-01-15	विश्व इंजीनियरिंग वर्क्स 62-ए, हाजरा रोड, कलकत्ता-700019 (प० बंगाल)	कृषि प्रयोजन के लिए भू पृष्ठ वाले जल के क्षैतिज अपकेन्द्री पम्प, केवल निम्नलिखित विवरण वाले साइज 75×65 मिमी चक्कर प्रति मिनट 1500 वर्ग/माडल/V-2 ड्यूटी/पाइंट 12.2 मीटर हैड डिस्चार्ज 15.7 एल पी एस कार्यदक्षता 56 प्रतिशत पम्प इनपुट 3.4 किवा— IS : 6595-1972
31.	सीएम/एल-8311 1980-01-05	80-01-16	81-01-15	नंदा एंड कम्पनी (इंजीनियरिंग) प्रा० लि०, 3/1, बी महेन्द्रा रोड कलकत्ता-700025	निम्नविवरण वाले कोयले और पत्थर की ज्वाला सह्य खोल— फर्म का वर्ग 'नन्दा' माडल-ए ग्रुप-1— IS : 2148-1968
32	सीएम/एल-8312 1980-01-15	80-01-16	81-01-15	तिरुपुर टैक्सटाइल प्रा० लि०, (होजिरी डिवीजन) एसएफ नं० 324 आफ 15 गाव वेलम्पलयम अनुप्पलयम डाकघर तिरुपुर-638603 (तमिलनाडु)	निम्न प्रकार की सादी बुनी सूती बनियान फैब्रिक गेज 24 व 26— IS : 4964 (भाग 1)-1975
33	सीएम/एल-8313 1980-01-15	80-01-16	81-1-15	नवयुग इलेक्ट्रिक कार्पोरेशन प्लाट 3 व 4, जी आई डी सी फेज 1 ओढव अहमदाबाद-382445	वर्ग ई रोधन वाली, 2.2 किवा, 3.7 किवा, 5 किवा व 7.5 किवा की तीन फेज की प्रेरण मोटर— IS : 325-1978

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
34	सी.एम/एल-8314 1980-01-05	80-01-16	81-01-15	फाइन बैलेन्सिंग डेयरी (प्रादेशिक को० आ० डेयरी फेडरेशन लि०) की एक यूनिट गगोल रोड परतापुर मेरठ (उत्तर प्रदेश)	सेपरेटा दूध का पाउडर— IS : 1165-1975
35	सी.एम/एल 8315 1980-01-17	80-02-01	81-01-31	एम. हनपुठम प्रा० लि० कुमारपत्तनम डाक 581123 गांव कवालेरु रानी-बेनुर तालुक जिला धारवाड निकट हारिहर रेलवे स्टेशन कर्नाटक इनका कार्यालय 87 थर्ड मेन रोड एन. नारायणपेट, बंगलौर 560002 में है।	ऊर्ध्वाधर पारसन व मान्द्र IS 633-1975
36.	सी.एम/एल-8316 1980-01-17	80-02-01	80-01-31	सुपर पेन्ट्स व वार्निशज, जुदा रोड गिरिडीह-815301, बिहार	बहिरंग संश्लिष्ट इनैमल (1) निचली परत देने का (2) फिनिश देने का IS 2932-1974
37	सी.एम/एल 8317 1980-01-18	79-12-01	80-11-30	प्रवर्तक जूट मिल्ज, बैरकपुर ट्रंक रोड, कमरहट्टी-700058 जिला 24 परगना (प० बंगाल), इनका कार्यालय 5 सिनागोग स्ट्रीट कलकत्ता-700001 में है।	ए. ट्विल पटसन के बोरे IS 1943 1964
38	सी.एम/एल-8318 1980-01-18	80-02-01	81-01-31	बैसक पाईप्स प्रा० लि०, 5 मत्स्य इंडस्ट्रियल एरिया, अलवर (राजस्थान)	संरचनात्मक प्रयोजन के लिए इस्पात की निम्न प्रकार की काली नलियां ग्रेड—वाईएसटी 210 साइज 80 मिमी एन-बी तक वर्ग क्लास-हल्की— IS : 1161-1979
39	सी.एम/एल-8319 1980-01-18	80-02-01	81-01-31	नन्दी स्टील वर्क्स प्रा०लि०, 69/2, टुमकुर रोड यशवन्तपुर बंगलौर-560022 इनका कार्यालय 35, थथप्पा लेन बंगलौर-560002 में है।	कंक्रीट प्रबलन के लिए ठंडी मरोड़ी इस्पात की सरियां— सांकेतिक साइज केवल 20 मिमी व्यास वाली IS 1786-1966
40.	सी.एम/एल-8320 1980-01-08	80-02-01	81-01-31	जैन स्टील रोलिंग मिल्ज, रेलवे स्टेशन के सामने मलेरकोटला-148023 जिला संगरूर (पंजाब)	संरचना इस्पात (मानक किस्म) IS : 226-1975
41	सी.एम/एल-8321 1980-01-18	80-02-01	81-01-31	जैन स्टील रोलिंग मिल्ज रेलवे स्टेशन के सामने मलेरकोटला-148023 जिला संगरूर (पंजाब)	संरचना इस्पात (साधारण किस्म)— IS : 1977-1975
42	सी.एम/एल-8322 1980-01-18	80-02-01	81-01-31	प्रताप स्ट्रिप मिल्ज सं—12 बी, पनकी इंडस्ट्रियल इस्टेट कानपुर (यू०पी०)	संरचना इस्पात (मानक किस्म)— IS 226 1975
43	सी.एम/एल-8323 1980-01-18	80-02-01	81-01-31	,,	संरचना इस्पात (साधारण किस्म)— IS : 1977-1975
44.	सी.एम/एल-8324 1980-01-18	80-02-01	81-01-31	सवरमन डी 59-60 सेक्टर 1 नौएडा काम्पलेक्स जिला गाजियाबाद।	कवचित/अकवचित एलुमिनियम चालकों वाले 1100 वोल्ट तक की कार्यकारी वोल्टता के लिए पीवीसी रोधित (भारी काम वाले) बिजली के केबल— IS : 1554(भाग 1)-1976
45	सी.एम/एल-8325 1980-01-18	80-02-01	81-01-31	,,	खोलदार एलुमिनियम चालक वाले 1100 वोल्ट तक की कार्यकारी वोल्टता के लिए पीवीसी रोधित केबल्ज (अनुमह केबलों को छोड़कर)— IS 694-1977
46	सी.एम/एल-8326 1980-01-18	80-02-01	81-01-31	हैफेड पेस्टीसाइड्स (हरियाणा राज्य को०ऑ० सप्लाई व मार्केटिंग फेडरेशन की यूनिट) जी०टी० रोड, तरावड़ी, जिला करनाल (हरियाणा)	बी एच सी (एच सी एच) जल परिक्षेपी तेज पाउडर— IS : 562 1978

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
47	सी०एम/एल 8327 1980-01-18	80-02-01	81-01-31	मैटलमैन पाइप मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी प्रा०लि० 17/19 मुकलिया इंडस्ट्रियल एरिया देवास रोड इन्दौर – 452003 (मध्य प्रदेश)।	संरचनात्मक प्रयोजन के लिए इस्पात की निम्न प्रकार की काली नलियां विद्युत प्रतिरोध वेल्डिंग ग्रेड वाईएसटी 210 साइज 65 मिमी एनबी तक वर्ग ब्लाक -- IS 1161 1979
48	सी०एम/एल-8328 1980-01-22	80-02-01	81-01-31	यूनाईटेड कैमीकल इंडस्ट्रीज गांव दाह फैक्टरी एरिया डाकघर मडियाला जिला होशियारपुर पंजाब।	पैराफिन मोम टाइप-3 IS 4654 1974
49	सी०एम/एल-8329 1980-01-22	80-02-01	81-01-31	कामधेनु रेस्टामाईड्स 50-ए/51 हडपसर इंडस्ट्रियल इस्टेट पुणे-411013 (महाराष्ट्र) इनका कार्यालय कृषि भवन, भवानी पेठ, पुणे-411002 में है।	डाईक्लोरवास पायसनीय सान्द्र – IS 5277-1978
50	सी०एम/एल-8330 1980-01-22	80-02-01	81-01-31	देवादयाल सेल्स प्रा० लि० 50 ए जी आई डी सी इस्टेट कलोल 389330 जिला पंचमहल गुजरात	डाइक्लोफाल पायसनीय सान्द्र-- IS 5279-1969
51	सी०एम/एल-8331 1980-01-23	80-02-01	81-01-31	यू०पी० मेटल इंडस्ट्रीज लि० सण्डीला इंडस्ट्रियल इस्टेट सण्डीला-241204 जिला हरदोई (यू०पी०)	संरचनात्मक प्रयोजन के लिए निम्न प्रकार की इस्पात की नलियां--नाममात्र छेद साइज 15 मिमी से 65 मिमी (हल्की) ग्रेड वाईएसटी 210 IS 1161-1979
52	सी०एम/एल-8332 1980-01-23	79-12-01	80-11-30	इंडिया जूट कं० लि० डाकघर श्रीरामपुर-712201 जिला हुगली (प० बंगाल) इनका कार्यालय 16 स्ट्रैंड रोड कलकत्ता 700001 में है।	ए टविल पटसन के बोरे-- IS 1943 1964
53	सी०एम/एल 8333 1980-01-23	79-12-01	80-11-30		हैसी या बोरे के थैलों या कपड़ा-- IS 2874 1964 व IS 3751-1966
54	सी०एम/एल-8334 1980-01-23	79-12-01	80-11-30		सैकिंग पटसन के बोरियां और कपड़ा IS 2875 1964 व IS 3750-1966
55	सी०एम/एल-8335 1980-01-23	80-02-01	81-01-31	ओरियन्ट केबल इंडस्ट्रीज गांव व डाक खामपुर मकान रोड दिल्ली।	कवचित/अकवचित एलुमिनियम चालकों वाले 1100 वोल्ट तक के कार्यकारी वोल्टता के लिए पी वी सी रोधित (भारी काम वाले) बिजली के केबल IS 1551 (भाग 1)-1976
56	सीएम/एल-8336 1980-01-23	80-02-01	81-01-31	गौतम केबल इंडस्ट्रीज डब्ल्यू जैड-34/13ए मुखराम एक्सटेंशन चौखंडी रोड तिलक रोड नई दिल्ली।	कवचदार/कवचरहित चालक वाले 1100 वोल्ट तक की कार्यकारी वोल्टता के लिए पी वी सी रोधित (भारी काम वाले) बिजली के केबल-- IS 1554(भाग 1) 1976
57	सीएम/एल-8337 1980-01-23	80-02-01	81-01-31	गौतम केबल इंडस्ट्रीज डब्ल्यू जैड 34/13ए मुखराम एक्सटेंशन चौखंडी रोड तिलक रोड नई दिल्ली।	कवचदार एलुमिनियम चालक वाले 1100 वोल्ट तक की कार्यकारी वोल्टता के लिए पीवीसी रोधित केबल्स (अनुग्रह केबलों को छोड़कर) – IS 694-1977

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
58	सीएम/एल-8338 1980-01-23	80-02-01	81-01-31	ब आर ए ज एड प्लास्टिक इंडस्ट्रीज ए-1/3-2 शेड नं० 5, बतवा इंडस्ट्रियल इस्टेट बतवा, जिला अहमदाबाद।	आवरणहित तांबे के चालकों वाले 1100 वोल्ट तक की कार्यकारी वोल्टता के लिए पी.वी.सी. रोधित केबल- IS 694 1977
59	सीएम/एल 8339 1980-01-33	80-02-01	81-01-31	स्पेशल केबल इंडस्ट्रीज ए-आई-404 जी आई डी सी इस्टेट निकट जी आई डी सी पानी की टंकी अंकलेश्वर (गुजरात)	आवरण रहित तांबे के चालकों वाले 1100 वोल्ट तक की कार्यकारी वोल्टता के लिए पी वी सी रोधित केबल IS 694 1977
60	सीएम/एल 8340 1980 01-25	80-02-01	81-01-31	नेशनल इंडस्ट्रियल वर्क्स, बलियाताड़, जिला बांकुरा (प० बंगाल)	संरचनात्मक इस्पात (मानक किस्म)-- IS 226 1975
61	सीएम/एल 8341 1980-01-25	80-02-01	81 01-31	वाल्गा इंजीनियरिंग कं०, प्रा० लि०, 75 सी पार्क स्ट्रीट, छठी मंजिल, ब्लाक ई कलकत्ता 700016	निम्न प्रकार के लिए ज्वाला सह आवरण- इ ऑयल स्टार्टर टाइप एफ 1, लाइटिंग ट्रांसफार्मर, टाइप एलटीएफ 1, ड्रिल नियंत्रण पैनल टाइप डीपीएफ-1 मिनी सर्किट ब्रेकर टाइप एमसीबीएफ-1 समूह-1 IS 2148-1968
62	सीएम/एल-8342 1980-01-25	80-02-01	81-01-31	पंजाब आयरन एंड स्टील कं० प्रा० लि०, जी टी रोड, जलंधर छावनी 144021	पुनर्बेल्लन से संरचनात्मक इस्पात (मानक किस्म) बनाने के लिए कार्बन इस्पात के ढले हुए बिलेट इंगट-- IS 6914--1978
63	सीएम/एल-8343 1980-01-25	80-02-01	81-01-31	"	पुनर्बेल्लन से संरचनात्मक इस्पात (सामान्य किस्म) बनाने के लिए कार्बन इस्पात के ढले हुए बिलेट इंगट--- IS 6915--1978
64	सीएम/एल--8344 1980-01-28	80-01-01	80-12-31	नौर्थ ब्रुक जूट कं० लि०, चांपदानी पोस्ट आफिस बैद्यबाटी-712222 जिला हुगली (प० बंगाल) इसका कार्यालय 6 लायंस रेंज कलकत्ता में है।	ए टि विल पटसन बोरे IS 1943-1964
65	सीएम/एल--8345 1980-01-28	80-01-01	80-12-31	"	हैवी सी बोरे और हैवी सी कपड़ा IS 1874--1964 व IS 3751--1966
66	सीएम/एल--8346 1980-01-28	80-01-01	80-12-31	"	हैवी सी बार व हैवी सी कपड़ा IS 871-1964 IS 3757--1966
67	सीएम/एल--8347 1980-01-28	80-01-01	80-12-31	"	सक्कर भरने के पटसन की बोरियां और कपड़ा IS 3794--1966 IS 3665--1966
68	सीएम/एल--8348 1980-01-28	80-02-01	81-01-31	शारदा कम्पनी लि० डाक घर टीटागढ़ जिला 24 परगना प० बंगाल इसका कार्यालय 7 वेलेस्ली प्लेस (पुराना नाम 7 बैंकशाल प्लेस) कलकत्ता-700001 में है।	ए ट्विल्ड पटसन बोरे IS 1943--1964
69	सीएम/एल--8349 1980-01-18	80-02-11	81-02-15	स्पेशल केबल्स इंडस्ट्रीज ए-वाई 504 जी आई डी सी इस्टेट जी आई डी सी वाटर टैंक के नजदीक अंकलेश्वर (गुजरात)	तांबे के चालक वाले 1100 वोल्ट तक की कार्यकारी वोल्टता के लिए पी वी सी रोधित (भारी काम वाले) बिजली के केबल--- IS 1554 (भाग 1)---1976
70	सीएम/एल-8350 1980-01-31	80-02-01	81-01-31	मत्स्यराईज इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग प्लाट नं० 93, ए-वी साकीविहार इंजीनियरिंग इस्टेट कार्ड बिन बम्बई-400067	2 केवी एआर 415 वोल्ट पावर तक के लिए शंट कैपेसिटर--- IS 1834--1961
71	सीएम/एल--8351 1980-01-31	80-02-01	81-01-31	भारत आयरन एंड स्टील कम्पनी प्रा० लि० अवरा रोड धनबाद (बिहार)	मशीन प्रबलन के लिए ठंडी मरोड़ी इस्पात की छड़ें IS 1786--1966

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
72	सीएम/एल—8352 1980-01-31	80-02-01	81-01-31	मद्रास इंडिया केबल्स प्लाट 14 इंडस्ट्रियल एरिया (फेज I) जयपुर—181009	एलुमिनियम चालक वाले 1100 वोल्ट तक के ... वायरिंग के लिए पी वी सी रोधित केबल — IS 694—1977
73	सीएम/एल—8353 1980-01-31	80-02-01	81-01-31	देहली स्टील रोलिंग मिल्ज लोनी रोड रामनगर शाहदरा दिल्ली	कंक्रीट प्रबलन के लिए ठंडे मरोड़े इस्पात की सरिया (टोर सरिया) ग्रुप (II)— IS 1786—1966
74	सीएम/एल—8354 1980-01-31	80-02-01	81-01-31	पैरियार प्लाईवुड हाऊस मुड़िकल्ल पेरुम्बवूर जिला एर्णाकुलम केरल	चायपेटी के लिए प्लाईवुड के तख्ते — IS 10 (भाग II)—1976
75	सीएम/एल—8355 1980-01-31	80-02-01	81-01-31	भारत पम्प्स एण्ड कम्प्रेसर्स लि० नैनी इलाहाबाद 211010 यू०पी०	ड्राइंग संख्या पी०सी०/जी०सी०/डब्ल्यू०सी० /8-14/डी के अनुसार 68 लिटर क्षमता वाले एलपीजी के सिलेंडर— IS 3196—1974
76	सीएम/एल—8356 1980-01-31	80-02-01	81-01-31	कश्मीर स्टील प्रा० लि० सौरा श्री नगर 190011 (जम्मू एवं कश्मीर)	स्टेनलेस इस्पात की चादरें— IS 6911—1972
77	सीएम/एल—8357 1980-01-31	80-02-11	81-10 31	पायनट डाइना मार्डल मोड़ जलन्धर शहर	5 किलोवार 415 वोल्ट पावर सर्व के लिए शट कैपेसिटर— IS 2834—1964
78	सीएम/एल—8358 1980-01-31	80-02-16	81-02-81	अमरावती निटिंग मिल्ज 89-एफ (16बी) कामराज रोड, तिरुपुर 638604 (तमिलनाडु)	निम्न प्रकार की सादी बुनी सूती बनियान टाइप गोल गले की व गोल गले बाजू वाली साइज 75 सेमी से 100 सेमी माप 26— IS 4964 (भाग II)—1975
79	सीएम/एल—8359 1980-01-31	80-02-16	81-02-15	श्री लक्ष्मी टेक्सटाइल्ज 74 कुमारन रोड, तिरुपुर 638601 (तमिलनाडु) इनका कार्यालय 12 छिकासा चटियार स्ट्रीट तिरुपुर में है।	निम्न प्रकार की सादी बुनी सूती बनियान टाइप गोल गले व गोल गले बाजू वाली साइज 75 सेमी से 100 सेमी माप 26— माप 26— IS 4964 (भाग II)—1975
80	सीएम/एल—8360 1980-01-31	80-02-16	81 02-15	एक्सेल निटर्स 88 एफ (15) कामराज तिरुपुर—638604	निम्न प्रकार की सादी बुनी सूती बनियान टाइप गोल गले व गोल गले बाजू वाली साइज 75 सेमी से 100 सेमी माप 26— IS 4964 (भाग II)—1975
81	सीएम/एल—8361 1980-01-31	80-02-16	81-02-15	एजेंस एग्रोवेट इंडस्ट्रीज प्रा० लि० 98 एस एम इंडस्ट्रियल इस्टेट, बाला-नगर हैदराबाद 500037 (आंध्र प्रदेश)	कुक्कुट आहार का पूरक खनिज मिश्रण— IS 567—1970
82	सीएम/एल—8362 1980-01-31	80-02-16	81-02-15	ईस्ट इंडिया कमर्शियल क० प्रा० लि० पद्मावती श्री कृष्ण जूट मिल्ज एलुरु 534002 जिला वैस्ट गोदावरी (आंध्र प्रदेश)	बी ट्विल्स पटसन बोरे— IS 2565—1965
83	सीएम/एल—8363 1980-01-31	80-02-16	81-02-15	नार्थ पॉटर्स फार्मास्युटिकल कम्पनी 17-1 200 सैदाबाद हैदराबाद-500059 (आंध्र प्रदेश)	निम्न प्रकार के रोगाणुनाशक काल सरल पदार्थ — वर्ग ए टाइप नार्मल ग्रेड 2 व 3 IS 1061—1975
84	सीएम/एल—8364 1980-01-31	80-02-16	81-02-15	जयश्री टेक्सटाइल्स एण्ड इंडस्ट्रीज प्रो० (दि इंडियन रेयन कार्पोरेशन) रिसरा 712248 जिला हुगली (प० बंगाल)	क्लोदिंग कपड़ा — IS 7610 (भाग 4)—76

[म० सी एम डी/13 11]

S.O. 3104 In pursuance of sub-regulation (1) of Regulation 8 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Regulation, 1955, as amended from time to time, the Indian Standards Institution hereby notifies that eightyfour licences, particulars of which are given in the following Schedule, have been granted during the month of January 1980 authorising the licensees to use the Standard Marks.

SCHEDULE

Sl. No.	Licence No. (CM/L-)	Period of Validity From	To	Name and Address of the Licensee	Article/Process covered by the Licences and the Relevant IS : Designation
1	2	3	4	5	6
1.	CM/L-8281 1980-01-02	80-01-16	81-01-15	Viswa Engg Works, 62-A, Hazra Road, Calcutta-700019 (W.B.)	Vertical, single cylinder, four stroke water cooled, diesel engines of the following rating : Output : 3.73 kw (5 HP)— Speed : 1500 RPM governing class B SFC 265 g/kW/h IS : 1601—1960
2.	CM/L-8282 1980-01-02	80-01-01	80-12-31	Standard Cylinders Pvt. Ltd., 15 H.S. I.D.C. Indl. Estate, Palam Gurgaon Road, Gurgaon-122006 (Haryana)	Welded low carbon steel gas cylinders of 33.3 litres water capacity for low pressure liquefiable gases— IS : 3196—1974
3.	CM/L-8283 1980-01-04	80-01-16	81-01-15	Lalsons, B-139, DDA Shed, Okhla Indl. Area, Phase I, New Delhi-110020	Ball valves of nominal sizes 15 mm, 20 mm and 25 mm of high pressure and low pressure classes only— IS : 1703—1977
4.	CM/L-8284 1980-01-04	80-01-16	81-01-15	-do-	Fancy bib taps and stop valves for water services, 15 mm only and angle stop valve, size 15 mm only— IS : 8931—1978
5.	CM/L-8285 1980-01-04	80-01-16	81-01-15	-do-	Ferrules for water services of nominal sizes 15 mm and 20 mm only— IS : 2692—1978
6.	CM/L-8286 1980-01-04	80-01-16	81-01-15	-do-	Pillar taps for water supply purposes, size 15 mm only— IS : 1795—1974
7.	CM/L-8287 1980-01-04	80-01-16	81-01-15	-do-	Bib taps sizes 15 mm to 25 mm and stop valves sizes 15 mm to 50 mm— IS : 781—1977
8.	CM/L-8288 1980-01-04	80-01-16	81-01-15	-do-	Fancy pillar taps for water services size 15 mm only— IS : 8934—1978
9.	CM/L-8289 1980-01-07	80-01-16	81-01-15	Nuchem Plastics Ltd., 54, Industrial Area, Faridabad (Haryana)	Synthetic resin adhesive for plywood, Type—Aminoplastic— IS : 848—1974
10.	CM/L-8290 1980-01-10	80-01-16	81-01-15	The Mysore Electrical Industries Ltd., Tumkur Road, Post Box No. 2211, Bangalore-560022	Flameproof enclosure for : (i) Starter control panel Type MFSC; (ii) Drum controller Type MFDC; and (iii) Resistance box Type MFRB Group I— IS : 2148—1968
11.	CM/L-8291 1980-01-10	80-01-16	81-01-15	Power Capacitors, P.B. No. 44, Near City Railway Station, Shimoga-577201	Shunt capacitors for power system 2 and 3 KVAR, 440 V— IS : 2834—1964
12.	CM/L-8292 1980-01-10	79-12-01	80-11-30	Gurepore Co. Ltd., Garifa-743166, Distt. 24 Parganas (W.B.) (Off : 2 Fairlie Place Calcutta-700001)	A-twill jute bags IS : 1943—1964
13.	CM/L-8293 1980-01-10	79-12-01	80-11-30	Hestings Mill Ltd, (Jute Mills Division), P.O. Rishra-712248, Distt Hooghly (W.B) (Off : 14, Netaji Subhash Road, Calcutta-700001)	A-twill jute bags IS : 1943—1964
14.	CM/L-8294 1980-01-10	80-01-16	81-01-15	Gagan Knitting Mills, 9/7, Kongunagar, Main Road, Tirupur-638602 (T.N.)	Plain knitted cotton vests Type : RN & RNS Size : 75 to 100 cm Gauge : 24 IS : 4964 (Part II)—1975

1	2	3	4	5	6
15.	CM/L-8295 1980-01-10	79-12-01	80-11-30	Empire Jute Co. Ltd., 15, B T. Road, P.O. Talpukur-743187 Distt 24 Parganas (W.B.) (Off : 8, Old Court House Street Calcutta-700001)	A-twill jute bags— IS : 1943- 1964
16.	CM/L-8296 1980-01-10	79-12-16	80-12-15	General Industrial Society Ltd , (Unit : Gondalpara Jute Mills), Chandernagore, P.O. Gondalpara-712137 Distt. Hooghly (W.B) (Off : 85, India Exchange Place, Calcutta-700001)	A-twill jute bags— IS : 1943 - 1964
17.	CM/L-8297 1980-01-10	79-12-01	80-11-30	Fort William Co. Ltd., (Jute Mills Division), 47/48, Rajnarain Roychowdhury Ghat Road, Sibpur-711102 Howrah (W.B.) (Off : 14 Netaji Subhas Road, Calcutta-700001)	A-twill jute bags-- IS : 1943- -1964
18.	CM/L-8298 1980-01-10	79-12-01	80-11-30	Empire Jute Co. Ltd., 15, B.T. Road, P O. Talpukur-743187 Distt. 24 Parganas (W.B.) (Off · Old Court House Street, Calcutta-700001)	Heavy cee bags-- IS : 2874— 1964
19.	CM/L-8299 1980-01-10	79-12-01	80-11-30	Gourepore Co. Ltd., Garifa-743166 Distt. 24 Parganas (W.B.) (Off : 2, Fairlie Place, Calcutta-700001)	Heavy cee jute bags and heavy cee cloth - IS : 2874— 1964; and IS : 3751- -1966
20.	CM/L-8300 1980-01-10	79-12-01	80-11-30	-do-	Jute corn sack & cloth - IS : 2875—1964; and IS : 3750—1966
21.	CM/L-8301 1980-01-11	80-10-16	81-01-15	Modi Steels, Modi Nagar, Distt. Meerut (U.P.)	Mild Steel wires for armouring cables-- IS : 3975—1967
22.	CM/L-8302 1980-01-11	80-01-16	81-01-15	Thakur Industries, Plot No. 53/4, 7th Street, MIDC Andheri, Bombay-400093	PVC insulated (heavy duty) electric cables for working voltages up to and including 1100 volts (with copper conductors)— IS : 1554 (Part I)—1976
23.	CM/L-8303 1980-01-11	79-12-01	80-11-30	Caledonian Jute & Inds., 18, Mehta Road, Badekali Nagar, P.O. Budge-743319 Distt. 24 Parganas (W.B.) (Off : 9, Brabourne Road, Calcutta-700001)	A-twill jute bags— IS : 1943—1964
24.	CM/L-8304 1980-01-11	80-01-16	81-01-15	Sevoke Plywood Inds. Pvt. Ltd., Salugurah, Siliguri, P.O. Ektieshel, Distt. Jalpaiguri (W.B.) (Off : 1, School Road, Halpu, Calcutta).	Tea-chest plywood panels— IS : 10 (Part II)—1976
25.	CM/L-8305 1980-01-11	80-01-16	81-01-15	Thakur Industries, Plot No. 53/4, 7th Street, MIDC Marol Indl. Area, Andheri (East), Bombay-400093	PVC insulated unsheathed cables for working voltages upto and including 1100 volts— IS : 694—1977
26.	CM/L-8306 1980-01-11	80-01-16	81-01-15	Palai Turnishing Co., XVIII/888, Jetty Road, Alleppey-688001 (Kerala)	Tea-chest plywood batter— IS : 10 (Part III)—1974
27.	CM/L-8307 1980-01-11	80-01-16	81-01-15	Standard Wires & Cables, D-110, Indl. Focal Point, Khanna (Punjab)	PVC insulated (heavy duty) electric cables for working voltages upto and including 1100 volts— IS : 1554 (Part I) —1976
28.	CM/L-8308 1980-01-14	80-01-16	81-01-15	Indian Rolling Mills, 79, Fazalganj, Kanpur	Structural steel (standard quality)— IS : 226—1975
29.	CM/L-8309 1980-01-15	81-01-16	81-01-15	Samvin Laboratories, Plot No. 213-214, Jawahar Co-op. Indl. Estate, Panvel-410206, Distt. Kolaba (Maharashtra)	Dimethoate EC (Repacking)— IS : 3903—1975
30.	CM/L-8310 1980-01-15	80-01-16	81-01-15	Viswa Engg. Works, 62-A, Hazra Road Calcutta-700019 (W.B.)	Horizontal, centrifugal pumps for clear, cold, fresh water for agricultural purposes of the following sizes - Size : 75 x 65 mm; Speed : 1500 RPM; Type/Model : V-2; and Duty Point : Head 12.2 M, Discharge 15.7 lps, Efficiency 56% and Pump Input 3.4 kW— IS : 6595—1972

1	2	3	4	5	6
31.	CM/L-8311 1980-01-15	80-01-16	81-01-15	Chanda & Co. (Engg) Pvt. Ltd., 3/1-B, Mahendra Road, Calcutta-700025	Flameproof enclosures for coal/stone, drill (firm's type 'CHANDA', Model 'A', Group I)— IS : 2148—1968
32.	CM/L-8312 1980-01-15	80-01-16	81-01-15	Tirupur Textile Pvt. Ltd., Hosiery Division, SF No, 324 of 15, Velampalayam Village, Anupparpalayam, P.O. Tirupur-638603 (T.N.)	Plain knitted cotton vests, fabric, Gauge : 24 & 26— IS : 4964 (Part I)—1975
33.	CM/L-8313 1980-01-15	80-01-16	81-01-15	Navyug Electric Corpn., Plot No. 3 & 4, GIDC, Phase I, Vatva, Ahmedabad-382445	Three-phase induction motors, 2.2 kW, 3.7 kW, 5 kW and 7 5 kW with Class 'E' insulation— IS : 325—1978
34.	CM/L-8314 1980-01-15	80-01-16	81-01-15	Feeder Balancing Dairy, (A Unit of Pradeshik Co-op. Dairy Federation Ltd.), Gangol Road, Partapur, Meerut (U.P.)	Skimmed milk powder— IS : 1165—1975
35.	CM/L-8315 1980-01-17	80-02-01	81-01-31	Agro Inputs Pvt. Ltd., Kumarapattanam Post-581123 Kavalettu Village, Ranibennur Taluk, Distt. Dharwar, Near Haribar Rly. Station (Karnataka) (Off : 87, III Main Road, New Tharagupet, Bangalore-560002)	DDT emulsifiable concentrates— IS : 633—1975
36.	CM/L-8316 1980-01-17	80-02-01	81-01-31	Super Paints & Varnished, Jundi Road, Giridih-815301 (Bihar)	Enamel, synthetic, exterior : (a) undercoating; and (b) finishing— IS : 2932—1974
37.	CM/L-8317 1980-01-18	79-12-01	80-11-30	Prabartak Jute Mills, Barrackpore Trunk Road, Kamarhatti-700058, Distt. 24 Parganas (W.B.) (Off : 5, Synagogue Street, Calcutta-700001)	A-twill jute bags— IS : 1943—1964
38.	CM/L-8318 1980-01-18	80-02-01	81-01-31	Bansal Pipes Pvt. Ltd., 5, Matsya Indl. Area, Alwar (Rajasthan)	Steel tubes for structural purposes black, Grade : Yst 210, Size : upto and including 80 mm NB Class : Light— IS : 1161—1979
39.	CM/L-8319 1980-01-18	80-02-01	81-01-31	Nandi Steel Works Pvt. Ltd., 69/2, Tumkur Road, Yeswanthpur, Bangalore-560022 (Off : 35, Shawthappa Lane, Bangalore-560002)	Cold twisted deformed steel bars for concrete reinforcement Size : 20 mm (nominal) dia only— IS : 1786—1966
40.	CM/L-8320 1980-01-18	80-02-01	81-01-31	Jain Steel Rolling Mills, Opposite Railway Station, Mallerkotla, Distt. Sangrur-148023 (Pb)	Structural steel (standard quality) IS : 226—1975
41.	CM/L-8321 1980-01-18	80-02-01	81-01-31	-do-	Structural steel (ordinary quality)— IS : 1977—1975
42.	CM/L-8322 1980-01-18	80-02-01	81-01-31	Pradhan Strip Mills, C-12-B, Panki Indl. Estate, Kanpur (U.P.)	Structural steel (standard quality)— IS : 226—1975
43.	CM/L-8323 1980-01-18	80-02-01	81-01-31	-do-	Structural steel (ordinary quality)— IS : 1977—1975
44.	CM/L-8324 1980-01-18	80-02-01	81-01-31	Mother Son, D-59-60, Sector VI, NOIDA Complex, Distt. Ghaziabad	PVC insulated (heavy duty) electric cables for working voltages upto and including 1100 V, armoured/unarmoured aluminium conductors— IS : 1554 (Part I)—1976
45.	CM/L-8325 1980-01-18	80-02-01	81-01-31	-do-	PVC insulated cables for working voltages upto and including 1100 volts, sheathed, aluminium conductors (except weathe -proof cables)— IS : 694—1977

1	2	3	4	5	6
46.	CM/L-8326 1980-01-18	80-02-01	81-01-31	Hafed Pesticides (A Unit of Haryana State Co-op. Supply & Marketing Federation Ltd), G.T. Road, Taraori, Distt. Karnal (Haryana)	BHC (HCH) water dispersible powder concentrates— IS : 562—1978
47.	CM/L-8327 1980-01-18	80-02-01	81-01-31	Metalman Pipe Mfg. Co. Pvt. Ltd., 17/19, Sukalia Indl. Area, Sanwar Road, Indore-452003 (M.P.)	Steel tubes for structural purposes black, Type : 'ERW'; Grade : Yst 210; Size : upto and including 65 mm NB; and Class : 'Light' IS : 1161—1968
48.	CM/L-8328 1980-01-22	80-02-01	81-01-31	United Chemical Inds., Factory Area, Village Dhah, P.O. Mandialan, Distt. Hoshiarpur (Punjab)	Paraffin wax, Type 3— IS : 4654—1974
49.	CM/L-8329 1980-01-22	80-02-01	81-01-31	Kamdhenu Pesticides, 50-A/51, Hadapsar Indl. Estate, Pune-411013 (Maharashtra) (Off : Krishi Bhawan, 1379, Bhawani Peth, Pune-411002)	Dichlorvos emulsifiable concentrates— IS : 5277—1978
50.	CM/L-8330 1980-01-22	80-02-01	81-01-31	Devidayal (Sales) Pvt. Ltd., 50-A, GIDC Estate, Kalol-389330, Distt. Panchmahals (Gujarat)	Dicofol emulsifiable concentrates— IS : 5279—1969
1.	CM/L-8331 1980-01-23	80-02-01	81-01-31	U.P. Metal Inds. Ltd., Sandila Indl. Estate, Sandila-241204, Distt. Hardoi (U.P.)	Steel tubes for structural purposes, nominal bore size 15 mm to 65 mm only Grade Yst 210— IS : 1161—1968
52.	CM/L-8332 1980-01-23	79-12-01	80-11-30	India Jute Co. Ltd., P.O. Serampore-712201, Distt. Hooghly (W.B.) (Off : 16, Strand Road), Calcutta-700001	A-twill jute bags— IS : 1943—1964
53.	CM/L-8333 1980-01-23	79-12-01	80-11-30	-do-	Heavy cee bags and Heavy cee cloth— IS : 2874—1964; and IS : 3751—1966
54.	CM/L-8334 1980-01-23	79-12-01	80-11-30	-do-	Jute corn sacks and Jute corn sack cloth— IS : 2875—1964 and IS : 3750—1966
55.	CM/L-8335 1980-01-23	80-02-01	81-01-31	Orient Cable Inds., Village & P.O. Mundka, Rohtak Road, Delhi	PVC insulated (heavy duty) electric cables for working voltages upto and including 1100 volts armoured and unarmoured with aluminium and copper conductors— IS : 1554 (Part I)—1976
56.	CM/L-8336 1980-01-23	80-02-01	81-01-31	Gautam Cable Inds., W/Z-34/13-A, Mukhram Extn., Chokhandi Road, Tilak Road, New Delhi.	PVC insulated (heavy duty) electric cables for working voltages upto and including 1100 volts armoured and unarmoured with copper conductors— IS : 1554 (Part I)—1976
57.	CM/L-8337 1980-01-23	80-02-01	81-01-31	-do-	PVC insulated cables for working voltages upto and including 1100 volts sheathed with aluminium conductors only including weather-proof cables— IS : 694—1977
58.	CM/L-8338 1980-01-23	80-02-01	81-01-31	V. R. Cables & Plastics Industries, C-I-A, Shed No. 5, Vatva Indl. Estate, Vatva, Distt. Ahmedabad.	PVC insulated cables with copper conductors for working voltage upto and including 1100 volts— s IS : 694—1977
59.	CM/L-8339 1980-01-23	80-02-01	81-01-31	Special Cable Inds., A-I-404, GIDC Estate, Near GIDC Water Tank, Ankleshwar (Gujarat)	PVC insulated unsheathed cables with copper conductors for working voltages upto and including 1100 volts— IS : 694-1977

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
60.	CM/L-8340 1980-01-25	80-02-01	81-01-31	Netaj Industrial Works, Beliatore, Distt. Bankura (W. B.)	Structural steel (standard quality) IS : 226—1975
61.	CM/L-8341 1980-01-25	80-02-01	81-01-31	Volga Engg. Co. Pvt. Ltd., 75-C, Park Street 6th Floor, Blok 'E', Calcutt - 700016	Flame proof enclosures for D. O.L. starter type SF-I, lighting transformer type LTF-I, drill control panel type DPF-I, Minicircuit breaker type MCBF-I, Group-I IS : 2148—1968
62.	CM/L-8342 1980-01-25	80-02-01	81-01-31	Punjab Iron & Steel Co. Pvt. Ltd. G. T. Road, Jullundur Cantt-144024	Carbon steel cast billet ingots for re-rolling into structural steel (standard quality)- IS : 6914—1978
63.	CM/L-8343 1980-01-25	80-02-01	81-01-31	-do-	Carbon steel cast billet for rolling into structural steel (ordinary quality)- IS : 6915-1978
64.	CM/L-8344 1980-01-28	80-01-01	80-12-31	North Brook Jute Co. Ltd., Champdany, P. O. Baidyabati-712222, Distt. Hooghly (W. B.) (Off : 6, Church Lane, Calcutta)	A-twill jute bags- IS : 1943—1964
65.	CM/L-8345 1980-01-28	80-01-01	80-12-31	North Brook Jute Co. Ltd., Champdany, P. O. Baidyabati-712222, Distt. Hooghly (W. B.) (Off : 6, Church Lane, Calcutta)	Heavy cee bags and Heavy cee cloth— IS : 2874—1964; and IS : 3751—1966
66.	CM/L-8346 1980-01-28	80-01-01	80-12-31	-do-	Jute corn sacks; and Jute corn sack cloth— IS : 2875—1964; and IS : 3750—1966
67.	CM/L-8347 1980-01-28	80-01-01	80-12-31	-do-	L-twill bags and L-twill cloth— IS : 3794—1966; and IS : 3668—1966
68.	CM/L-8348 1980-01-28	80-02-01	81-01-31	Khardah Co. Ltd., P. O. Titagarh-743188, Distt. 24-Parganas (W. B.) (Off : 7 Red Cross Place, Formerly 7, Wellesley Place, Calcutta-700001)	A-twil jute bags— IS : 1943—1964
69.	CM/L-8349 1980-01-28	80-02-16	81-02-15	Special Cables Inds., A-I-404 GIDC Estate, Near GIDC Water Tank, Ankleshwar (Gujarat)	PVC insulated (heavy duty) electric cables with copper conductors for working voltages upto and including 1100 volts— IS : 1554 (Part I)— 1976
70.	CM/L-8350 1980-01-31	80-02-01	81-01-31	Sunrise Electric Corpn., Plot No. 92, A-B, Kandivli Indl. Estate, Kandivli, Bombay-400067	Shunt capacitors for power systems 2 KVAR, 415 Volts— IS : 2834—1964
71.	CM/L-8351 1980-01-31	80-02-01	81-01-31	Narang Iron & Steel Co. Pvt. Ltd., Barwa Road, Dhanbad (Bihar)	Cold twisted deformed steel bars concrete reinforcement— IS : 1786—1966
72.	CM/L-8352 1980-01-31	0-02-01	81-01-31	Central India Cables, S-14, Indl. Area, Richhai, Jabalpur-482009	PVC insulated cables with aluminium conductors for working voltages upto and including 1100 volts— IS : 694—1977
73.	CM/L-8353 1980-01-31	80-02-01	81-01-31	Delhi Steel Rolling Mills, Loni Road, Ram Nagar, Shahdara, Delhi	Cold twisted deformed steel bars (tor steel bars) for concrete reinforcement (Group II)— IS : 1786—1966
74.	CM/L-8354 1980-01-31	80-02-01	81-01-31	Periyar Plywoods, Mudickal P. O. Perumbavoor, Ernakulam Distt. Kerala (Kerala)	Tea-chest plywood panels— IS : 10 (Part II)— 1976
75	CM/L-8355 1980-01-31	80-02-01	81-01-31	Bharat Pumps & Compressors Ltd., Nain, Allahabad-211010 (U. P)	68 Litres capacity LPG cylinders a per drawing No. BPC/GC/WC-87 14/D— IS : 3196-1974
76.	CM/L-8356 1980-01-31	80-02-01	81-01-31	Kashmir Steel Pvt. Ltd., Soura, Srinagar-190011 (J & K)	Stainless steel sheets— IS : 6911— 1972
77.	CM/L-8357 1980-01-31	80-02-01	81-01-31	Pilot India, Sodal Chowk, Jullundur City.	Shunt capacitors for power system 5 KVAR, 415 Volts— IS : 2834— 1964

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
78.	CM/L-8358 1980-01-31	80-02-16	81-02-15	Amaravati Knitting Mills 88-F (16-B) Kamraj Road, Tirupur-638604 (T. N.)	Plain knitted cotton vests Type : RN& RNS; Size : 75 to 100 cms; and Gauge 26 IS : 4964 (Part II)—1975
79.	CM/L-8359 1980-01-31	80-02-16	81-02-15	Selakshmi Textiles, 74 Kumaran Road, Tirupur-638604 (T. N.) (Off : 12, Chickkanna Chettier Street, Tirupur-638604)	Plain knitted cotton vests Type : RN & RN/7S; Size : 75 to 100 cms; and Gauge : 26— IS : 4964 (Part II)—1975
80.	CM/L-8360 1980-01-31	80-02-16	81-02-15	Exlan Knitters, 88F (15) Kamraj Road, Tirupur-638604 (T. N.)	Plain knitted cotton vests Type : RN & RNS; Size 75 to 100 cms; and Gauge : 24— IS 4964 (Part II)—1975
81.	CM/L-8361 1980-01-31	80-02-16	81-02-15	Aries Agro-Vet Industries Pvt. Ltd., 98, Co-op. Indl. Estate, Balanagar, Hyderabad-500037 (Andhra Pradesh.)	Mineral mixtures for supplementing poultry feeds— IS : 5672—1970
82.	CM/L-8362 1980-01-31	80-02-16	81-02-15	East India Commercial Co.; Pvt. Ltd., Lessee : Sri Krishna Jute Mills, Eluru-534002, West Godavari Distt. (A. P.)	B-twill jute bags— IS : 2566—1965
83.	CM/L-8363 1980-01-31	81-02-16	81-02-15	Nath Peters Pharmaceutical Co., 17-1-200, Saidabad, Hyderabad-500659 (A. P.)	Disinfectant fluids, black, Class : A Type : Normal Grade : 2 and 3 IS : 1061—1975
84.	CM/L-8364 1980-01-31	80-02-16	81-02-15	Jayashree Textiles & Inds. (Prop : The Indian Rayon Corpn. Ltd.) Rishra-712248, Distt Hooghly (W. B.)	Printing cloth— IS : 7610 (Part IV)—1976

[No. CMD/13 : 11]

नई दिल्ली, 1982-08-17

का०आ० 3105.—भारत के राजपत्र भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) दिनांक 1970-04-14 और 1971-08-14 में प्रकाशित तत्कालीन औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा कम्पनी मामलों का मंत्रालय (औद्योगिक विभाग) और औद्योगिक विकास मंत्रालय (भारतीय मानक संस्था) अधिसूचना [सं० एसओ 1232 दिनांक 1970-03-12 और एसओ 3022 दिनांक 1971-07-14 का अतिक्रमण करते हुए भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि सामान्य कार्यों के लिए अधःस्वक सूईयों की नामक चिह्न में कुछ संशोधन किया गया है। मानक चिह्न की यह संशोधित डिजाइन तत्सम्बन्धी भारतीय मानकों के शीर्षक और डिजाइन का शाब्दिक विवरण सहित नीचे अनुसूची में दिए गए हैं।

भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) अधिनियम 1952 तथा उसे अधीन बने नियमों और विनियमों के कार्यों के लिए यह मानक चिह्न 1982-02-16 से लागू होगा।

अनुसूची

क्र०सं०	मानक चिह्न की डिजाइन	उत्पाद/उत्पाद की श्रेणी	तत्संबंधी भारतीय मानक की सं० और शीर्षक	मानक चिह्न के डिजाइन का शाब्दिक विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	IS:3236-80 ISI	सामान्य कार्यों के लिए अधःस्वक सूइयां	IS : 3236—1980 सामान्य कार्यों के लिए अधोस्वक सूइयों की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	भारतीय मानक संस्था का मोनोग्राम जिसमें 'ISI' शब्द होते हैं, स्तम्भ (2) में दिखाई गई शैली और अनुपात में तैयार किया गया है और जैसा डिजाइन में दिखाया गया है मोनोग्राम के बाईं ओर और भारतीय मानक की पद संख्या और दाईं ओर वर्ष अंकित किया गया है।
	IS:3236-80 ISI			

[सी एम डी/13:9]

New Delhi, 1982-08-17

S O 3105 —In supersession of the then Ministry of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Deptt of Industrial Development) and Ministry of Industrial Development (Indian Standards Institution) notifications numbers S O 1 '2 dated 1970 03 12 and S O 3022 dated 1971-07-19 published in the Gazette of India, Part-II, Section, 3, Sub-section (ii) dated 1970-04 04 and 1971-08-14 respectively, the Indian Standards Institution, hereby, notifies that the Standard Marks for hypodermic syringes for general purposes have been revised The revised designs of the Standard Marks together with the title of the relevant Indian Standard and verbal description of the designs are given in the following Schedule

These Standard Marks, for the purpose of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Act 1952, and the Rules and Regulations framed thereunder shall come into force with effect from 1982-02-16

SCHEDULE

Sl No	Design of the Standard Mark	Product/Class of Product	No. and Title of the Relevant Indian Standard	Verbal Description of the Design of the Standard Marks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	IS 3236 80 IS 3236 80	Hypodermic syringes for general purposes	IS 3236-1980 Specification for hypodermic syringes for general purposes (**first revision**)	The monograms of the Indian Standards Institution consisting of letters 'ISI' drawn in the exact style and relative proportions as indicated in Col (2), the number of the Indian Standard being superscribed on the left hand and right hand sides alongwith its year, of the monograms as indicated in the designs

[No CMD/13 9]

का०आ० 3109—भारत के राजपत्र भाग II, खड 3, उपखड (ii) दिनाक 1977-03-17 मे प्रकाशित तत्कालीन वाणिज्य एव उद्योग मत्रालय (भारतीय मानक सस्था) अधिसूचना सख्या एसओ 748 दिनाक 1962-03-05 का अतिक्रमण करते हुए भारतीय मानक सस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि बेकर द्वारा प्रयुक्त खमीरे की मानक चिह्न मे कुछ सशोधन किया गया है। मानक चिह्न की सशोधित डिजाइन तत्सबधी भारतीय मानक का शीर्षक और डिजाइन के शाब्दिक विवरण सहित नीचे अनुसूची म दी गई है।

भारतीय मानक सस्था (प्रमाणन चिह्न) अधिनियम, 1952 तथा उसके अधीन बने नियम और विनियम के कार्यो के लिए यह मानक चिह्न 1982-01-01 से लागू होगा

अनुसूची

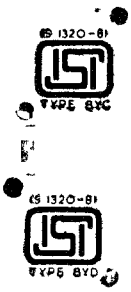

क्र०स०	मानक चिह्न की डिजाइन	उत्पाद/उत्पाद की श्रेणी	तत्सबधी भारतीय मानक की स० और शीर्षक	मानक चिह्न के डिजाइन का शाब्दिक विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Type bye IS 1320-81 TYPE BYC IS 1320-81 TYPE BYD	बेकरो द्वारा प्रयुक्त खमीरा	IS 1320-1981 बेकरो द्वारा प्रयुक्त खमीरे की विशिष्टि (दूसरा पुनरीक्षण)	भारतीय मानक सस्था का मोनोग्राम जिसमे ISI शब्द होते है स्तम्भ (2) म दिखाई गई शैली और अनुपात म तैयार किया गया है और जैसा डिजाइन म दिखाया गया है मोनोग्राम के ऊपर की ओर भारतीय मानक की पदसख्या तथा वर्ष दिए गए है और मोनोग्राम के नीचे की ओर तत्सबधी टाइप का पदनाम अकित किया गया है।

[सीएमडी/13 9]

S.O 3106 —In supersession of the then Ministry of Commerce and Industry (Indian Standards Institution) notification number S O 748 dated 1962-03-05, published in the Gazette of India, Part-II, Section-3, Sub-section (ii) dated 1973 03-17, the Indian Standards Institution, hereby, notifies that the Standard Mark of baker's yeast have been revised The revised designs of the standards Marks together with the title of the relevant Indian Standard and verbal description of the designs are given in the following Schedule

These Standard Marks for the purpose of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Act, 1952 and the Rules and Regulations framed thereunder, shall come into force with effect from 1982-01-01

SCHEDULE

Sl. No.	Design of the Standard Mark	Product/Class of Product	No. & Title of the Relevant Indian Standards	Verbal Description of the Design of the Standard Mark
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.		Baker's yeast	IS : 1320-1981 Specification for baker's yeast (*second revision*)	The monograms of the Indian Standards Institution, consisting of letters 'ISI', drawn in the exact style and relative proportions as indicated in Col. (2), the number of the Indian Standard, alongwith its years, being superscribed on the top sides and the relevant types designations being subscribed under the bottom sides of the monograms as indicated in the designs.

[No. CMD/13 : 9]

का॰आ॰ 3107.—समय समय पर संशोधित भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) विनियम 1955 के विनियम 8 के उपविनियम (1) के अनुसार भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि जिन 279 लाईसेंसों के ब्यौरे नीचे अनुसूची में दिए गए हैं, उनका दिसम्बर 1981 में नवीकरण किया गया है।

अनुसूची

क्रम संख्या	सी.एम/एल संख्या	वैध से	वैध तक	भारतीय मानक विशिष्टि की पद संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	0003612	81-11-16	82-11-15	IS : 398 (भाग 1 और 2)—1976
2.	0003713	81-11-16	82-11-15	IS : 434 (भाग 1 और 2)—1964
3.	0018827	81-11-16	82-11-15	IS : 1184—1977
4.	0036122	81-12-16	82-12-15	IS : 916—1975
5.	0036930	82-01-01	82-12-31	IS : 916—1975
6.	0038934	81-11-16	82-11-15	IS : 684—1977
7.	0059841	81-12-01	82-11-30	IS : 694—1977
8.	0061626	81-10-16	82-10-15	IS : 398 (भाग 1 और 2)—1976
9.	0065432	81-03-01	82-02-28	IS : 561—1978
10.	0069642	81-11-16	82-11-15	IS : 1554 (भाग 1)—1976
11.	0083939	81-12-01	82-11-30	IS : 1221—1971
12.	0097748	81-12-01	82-11-30	IS : 220—1972
13.	0109426	81-12-16	82-12-15	IS : 226—1975
14.	0120919	81-12-01	82-11-30	IS : 398 (भाग 2)—1976
15.	0121921	82-01-01	82-12-31	IS : 814 (भाग 1और 2)—1974
16.	0143224	81-11-16	82-11-15	IS : 1596—1977
17.	0143628	81-11-01	82-10-31	IS : 7452—1974
18.	0154532	81-11-16	82-11-15	IS : 325—1978
19.	0169848	81-11-16	82-11-15	IS : 226—1975
20.	0169949	81-11-16	82-11-15	IS : 1977—1975
21.	0170328	81-11-16	82-11-15	IS : 2037—1962
22.	0170732	81-11-16	82-11-15	IS : 398 (भाग 1 और 2)—1976
23.	0171532	81-12-16	82-12-15	IS : 226—1975
24.	0171633	81-12-16	82-12-15	IS : 1977—1975
25.	0173435	81-11-01	82-10-31	IS : 417 (भाग 1,2 और 3)—1974
26.	0188246	82-01-01	82-12-30	IS : 3196—1974
27.	0215526	81-10-16	82-10-15	IS : 10 (भाग 3)—1974
28.	0225428	81-11-01	82-10-31	IS : 1989 (भाग 1)—1978
29.	0231322	81-11-01	82-10-31	IS : 3686—1966
30.	0243632	81-11-16	82-11-15	IS : 2593—1964
31.	0245636	81-11-16	82-11-15	IS : 1165—1975
32.	0269044	81-11-16	82-11-15	IS : 325—1978
33.	0273843	81-12-01	82-11-30	IS : 1554 (भाग 1)—1976
34.	0274643	81-12-16	82-12-15	IS : 2548—1967
35.	0281034	81-11-16	82-11-15	IS : 780—1969
36.	0283846	81-12-16	82-12-15	IS : 1786—1966
37.	0286044	82-01-01	82-12-31	IS : 398 (भाग 1)—1976
38.	0303927	81-10-16	82-10-15	IS : 398 (भाग 1 और 2)—1976
39.	0310520	81-12-16	82-12-15	IS : 1011—1968
40.	0312625	81-12-01	82-11-30	IS : 2082—1978
41.	0319336	81-11-01	82-10-31	IS : 398 (भाग 1और 2)—1976
42.	0320725	81-12-16	82-12-15	IS : 694—1977
43.	0324430	81-12-16	82-12-15	IS : 10 (भाग 2)—1976

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
44.	0328438	82-01-01	82-12-31	IS : 694—1977
45.	0328539	82-10-01	82-12-31	IS : 1554 (भाग 1) —1976
46.	0340226	81-11-01	82-10-31	IS : 398 (भाग 1 और 2)— 1976
47.	0336140	81-12-16	82-12-15	IS : 1786 —1979
48.	0358851	81-11-16	82-11-15	IS : 6438— 1980
49	0359045	81-11-16	82-11-15	IS : 5423 —1978
50.	0359651	81-12-01	82-11-30	IS : 1726 (भाग 2,4,5 6 खण्ड 2 —1974)
51.	0360030	81-11-16	82-11-15	IS : 564 —1975
52.	0360535	81-12-01	82-11-30	IS : 1872- —1975
53.	0360939	81-12-01	82-11-30	IS : 5455—1969
54.	0382141	81-11-01	82-10-31	IS : 3975 —1975
55	0384852	81-12-16	82-12-15	IS : 1554 (भाग 1)—1976
56.	0387252	81-08-16	82-08-15	IS : 10 (भाग 4)—1976
57.	0401927	81-11-01	82-10-31	IS : 398 (भाग 2)—1976
58.	0403224	81-12-01	82-11-30	IS : 2548—1967
59.	0405733	81-11-16	82-11-15	IS : 633—1975
60.	0406129	81-12-01	82-11-30	IS : 398 (भाग 1 और 2 —1976)
61.	0408032	81-12-01	82-11-30	IS : 335 —1972
62.	0410827	82-01-01	82-12-31	IS : 4246—1978
63.	0437544	81-11-16	82-11-15	IS : 2567—1978
64.	0458350	81-12-01	82-11-30	IS : 419—1967
65.	0461036	81-12-01	82-11-30	IS : 10 (भाग 4)—1976
66.	0469658	81-11-16	82-11-15	IS : 1848—1971
67.	0471544	81-10-01	82-09-30	IS : 1848—1971
68.	0472950	81-10-16	82-10-15	IS : 1165—1975
69.	0473043	81-11-16	82-11-15	IS : 633—1975
70.	0474752	81-11-01	82-10-31	IS : 10 (भाग 3)—1974
71.	0474853	81-11-01	82-10-31	IS : 3055 (भाग 1) —1977
72.	0475754	81-11-01	82-10-31	IS : 10 (भाग 3) —1974
73.	0476756	81-10-16	82-10-15	IS : 814 (भाग 1 और2) —1974
74.	0477253	81-11-01	82-10-31	IS : 829—1978
75.	0478659	81-11-16	82-11-15	IS : 1660 (भाग 1) 1967
76.	0478760	81-11-01	82-10-31	IS : 916—1975
77.	0479257	81-11-16	82-11-15	IS : 325 —1978
78.	0479661	81-12-01	82-11-30	IS : 1221—1971
79.	0480949	81-12-01	82-11-30	IS : 2865- 1978
80.	0481042	81-12-01	82-11-30	IS : 204 (भाग 2)—1978
81.	0482852	81-11-16	82-11-15	IS 1848 1971
82.	0483854	81-11-16	82-11-15	IS 171 1973
83.	0484452	81-12-01	82-11-30	IS 1717 —1975
84.	0484553	81-12-01	82-11-30	IS : 901 1975
85.	0484654	81-12-01	82-11-30	IS : 1079—1973
86.	0484755	81-12-01	82-11-30	IS : 2002—1962
87.	0484856	81-12-01	82-11-30	IS : 2062—1969
88.	0484957	81-12-01	82-11-30	IS : 6240—1976
89.	0485050	81-12-01	82-11-30	IS : 226 —1975
90.	0485555	81-12-01	82-11-30	IS : 6003- —1970
91.	0487761	81-12-16	82-12-15	IS : 4964—1980
92.	0488056	81-12-16	82-12-15	IS : 419 1967
93.	0500323	82-01-01	82-12-31	IS : 398 (भाग 1) 1976
94.	0501325	81-11-16	82-11-15	IS : 633 1975
95.	0501527	81-11-16	82-11-15	IS . 7122—1973
96.	0527949	81-12-16	82-12-15	IS : 2148 1968
97.	0533843	81-12-16	82-12-15	IS : 6914 —1978
98.	0533944	81-12-16	82-12-15	IS : 6915—1978
99.	0554845	81-12-16	82-12-15	IS : 561—1978
100.	0550136	82-01-01	82-12-31	IS : 1786—1979
101.	0556148	81-11-01	82-10-31	IS: 561-1978
102.	0559356	81-12-01	82-11-30	IS: 2906-1969
103.	0562648	81-11-16	82-11-15	IS: 10 (भाग 2)-1976
104.	0583044	81-11-16	81-11-15	IS: 419-1967
105.	0563145	81-11-16	81-11-15	IS: 1308-1974
106.	0563246	81-12-01	82-11-30	IS: 3747-1966
107.	0563852	81-12-01	82-11-30	IS: 10 (भाग 4)-1976
108.	0564046	81-12-01	82-11-30	IS : 325 —1970
109.	0564248	81-12-01	82-11-30	IS : 10 (भाग 4) -1976
110.	0565957	81-11-16	82-11-15	IS : 171 - 1975
111.	0566656	81-12-01	82-11-30	IS : 1011 —1968
112.	0569561	81-12-10	82-11-30	IS : 171—1975
113.	0571649	81-12-01	82-11-30	IS : 633 1975
114.	0573047	82-01-01	82-12-31	IS : 1239 (भाग 1)—1976
115.	0581147	81-11-16	82-11-15	IS : 1307—1973
116.	0597869	81-12-01	82-11-30	IS : 6914—1978
117.	0607442	81-12-01	82-11-30	IS : 458 1971
118.	0607846	81-12-01	82-11-30	IS : 2339—1963
119.	0609547	81-11-16	82-11-15	IS : 1005 —1976
120.	0609749	81-12-01	82-11-30	IS : 171—1973
121.	0626446	81-11-16	82-11-15	IS : 3903—1973
122.	0627549	81-12-01	82-11-30	IS : 513—1973
123.	0637956	81-12-01	82-11-30	IS : 164—1951
124.	0642848	81-11-16	82-11-15	IS : 4984—1980
125.	0643345	81-10-01	82-09-30	IS : 6047- —1970
126.	0643547	81-10-01	82-09-30	IS : 5430—1969
127.	0644751	81-12-01	82-11-30	IS : 133- 1975
128.	0650039	81-11-01	82-10-31	IS : 2566 —1965
129.	0650342	81-12-01	82-11-30	IS . 5986 -1970
130.	0651344	81-11-16	82-11-15	IS : 633— 1975
131.	0851445	81-11-01	82-10-31	IS : 6914 -1978
132.	0651546	81-11-01	82-10-31	IS : 6915 —1978
133.	0651647	81-11-16	82-11-15	IS : 561- 1978
134.	0652043	81-11-01	82-10-31	IS : 2580—1965
135.	0652952	81-11-16	82-11-30	IS : 3652—1974
136	0653550	81-11-16	82-11-15	IS : 6914— 1978
137.	0653651	81-11-16	82-11-15	IS : 6915 1978
138.	0653752	81-12-01	82-11-30	IS : 780- 1969
139.	0654653	81-12-01	82-11-30	IS : 4964—1980
140.	0654855	81-12-01	82-11-30	IS : 6914—1978
141.	0654956	81-12-01	82-11-30	IS : 6915- —1978
142.	0655150	81-12-01	82-11-30	IS : 4964- —1980
143.	0655453	81-11-16	82-11-15	IS : 1547—1968

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
144.	0656354	81-12-01	82-11-30	IS : 226—1975
145.	0656556	81-12-01	82-11-30	IS : 1786—1966
146.	0658762	82-01-01	82-12-31	IS : 1161—1979
147.	0690556	82-01-01	82-12-31	IS : 8052—1976
148.	0692863	81-11-01	82-10-31	IS : 4250—1967
149.	0697873	81-11-16	82-11-15	IS : 285—1974
150.	0703236	81-12-16	82-12-15	IS : 2834—1964
151.	0715647	80-10-01	82-09-30	IS : 781—1977
152.	0715849	80-10-01	82-09-30	IS : 1703—1977
153.	0718249	81-08-01	82-08-31	IS : 8268—1976
154.	0719554	81-11-16	82-11-15	IS : 2567—1973
155.	0726147	81-10-16	82-10-15	IS : 3652—1974
156.	0726955	81-10-16	82-10-15	IS : 561—1978
157.	0727755	81-11-01	82-10-31	IS : 829 -1978
158.	0729658	81-11-01	82-10-31	IS : 4985—1968
159.	0731847	81-11-16	82-11-15	IS : 694—1964
160.	0731948	81-11-16	18-11-15	IS : 226—1975
161.	0734853	81-12-01	82-11-30	IS : 565—1975
162.	0755047	81-12-01	82-11-30	IS : 1251—1973
163.	0735249	81-12-01	82-11-30	IS : 1786—1966
164.	0736756	81-12-01	82-11-30	IS : 226—1975
165.	0736857	81-12-01	82-11-30	IS : 1977—1975
166.	0737051	81-12-01	82-11-30	IS : 1977—1975
167.	0737152	81-12-01	82-11-30	IS : 1239 (भाग 1) —1977
168.	0737253	81-12-01	82-11-30	IS : 1320—1981
169.	0737354	81-12-01	82-11-30	IS : 694—1977
170.	0737859	81-12-01	82-11-30	IS : 694—1977
171.	0738053	81-12-16	82-12-15	IS : 633—1975
172.	0738558	81-12-01	82-11-30	IS : 398 (भाग 1 और 2)—1976
173.	0739055	81-12-01	82-11-30	IS : 1879—1975
174.	0739257	81-12-16	82-12-15	IS : 565—1975
175.	0741244	81-12-16	82-12-15	IS : 7452—1974
176.	0742751	82-01-01	82-12-31	IS : 1970 (भाग 1) -1974
177.	0745248	82-01-01	82-12-31	IS : 4654—1974
178.	0744250	82-01-01	82-12-31	IS : 1601—1960
179.	0744351	82-01-01	82-12-31	IS : 1601—1960
180.	0746961	81-11-16	82-11-15	IS : 4964—1980
181.	0747054	81-11-16	82-11-15	IS : 4964—1980
182.	0749664	81-12-01	82-11-30	IS : 694—1977
183.	0752047	81-11-16	82-11-15	IS : 4964—1980
184.	0768971	81-04-16	82-04-15	IS : 1977—1975
185.	0776768	81-09-16	82-09-15	IS : 5410—1969
186.	0788472	81-11-01	82-10-31	IS : 226—1975
187.	0792968	81-09-01	82-08-31	IS : 4989—1974
188.	0799376	81-09-16	82-09-15	IS : 1051—1973
189.	0803947	81-10-16	82-10-15	IS : 3906 (भाग 1) —1974
190.	0804040	81-10-16	82-10-15	IS : 4654—1974
191.	0804343	81-10-16	82-10-15	IS : 398 (भाग 1 और 2)—1976
192	0804747	81-10-16	82-10-15	IS : 6595—1972 और IS : 7538—1975
193.	0805042	81-10-16	82-10-15	IS : 8054—1976
194.	0806650	81-11-01	82-10-31	IS : 774—1974
195	0808048	81-12-01	82-11-30	IS : 3536—1966
196	0808149	81-12-01	82-11-30	IS : 3537—1966
197.	0808957	81-11-01	82-10-31	IS : 1786—1966
198.	0809151	81-11-16	82-11-15	IS : 8500—1977
199.	0809454	81-11-16	82-11-15	IS : 226- 1975
200.	0809555	81-11-16	82-11-15	IS : 1977—1975
201.	0809959	81-11-16	82-11-15	IS . 226—1975
202.	0810035	81-11-16	82-11-15	IS . 226—1975
203.	0811138	81-11-16	82-11-15	IS : 133—1975
204.	0811441	81-11-16	82-11-15	IS : 6595—1972
205.	0813849	81-12-01	82-11-30	IS : 2932 -1974
206.	0814750	81-11-16	82-11-15	IS : 1786—1966
207.	0814851	81-11-01	81-11-15	IS : 1786—1979
208.	0814952	81-11-16	82-11-15	IS : 633—1975
209.	0815247	81-12-01	82-11-30	IS : 1135—1973
210.	0815348	81-11-16	82-11-15	IS : 1786—1976
211.	0815550	81-12-01	82-11-30	IS : 7121—1973
212.	0816148	81-12-01	82-11-30	IS : 1785 (भाग 2) —1966
213.	0816350	81-12-01	82-11-30	IS : 1654 (भाग 1) —1976
214.	0816653	81-12-01	82-11-30	IS : 2208—1962
215.	0816853	81-12-01	82-11-30	IS : 226—1975
216.	0819861	81-12-16	82-12-15	IS : 7122—1973
217.	0820644	81-12-16	82-12-15	IS : 4964—1980
218.	0821747	81-12-16	82-12-15	IS : 1554 (भाग 1) - -1976
219.	0823549	82-01-01	82-12-31	IS : 4654—1974
220.	0826353	82-01-01	82-12-31	IS : 1061—1975
221.	0826959	81-01-01	82-12-31	IS : 1554 (भाग 1) —1976
222.	0828256	82-01-01	82-12-31	IS : 3196—1974
223.	0892063	81-09-01	82-08-31	IS : 1977 -1975
224.	0900339	81-10-01	82-09-30	IS : 1554 (भाग 1) - -1976
225.	0902646	81-10-16	82-10-15	IS : 2052—1979
226.	0903951	81-10-16	82-10-15	IS : 8748—1978
227.	0904751	81-10-16	82-10-15	IS : 7121—1973
228.	0906654	81-11-01	82-10-31	IS : 3901—1975
229.	0908052	81-11-01	82-10-31	IS : 398 (भाग 1 और 2)- -1976
230.	0908153	81-11-01	82-10-31	IS : 398 (भाग 1 और 2)—1976
231.	0908557	81-11-16	82-11-15	IS : 694—1977
232.	0908658	81-11-16	82-11-15	IS : 158—1968
233.	0908860	81-11-16	82-11-15	IS : 4654—1974
234.	0909054	81-11-16	82-11-15	IS : 1786—1979
235.	0909256	81-11-16	82-11-15	IS : 8828- 1978
236.	0909357	81-11-01	82-01-31	IS : 398 (भाग 1 और 2)—1976
237.	0909660	81-11-16	82-11-30	IS : 1786- 1979
238.	0909963	81-11-16	82-11-15	IS : 8960—1978
239.	0910544	81-11-16	82-11-15	IS : 4588—1977
240.	0910847	81-11-16	82-11-15	IS . 1165—1978
241.	0911647	81-11-16	82-12-15	IS : 2567—1978
242.	0912144	81-11-16	82-11-15	IS : 8249—1976
243.	0912548	81-11-16	82-11-15	IS . 2567 1978
244.	0913045	81-11-16	82-11-15	IS : 565—1975
245.	0913348	81-11-16	82-11-15	IS : 4964—1980

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
246.	0913954	81-12-01	82-12-30	IS : 612—1971
247.	0914047	81-12-01	82-11-30	IS : 226—1975
248.	0914148	81-12-01	82-11-30	IS : 1786—1966
249.	0914249	81-12-01	82-11-30	IS : 8960—1978
250.	0914653	82-12-01	82-11-30	IS : 158—1968
251.	0914754	81-12-01	82-11-30	IS : 341—1973
252.	0914855	81-12-01	82-11-30	IS : 694—1977
253.	0914956	81-12-01	82-11-30	IS : 562—1978
254.	0915049	81-12-01	82-11-30	IS : 1161—1979
255.	0915150	81-12-01	82-11-30	IS : 1554 (भाग 1) —1976
256.	0915352	81-12-01	82-11-30	IS : 565—1975
257.	0915453	81-12-21	82-11-30	IS : 371—1979
258.	0915756	81-12-01	82-11-30	IS : 10 (भाग 4) —1978
259.	0916253	81-12-01	82-11-30	IS : 9128—1979
260	0916354	81-12-01	82-11-30	IS : 4250—1980
261.	0916556	81-12-01	82-11-30	IS : 1786—1979
262.	0916657	81-12-01	82-11-30	IS : 1977—1975
263.	0916758	81-12-01	82-11-30	IS : 226—1975
264.	0916960	81-12-01	82-11-30	IS : 1391—1971
265.	0917154	81-12-01	82-11-30	IS : 2208—1962
266.	0916560	81-12-16	82-12-15	IS : 694—1977
267.	0918661	81-12-16	82-12-15	IS : 1554 (भाग 1) —1976
268.	0918964	81-12-16	82-12-15	IS : 2713 (भाग 2) —1980
269.	0919865	81-12-01	82-11-30	IS : 4159—1976
270.	0920850	81-12-16	82-12-15	IS : 3447—1965
271.	0922248	81-12-16	82-12-15	IS : 758—1975
272.	922753	81-12-16	82-12-15	IS : 1786—1979
273.	0923250	81-12-16	82-12-15	IS : 4431—1978
274.	0923957	82-01-01	82-12-31	IS : 3854—1966
275.	0924050	82-01-01	82-12-31	IS : 694—1977
276.	0924151	82-01-01	82-12-31	IS : 1554 (भाग 1) —1976
277.	0924656	81-12-16	82-12-15	IS : 863—1969
278.	0926357	82-01-01	83-12-31	IS : 8737 भाग 2 —1978
279.	0933455	82-02-01	83-01-31	IS : 4246—1978

[सं० सी० एम० डी० 13 : 12]

ए० पी० बनर्जी, अपर महानिदेशक

S.O. 3107.—In pursuance of sub-regulation (1) of Regulation 8 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Regulations, 1955, as amended from time to time, the Indian Standards Institution, hereby, notifies that 279 licences, particulars of which are given in the following Schedule, have been renewed during the month of December 1981 :

SCHEDULE

Sl. No.	CM/L No.	Valid From	Valid To	Indian Standard Specification No.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	0003612	81-11-16	82-11-15	IS : 398 (Part I &II)-1976
2.	0003713	81-11-16	82-11-15	IS : 434 (Part I & II)—1964
3.	0018827	18-11-16	82-11-15	IS : 11-84-1977
4.	0036122	81-12-16	82-12-15	IS : 916-1975
5.	0036930	82-01-01	82-12-31	IS : 916-1975
6.	0038934	81-11-16	82-11-15	IS : 694-1977
7.	0059841	81-12-01	82-11-30	IS : 694-1977
8.	0061626	81-10-16	82-10-15	IS : 398 (Part I & II)—1976
9.	0065432	81-03-01	82-02-28	IS : 561-1978
10.	0069642	81-11-16	82-11-15	IS : 1554 (Part I)—1976
11.	0083939	81-12-01	82-11-30	IS : 1221-1971
12.	0097748	81-12-01	82-11-30	IS : 220-1972
13.	0109426	81-12-16	82-12-15	IS : 226-1975
14.	0120919	81-12-01	82-11-30	IS : 398 (Part II)—1976
15.	0121921	82-01-01	82-12-31	IS : 814 (Part I & II)—1974
16.	0143224	81-11-16	82-11-15	IS : 1596-1977
17.	0143628	81-11-01	82-10-31	IS : 7452-1974
18.	0154532	81-11-16	82-11-15	IS : 325-1978
19.	0169848	81-11-16	82-11-15	IS : 226-1975
20.	0169949	81-11-16	82-11-15	IS : 1977-1975
21.	0170328	81-11-16	82-11-15	IS : 2037-1962
22.	0170732	81-11-16	82-11-15	IS : 398 (Part I & II)—1976
23.	0171532	81-12 16	82-12-15	IS : 226-1975
24.	0171633	81-12-16	82-12-15	IS : 1977-1975
25.	0173435	81-11-01	82-10-31	IS : 417 (Part I, II & III) —1974
26.	0188246	82-01-01	82-12-31	IS : 3196-1974
27.	0215526	81-01-16	82-10-15	IS : 10 (Part III)—1974
28.	0225428	81-11-01	82-10-31	IS : 8969 (Part I)—1978
29.	0231322	81-11-01	82-10-31	IS : 3686-1966
30.	0243632	81-11-16	82-11-15	IS : 2593-1964
31.	0245636	81-11-16	82-11-15	IS : 1165-1975
32.	0269044	81-11-16	82-11-15	IS : 325-1978
33.	0273843	81-12-01	82-11-30	IS : 1554 (Part I)—1976
34.	0274643	81-12-16	82-12-15	IS : 2548-1967
35.	0281034	81-11-16	82-11-15	IS : 780-1969
36.	0273846	81-12-16	82-12-15	IS : 1786-1966
37.	0286044	82-01-01	82-12-31	IS : 398 (Part I)—1976
38.	0303927	81-10-16	82-10-15	IS : 398 (Part I & II)—1976
39.	0310520	81-12-16	82-12-15	IS : 1011-1968
40.	0312625	81-12-01	82-11-30	IS : 2082-1978
41.	0319336	81-11-01	82-10-31	IS : 398 (Part I & II)—1976
42.	0320725	81-12-16	82-12-15	IS : 694-1977
43.	0324430	81-12-16	82-12-15	IS : 10 (Part II)—1976
44.	0328438	82-01-01	82-12-31	IS : 694-1977
45.	0328539	82-01-01	82-12-31	IS : 1554 (Part I)—1976
46.	0340226	81-11-01	82-10-31	IS : 398 (Part I & II)—1976
47.	0356140	81-12-16	82-12-15	IS : 1786-1969
48.	0358851	81-11-16	82-11-15	IS : 6438-1980
49.	0359045	81-11-16	82-11-15	IS : 5423-1978
50.	0359651	81-12-01	82-11-130	IS : 1726 (Part II, IV, V, VI/Sec. 2)—1974
51.	0360030	81-11-16	82-11-15	IS : 564-1975
52.	0360535	81-12-01	82-11-30	IS : 1879-1975

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
53.	0360939	81-12-01	82-11-30	IS : 5455-1969
54.	0382141	81-11-01	82-10-31	IS : 3975-1975
55.	0384852	81-12-16	82-12-15	IS : 1554 (Part I)—1976
56.	0387252	81-08-16	82-08-15	IS : 10 (Part IV)—1975
57.	0401927	81-11-01	82-10-31	IS : 398 (Part II)—1976
58.	0403224	81-12-01	82-11-30	IS : 2548-1967
59.	0405733	81-11-16	82-11-15	IS : 633-1975
60.	0406129	81-12-01	82-11-30	IS : 398 (Part I & II)—1976
61.	0408032	81-12-01	82-11-30	IS : 335-1972
62.	0410827	82-01-01	82-12-31	IS : 4246-1978
63.	0437544	81-11-16	82-11-15	IS : 2567-1978
64.	0458350	81-12-01	82-11-30	IS : 419-1967
65.	0461036	81-12-01	82-11-30	IS : 10 (Part IV)—1976
66.	0469658	81-11-16	82-11-15	IS : 1848-1971
67.	0471544	81-10-01	82-09-30	IS : 1848-1971
68.	0472950	81-10-16	82-10-15	IS : 1165-1975
69.	0473043	81-11-16	82-11-15	IS : 633-1975
70.	0474752	81-11-01	82-10-31	IS : 10 (Part III)—1974
71.	0474853	81-11-01	82-10-31	IS : 3055 (Part I)—1977
72.	0475754	81-11-01	82-10-31	IS : 10 (Part III)—1974
73.	0476756	81-10-16	82-10-15	IS : 814 (Part I & II)—1974
74.	0477253	81-11-01	82-10-31	IS : 829-1978
75.	0478659	81-11-16	82-11-15	IS : 1660 (Part I)—1967
76.	0478760	81-11-01	82-10-31	IS : 916-1975
77.	0479257	81-11-16	82-11-15	IS : 325-1978
78.	0479661	81-12-01	82-11-30	IS : 1221-1971
79.	0480949	81-12-01	82-11-30	IS : 2865-1978
80.	0481042	81-12-01	82-11-30	IS : 204 (Part II)—1978
81.	0482852	81-11-16	82-11-15	IS : 1848-1971
82.	0483854	81-11-16	82-11-15	IS : 171-1973
83.	0484452	81-12-01	82-11-30	IS : 1977-1975
84.	0484553	81-12-01	82-11-30	IS : 961-1975
85.	0484654	81-12-01	82-11-30	IS : 1079-1973
86.	0484755	81-12-01	82-11-30	IS : 2002-1962
87.	0484856	81-12-01	82-11-30	IS : 2062-1969
88.	0484957	81-12-01	82-11-30	IS : 6240-1976
89.	0485050	81-12-01	82-11-30	IS : 226-1975
90.	0485555	81-12-01	82-11-30	IS : 6003-1970
91.	0487761	81-12-16	82-12-15	IS : 4964-1980
92.	0488056	81-12-16	82-12-15	IS : 419-1967
93.	0500323	82-01-01	82-12-31	IS : 398 (Part I)—1976
94.	0501325	81-11-16	82-11-15	IS : 633-1975
95.	0501527	81-11-16	82-11-15	IS : 7122-1973
96.	0527949	81-12-16	82-12-15	IS : 2148-1968
97.	0533843	81-12-16	82-12-15	IS : 6914-1978
98.	0533944	81-12-16	82-12-15	IS : 6915 : 1978
99.	0534845	81-12-16	82-12-15	IS : 561-1978
100.	0550136	82-01-01	82-12-31	IS : 1786-1979
101.	0556148	81-11-01	82-10-31	IS : 561-1978
102.	0559356	81-12-01	82-11-30	IS : 2906-1969
103.	0562648	81-11-16	82-11-15	IS : 10 (Part II)—1976
104.	0563044	81-11-16	82-11-15	IS : 419-1967
105.	0563145	81-11-16	82-11-15	IS : 1308-1974
106.	0563246	81-12-01	82-11-30	IS : 3747-1966
107.	0563852	81-12-01	82-11-30	IS : 10 (Part IV)—1976
108.	0564046	81-12-01	82-11-30	IS : 325-1970
109.	0564248	81-12-01	82-11-30	IS : 10 (Part IV)—1976
110.	0565957	81-11-16	82-11-15	IS : 171-1973
111.	0566656	81-12-01	82-11-30	IS : 1011-1968
112.	0569561	81-12-01	82-11-30	IS : 71-1973
113.	0571649	81-12-01	82-11-30	IS : 633-1975
114.	0573047	82-01-01	82-12-31	IS : 1239 (Part I)—1976
115.	0581147	81-11-16	82-11-15	IS : 1307-1973
116.	0597869	81-12-01	82-11-30	IS : 6914-1978
117.	0607442	81-12-01	82-11-30	IS : 458-1971
118.	0607846	81-12-01	82-11-30	IS : 2339-1963
119.	0609547	81-11-16	82-11-15	IS : 1005-1976
120.	0609749	81-12-01	82-11-30	IS : 171-1973
121.	0626446	81-11-16	82-11-15	IS : 3903-1973
122.	0627549	81-12-01	82-11-30	IS : 513-1973
123.	0637956	81-12-01	82-11-30	IS : 164-1951
124.	0642848	81-11-16	82-11-15	IS : 4964-1980
125.	0643345	81-10-01	82-09-30	IS : 6047-1970
126.	0643547	81-10-01	82-09-30	IS : 5430-1969
127.	0644751	81-12-01	82-11-30	IS : 133-1975
128.	0650039	81-11-01	82-10-31	IS : 2566-1965
129.	0650342	81-12-01	82-11-30	IS : 5986-1970
130.	0651344	81-11-16	82-11-15	IS : 633—1975
131.	0651445	81-11-01	82-10-31	IS : 6914—1978
132.	0651546	81-11-01	82-10-31	IS : 6915—1978
133.	0651647	81-11-16	82-11-15	IS : 561—1978
134.	0652043	81-11-01	82-10-31	IS : 2580—1965
135.	0652952	81-11-16	82-11-30	IS : 3652—1974
136.	0653550	81-11-16	82-11-15	IS : 6914—1978
137.	0653651	81-11-16	82-11-15	IS : 6915—1978
138.	0653752	81-12-01	82-11-30	IS : 780—1969
139.	0654653	81-12-01	82-11-30	IS : 4964—1980
140.	0654855	81-12-01	82-11-30	IS : 6914—1978
141.	0654956	81-12-01	82-11-30	IS : 6915—1978
142.	0655150	81-12-01	82-11-30	IS : 4964—1980
143.	0655453	81-11-16	82-11-15	IS : 1547—1968
144.	0656354	81-12-01	82-11-30	IS : 226—1975
145.	0656556	81-12-01	82-11-30	IS : 1786—1966
146.	0658762	82-01-01	82-12-31	IS : 1161—1979
147.	0690556	82-01-01	82-12-31	IS : 8052—1976
148.	0692863	81-11-01	82-10-31	IS : 4250—1967
149.	0697873	81-11-16	82-11-15	IS : 285—1974
150.	0703236	81-12-16	82-12-15	IS : 2834—1964
151.	0715647	80-10-01	82-09-30	IS : 781—1977
152.	0715849	80-10-01	82-09-30	IS : 1703—1977
153.	0718249	81-09-01	82-08-31	IS : 8268—1976
154.	0719554	81-11-16	82-11-15	IS : 2567—1973
155.	0726147	81-10-16	82-10-15	IS : 3652—1974
156.	0726955	81-10-16	82-10-15	IS : 561—1978
157.	0727755	81-11-01	82-10-31	IS : 829—1978
158.	0729658	81-11-01	82-10-31	IS : 4985—1968
159.	0731847	81-11-16	82-11-15	IS : 694—1964
160.	0731948	81-11-16	82-11-15	IS : 226—1975
161.	0734853	81-12-01	82-11-30	IS : 565—1975
162.	0735047	81-12-01	82-11-30	IS : 1251—1973
163.	0735249	81-12-01	82-11-30	IS : 1786—1966
164.	0736756	81-12-01	82-11-30	IS : 226—1975
165.	0736857	81-12-01	82-11-30	IS : 1977—1975
166.	0737051	81-12-01	82-11-30	IS : 1977—1975
167.	0737152	81-12-01	82-11-30	IS : 1239—(Part I)—1977
168.	0737253	81-12-01	82-11-30	IS : 1320—1981
169.	0737354	81-12-01	82-11-30	IS : 694—1977
170.	0737859	81-12-01	82-11-30	IS : 694—1977
171.	0738053	81-12-16	82-12-15	IS : 633—1975
172.	0738558	81-12-01	82-11-30	IS : 398 (Part I & II)—1976
173.	0739055	81-12-01	82-11-30	IS : 1879—1975
174.	0739257	81-12-16	82-12-15	IS : 565—1975
175.	0741244	81-12-16	82-12-15	IS : 7452—1974
176.	0742751	82-01-01	82-12-31	IS : 1970 (Part I)—1974
177.	0743248	82-01-01	82-12-31	IS : 4654—1974
178.	0744250	82-01-01	82-12-31	IS : 1601—1960
179.	0744351	82-01-01	82-12-31	IS : 1601—1960
180.	0746961	81-11-16	82-11-15	IS : 4964—1980

1	2	3	4	5
181.	0747054	81-11-16	82-11-15	IS : 4964—1980
182.	0749664	81-12-01	82-11-30	IS : 694—1977
183.	0752047	81-11-16	82-11-15	IS : 4964—1980
184.	0768971	81-04-16	82-04-15	IS : 1977—1975
185.	0776768	81-09-16	82-09-15	IS : 5410—1969
186.	0788472	81-11-01	82-10-31	IS : 226—1975
187.	0792968	81-09-01	82-08-31	IS : 4989-1974
188.	0799376	81-09-16	82-09-15	IS : 1051—1973
189.	0803947	81-10-16	82-10-15	IS : 3906 (Part I)—1974
190.	0804040	81-10-16	82-10-15	IS : 4654—1974
191.	0804343	81-10-16	82-10-15	IS :398 (Part I & II)—1976
192.	0804747	81-10-16	82-10-15	IS : 6595—1972 & IS : 7538—1975
193.	0805042	81-10-16	82-10-15	IS : 8054—1976
194.	0806650	81-11-01	82-10-31	IS : 774—1974
195.	0808048	81-12-01	82-11-30	IS : 3536—1966
196.	0808149	81-12-01	82-11-30	IS : 3537—1966
197.	0808957	81-11-01	82-10-31	IS : 1786—1966
198.	0809151	81-11-16	82-11-15	IS : 8500—197.
199.	0809454	81-11-16	82-11-15	IS : 226—1975
200.	0809555	81-11-16	82-11-15	IS : 1977—1975
201.	0809959	81-11-16	82-11-15	IS : 226—1975
202.	0810035	81-11-16	82-11-15	IS : 226—1975
203.	0811138	81-11-16	82-11-15	IS : 133—1975
204.	0811441	81-11-16	82-11-15	IS : 6595—1972
205.	0813849	81-12-01	82-11-30	IS : 2932—1974
206.	0814750	81-11-16	82-11-15	IS : 1786—1966
207.	0814851	81-11-01	82-11-15	IS : 1786—1979
208.	0814945	81-11-16	82-11-15	IS : 633—1975
209.	0815247	81-12-01	82-11-30	IS : 1135—1973
210.	0815348	81-11-16	82-11-15	IS : 1786—1976
211.	0815550	81-12-01	82-11-30	IS : 7121—1973
212.	0816148	81-12-01	82-11-30	IS : 1785—(Part II)—1966
213.	0816350	81-12-01	82-11-30	IS : 1554 (Part I)—1976
214.	0816653	81-12-01	82-11-30	IS : 2208—1962
215.	0816855	81-12-01	82-11-30	IS : 226—1975
216.	0819861	81-12-16	82-12-15	IS : 7122—1973
217.	0820644	81-12-16	82-12-15	IS : 4964—1980
218.	0821747	81-12-16	82-12-15	IS : 1554(Part I)—1976
219.	0823549	82-01-01	82-12-31	IS : 4654—1974
220.	0826353	82-01-01	82-12-31	IS : 1061—1975
221.	0826959	82-01-01	82-12-31	IS : 1554 (Part I)—1976
222.	0828256	82-01-01	82-12-31	IS : 3196—1974
223.	0892063	81-09-01	82-08-31	IS : 1977—1975
224.	0900339	81-10-01	82-09-30	IS : 1554 (Part I)—1976
225.	0902646	81-10-16	82-10-15	IS : 2052—1979
226.	0903951	81-10-16	82-10-15	IS : 8748—1978
227.	0904751	81-10-16	82-10-15	IS : 7121—1973
228.	0906654	81-11-01	82-10-31	IS : 3901—1975
229.	0908052	81-11-01	82-10-31	IS : 398 (Part I & II)—1976
230.	0908153	81-11-01	82-10-31	IS : 398 (Part I & II)—1976
231.	0908557	81-11-16	82-11-15	IS : 694—1977
232.	0908658	81-11-16	82-11-15	IS : 158—1968
233.	0908860	81-11-16	82-11-15	IS : 4654—1974
234.	0909054	81-11-16	82-11-15	IS : 1786—1979
235.	0909256	81-11-16	82-11-15	IS : 8828—1978
236.	0909357	81-11-01	82-10-31	IS : 398 (Part I & II)—1976
237.	0909660	81-11-16	82-11-30	IS : 1786—1979
238.	0909963	81-11-16	82-11-15	IS : 8960—1978
239.	0910544	81-11-16	82-11-15	IS : 4588—1977
240.	0910847	81-11-16	82-11-15	IS : 1165—1978
241.	0911647	81-11-16	82-11-15	IS : 2567—1978
242.	0912144	81-11-16	82-11-15	IS : 8249—1976
243.	0912548	81-11-16	82-11-15	IS : 2567—1978
244.	0913045	81-11-16	82-11-15	IS : 565—1975
245.	0913348	81-11-16	82-11-15	IS : 4964—1980
246.	0913954	81-12-01	82-11-30	IS : 612—1971
247.	0914047	81-12-01	82-11-30	IS : 226—1975
248.	0914148	81-12-01	82-11-30	IS : 1786—1966
249.	0914249	81-12-01	82-11-30	IS : 8960—1978
250.	0914653	81-12-01	82-11-30	IS : 158—1968
251.	0914754	81-12-01	82-11-30	IS : 341—1973
252.	0914855	81-12-01	82-11-30	IS : 694—1977
253.	0914956	81-12-01	82-11-30	IS : 562—1978
254.	0915049	81-12-01	82-11-30	IS : 1161—1979
255.	0915150	81-12-01	82-11-30	IS : 1554 (Part I)—1976
256.	0915352	81-12-01	82-11-30	IS : 565—1975
257.	0915453	81-12-01	82-11-30	IS : 371—1979
258.	0915756	81-12-01	82-11-30	IS : 10 (Part IV)—1976
259.	0916253	81-12-01	82-11-30	IS : 9128—1979
260.	0916354	81-12-01	82-11-30	IS : 4250—1980
261.	0916556	81-12-01	82-11-30	IS : 1786—1979
262.	0916657	81-12-01	82-11-30	IS : 1977—1975
263.	0916758	81-12-01	82-11-30	IS : 226—1975
264.	0916960	81-12-01	82-11-30	IS : 1391—1971
265.	0917154	81-12-01	82-11-30	IS : 2208—1962
266.	0918560	81-12-16	82-12-15	IS : 694—1977
267.	0918661	81-12-16	82-12-15	IS : 1554 (Part I)—1976
268.	0918964	81-12-16	82-12-15	IS : 2713 (Part II)—1980
269.	0919865	81-12-01	82-11-30	IS : 4159—1976
270.	0920850	81-12-16	82-12-15	IS : 3447—1965
271.	0922248	81-12-16	82-12-15	IS : 758—1975
272.	922753	81-12-16	82-12-15	IS : 1786—1979
273.	0923250	81-12-16	82-12-15	IS : 4431—1978
274.	0923957	82-01-01	82-12-31	IS : 3854—1966
275.	0924050	82-01-01	82-12-31	IS : 694—1977
276.	0924151	82-01-01	82-12-31	IS : 1554 (Part I)—1976
277.	0924656	81-12-16	82-12-15	IS : 863—1969
278.	0926357	82-01-01	82-12-31	IS : 8737 (Part II)—1978
279.	0933455	82-02-01	83-01-31	IS : 4246—1978

[No. CMD/13 : 12]

A. P. BANERJI, Addl. Director General

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, 16 अगस्त, 1982

का०आ० 3108.—यतः भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के उपबन्धों का पालन करते हुए कश्मीर विश्वविद्यालय की सीनेट द्वारा मनोनीत डा० सयीद जहूर अहमद को 1 जून, 1982 से भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद का सदस्य निर्वाचित किया गया है,

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार की 9 जनवरी, 1960 की अधिसूचना संख्या 5-13/51-एम-1 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में "धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) अधीन मनोनीत" शीर्ष के अन्तर्गत क्रम संख्या 51 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएं, अर्थात् :—

"51, डा० सयीद जहूर अहमद,
प्रधानाचार्य,
राजकीय मेडिकल कालेज,
श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर"

[सं० वी० 11013/10/82-एम०ई० (पालिसी)]

पी० सी० जैन, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Depatrment of Health)

New Delhi, the 16th August, 1982

S.O. 3108.—Whereas in pursuance of the provision of clause (b) of sub-section (1) of section 3 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956) Dr. Syed Zahoor Ahmad had been elected by the Senate of Kashmir University to be a member of the Medical Council of India with effect from the 1st June, 1982.

Now, therefore, in pursuance of sub-section (1) of section 3 of the said Act, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the late Ministry of Health No. 5-13/59-MI, dated the 9th January, 1960, namely :—

In the said notification, under the head "Elected under clause (b) of sub-section (1) of section 3", for serial number 51 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be submitted, namely :—

"51. Dr. Syed Zahoor Ahmad,
Principal, Government Medical College,
Srinagar, Jammu & Kashmir."

[No. V. 11013/10/82-M.E.(Policy)]

P. C. JAIN, Under Secy.

परमाणु ऊर्जा विभाग

बम्बई, 26 जुलाई, 1982

का०आ० 3109.—केन्द्रीय सरकार, सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40वां) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे सारणी के स्तम्भ (1) में उल्लिखित अधिकारी को, जो सरकार के राजपत्रित अधिकारी के समतुल्य है, उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए सम्पदा अधिकारी नियुक्त करती है तथा उक्त अधिकारी उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अधीन सम्पदा अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और अधिरोपित कर्तव्यों का पालन उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट सरकारी स्थानों के संबंध में अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं में करेगा ।

सारणी

अधिकारी का पदनाम	सरकारी स्थानों की श्रेणियां तथा अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं
1	2
प्रशासनिक अधिकारी (iii) भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र सम्मिश्र तारापुर, जिला थाना (महाराष्ट्र)	महाराष्ट्र के थाना जिले में पालघर तथा दहानु तालुकों में स्थित भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के अपने या उसके प्रबन्धनाधीन स्थान ।

[फा० सं० जे०एस०पी०/ए०एम०टी०/एल०एस०डी०]

राजीव अग्रवाल,
अवर सचिव

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

Bombay, the 26th July, 1982.

S. O.3109:—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971, (40 of 1971), the Central Government hereby appoints the Officer mentioned in column (1) of the Table below, being an Officer equivalent to the rank of a gazetted Officer of Government to be the Estate Officer for the purpose of the said Act, and the said Officer shall exercise the powers conferred and perform the duties imposed on Eatate Officers by or under the said Act within the local limits of his jurisdiction in respect of the public premises specified in column (2) of the said Table.

TABLE

Designation of the Officer	Categories of public premises & local limits of jurisdiction
(1)	(2)
Administrative Officer III BARC Complex Tarapur District Thane (Maharashtra).	Premises belonging to or under the management of Bhabha Atomic Research Centre in Palghar and Dahanu Taluka, Distt. Thane, Maharashtra State.

[File No. JSP/AST/LND]

RAJIV AGARWAL, Under Secy.

ऊर्जा मंत्रालय

(विद्युत विभाग)

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 1982

का० आ० 3110.—केन्द्रीय सरकार, दामोदर घाटी निगम अधिनियम, 1948 (1948 का 14) की धारा 48 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय (विद्युत विभाग) की अधिसूचना संख्या का० आ० 2212 तारीख 12 मई, 1975 तथा का० आ० 1232 तारीख 24 मार्च, 1981 के अधीन जारी किए गए अनुदेशों के अतिरिक्त, दामोदर घाटी निगम को यह अनुदेश देती है कि उसके उपभोक्ताओं के लिए विद्युत के प्रदाय की प्रभार-अनुसूची में सम्पूर्ण दर में 7 पैसे प्रति किलोवाट की वृद्धि की जाएगी ।

[एफ० सं० 17/29/80-डी० II/डी०वी०सी० (पार्ट)]

वी० के० सूद, उप सचिव

MINISTRY OF ENERGY

(Department of Power)

New Delhi, the 31st July, 1982

S.O. 3110.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 48 of the Damodar Valley Corporation Act, 1948 (14 of 1948) and in addition to the instructions issued by the Government of India in the Ministry of Energy (Department of Power) under notification Nos. S.O. 2212, dated the 12th May, 1975, and S.O. 1232 dated the 24th March, 1981, respectively, the Central Government hereby instructs the Damodar Valley Corporation that the schedule of charges for the supply of electricity to its consumers shall be enhanced by another 7 paise per kwh, in overall rate.

[F. No. 17/29/80-D.II/DVC (Pt.)]

V. K. SOOD, Dy. Secy.

कृषि मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 1982

आदेश

का० आ० 3111.—यत: केन्द्रीय सरकार ने खाद्य विभाग, क्षेत्रीय खाद्य निदेशालयों, उपाप्ति निदेशालयों और खाद्य विभाग के वेतन तथा लेखा कार्यालयों द्वारा किए जाने वाले खाद्यान्नों के क्रय, भण्डारकरण, संचलन, परिवहन, वितरण तथा विक्रय के कृत्यों का पालन करना बंद कर दिया है जो कि खाद्य निगम अधिनियम, 1964 (1964 का 37) की धारा 13 के अधीन भारतीय खाद्य निगम के कृत्य हैं ;

और यत: खाद्य विभाग, क्षेत्रीय खाद्य निदेशालयों, उपाप्ति निदेशालयों और खाद्य विभाग के वेतन तथा लेखा कार्यालयों में कार्य कर रहे और उपरिवर्णित कृत्यों के पालन में लगे निम्नलिखित अधिकारियों और कर्मचारियों ने केन्द्रीय सरकार के तारीख 16 अप्रैल, 1971 के परिपत्र के प्रत्युत्तर में उसमें विनिर्दिष्ट तारीख के अन्दर भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारी न बनने के अपने आशय को उक्त अधिनियम की धारा 12ए की उपधारा (1) के परन्तुक द्वारा यथा अपेक्षित सूचना नहीं दी है ।

अत: अब खाद्य निगम अधिनियम, 1964 (1964 का 37) यथा अद्यतन संशोधित की धारा 12ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित कर्मचारियों को प्रत्येक के सामने दी गई तारीख से भारतीय खाद्य निगम में स्थानान्तरित करती है :—

क्रम० सं०	अधिकारी कर्मचारी का नाम	केन्द्रीय सरकार के अधीन स्थायी पद	स्थानान्तरण के समय केन्द्रीय सरकार के अधीन पद	भारतीय खाद्य निगम में स्थानान्तरण की तारीख
1.	श्री अतर सिंह सुपुत्र श्री राम सरन	तोला	गोदाम लिपिक	1-3-69

[संख्या 52/1/82-एफ०सी०-III]

आर० के० सिंह,
उप सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Food)

ORDER

New Delhi, the 10th August, 1982

S.O. 3111—Whereas the Central Government has ceased to perform the functions of purchase, storage, movement, transport, distribution and sale of food-grains done by the Department of Food, the Regional Directorates of Food, the procurement Directors and Pay & Accounts Offices of the Department of Food which under section 13 of Food Corporations Act, 1964 (37 of 1964) are the functions of the Food Corporation of India.

And whereas the following officers and employees serving in the Department of Food, the Regional Directorate of Food, the procurement Directorates and the Pay & Accounts Offices of the Department of Food and engaged in the performance of the functions mentioned above have not in response to the circular of the Cantral Government dated the 16th April, 1971 intimated, within the date specified therein, their intention of not becoming employees of the Food Corporation of India as required by the proviso to sub-section (1) of Section 12A of the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by s tion 12A of the Food Corporation Act, 1964 (37 of 1964) as amended upto date the Central Government hereby transfer the following officers and employees to the Food Corporation of India with effect from the date mentioned against each of them.

S. No.	Name of the Officer employee	Permanent post held under the Central Govt.	Post held under the Central Govt. at the time of transfer	Date of transfer to FCI
1.	Sh. Attar Singh S/o Sh. Ram Saran	Weighman	Godown Clerk	1-3-69

[No. 52/1/82-FC- III]

R.K. SINGH, Dy. Secy.

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(हिन्दी अनुभाग)

नई दिल्ली, 17 अगस्त 1982

का० आ० 3112 भारत सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उपनियम (4) के अनुसरण में नौवहन और परिवहन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में स्थित बम्बई पोर्ट ट्रस्ट, बम्बई कार्यालय को जहां 80 प्रतिशत और उससे अधिक कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है ।

[सं० एम० पी० यू०/147/82]

चन्द्रभान जड़गुजर, निदेशक

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Hindi Section)

New Delhi, the 17th August, 1982

S.O. 3112.—In pursuance of sub-rule (4) of Rule 10 of the Official Language (Use for the official purpose of the

Union) Rules, 1976, the Government of India hereby notifies the office of Bombay Port Trust, Bombay under the administrative control of Ministry of Shipping and Transport, 80% staff whereof have acquired working knowledge of Hindi.

[No. HPU/147/82]

C. B. BUDGUJAR, Director

अंतरिक्ष विभाग

बंगलौर, 16 जुलाई, 1982

का० आ० 3113 राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अंतरिक्ष विभाग कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1976 में और संशोधन करने के लिए निम्न लिखित नियम बनाते है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का नाम अंतरिक्ष विभाग कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) संशोधन नियम, 1982 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. अंतरिक्ष विभाग कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1976 के नियम 11 के उपनियम (8) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:—

"8(क) कर्मचारी अपनी ओर से मामला उपस्थापित करने के लिए किसी अन्य कर्मचारी या सहकारी सेवक की सहायता ले सकेगा, किन्तु इस प्रयोजन के लिए कोई विधि व्यवसायी तब तक नहीं नियुक्त कर सकेगा जब तक कि अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा नियुक्त उपस्थापित अधिकारी विधि व्यवसायी न हो, या अनुशासनिक प्राधिकारी, मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, ऐसी अनुज्ञा न दें:

परन्तु अन्य कर्मचारी या सरकारी सेवक के हाथ में ऐसे दो अनुशासनिक मामले, जिनमें उसे सहायता देनी है, लम्बित नहीं होंगे।

(ख) कर्मचारी अपनी ओर से मामला उपस्थापित करने के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी की भी सहायता ले सकता है:—

(i) सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी केन्द्रीय सरकार के अधीन सेवा से सेवानिवृत्त हो चुका हो;

(ii) सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी के हाथ में ऐसे तीन अनुशासनिक मामले, जिनमें उसे सहायता देनी है, लम्बित नहीं होंगे;

(iii) सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी तब तक विधि व्यवसायी नहीं होगा जब तक कि अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा नियुक्त उपस्थापक अधिकारी विधि व्यवसायी न हो, या अनुशासनिक प्राधिकारी, मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, ऐसी अनुज्ञा न दें;

(iv) सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तारीख के पश्चात् तीन वर्ष व्यतीत नहीं हो चुके हों।"

[सं० 2/8(1)81]

पी०ए० मेनन, सचिव

DEPARTMENT OF SPACE

Bangalore, the 16th July, 1982

S.O. 3113.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Department of Space Employees' (Classification, Control and Appeal) Rules, 1976, namely :—

1. (1) These rules may be called the Department of Space Employees' (Classification, Control and Appeal) Amendment Rules, 1982.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In rule 11 of the Department of Space Employees' (Classification, Control and Appeal) Rules, 1976, for sub-rule (8), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(8) (a) The Employee may take the assistance of any other employee or a Government servant to present the case on his behalf, but may not engage a legal practitioner for the purpose unless the Presenting Officer, appointed by the disciplinary authority is also a legal practitioner, or the disciplinary authority having regard to the circumstances of the case, so permits :

Provided that the other employee or the Government servant shall not have two pending disciplinary cases on hand in which he has to give assistance.

(b) The employee may also take the assistance of a retired Government servant to present the case on his behalf, subject to the conditions that—

(i) the retired Government servant should have retired from the service under the Central Government ;

(ii) the retired Government servant does not have three pending disciplinary cases on hand in which he has to give assistance ;

(iii) the retired Government servant may not be a legal practitioner unless the Presenting Officer, appointed by the disciplinary authority is also a legal practitioner, or unless the disciplinary authority, having regard to the circumstances of the case, so permits ;

(iv) three years have not elapsed after the date of retirement of the retired Government servant".

[No. 2/8(1)/81-II]

P. A. MENON, Dy. Secy.

बंगलौर, 12 अगस्त, 1982

का० आ० 3114.—केन्द्रीय सरकार, सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (1) में वर्णित अधिकारी को जो सरकार के राजपत्रित अधिकारी की पंक्ति के समतुल्य का अधिकारी है, उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए सम्पदा अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है, जो उक्त सारणी के स्तंभ (2) की तत्स्थानी प्रविष्टि मे विनिर्दिष्ट सरकारी स्थानों की बाबत अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अधीन सम्पदा अधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करेगा :

सारणी

अधिकारी का पदाभिधान	सरकारी स्थानों के प्रवर्ग और स्थानीय अधिकारिता की सीमाएं
(1)	(2)
प्रशासन अधिकारी-I, प्रधान नियंत्रण सुविधा, अंतरिक्ष विभाग, हसन, कर्णाटक	(1) हसन जिले में कंचमारनहल्लि के सर्वे सं० 119, 13 और 52 में हसन स्थित प्रधान नियंत्रण सुविधा कम्प्लेक्स का परिसर। सीमाएं : उत्तर में हसन हेलाबिड रोड, दक्षिण में मौजे मुगनहल्लि, पश्चिम मे गोविन्दपुरा, पूर्व में सर्वे सं० 119 का शेष भाग। (2) हसन जिले में मौजे हरलाहल्लि के सर्वे सं० 22 और 24 में अंतरिक्ष विभाग का आवासीय कालोनी का परिसर । सीमाए . पूर्व में मौजे चिक्कुहरनहल्लि, उत्तर में सर्वे सं० 21035, पश्चिम में सर्वे सं० 34, 2528, 26 और 27 तथा कोप्पालू, दक्षिण में सर्वे सं० 65।

[सं० 9/2(2)/82-III]

के० आर० रामनाथ, अवर सचिव

Bangalore, the 12 August, 1982

S. O. 3114.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971), the Central Government hereby appoint the Officer mentioned in column (1) of the Table below, being an officer equivalent to the rank of Gazetted Officer of Government to be Estate Officer for the purpose of the said Act. who shall exercise the powers conferred and perform the duties imposed on Estate Officer by or under the said Act, within the local limits of his jurisidiction in respect of the public premises specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table :

TABLE

Designation of the Officer	Categories of public premises and local limits of the jurisdiction
(1)	(2)
Administrative Officer-I, Master Control Facility, Department of Space, Hassan, Karnataka	(1) Premises of Master Control Facility Complex at Hassan in Survey Nos. 119, 13 & 52 of Kenchamaranahalli in Hassan District. Boundaries : Hassan Halebid road on North Monje Muganahalli on South Govindapura on West. Remaining area of S. No. 119 on East. (2) Premises in the Department of Space Housing Colony in Survey Nos. 22 & 24 of Monje Harlahalli in Hassan District. Boundaries : Monje Chikkuharanahalli to East S. No. 21035 to North S. No. 34, 2528, 26 & 27 and Koppalu to West. S. No. 65 to South.

[No. 9/2(2)/82-III]

K.R. RAMNATH, Under Secy.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 16 अगस्त, 1982

का०आ० 3115.—केन्द्रीय सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उप-नियम (4) के अनुसरण में, निम्नलिखित कार्यालयों को, जिनके कर्मचारीवृन्द ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है :—

(1) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लि०, बम्बई (सूचना और प्रसारण मंत्रालय के नियंत्रणाधीन एक उपक्रम)।

(2) क्षेत्रीय कार्यालय, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लि०, नई दिल्ली।

[संख्या ई०-11011/5/82-हिन्दी]

इन्दु भूषण कर्ण, अवर सचिव

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

New Delhi, the 16th August, 1982

S.O. 3115.—In pursuance of sub-rule (4) of Rule 10 of the Official Language (Use for Official Purposes of the Union) Rules, 1976, the Central Government hereby notifies the following offices, the staff whereof have acquired the working knowledge of Hindi :—

(1) National Film Development Corporation Ltd., Bombay (An Undertaking under the control of the Ministry of Information and Broadcasting).

(2) Regional Office, National Film Development Corporation Ltd., New Delhi.

[No. E-11011/5/82-Hindi]

I. B. KARN, Under Secy.

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय

(पुनर्वास विभाग)

नई दिल्ली, 30 जुलाई, 1982

का० आ० 3116.—निष्क्रान्त सम्पत्ति प्रशासन अधिनियम, 1950 (1950 का 31) की धारा 55 की उपधारा (3) द्वारा महा अभिरक्षक के रूप में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं इस के द्वारा इस विभाग की दिनांक 30 जुलाई, 1982 की अधिसूचना सं० 1(14)/विशेष सैल/82-एसएस-II (क) द्वारा हरियाणा राज्य के लिए नियुक्त सहायक महा अभिरक्षक निष्क्रान्त सम्पत्ति को महा अभिरक्षक की निम्नलिखित शक्तियां सौंपता हूं :—

(1) अधिनियम की धारा 24 और 27 के अधीन शक्तियां।

(2) अधिनियम की धारा 10(2)(0) के अधीन किसी भी निष्क्रान्त सम्पत्ति के हस्तांतरण के अनुमोदन की शक्तियां।

(3) निष्क्रान्त सम्पत्ति प्रशासन (केन्द्रीय) नियमावली, 1955 के नियम 30-क के अधीन मामलों के हस्तांतरण की शक्तियां।

इससे अधिसूचना सं० 1(8)/विशेष सैल/77-एसएस-II(ख) दिनांक 11 फरवरी, 1982 का अधिक्रमण किया जाता है।

[सं० 1(14)/विशेष सैल/82-एसएस-II(ख)]

एस० के० बसु, महा अभिरक्षक

MINISTRY OF SUPPLY AND REHABILITATION

(Department of Rehabilitation)

New Delhi, the 30th July, 1982

S.O. 3116.—In exercise of the powers conferred on me as Custodian General by sub-section 3 of Section 55 of the Administration of Evacuee Property Act, 1950 (31 of 1950), I do hereby delegate to the Assistant Custodian General for the State of Haryana, appointed vide Notification No. 1(14)/Spl. Cell/82-SS-II(A), dated the 30th July, 1982, the following powers of the Custodian General :—

(i) Powers under Section 24 and 27 of the Act.

(ii) Powers of approval of transfer of any evacuee property under Section 10(2)(0) of the Act.

(iii) Powers of transfer of cases under Rule 30-A of the Administration of Evacuee Property (Central) Rules, 1955.

This supersedes Notification No. 1(8)/Spl.-Cell/77-SS.II (B) dated the 11th February, 1982.

[No. 1(14)/Spl. Cell/82-SS.II(B)]

S. K. BASU, Custodian General

श्रम मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 19 जुलाई, 1982

का०आ० 3117.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में स्टील आथोरिटी आफ इंडिया लि० के राउरकेला स्टील प्लांट के प्रबन्धतन्त्र से सम्बद्ध एक औद्योगिक विवाद नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच विद्यमान है,

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है,

अतः, केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7क और धारा 10 की उप-धारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री जे०एम० महापात्रा होंगे, जिनका मुख्यालय भुवनेश्वर में होगा और उक्त विवाद को उक्त अधिकरण को न्याय निर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

"क्या स्टील अथोरिटी आफ इंडिया लिमिटेड के अधीन राउरकेला स्टील प्लांट के प्रबन्ध तन्त्र की श्री अनख प्रसाद राय, लायब्रेरियन-भंडार सहायक, बरसुआ आयरन माईन्स को सेवा की अवधि का लाभ व लिंकड पर्सनल ग्रेड योजना न देने की कार्रवाई न्यायोचित है ? यदि नहीं तो कामगार किस अनुतोष का हकदार है ?"

[सं० एल० 29012/12/81-डी०बी०/III(B)]

कंवर राजिन्द्र सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF LABOUR

ORDER

New Delhi, the 19th July, 1982

S.O. 3117.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Rourkela Steel Plant of Steel Authority of India Limited, and their workmen in respect of the matter specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 7A, and clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri J. M. Mahapatra shall be the Presiding Officer, with headquarters at Bhubaneshwar and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Rourkela Steel Plant, Steel Authority of India Limited, in not giving the benefit of services, linked personal grade schemes to Shri Alekh Prasad Ray, Librarian-cum-Stores Assistant, Barsua Iron Mines is justified ? If No, to what relief is the concerned workmen entitled ?".

[No. L-29012/12/81-D.III(B)]

New Delhi, the 16th August, 1982

S.O. 3118.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Resident Chief Executive, Duliajan, Assam and three others and their workmen which was received by the Central Government on 10th August, 1982.

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL, CALCUTTA

Reference No. 3 of 1982

PARTIES :

Employers in relation to the management of :

1. Resident Chief Executive, Oil India Limited, Duliajan, P.O. Duliajan, Assam.
2. Messrs Duliajan Commercial Co-operative Society Limited, Contractors, Oil India Limited, Duliajan, Assam.
3. Messrs Kheremia Samabai Samity Limited, Contractors, Oil India Limited, Duliajan.
4. Messrs Singh Brothers and Co. Contractors, Oil India Limited, Duliajan, Assam.

AND

Their Workmen.

PRESENT :

Mr. Justice M. P. Singh—Presiding Officer.

STATE : Assam INDUSTRY : Oil

AWARD

By Order No. L-30011/10/80-D.III(B) dated 15 January, 1982 the Government of India, Ministry of Labour, sent an industrial dispute existing between the managemtnt of Resident Chief Executive, Oil India Limited, Duliajan, Assam and three others and their Workmen, to this Tribunal for adjudication. The dispute mentioned in the Schedule to the Order of Reference reads as :

"Whether the non-employment of Shri Anil Das engaged by the Resident Chief Executive, Oil India Limited, Duliajan through Messrs Duliajan Commercial Co-operative Society Limited, Contractors, Oil India Limited, Duliajan from the 11th June, 1979 is justified ? If not to what relief is the workman entitled ?"

"Whether non-employment of Sarvashri Balli Dass, Ranjan Dev and Kartick Nag workmen engaged by Resident Chief Executive Oil India Limited, Duliajan through Messrs Singh Brothers, Contractors, Oil India Limited, Duliajan from the 18th October, 1979, the 1st May, 1979 and the 1st July, 1979 respectively is justified ? If not to what relief these workmen entitled ?"

"Whether non-employment of Shri Kanai Das engaged by Resident Chief Executive, Oil India Limited, Duliajan through Messrs Kheremia Samabai Samiti Limited, Contractors Oil India Limited, Duliajan from the 30th June, 1979 is justified : If not, to what relief is the workman entitled ?"

2. On receipt of the reference due notices were served upon the parties for submission of their respective written statement. But instead of submitting any written statement the parties negotiated the matter amongst themselves and arrived at a settlement and sent copies of such settlement to this Tribunal to record the same and to pass a "No dispute" award in terms of the said settlement. I have gone through the settlement and find the same to be legal and genuine.

3. In the result, I pass a "No dispute" award as prayed for by the parties in terms of the settlement which will form part of this Award as Annexure "A".

Dated, Calcutta, the 30th July, 1982.

M. P. SINGH, Presiding Officer

ANNEXURE 'A'

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL, CALCUTTA

In the Matter of :

An Industrial Dispute under Government order of Refrrence No. 3 of 1982

BETWEEN

1. Resident Chief Executive, Oil India Limited, Duliajan, Assam.
2. M/s. Duliajan Commercial Co-operative Society Limited, Duliajan.
3. M/s. Kheremia Samabai Samity Limited, Duliajan.
4. M/s. Singh Brothers and Co., Contractors, Oil India Limited, Duliajan, Assam.

AND

Their workmen represented by the Oil India Contractor's Workers' Association, Duliajan.

The humble petition of the above-named Association most respectfully—

SHEWETH :

1. The above Reference No. 3 of 1982 was taken out at the instance of the workmen represented herein by the Oil India Contractor's Workers' Association, Duliajan, the Association abovenamed.

2. Sometime after the Reference, parties enterd into negotiations as a result whereof the workman represented by the said Oil India Contractor's Workers' Association, Duliajan, decided not to further prosecute the present adjudication.All the disputes and differences inter se the parties in respect of the adjudication under reference have been finally set at rest.

3. The Association accordingly submits that it would be just and proper to make a non-dispute award as the Association is not willing to contest the Reference.

4. It has been ascertained that the Resident Chief Executive, Oil India Ltd., Duliajan, M/s. Duliajan Commercial Co-operative Society Ltd., Duliajan, M/s. Kheremia Samabai Samity Ltd., Duliajan, and M/s. Singh Brothers and Co. Contractors Oil India Ltd., Duliajan, Assam have no objection to the prayer being granted.

5. This application is made bonafide and in interest of justice. In the premises your petitioners humbly pray that your Honour will graciously he pleased to pass a no dispute award and answer accordingly this reference and pass such other order as may appear fit and proper to your Honour.

And your petitioners as in duty bound shall everpray.
(NIRPEN BARUAH)

For M/s. Duliajan Commercial Co-operative Society, Duliajan
(PRATAP HAZARIKA)

For M/s. Kheremia Samabai Samity
Duliajan
(ANANDA BEZBARUAH)

Industrial Relations Manager

For Resident Chief Executive,

Oil India Liimted.
(SHYAM BAHADUR SINGH)

For M/s. Singh Brothers and Co., Duliajan
(KSHITISH SARKAR)

For Oil India Contractors' Workers' Association, Duliajan.

[No. L-30011/10/80-D.III(B)]

New Delhi, the 18th August, 1982

S.O. 3119.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following Award of the Central Government Industrial Tribunal, Bombay in the industial dispute between the employers in relation to the management of M/s. Chowgule and Co. Pvt. Ltd. and their workman, which was received by the Central Government on 10th August, 1982.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 2 BOMBAY

Reference No. CGIT-2/25 of 1981

PARTIES :

Employers in relation to the management of M/s. Chowgule and Co. Pvt. Ltd.,

AND

Their workmen.

APPEARANCES :

For the Employers—Shri D. P. Sinha, Manager, Industrial Relations.

For the Workmen—No appearance.

INDUSTRY : Mines STATE : Goa, Daman and Diu

Bombay, the 2nd August, 1982

AWARD

By their order No. L-29012/28/80-D-III(B) dated 30-9-1981/3-10-81 the Central Government has referred the following dispute for adjudication under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 :—

"Whether the management of M/s. Chowgule and Co. Pvt. Ltd., is justified in terminating the services of Shri Raghunath Masurkar Watchman working at Gavanem Mines, when the union raised an industrial dispute demanding his confirmation, if not, what relief the workman is entitled to ?"

2. The dispute as is evident from the reference relates to one Shri Raghunath Masurkar alleged to be in the service of M/s. Chowgule and Co. Pvt. Ltd., as a Watchman working at Gavanem mines, whose services, it is alleged, were terminated by the management illegally. It appears that the dispute is espoused by the Union but after the reference was made, neither the alleged workman nor the Union showed interest in the reference and despite notice they remained all along absent.

3. Against this it is the contention of the management that Masurkar was never in their service or employed by them as a watchman but being a resident of a place where the company had constructed certain quarters for their employees, after the mines were closed sometime in the year 1978, Shri Raghunath Masurkar was asked to look after those quarters on a consideration of Rs. 300 per month and that when it was found that no useful purpose was being served by appointing a caretaker at Gavanem, the contract was terminated with effect from 6th October, 1980.

4. Of course when once Rs. 300 per month were being paid to Shri Masurkar the question would arise whether what was being paid was wages or by way of contract money and if the finding was in favour of wage the relationship of workman and employer would stand established. Yet for the said purpose some assertion on the part of the workman was necessary which the Union or the workman has failed to do. There is therefore on record only the written statement filed by the management denying the very relationship of employer-employee subsisting between the parties and since there is no statement of claim on behalf of the Union or the workman repudiating these allegations requiring clear proof the only course left is to hold the said relationship not established with the result when the contract was terminated, no grievance can be made out. The findings therefore which is to be noted is that the same is justified with the result the workman concerned would not be entitled to any relief. The reference therefore fails. No order as to costs.

M. A. DESHPANDE, Presiding Officer

[No. L-29012/28/80-D.III B]

S.O. 3120.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Bombay in the industrial dispute between the employers in relation to the management of M/s. Shantilal Khushaldas & Bros. Pvt., Gosalia Building, Margao, Goa and their workmen, which was received by the Central Government on 17th August, 1982.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 2 BOMBAY

Reference No. CGIT-2|16 of 1982

PARTIES :

Employers in Relation to the Management of M/s. Shantilal Khushaldas & Bros. Pvt. Ltd., Gosalia Building, Margao, Goa.

Vs.

Their Workmen

APPEARANCES :

For the Employers—No appearance

For the workmen—No appearance

STATE : Goa, Daman and Diu INDUSTRY : Mining

Bombay, dated the 3rd August, 1982

AWARD

By their order No. L-29011/50/81-D.III(B) dated 15-2-1982 the following dispute has been referred for adjudication under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes :—

"Whether the action of the maangement of M/s. Shantilal Khushaldas & Bros. Pvt. Ltd., in relation to their Thatodi Iron Ore Mine, Goa in dismissing Shri Narayan Parulekar, Mechanic Helper from service is justified. If not, to what relief is the workman entitled?"

2. Although the matter is repeatedly being adjourned for the statement of claim and although at one stage some proposal of compromise was made by the Union, who is espousing the cause of the workman, statement of claim in support of the demand never materialised with the result that on behalf of the Union there is absolutely nothing to substantiate the reference and the cause pleaded. Against this the management has put in their written statement dated 14-7-1982 contending that since no claim statement has been filed the reference cannot be proceeded and the same deserved to be disposed of. There is great force in this say of the management that despite several adjournments to get the statement of claim on record the Union never cared to file the same, the only conclusion possible is that neither the Union nor the workman is interested in prosecuting the proceedings.

The reference therefore is rejected.

No order as to costs.

5-8-1982.

M. A. DESHPANDE, Presiding Officer.

[No. L-29011/50/81-D.III(B)]

KANWAR RAJINDER SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 21 अगस्त, 1982

का०आ० 3121—चूना पत्थर और डोलोमाइट खानश्रम कल्याण अधिनियम, 1973 के नियम (3) के उप-नियम (1) के साथ पठित चूना पत्थर और डोलोमाइट खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1972 की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार भारत के राजपत्र, भाग दो, खंड 3, उप-खंड (II) तारीख 31 अक्तूबर 1981 के पृष्ठ 3583 पर प्रकाशित भारत सरकार, श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का०आ० 3005 तारीख 15 अक्तूबर, 1981 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, क्रमांक 5(ii) और 5(v) के सामने निर्दिष्ट प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

5(ii) श्री आर० एस० शास्त्री,
वि बिसरा स्टोन लाइम कम्पनी लिमिटेड,
पो० बाक्स नं० 46,
चार्टरड बैंक बिल्डिंग,
कलकत्ता-700001।

5(v) श्री सी०एस० ब्रह्मा,
प्रबंध निदेशक,
नार्थ बंगाल डोलोमाइट लिमिटेड,
नीलम्बर हाउस,
28 बी, शेक्सपियर सारणी,
कलकत्ता।

[फाइल सं० यू-23018/10/80-एम०वी०]

टी० डी० सलहोत्रा, अवर सचिव

New Delhi, the 21st August, 1982

S.O. 3121.—In pursuance of the powers conferred by section 7 of the Limestone and Dolomite Mines Labour Welfare Fund Act, 1972 (62 of 1972) read with sub-rule (1) of rule 3 of the Limestone and Dolomite Mines Labour Welfare Fund Rules, 1973, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification number S.O. 3005 dated the 15th October, 1981, of the Government of India in the Ministry of Labour published at pages 3583 to 3584 of the Gazette of India, Part-II Section 3, Sub-section (ii) dated 31st October, 1981, namely :—

In the said notification, for the entries against serial numbers 5(ii) and 5(v), the following shall respectively be substituted namely :—

"5(ii) Shri R. S. Sastry,
The Bisra Stone Lime Company Limited,
Post Box No. 46,
Chartered Bank Building,
Calcutta-700001.

"5(v) Shri C. S. Brahma,
Managing Director,
North Bengal Dolomite Limited,
Neelambar House,
28B, Shakespeame Sarani,
Calcutta-17."

[F. No. U-23018/10/80-M.V.]

T. D. SALHOTRA, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 17 जुलाई 1982

का०आ० 3122—इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट औद्योगिक विवाद श्री बी० प्रसाद राव, पीठासीन अधिकारी, औद्योगिक अधिकरण, हैदराबाद के समक्ष लंबित है,

और श्री बी० प्रसाद राव की सेवाएं अब उपलब्ध नहीं रह गई हैं;

अतः, केन्द्रीय सरकार औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947

का 14) की धारा 33-ख की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 7-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री एस०वी० रामन रैड्डि होंगे, जिनका मुख्यालय हैदराबाद में होगा और उक्त श्री बी० प्रसाद राव पीठासीन अधिकारी, औद्योगिक अधिकरण, वरंगल के समक्ष लंबित उक्त विवादों से सम्बद्ध कार्यवाहियों को वापस लेती है और उसे श्री एस०वी० रामन रैड्डी, पीठासीन अधिकारी, औद्योगिक अधिकरणी हैदराबाद को इस निदेश के साथ अन्तरित करती है कि उक्त अधिकरण आगे कार्यवाही उस प्रक्रम से करेगा जिस पर वह उसे अन्तरित की जाएं तथा विधि के अनुसार उनका निपटान करेगा।

अनुसूची

क्रमांक आई०डी० संख्या	आदेश सं० और तारीख	पक्षकारों के नाम
1	2	3	4
1.	आई०डी०सं० 8/80	भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली का आदेश सं० एल-21011/18/79-डी-IV बी तारीख 7-7-1980	एस० सी० कम्पनी लि०, येलेन्दू खम्माम जिला के प्रबन्धतंत्र और कर्मकार।
2.	आई०डी०सं० 14/80	भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली का आदेश सं० एल-12011/47/79-डी-II ए, तारीख 3-10-1980	सिंडीकेट बैंक और 10 अन्य बैंकों का प्रबन्धतन्त्र और कर्मकार।
3.	आई०डी०सं० 20/80	भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली का आदेश सं० एल-12012/12/80-डी-4 बी तारीख 15-12-80	एस० सी० कम्पनी लि०, कोठागुडम का प्रबन्धतंत्र और कर्मकार।
4.	आई०डी० सं० 3/80	भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली का आदेश सं० एल-21011/13/80-डी-4 बी तारीख 13-3-81	एस०सी० कम्पनी लि०, बैलामपल्ली डिवीजन II आदिलाबाद जिला (आ०प्र०) का प्रबन्धतंत्र और कर्मकारी।
5.	आई०डी० सं० 4/81	भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली का आदेश सं० एल-13011/1/78-डी-2 बी तारीख 31-3-81	छावनी बोर्ड, सिकन्दराबाद का प्रबन्धतंत्र और कर्मकार।
6.	आई० डी० सं० 7/81	भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली का आदेश सं० एल-12012/265/80-डी-2 ए तारीख 22-4-81	यूनियन बैंक आफ इंडिया, विजयवाडा का प्रबंधतंत्र और कर्मकार।
7.	आई०डी० सं० 10/81	भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली का आदेश सं० एल-34011/2/81-डी-4 ए तारीख 5-6-81	विशाखापटनम पोर्ट ट्रस्ट, विशाखापटनम का प्रबन्धतंत्र और कर्मकार।
8.	आई०डी०सं० 13/81	भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली का आदेश सं० एल-17012/6/81-डी-4 ए तारीख 29-6-81	भारतीय जीवन बीमा, निगम, हैदराबाद का प्रबन्धतंत्र और कर्मकार।
9.	आई०डी० सं० 15/81	भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली का आदेश सं० एल-13011/3/80-डी-3 बी तारीख 29-7-81	तेल और प्राकृतिक गैस आयोग, राजामुन्दरी का प्रबन्धतंत्र और कर्मकार।
10.	आई०डी० सं० 16/81	भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली का आदेश सं० एल-12012/253/80-डी-2ए तारीख 1-8-81	भारतीय स्टेट बैंक, हैदराबाद (कंकिनाडा शाखा) का प्रबन्धतंत्र और कर्मकार।
11.	आई०डी० सं० 17/81	भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली का आदेश सं० एल-12011/41/80-डी 2ए तारीख 30-7-81	भारतीय स्टेट बैंक, हैदराबाद का प्रबन्धतंत्र और कर्मकार।
12.	आई०डी० सं० 21/81	भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली का आदेश सं० एल-42012/26/77-डी-2 बी तारीख 21-2-81	भारतीय खाद्य निगम, टाडेपल्लीगुडेम का प्रबन्धतंत्र और कर्मकार।
13	आई०डी०सं० 24/81	भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली का आदेश सं० एल-21025/1/80-डी-4 बी तारीख 29-9-81	एस०सी० कम्पनी लि०, सोमागुडम डिवीजन 1 का प्रबन्धतंत्र और कर्मकार।
14.	आई०डी० सं० 25/81	भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली का आदेश सं० एल-21012/4/81-डी-4 बी तारीख 16-10-81	एस०सी० कम्पनी लि०, बेलमपल्ली डाकघर आदिलाबाद जिला (आ० प्र०) का प्रबन्धतंत्र और कर्मकार।
15.	आई०डी०सं० 27/81	भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली का आदेश सं० एल-21011/8/81-डी-4 बी तारीख 31-10-81	एस०सी० कम्पनी लि०, कोठागुडेम का प्रबन्धतंत्र और कर्मकार।
16.	आई०डी०सं० 28/81	भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली का आदेश सं० एल-12012/44/81-डी-2 ए, तारीख 6-11-81	आन्ध्र बैंक, हैदराबाद का प्रबन्धतंत्र और कर्मकार।

1	2	3	4
17.	आई०डी० सं० 30/81	भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली का आदेश सं० एल-12012/118/81-डी-2 ए तारीख 28-11-81	—यथोक्त—
18.	आई०डी० सं० 31/81	भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली का आदेश सं० एल-21012/8/81-डी-4 बी तारीख 1-12-81	एस०सी० कं० लि०, बेलमपल्ली डिवीजन-II का प्रबन्धतंत्र और कर्मकार ।
19.	आई०डी० सं० 1/82	भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली का आदेश सं० एल-21012/5/81-डी-4 बी तारीख 15-1-82	मैसर्स एस०सी०कं० लि०, बेलमपल्ली क्षेत्र, आदिलाबाद जिला का प्रबन्धतंत्र और कर्मकार
20.	आई०डी० सं० 2/82	भारत सरकार, श्रम मंत्रालय नई दिल्ली का आदेश सं० एल-21011/13/81-डी-4 बी तारीख 2-2-82	एस०सी० कं० लि०, बेलमपल्ली का प्रबन्धतंत्र और कर्मकार
21.	आई०डी० सं० 3/82	भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली का आदेश सं० एल-21011/9/81-डी-4 बी तारीख 3-2-82	—यथोक्त—
22.	आई०डी० सं० 5/82	भारत सरकार, श्रम मंत्रालय नई दिल्ली का आदेश सं० एल-21012/2/81-डी-4 बी तारीख 18-1-82	एस०सी० कं० लि० मंजमरी एंड रामकृष्णपुर क्षेत्र, आदिलाबाद का प्रबन्धतंत्र और कर्मकार ।
23.	आई०डी०सं० 6/82	भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली का आदेश सं० एल-21011/15/81-डी-4 बी तारीख 23-1-82	एस० सी० कं० लि०, रामागुंडम डिवीजन-II गोदावरी खानी जिला, करीमनगर, का प्रबन्धतन्त्र और कर्मकार।
24.	आई०डी० सं० 7/82	भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली का आदेश सं० एल-21011/10/81-डी-4 बी तारीख 15-2-82	एस०सी० कं० लि०, बेलमपल्ली का प्रबंधतंत्र और कर्मकार ।
25.	आई०डी०सं० 8/82	भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली का आदेश सं० एल-21012/14/81-डी-4 बी तारीख 16-2-82	एस० सी० कं०, बेलमपल्ली लि०-I का प्रबन्धतंत्र और कर्मकार ।
26.	आई०डी० सं० 9/82	भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली का आदेश सं० एल-12011/41/81-डी-4 ए तारीख 19-2-82	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद का प्रबन्धतंत्र और कर्मकार ।
27.	आई०डी० सं० 10/82	भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली का आदेश सं० एल० 21012/10/81-डी-4 बी तारीख 20-2-82	एस०सी० कं०, लि० कोठागुडम (आ० प्रदेश) खम्माम जिला का प्रबंधतंत्र और कर्मकार ।
28.	आई०डी० सं० 11/82	भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली का आदेश सं० एल-21011/14/81-डी-4 बी तारीख 20-2-82	एस० सी० कं० लि०, गोदावरीखानी, करीमनगर (आ० प्रदेश) का प्रबन्धतंत्र और कर्मकार ।
29.	आई०डी०सं० 12/82	भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली का आदेश सं० एल०-21011/1/81-डी-4 बी तारीख 27-2-82	एस० सी० कं० लि०, रामागुंडम डिवीजन-II का प्रबंधतंत्र और कर्मकार ।
30.	आई० डी० सं० 13/82	भारत सरकार, श्रम मंत्रालय नई दिल्ली का आदेश सं० एल०-12012/188/81-डी० 4ए० तारीख 3-3-82	भारतीय स्टेट बैंक, हैदराबाद का प्रबंधतंत्र और कर्मकार
31.	आई० डी० सं० 14/82	भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली का आदेश सं० एल०-29011/3/81-डी० 3 बी० तारीख 20-3-82	मै० बेरियम कैमिकल्स लि०, कोठागुडम खम्माम जिला (आंध्र प्रदेश) का प्रबंधतंत्र और कर्मकार
32.	आई० डी० सं० 15/82	भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली का आदेश सं० एल०-34012/3/81-डी० 4ए० दिनांक 23-3-82	विशाखापटनम पत्तन ग्यास, विशाखापटनम का प्रबंधतंत्र और कर्मकार
33.	आई० डी० सं० 16/82	भारत सरकार, श्रम मंत्रालय नई दिल्ली के आदेश सं० 20011/16/81-डी० 4 बी० तारीख 23-3-82	एस० सी० कं० लि० कोठागुडम खम्माम जिला (आन्ध्र प्रदेश) का प्रबंधतंत्र और कर्मकार
34.	आई० डी० सं० 17/82	भारत सरकार, श्रम मंत्रालय नई दिल्ली का आदेश सं० एल० 42011/7/81-ए० सी० आई० डी० 4-ख० ता० 26-3-82	भारतीय खाद्य निगम जिला कैरलोर, (आन्ध्र प्रदेश) का प्रबंधतंत्र और कर्मकार।
35.	आई० डी० सं० 18/82	भारत सरकार, श्रम मंत्रालय नई दिल्ली का आदेश सं० एल-12011/20/81-डी० 4 बी० तारीख 13-4-82	एस० सी० क० लि० कोठागुडम, खम्माम जिला (आन्ध्र प्रदेश) का प्रबंधतंत्र और कर्मकार ।
36.	आई० डी० सं० 19/82	भारत सरकार, श्रम मंत्रालय नई दिल्ली का आदेश सं० एल०-21011/81-डी० 4 बी० तारीख 20-4-82	एस० सी० कं० लि० बेलमपल्ली डिवीजन-1, आदिलाबाद जिला का प्रबंधतंत्र और कर्मकार ।

1	2	3	4
37.	आई० डी० सं० 20/82	भारत सरकार श्रम मंत्रालय नई दिल्ली का आदेश सं० 21012/2/82-डी० 4-बी० तारीख 23-4-82	मैसर्स एस० सी० कं० लि० बेलागुडम डिवीजन-I गोदावरीखानी का प्रबंधतंत्र और कर्मकार।
38.	आई० डी०	भारत सरकार, श्रम का मंत्रालय नई दिल्ली आदेश सं० एल० 42011/27/81-डी० 4 ए० तारीख 13-5-82	भारतीय खाद्य निगम नालगोंडा का प्रबंधतंत्र और कर्मकार।

केन्द्रीय सरकार की लंबित विविध याचिकाएं

1	2	3	4
1	आई० डी० सं० 12/79 में वि० या० 111/80	डिविजनल अध्यक्ष, एस० सी० कं० लि० येलेन्दु, जिला येलेन्दु	बनाम श्री डी० सोमेश, कोल फिलर गेंग सं० 1 डी०, पालमपल्ली खान डाक घर येलुन्दु
2.	आई० डी० सं० 12/79 में वि० या० सं० 98/81	एस० सी० कं० लि०, मानुगुरु का प्रबंधतंत्र	बनाम श्री सहीबोइना वेंकटी, कोल पिलर पी० के०-2 इन्क्लाइन मानुगुरु।
3.	आई० डी० सं० 18/71 में वि० या० सं० 116/81	आन्ध्र प्रदेश, सुलतान बाजार का प्रबंधतंत्र	बनाम श्री जे० दक्षिणमूर्ति 2, इंकलाइन, संपतनगर गुंटुर 522004
4.	आई० डी० सं० 18/71 में वि० या० सं० 118/81	आंध्र बैंक सुल्तान बाजार का प्रबंधतंत्र	बनाम श्री एल० पांडुरंगाराव, गणेश बस्ती कोठागुडम, खम्माम जिला।
5.	आई० डी० सं० 11/81 में वि० या० सं० 117/81	एस० सी० के० लि० बैलमपल्ली जिला आदिलाबाद के कर्मकार।	बनाम एस० सी० के० बेलमपल्ली का प्रबंधतंत्र
6.	आई० डी० सं० 14/80 में वि० या० सं० 6/82	सिंडीकेट बैंक और 10 अन्य बैंकों के कर्मकार	बनाम वैश्य बैंक का प्रबंधतंत्र
7.	आई० डी० सं० 14/80 में वि० या० सं० 10/82	—यथोक्त—	बनाम आन्ध्र बैंक का प्रबंधतंत्र
8.	आई० डी० सं० 14/80 में वि० या० सं० 11/82	—यथोक्त—	बनाम स्टेट बैंक आफ हैदराबाद का प्रबंधतंत्र
9.	आई० डी० सं० 14/80 में वि० या० सं० 12/82	—यथोक्त—	बनाम इंडियन बैंक का प्रबंधतंत्र
10	आई० डी० सं० 14/80 में वि० या० सं० 14/82	सिंडिकेट बैंक और 10 अन्य बैंकों के कर्मकार	बनाम कनारा बैंक का प्रबंधतंत्र
11.	आई० डी० सं० 14/80 में वि० या० सं० 15/82	—यथोक्त—	बनाम भारतीय स्टेट बैंक का प्रबंधतंत्र
12	आई० डी० सं० 16/81 में वि० या० सं० 71/82	भारतीय स्टेट बैंक, हैदराबाद के कर्मकार	बनाम भारतीय स्टट बैंक, हैदराबाद का प्रबंधतंत्र
13	आई० डी० सं० 14/80 में वि० या० सं० 73/82	आंध्र-प्रदेश बैंक कमीशन एजेंटस यूनियन	बनाम आन्ध्र बैंक का प्रबंधतन्त्र
14.	आई० डी० सं० 14/80 में वि० या० सं० 14/82	—यथोक्त—	बनाम विजय बैंक का प्रबंधतंत्र
15.	आई० डी० सं० 14/80 में वि० या० सं० 75/82	—यथोक्त—	बनाम स्टेट बैंक आफ हैदराबाद का प्रबंधतंत्र
16	आई० डी० सं० 14/80 में वि० या० सं० 76/82	—यथोक्त—	बनाम सिंडीकेट बैंक का प्रबंधतंत्र
17	आई० डी० सं० 11/80 में वि० या सं० 77/82	—यथोक्त—	बनाम वैश्य बैंक का प्रबंधतंत्र
18	आई० डी० सं० 98/81 में वि० या० सं० 80/82	एस० सी० के० लि० मानुगुरु के कर्मकार	बनाम एस० सी० के० लि०, मानुगुरु का प्रबंधतंत्र

[सं० एस०-11025(2)/82-डी० 4बी०]

ORDER

New Delhi, the 17th July, 1982.

S.O. 3122:—Whereas the Industrial disputes specified in the Schedule hereto annexed are pending before Shri B. Prasada Rao, the Presiding Officer, Industrial Tribunal, Hyderabad;

And Whereas the services of Shri B. Prasada Rao are no longer available;

Now, Therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A read with sub-section (1) of the section 33B of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal, the Presiding Officer of which shall be Shri S. V. Ramana Reddy with headquarters at Hyderabad and withdraws the proceedings in relation to the said disputes pending before the said Shri B. Prasada

Rao, Presiding Officer, Industrial Tribunal, Hyderabad and transfers the same to Shri S. V. Ramana Reddy, Presiding Officer, Industrial Tribunal, Hyderabad, with the direction that the said Tribunal shall proceed with the proceedings from the stage at which they are transferred to it and dispose of the same according to law.

SCHEDULE

Sl. No.	I. D. No.	Number & Date of the Order.	Name of the parties
1	2	3	4
1.	I.D. No. 8/80	Order No. L-21011 (18)/79-D. IV B dt. 7-7-80 from Govt. of India, Ministry of Labour, New Delhi.	Workmen and the management of S. C. Co. Ltd., Yellendu, Khammam Distt
2.	I.D. No. 14/80	Order No. L-12011/ 47/79. D. II. A dt. 3-10-80 from Govt. of India Ministry of Labour, New Delhi.	Workmen and the management of Syndicate Bank and 10 others Banks.
3.	I.D. No. 20/80	Order No. L-21012 (12)/80-D. IV B dt. 15-12-80 from Govt. of India, Ministry of Labour, New Delhi.	Workmen and the management of S.C. Co. Ltd., Kothagudem.
4.	I.D. No. 3/80	Order No. L-21011/ 13/80D. IV B. dt. 13-3-81 from Govt of India, Ministry of Labour, New Delhi.	Workmen and the management of S.C. Co. Ltd., Bellampelli Divi. II, Adilabad Distt. (A.P.).
5.	I.D. No. 4/81	Order No. L-12011/ 1/78-D. II B. dt. 31-3-81, from Govt. of India, Ministry of Labour, New Delhi.	Workmen and the management of Cantonment Board, Secunderabad.
6.	I.D. No. 7/81	Order No. L-12012 (265)/80-D. II. A, dt. 22-4-81 from Govt. Of India, Ministry of Labour New Delhi.	Workmen and the management of Union Bank of India, Vijayawada.
7.	I.D. No. 10/81	Order No. L-34011 (2)/81-D. IV A, dt. 5-6-81, from Govt. of India, Ministry of Labour, New Delhi	Workmen and the management of Visakhapatnam Port Trust, Visakhapatnam.
8.	I.D. No. 13/81	Order No. L-17012 (6)/81-D.IV A, dt. 29-6-81, from Govt. of India, Ministry of Labour, New Delhi	Workmen and the management of Life Insurance Corporation of India, Hyderabad.
9.	I.D. No. 15/81	Order No. L-30011/ 3/80-D. III. B, dt. 29-7-81, from Govt, of India, Ministry of Labour, New Delhi.	Workmen and the management of Oil and Natural Gas Commission, Rajahmundry.
10.	I.D. No. 16/81	Order No. L-12012/ 253/80-D. II. A, dt. 1-8-81, from Govt. of India, Ministry of Labour, New Delhi.	Workmen and the management of State Bank of India Hyderabad. (Kakinada Branch)
11.	I.D. No. 17/81	Order No. L-12011/ 41/80-D.II. A, dt. 30-7-81, from the Govt. of India, Ministry of Labour, New Delhi.	Workmen and the management of State Bank of India, Hyderabad.
12.	I.D. No. 21/81	Order No. L-42012 (26)/77-D. II. B, dt, 21-2-81, from Govt. of India, Ministry of Labour, New Delhi.	Workmen and the management of Food Corporation of India, Tedepalligudem.
13.	I.D. No. 24/81	Order No. L-21025/ 1/80-D.IV B, dt. 29-9-81, from Govt. of India, Ministry of Labour, New Delhi.	Workmen and the management of S.C. Co. Ltd., Somagundam Division-I.
14.	I.D. No. 25/81	Order No. L-21012/ 4/81-D. IV B. dt. 16-10-81, from Govt. of India, Ministry of Labour, New Delhi.	Workmen and the management of S.C. Co. Ltd., Bellampalli Post Office Adilabad Distt. (A.P.).
15.	I.D. No. 27/81	Order No. L-21011/ 8/81- D. IV B, dt. 31-10-81, from Govt. of India, Ministry of Labour, New Delhi	Workmen and the management of S.C. Co. Ltd., Kothagudem.
16.	I.D. No. 28/81	Order No. L-12012/ 44/81-D. II A, dt. 6-11-81, from Govt. of India, Ministry of Labour, New Delhi.	Workmen and the management of Andhra Bank, Hyderabad.
17.	I.D. No. 30/81	Order No. 12012/ 118/81-D. II. A, dt. 28-11-81, from Govt. of India, Ministry of Labour, New Delhi.	Workmen and the management of Andhra Bank, Hyderabad.
18.	I.D. No. 31/81	Order No. L-21012/ 8/81-D. IV B, dt. 1-12-81, from Govt. of India, Ministry of Labour, New Delhi.	Workmen and the management of S.C. Co. Ltd., Bellampalli Division-II.
19.	I.D. No. 1/82	Order No. L-21012/ 5/81-D. IV. B. dt. 15-1-82, from Govt. of India, Ministry of Labour, New Delhi.	Workmen and the management of M/s. S. C. Co. Ltd., Bellampalli Area, Adilabad District.

1	2	3	4
20.	I.D. No. 2/82	Order No. L-21011/13/81-D. IV. B., dt. 2-2-82, from Govt. of India, Ministry of Labour, New Delhi.	Workmen and the management of S.C. Co. Ltd., Bellampalli.
21.	I.D. No. 3/82	Order No. L-21011/9/81-D. IV. B. dt., 3-2-82, from Govt. of India, Ministry of Labour, New Delhi.	Workmen and the management of S.C. Co. Ltd., Bellampalli.
22.	I.D. No. 5/82	Order No. L-21012 (2)/81-D. IV B. dt., 18-1-82, from Govt. of India, Ministry of Labour, New Delhi.	Workmen and the management of S.C. Co. Ltd., Mandamari and Rama-Krishnapur Area, Adilabad.
23.	I.D. No. 6/82	Order No. L-21011/15/81-D. IV B., dt. 23-1-82, from Govt. of India, Ministry of Labour, New Delhi.	Workmen and the management of S.C. Co. Ltd., Ramagundam Div-II, Codavarikhani, Karim Nagar District.
24.	I.D. No. 7/82	Order No. L-21011/10/81-D. IV B., dt. 15-2-82, from Govt. of India, Ministry of Labour, New Delhi.	Workmen and the management of M/s. S.C. Co. Ltd., Bellampalli.
25.	I.D. No. 8/82	Order No. L-21012/14/81-D. IV. B., dt. 16-2-82, from Govt. of India, Ministry of Labour, New Delhi.	Workmen and the management of S.C. Co. Ltd., Bellampalli Divin-I.
26.	I.D. No. 9/82	Order No. L-12011 (41)/D. II. A, dt. 19-2-82, from Govt. of India, Ministry of Labour, New Delhi.	Workmen and the management of State Bank of Hyderabad.
27.	I.D. No. 10/82	Order No. L-21012/10/81-D. IV. B, dt. 20-2-82, from Govt. of India, Ministry of Labour, New Delhi.	Workmen and the management of S.C. Co. Ltd., Kothagudem, Khammam District (A.P.).
28.	I.D. No. 11/82	Order No. L-21011/(14)/81-D. IV B, dt. 20-2-82, from Govt. of India, Ministry of Labour, New Delhi.	Workmen and the management of S.C. Co. Ltd., Godavarikhani Karimnagar, Dist. (A.P.).
29.	I.D. No. 12/82	Order No. L-21011/1/81-D. IV. B, dt. 27-2-82, from Govt. of India, Ministry of Labour, New Delhi.	Workmen and the management of S.C. Co. Ltd., Ramagundam Divn. II.
30.	I.D. No. 13/82	Order No. L-12012/188/81-D. II A, dt. 3-3-82, from Govt. of India, Ministry of Labour, New Delhi.	Workmen and the management of State Bank of India, Hyderabad.
31.	I.D. No. 14/82	Order No. L-29011 (3)/81-D. III. B, dt. 20-3-82, from Govt. of India, Ministry of Labour, New Delhi.	Workmen and the manaegement of M/s. Barium Chemicals Ltd., Kothagudem, Khammam Dist. (A.P.).
32.	I.D. No. 15/82	Order No. L-34012/3/81-D. IV. A, dt. 23-3-82, from Govt. of India, Ministry of Labour, New Delhi.	Workmen and the Management of Visakhapatnam Port Trust, Visakhapatnam.
33.	I.D. No. 16/82	Order No. L-22011/(16)/81-D. IV. B, dt. 23-3-82, from Govt. of India, Ministry of Labour, New Delhi.	Workmen and the Management of S.C. Co. Ltd., Kothagudem, Khammam District (A.P.).
34.	I.D. No. 17/82	Order No. L-42011/7/81-FCI/D. IVA, dt. 26-3-82, from Govt. India, Ministry of Labour New Delhi.	Workmen and the Management of Food Corporation of India, Nellore Distt. (A.P.).
35.	I.D. No. 18/82	Order No. L-21011/20/81-D. IV B, dt. 13-4-82, from Govt. of India Ministry of Labour New Delhi.	Workmen and the Management of S.C. Co. Ltd., Kothagudem, Khammam District (A.P.).
36.	I.D. No. 19/82	Order No. L-21012/1/82-D. IV B, dt. 20-4-82 from Govt. of India, Ministry of Labour New Delhi.	Workmen and the Management of S.C. Co- Ltd. Bellampall Divin-I, Adilabad District.
37.	I.D. No. 20/82	Order No. 21012/2/82-D. IV. B. dt., 23-4-82, from Govt. of India, Ministry of Labour, New Delhi.	Workmen and the Management of M/s. S. C. Co. Ltd., Ramagundam Divn-I, Godavarikhani, Karimnagar Distt. (A.P.).
38.	I.D.No. ——	Order No. L-42011/27/81 D. IV. A, dt. 13-5-82, from Govt. of India, Ministry of Labour New Delhi.	Workmen and the Management of Food Corporation of India, Nalgonda.

CENTRAL GOVERNMENT'S PENDING MISCELLANEOUS PETITIONERS

1	2	3	4
1.	M.P. No. 111/80 in I.D.No. 12/79.	The Divisional Suparintandent, S.C. Co, Co. Ltd., Yellandu, Divn. P.O. Yellandu.	Vs. Sri D. Somaish, Coal Filler, Cang. No. 1B, Polampalli Mine, P.O. Yellandu.
2.	M.P. No. 98/81 in I.D. No. 12/79.	The Management of S.C. Co. Ltd., Manuguru.	Vs. Sri Sandiboina Venkati, Coal Filler, P. K. No. 2 Incline, Manuguru.
3.	M.P. No. 116/81 in I.D. No. 18/71.	The Management of Andhra Bank, Sultan Bazar.	Vs. Mr. J. Dakshina Murthy, 2nd line, Sampatinagar, Guntur-522004.
4.	M.P. No. 118/81 in I.D. No. 18/71.	The Management of Andhra Bank, Sultan Bazar.	Vs. Mr. L. Panduranga Rao, Ganesh Basti, Kothagudem, Khammam Distt.

2	3		4
5. M.P No. 117/81 in I D No 11/81	The Workmen of S.C Co Ltd, Ballampalli, Adilabad Dt.	VS	The Management of S. C. Co. Ltd, Ballampalli.
6. M.P. No. 6/82 in I.D No. 14/80	The Workman of Syndicate Bank & 10 other Banks	Vs	The Management of Vysya Bank.
7. M.P No 10/82 in I.D.No. 14/80	The Workmen of Syndicate Bank & 10 other Banks	Vs	The Management of Andhra Bank.
8. M.P No. 11/82 in I.D. No. 14/80	The Workm n of Sydnicate Bank & 10 other Banks.	Vs.	The Management of State Bank of Hyderabad.
9. M.P. No. 12/82 in I.D. No. 14/80	The Workmen of Syndicate Bank & 10 other Banks.	Vs.	The Management of Indian Bank.
10. M.P. No. 14/82 in I D No. 14/80	The Workmen of Sydincate Bank & 10 other Banks.	Vs.	The Management of Canara Bank.
11 M.P. No 15/82 in I.D. No. 14/80	The Workmen of Syndicate Bank & 10 other Banks.	Vs	The Management of State Bank of India.
12. M.P. No. 71/82 in I.D. No. 16/81	The Workman of State Bank of India, Hyderabad	Vs.	The Management of State Bank of India, Hyderabad.
13. M.P. No. 73/82 in I.D. No 14/80	A.P. Banks Commission Agants Union.	Vs.	The Management of Andhra Bank.
14. M.P. No. 74/82 in I D No. 14/80	A.P. Banks Commission Agents Union.	Vs.	The Management of Vijaya Bank.
15. M.P. No 75/82 in I.D No. 14/80	A P. Banks Commission Agents Union.	Vs	The Management of State Bank of Hyderabad.
16. M.P. No. 76/82 in I.D. No. 14/80	A.P. Banks Commission Agents Union.	Vs.	The Management of Syndicate Bank.
17. M.P. No 77/82 in I.D. No. 14/80	A.P. Banks Commission Agents Union.	Vs.	The Management of Vysya Bank.
18 M.P. No. 80/82 in I.D. No. 98/81	Workman of S.C. Co. Ltd, Manuguru	Vs	The Management of S.C. Company Ltd., Manuguru.

[No. S-11025(2)/82-D.IV(B)]

New Delhi, the 19th August, 1982

S.O. 3123—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Khottadih Colliery, and their workman, which was received by the Central Government and their workmen, which was received by the Central Government on the 17 August, 1982.

609 GI/82—11.

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL : CALCUTTA

Reference No. 47 of 1980

PARTIES

Employers in relation to the management of Khottadhi Colliery P O. Khottadia, Dt. Burdwan.

AND

Their Workman.

APPEARANCES

On behalf of Employers—Mr. R N. Tewari Deputy Personnel Manager.

On behalf of Workmen—Mr. R. Das Gupta Org. Secretary, with Mr. B.S. Azad, Genl. Secretary of the Union.

STATE : West Bengal INDUSTRY : Coal Mine

AWARD

By its Order No. L-19012 (14)/80-L. IV (B) dated 1st July 1980 the Government of India, Ministry of Labour, referred an industrial dispute existing between the employers in relation to the management of Khottadih Colliery and their workman to this Tribunal for adjudication. The dispute mentioned in the Scheduled to the order of reference reads as :—

"Whether the action of the management of Khottadih Colliery of Messrs Eastern Coalfields Limited, Post Office Khottadhi, District Burdwan, in superannuating Shri Udit Narayan Singh, Havildar on 30th December, 1979 is justified ? If not, to what relief is the concerned workman entitled ?"

2. The sole question involved in the case is whether the concerned workman Udit Narayan Singh, a Havildar was born on 1st July 1928 as alleged by him or he was aged 59 years on 12th December 1978 as found by the Appellate Medical Board, Sanctoria. This Havildar was appointed on 8-9-1958 at Ramnagar colliery in the permanent vacancy. He was superannuated with effect from 31st December 1979 on completion of 60 years age. In support of his case reliance has been placed on his behalf on the Identity Card, Ext. W-1, No. 26-1582 issued by the management: It is not possible to rely on this document. As against column "Date of Birth" the age is 59 years on 15-11-76 and then again the date of birth has been shown as 1-7-1928 as per CMPF record. The figure 1-7-1928 clearly seems to be an over-writting The words "as per CMPF record" also appear to be an over-writing. Below that expression there is something which appears to have been rubbed out. WW-1 Udit Narayan Singh says in his evidence that Mr. Chandra (probably he means the Labour Officer) disputed his signature on the identity card when it had been shown to him. The order-sheet of this case does not show that the concerned workman ever pressed for sending the signature of Mr. Chandra to be examined by any hand-writting expert. His identity card does not bear any seal. A portion of it has not been attested by any one I, therefore, do not rely upon Ext W-1, the identity card. My impression is that it has been forged and fabricated for the purposes of this case and that it should not have been filed or used in this case.

3. It was vehemently contended on behalf of the concerned workmen that Form A register which is maintained by the CMPF mentions the date of birth as 1st July 1928 and the same should be called for by this Tribunal. In my opinion it is not necessary to call for it at this stage when no prayer for the same was made earlier Any way, it will appear that the date of birth as mentioned in that register had been called by the Assistant Labour Commissioner (Central) by letter dated 16-11-1979 during the conciliation proceedings The Regional Commissioner, CMPF, Asansol sent a reply by letter dated 5th December 1979 which is Annexure 'K' to the written statement of the workmen. It is as follows

Office of the Regional Commissioner Coal Mines Provident Fund
Asansol.

CPF|56|Misc|Files|SRC. 7|365/3334

Asansol, the 10-12-1979

To

The Asstt. Labour Commissioner (Central)
Raniganj,
Dist. Burdwan.

Sub : Age in respect of Sri Udit Naryan Singh holding A/C No. B/391687

Sir,

With reference to your letter No. 1/108/79/alcr dated 16-11-79 I am to state that as per this office record (Form 'A') the member's age is 1st July 1928. The Form 'A' has been signed by C.L.W.O. of Kendra Colliery on 17-3-1959. We cannot confirm whether the signature of the C.L.W.O. in the form 'A' is genuine or not.

Yours faithfully,

Sd/-B. K. Sinha, Regional Commissioner 5-12-79

From the above it is obvious that it purports to have been signed by the C.L.W.O. on 17th March 1959 and it was not confirmed whether this signature was genuine or not. Its authenticity or genuineness cannot therefore be accepted. The circumstance shows that there has been some manoeuvering in the CMPF office. Udit Narayan Singh, Havildar was appointed by the management of Ramnagar Colliery on 8-9-58. A form B Register is admittedly maintained there in which the name, father's name and other particulars including the date of birth of the concerned workman are mentioned. WW-1 Udit Narayan Singh himself accepted in cross-examination that such a register is maintained by the management. This register has been produced in this case. The relevant entry concerning Udit Nrayan Singh is Sl. No. 1357 (Ext. M-7). In this entry the age of Udit Narayan Singh have been recorded as 59 years on 15th November 1976 as had been found on examination by the Regional Madical Board. In this very entry of Form B Register the age of Udit Narayan Singh has again mentioned as 59 years on 12th December 1978 after examinations by the Appellate Medical Board, Sanctoria, done at the instance of the Colliery Mazdoor Congress (HMS). It appears that on the basis of the first entry in which his age had been recorded as 59 years on 15-11-76 Udit Narayan Singh was asked to retire on 15-11-77. But heprotested. The Colliery Mazdoor Congress (HMS) of which Udit Narayan Singh was at that time a member took up the matter with he management on 14th July 1978 and then this man was re-examined by the Appellate Medical Board of Sanctoria on 12-12-1978 and his age was then found to be 59 years. So the concerned workman was allowed to rejoin on 30th December 1978. He had thereafter been superannuated with effect from 31-12-1979. The correctness of the entry in B form register has not been challenged and cannot be challenged. It has been signed by Udit Narayan Singh who has admitted his signature put there. The witness has said in his evidence that if a workman is transferred from one colliery to another, the next extract from the ralevant register is sent to the transferred place. Udit Narayan Singh was transferred sometime in 1978 from Ramnagar to Khottadih colliery from where he has been superannuated with effect from 31st December 1979. The management has stated in para 11 of its written statement that it was astonishing as to how the date of birth was inserted in Form 'A' of CMPF office when there was no entry of the date of birth in the earliest register namely the Form B register. I think that the management has rightly thought so I have already said that the date of birth should have been noted in the earliest register from B at the time of appointment if the same was available If it had not been so noted in that register then it is really surprising how subsequently the date of birth will be mentioned in form A register maintained in the office of the Coal Mines Provident Fund. To me it appears that somebody in collusion with some staff committed the mischief there also. It was during the conciliation proceeding that it was made out by the concerned workman that is date of birth was 1st July 1928. It was after a number of discussions during the conciliation proceedings that form A register was produced from the office of CMPF. The Labour Officer who is said to have signed has not been examined. No one from CMPF office has come to say that the entry in form A register was genuine. It may be mentioned that the Appellate Medical Board was constituted with several specialist Medical Officers of different branches of the company and it is not possible to believe the assertion of the concerned workman that he was forsibly taken there for examination. There is no doubt that in a situation when the exact date of birth is not availavle the opinion of the Medical Board is relevant and should be accepted vide case of Jiwan Kishore of Delhi Tarsport Corporation and Another, (1982) ILLJ 271. In my opinion WW-1 is wholly an unreliable witness.

4. The other documents on record are not of assistance for proving the date of birth of the concerned workman and therefore it is not necessary to discuss them. The management has argued that the sponsoring union is not competent to take up the cause of Udit Narayan Singh as it had no following whatsoever in the colliery and there is no resolution entitling it to sponsore the dispute on behalf of the concerned workman. I do not think it necessary to go into this question in the view which I have already expressed about this case.

5. In the result, I hold that the concerned workman Udit Narayan Singh was aged 59 years on 12-12-1978 as found by the Appellate Medical Board, that the action of the management of Khottadhi Colliery of Messers Eastern Coalfields Limited in superannuating Udit Narayan Singh, Havildar with effect from 30th December 1979 is perfectly justified and that Udit Nrayan Singh, Havildar is not entitled to any relief.

This is my award

Sd/

M. P. SINGH, Presiding Officer

[No. L-19012 (14)/80-D.IV (B)]

S.S. MEHTA, Desk Officer

Dated, Calcutta,

The 3rd August, 1982.

New Delhi, the 19th August, 1982

S.O. 3124.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes, the followng award of the Central Government Industrial Tribunal No. 2, Bombay in the industrial dispute between the employers in relation to the Management of Messrs Darabshaw B. Cursetjee's Sons (Bombay) and their workmen, which was received by the Central Government on the 10th August, 1982.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 2, BOMBAY

Reference No. CGIT-2/19 of 1981

PARTIES :

Employers in relation to the management of Messrs Darabshaw B. Cursetjee's Sons (Bombay) Private Limited, Bombay

AND

Their workmen

APPEARANCES :

For the Employers—Shri V. D. Gokhale, Advocate

For the Employees—1. Shri M. N. Bhatkal 2, Shri K. R. Dengle, Advocate.

STATE : Maharashtra INDUSTRY : Ports & Docks

Bombay, dated the 19th July, 1982

AWARD

By their order No. L-31012(1)/81-D.IV(A) dated 19-8-1981 the Central Government has referred the following dispute for adjudication under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 :—

"Whether the action of the management of Messrs Darabshaw B. Cursetjee's Sons (Bombay) Private Limited, Bombay in terminating the services of Shri Naval Kishore, Cargo Supervisor, with effect from the 1st March, 1980 is justified? If not to what relief is the concerned workman entitled?"

2. The contention of the Union on behalf of the workman concerned by their written statement Ex. 3/W is that the workman who was serving as a Cargo Supervisor with the Respondent company was wrongfully cashiered from the service without stating any reason and without holding any enquiry as per the law and therefore their prayer is for reinstatement with all the back wages.

3. By their written statement Ex. 2/M the contentions of which are reiterated in their rejoinder Ex. 4/M management question the status of the employees concerned as a workman and since according to them, Shri Naval Kishore was working as a Dock Supervisor drawing Rs. 1,052.28 as emoluments, he cannot fall under the category of workman as defined in the Industrial Disputes Act and as such the whole reference must fail. It is further urged that the Port Trust authorities for their own reasons cancelled the Dock Entry permit issued in favour of Shri Naval Kishore and insisted upon its surrender, as a result of which the Cargo Supervisor could not have entered the dock area, thus frustrating the contract of service between the employer and employee. It is alleged that despite the instructions issued by the Port Trust authorities, the employee failed to surrender the permit and further that though he was directed to attend the head office, the company was not satisfied with his attendance or attitude and therefore although repeated attempts were made by the Respondent Company to get the order of cancellation of the permit revoked there was no concrete result and therefore the Respondent Company had to terminate the services. It is alleged that the Port Trust authorities found Shri Naval Kishore not a desirable person to enter the Docks and to handle cargoes because of his alleged complicity in certain thefts from the Docks/Bunders and in these circumstances acting bona fide they brought about the severence of the relationship.

4. The Union has filed rejoinder Ex. 5/W whereby the plea that the employee is a workman has been reiterated and further it wants to cast the responsibility on the employer to find out as to why the Dock entry permit was cancelled or to procure the same for the workmen concerned in the light of these proceedings and having regard to the nature of the dispute the following issues arise for consideration :—

Issues	Findings
(1) Does the management prove that because the Entry Pass of Shri Navalkishore was cancelled by the Port Trust authorites and therefore, he could not have carried on his normal duties as employee of Darabshaw B.Cursetjee's Sons, Bombay.	Yes as Cargo Supervisor
(1A) Whether Shri Naval Kishore is a workman	Yes
(2) If so, whether the contract of service automatically came to an end on account of frustration and there remained no relationship of employer-employee between the parties ?	No
(3) If not, whether the termination of services of Shri Naval Kishore amounted to retrenchment as defined under Section 2(oo) of the Industrial Disputes Act ?	Yes
(4) Whether the retrenchment was valid and legal ?	No
(5) If not, whether the services of Shri Naval Kishore were validly terminated ?	No
(6) To what relief the employee is entitled, Whether of reinstatement or compensation ?	No reinstatement but compensation only.
(7) If compensation is a relief, what quantum ?	Rs 15,000/—
(8) What Award	As per order.

REASONS

5. The employee was serving as a Cargo Supervisor is a fact which stands admitted. Similarly it is a fact that he was drawing emoluments exceeding more than Rs. 500/- per month. Linking these two facts together it was urged on behalf of the employers that the employee being performing what is known as supervisory duties and further being drawing salary of more than Rs. 500 cannot fall under the definition of workman under Section 2(s) of the Industrial Disputes Act and therefore the reference cannot survive and if there is any wrong, the employee may have to chose some other forum. Now whether a particular employee being employed in a supervisory capacity and theretore not falling under the definition of workman would be simply a question of facts and the same would depend upon the proof or otherwise of the nature of work or duties performed by the persons concerned. It was purely a question of evidence but as the record goes neither the management nor the workman or the Union on his behalf has adduced any oral evidence on record and that during the arguments there was reference to the duties performed, but since there is no evidence as such on record, merely what was argued particularly when what is contended by the Union was denied by the management and vice-versa, no conclusion can be arrived at because the argument cannot take place of proof. Although there is no oral evidence on record there is one Award which is Ex. 33/W based upon a settlement between the Bombay Stevedores' Association and their workmen whereby all the benefits of the settlement were extended to Cargo Supervisors whether Grade 'A' or Grade 'B' and the Supervisors of these two grades were treated as workmen employed under the members of the Association. Consequently when as long back as in the year 1959 the Cargo Supervisors by the consent of the parties were treated as workmen, unless there was some material to hold that the subsequently the nature of duties changed, that too to such an extent that the employee no longer came within the definition of workman, the force of settlement and the facts admitted shall be treated as still existing and when viewed accordingly, no other conclusion is possible than to hold that the Cargo Supervisor though drawing more than Rs. 500/- per month is still a workman. Salary exceeding Rs. 500/- would only be a dtermining factor if the employee is employed in a supervisory capacity in other words he falls under Section 2(s)(iv) of the Act, for which there's no proof on record. The contention that Shri Naval Kishore is not a workman and therefore the reference is bad must fail

6. What happened at about the relevant time which ultimately led the company to terminate the service of the workman is borne out from the copies of correspondence produced by the employers at Ex. 6/M of the list dated 20-1-1982. From the pleadings as well as from the exchange of letters, especially between the management and the Port Trust authorities, as well as the from the communication received from the Port Trust on record at Ex. 32/M, there is every reason to believe that the Port Trust authorities felt that Shri Naval Kishore was responsible for the loss of original tally sheets and this must have occasioned with certain ulterior motive. I am not called upon to determine here in this proceeding whether the conclusions arrived at by the Port Trust authorities were supported by any evidence or not, but the fact remain that though they were authorised to isssue dock entry permits, for their own reason ultimately were constrained to cancel the same. The Union has brought on record Ex. 34/W a specimen copy of the application for dock entry permit where the particulars required to be fill in in the application have been mentioned but in the application form almost at the beginning we notice a note where it has been stated that this administration reserves the right to refuse, withdraw or cancel the number of dock Entry Permits applied for or granted without assigning reasons."

7. In exercise of the powers vested in the Port Trust authorities when they cancelled the Dock Entry permits of Shri Naval Kishore and when despite letters written by the employers to the Port Trust authorities, the decision to cancel the permit was not rescinded, the management must be deemed to be helpless in the matter.

8. It is tried to be urged that the procurement of Dock Entry permit was a joint responsibility of the workman and the management and because the management did not challenge the order of Port Trust authorities, they subsequent

to passing the order of cancellation shall be deemed to have not taken any steps in the matter. To suggest that it was a joint responsibility, my attention was again drawn to the specimen application form Ex. 34/W where the employer is expected to give certain certificate and propriety of the employee to hold the permit entitling him to enter the Bombay Dock and the protected area. However, merely because such a certificate was expected, it does not cast any duty on the employer so as to hold him jointly responsible for moving in the matter. If Shri Naval Kishore or the Union on his behalf was aggrieved by the cancellation of the Dock entry permit, the primary duty to get the order rescinded either by convincing the Port Trust authorities or by approaching the court of law rested with the employee himself, without following such a course, they merely tried to throw the entire blame on the employer which would never be permissible. When the management drew his attention of the Port Trust authorities to take early action in the matter, and wrote atleast more than two letters, nothing more was expected of the management in the absence of action on the part of the employee concerned, and no mala fide can be attributed as tried to be done in the present case. The Port Trust authorities were satisfied about the undesirability of the workman concerned in the Dock area, and the said order was never challenged. In the absence of any Dock Entry permit, Shri Naval Kishore was not entitled to enter the dock area or to perform his duties as a Cargo Supervisor. Therefore all the arguments advanced on behalf of the workman that the ultimate action taken by the management was not bonande or that management connived at such action cannot but fail.

9. Once we arrive at this conclusion it means that there was ground for the management to bring about the severence. Therefore, the next question posing for determination will be whether the said severence is validly done, for, even if the said act is found to be justified, the question would still remain whether it was legally and validly performed and if the termination is required to be effected in a particular manner under the Industrial Disputes Act, unless the requirements of law are fulfilled no seal can be put on such action. Even the written statement of the management indicates that after the cancellation of the Dock Entry permit the employee was asked to work in the head office. It is not therefore the case of the management that the employee was singularly a Cargo Supervisor holding no other status independently of the Dock Entry permit but admission in the written statement indicates that even after the cancellation of the entry permit according to the management themselves the relation ship of employer-employee continued and there was attempt on the part of the employer to provide the employment somewhere else. In this connection the plea in the written statement is that the employee was reluctant to work in the head office and was not regular in his attendance. Events in chronological order would be the cancellation of the Dock Entry permit, posting of the employee in the Head Office and lastly the termination of service. Now if the intervening stage is taken into account when the employee was posted in the head office and if the employer wanted to contend because of the reluctance and irregular attendance they were not satisfied with the work of the employee it would mean nothing else but attribute some misconduct on the part of the employee in which case certain action could have been taken either an enquiry was necessary or some proof in support was essential before the Tribunal. There is no such proof therefore remains the word of the employer saying something else against Shri Naval Kishore.

10. With the result that there is no proof of misconduct as such and at the same time there is proof that after the cancellation of the Dock Entry permit by the Port Trust authorities, the employee was unable to perform his duties as Cargo Supervisor and in that case the management could have terminated the services.

11. If there was no misconduct and there is no proof to that effect, and if the management was bringing about severence of the relationship, what was necessary was the compliance of the provisions of Section 25F of the Industrial Disputes Act, for, any termination whatsoever reason barring exceptions under Section 2(oo) of the Industrial Disputes Act amounts to retrenchment and such retrenchment can be brought about only by following Section 25F of the Act of which management, the record goes, failed to do. Neither there being any notices or notice pay nor any compensation as stipulated under the provisions of Section 25F are not followed, the termination is rendered invalid.

12. Once it is so held, what is to be considered is whether reinstatement is to be ordered or any compensation. It was tried to be urged on behalf of the Union that in the light of the finding to which the Tribunal has arrived at, there is no other order legally permissible except the order of reinstatement. However, the facts of the instant case are such that because of the action of the Port Trust authorities which acion they could legally take by virtue of the contents of the application form itself, the employee was not in a position to render the service to the employer, the service for which he was appointed. If there is no Dock Entry permit, Shri Naval Kishore cannot enter the Dock and if he cannot enter the dock he cannot supervise the loading and unloading of cargo. Therefore, the order of reinstatement in case is passed would create a vaccum, there would be no work to the employee to carry on his normal duties expected of his post. In these circumstances in my view reinstatement is not at all possible.

13. Even in Hindustan Steels Limited Vs. A. K. Roy, AIR 1970 Supreme Court 1401, (1970 LAB. I.C. 1166)) in the case of illegal discharge or dismissal of a workman, on the strength of the facts on the said case no order of reinstatement was passed but that of compensation only. It is not therefore that in each and every case the order of reinstatement is a must as tried to be urged on behalf of the Union. In my view for the reasons already stated no reinstatement is possible. This shall bring us to the question of compensation. The services of the workman were terminated from 1st April, 1980. On record there is nothing to show that he was in anybody's service or he was gainfully employed or not. Having regard to these facts at the same time having found the order of termination as invalid on account of non-fulfilment of Section 25F, the ends of justice would be met if a compensation of Rs. 15,000 is paid to the workman.

Award Accordingly.

Sd/-

M. A. DESHPANDE, Presiding Officer

[No. L-31012/1/81-D.IV(A)]

S.O. 3125.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Madras, in the Industrial dispute between the employers in relation to the management of Messrs Gordon Woodroffe Limited Madras, and their workmen, which was received by the Central Government on the 10th August, 1982.

BEFORE THIRU T. SUDARSANAM DANIEL, B.A.,B.L. PRESIDING OFFICER

Industrial Tribunal, Tamil Nadu Madras.

(Constituted by the Government of India)

Tuesday, the 3rd day of August, 1982

Industrial Dispute No. 78 of 1981

(In the matter of the dispute for adjudication under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 between the workmen and the Management of Messrs. Gordon Woodroffe Limited and Stevedores Association, Madras.)

BETWEEN

The workmen represented by
The General Secretary,
Madras Harbour Workers Union,
No. 204, Broadway Madras-600 001.

AND

1. The Managing Director,
Messrs. Gordon Woodroffe Limited,
Rajaji Road, Madras-600 001.

2. The Secretary,
Madras Stevedores Association,
MDT B Buildings, Rajaji Road, Madras-600 001.

REFERENCE :

Order No. L-33011/3/81-D. IV(A) dated 22-10-1981 of the Ministry of Labour, Government of India, New Delhi.

This dispute coming on for final hearing on Tuesday, the 27th day of July, 1982 upon perusing the reference, claim and counter statements and all other material papers on record and upon hearing the arguments of Thiru P. T. Seetharaman, Advocate for the workmen and of Thiru N. Kannan, Assistant Secretary of Employers' Federation of Southern India, Madras-1 for Management No. 1 and Thiru R. Arumugham for Thiruvalargal Aiyar and Dolia and R. Arumugham Advocates for Management No. 2 and this dispute having stood over till this day for consideration, this Tribunal made the following :

AWARD

This is an Industrial Dispute between the workmen and the management of M/s. Gordon Woodroffe Limited, Madras and Madras Stevedores Association, Madras referred to this Tribunal for adjudication under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 by the Government of India in Order No. 33011/3/81-D. IV(A), dated 22-10-1982 of the Ministry of Labour, in respect of the following issue :

"Whether the non-inclusion of the undermentioned 10 Watchmen of Messrs. Gordon Woodroffe Limited, Madras, in the Watchmen Pool run by the Madras Stevedores Association is proper and justified ? If not, to what relief are the concerned workmen entitled and from what date ?

Name of the Watchmen

1. Shri K. Dhakshinamurthy
2. Shri R. Jayendran
3. Shri V. Kothandan
4. Shri D. Kannaiah
5. Shri V. Mariasoosai
6. Shri M. Mehboobkan
7. Shri V. Rangiah
8. Shri M. Thirumalai
9. D. S Viswanathan
10. Shri M. Chandran."

(2) Facts leading upto this dispute are as follows : The reference made by the Government of India Ministry of Labour is made at the instance of Madras Harbour Workers Union, No. 204, Broadway, Madras-600 001, Tamil Nadu. The 10 workmen mentioned in the reference are employed by Messrs. Gordon Woodroffe Limited, Rajaji Road, Madras-1. The case of these aggreived watchmen briefly stated is that their non-inclusion in the Watchmen Pool run by Madras Stevedores Association is unjustified. There is no controversy that these 10 watchmen were employed by Messrs. Gordon Woodroffe Limited, Madras at any rate from even prior to 1968 as casual workmen. The labour employed in the Madras Docks are under the overall control of the Madras Dock Labour Board either as direct employer or as the statutory authority to regulate and supervise the functions, service conditions etc. of the labour engaged in the Dock areas for the labour engaged by or under the control of Dock Labour Board.—vide The Madras Dock Labour Scheme. The Madras Stevedores Association representing the body of stevedores has entered into various settlements/agreement on various issues relating to this labour. It is common case that in 1968, there was a proposal that the Clerks and the Watchmen attached to the godowns of Messrs. Gordon Woodroffe Limited in the Madras Harbour area should be brought within the scope of pool of listed labour. This was in conformity with the position obtaining in respect of other companies also However, when the pool was prepared, the clerks and watchmen of Messrs. Gordon Woodroffe Limited were excluded. Therefore, the Petitioner-Union raised a dispute as early as 1973. The remarks of the Gordon Woodroffe Limited are found in Ex. W-15. At that stage, the Madras Stevedores Association participated in the conciliation and agreed to examine the claim of these workmen. Meanwhile, the clerks have since been absorbed by Messrs Gordon Woodroffe Limited and therefore the ten watchmen mentioned in the present reference along remained unabsorbed. It is true that during the conciliation proceeding discussions took place between the Petitioner-Union of the Gordon Woodroffe Limited and the Stevedors Association in the presence of Thiru V. Karthikeyan, I.A.S., the then Chairman of Madras Port Trust Most of the relevant facts are found in Ex. W-4. Eventually on 30-8-1968 the Chairman of Port Trust has passed the following order which is seen at paragraph (12) in page 3 of Ex. W-4. The Chairman observed that "if Gordon Woodroffe & Co., were not drawing men from the stevedores and utilising their own watchmen as in the past, they cannot be expected to draw men from the pool." Much water has flowed under the bridge ever since.

(3) The Madras Dock Labour Board has considered amendments to the Dock Labour Scheme to cover and to include the workmen empl yed in Clearing and Forwarding, viz, under the stevedores, within the framework of "the Madras Registered Dock Clearing and Forwarding Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1980." In terms of the settlement reached on 5-11-1969 before the Regional Labour Commissioner (Central), Madras to which Messrs. Gordon Woodroffe and Madras Stevedores Association were also parties it was agreed that the poll of casual workmen run by Madras Stevedores Association under the Madras unregistered Dock Workers' (Regulation of Employment) Scheme, 1957 as amended in 1968 covered certain categories of workmen including watchmen and such workers would be entitled to the benefits admissible to the listed dock workers with effect from 3-3-1969. The Stevedores Association has agreed to give all benefits as per the minutes of discussion held in 1973 before Thiru Karthikeyan, the then Chairman of the Madras Port Trust. On the facts so far stated, it should appear that the Madras Stevedores Association had agreed to take these 10 watchmen also to be included in the list of pool workers.

(4) At this juncture, I may refer to the stand taken up by the Company, namely, Gordon Woodroffe Limited and also the Madras Stevedores Association. The Company maintains that the workmen concerned in the dispute should be absorbed in the Watchmen Pool run by the Madras Stevedores Association. But Messrs. Gordon Woodroffe Limited also takes up the stand that there was no industrial dispute as such between the Company and the workmen and therefore there is no proper dispute against the Company and therefore the reference made by the Government of India including the Company as a party is misconceived. To a similar effect is the main stand of Stevedores Association that as between the 10 watchmen concerned in the dispute and the Stevedores Association, there is no jural relationship as such and therefore there is no industrial dispute as contemplated under the Industrial Disputes Act, 1947 between these 10 workmen and the Stevedores Association would come forward with a plea at held to be incompetent. Regard being had to the claim of these watchmen to be included in the list even from 1968 onwards and taking into consideration the attempted arbitration by the Chairman of the Madras Port Trust in the presence of Messrs. Gordon Woodroffe Limited as well as the Madras Stevedores Association it is rather surprising that Gordon Woodroffe Limited and much more the Madras Stevedores Association would come forward with a plea at this stage that there is no industrial dispute as such as contemplated under the Industrial Disputes Act, 1947. As pointed out by the Petitioner-Union and the Gordon Woodroffe Limited, even during the conciliation proceedings the Madras Stevedores Association adopted unhelpful attitude and refused to participate in the conciliation proceedings and therefore the conciliation failure report Ex. W-1 clearly indicates the non-participation of others excepting Messrs. Gordon Woodroffe Limited. On receipt of this conciliation failure report, the Madras Stevedores Association has made its remarks to the Government of India under the original of Ex. M-4 on 26-5-1981. According to the stand of the Madras Stevedores Association it appears that the claim of these 10 workmen became a closed chapter even by about August, 1968. On a total appraisal of all the materials, I am unable to accept the stand of the Madras Stevedores Association that the claim of these 10 watchmen was given a quietus by the observation of the Chairman of the Madras Port Trust in the Proceedings

dated 30-8-1968, extract of which is found at page 2 of Ex. M-4. All that the Chairman has stated at that stage was, because Gordon Woodroffe Limited were not drawing men from the Stevedores and utilising their own watchmen as in the past, they cannot be expected to draw men from the pool. That cannot be any exception to this observation. However certain other developments had taken place. As seen from Ex. W-7, the shipping agency of M/s. Gordon Woodroffe Limited, namely, *Clan Line* was terminated by the principals towards the end of the year 1977 and although the workmen became redundant the Management purely on compassionate grounds continued to retain them in service. The stevedoring business of the Company has now taken by another Company International Services, which however refused to employ these 10 workmen. But the hard fact remains that the International Agency draws the workmen from the pool maintained by Madras Stevedores Association Therefore, in view of changed situation when International Services is drawing man from the pool, certainly the watchmen already employed and who had agitated their rights even from 1968 onwards must be included in the pool maintained by the Madras Stevedores Association It is true that there is no direct contractual obligation between these 10 workmen and the Madras Stevedores Association but in view of the legal duty and obligation cast on the Madras Stevedores Association to employ any workman rendered surplus or reduce out for any reason, it is just and proper that these watchmen must be included in the pool maintained by Madras Stevedores Association. Even if the exterme stand taken up by the Gordon Woodroffe Limited and also the Madras Stevedores Association that there is no industrial dispute and as such as against them, still their presence before this Tribunal on the facts of the case is perfectly justified as coming within Section 18(3) (b) of the Industrial Disputes Act, 1947. By no stretch of imagination can it be said that Messrs Gordon Woodroffe Limited or Madras Stevedores Association has been summoned by this Tribunal without proper cause. In Ex. M-4, the Madras Stevedores Association has also pointed out that the Government of India in the Ministry of Transport and Shipping is considering the inclusion of Madras Stevedores Association Pool labour, within the fold of Madras Dock Labour Board. Regard being had to the claim of these watchmen even from 1968 onwards to be included in the pool, their non inclusion by Madras Stevedores Association cannot be held to be justified. However, there is no question of any retrospective effect to be given for the inclusion of these workmen. It is stated at the bar that the Madras Stevedores Association can employ considerable work force to implement the duty and obligation cast on it. Therefore, there cannot be any practical difficulty to Madras Stevedores Association to include these 10 workmen in the pool list and give them employment as and when necessity arises.

(5) In the result, an Award is passed holding that the non-inclusion of the watchmen of Messrs Gordon Woodroffe Limited in the Watchmen Pool run by the Madras Stevedores Association is improper. These 10 workmen would be deemed to be included in the Watchmen Pool of Madras Stevedores Association from the date of this Award and will be offered employment as and when suitable occasion arises. In the peculiar circumstances, I direct all the parties to bear their respective costs.

Dated, this 3rd day of August 1982.

T. SUNDARSANAM DANIEL, Presiding Officer, Industrial Tribunal

Witnesses Examined

For both sides . None.

Documents Marked

For workmen

Ex. W-1/8-5-81—Conciliation failure report. (True copy)

Ex. W-2/21-1-81—Letter from the Madras Dock Labour Board to the Union and Management No. 1 sending copies of letters received from Thiru P. C Tilak. (true copy).

Ex W-3/14-11-80—Letter from the Madras Steamer Agents Association to Management—1 regarding pool of casual workers at Madras Port. (True copy)

Ex. W-4—Note regarding formation of casual pool at Madras Port. (True copy)

Ex. W-5/5-11-80—Letter from Management-I to the Madras Dock Labour Board urging to embrace the casual workers in the employment of Steamer Agents. (True copy)

Ex. W-6/1-7-80—Letter from the Union to Management No. 1 for confirming the serivces of some clerks. (true copy)

Ex. W-7/1-11-79—Statement of remarks submitted by Management No. 1 to the Assistant Commissioner of Labour (C), Madras, in reply to the charter of demands of the Union. (True copy)

Ex. W-8/12-10-79—Letter from the Union to Management No. 1 regarding increase in minimum guarantee period and payment of weekly off to the casual clerks and watchmen. (True copy)

Ex. W-9/36 1-79—Letter from Management No. 1 to the Union about the enrollement of casuals into Dock Labour Board. (True copy)

Ex. W-10/11-12-78—Letter from Management No. 1 to the Madras Port Trust requesting to get International Services to take over the casuals or arrange for the casual pool to absorb them for employment. (True copy)

Ex. W-11/1-11-78—Letter from Management No. 1 to the Union regarding charter of demands dated 24-10-77 of the Union. (True copy)

Ex. W-12/30-5-75—Memorandum of settlement u/s. 12(3) of the I.D. Act, 1947 between the Union and Management No. 1. (True copy)

Ex. W-13/16-8-73—Conciliation report of the Assistant Labour Commissioner (C)/I, Madras. (True copy)

Ex. W-14/10-8-73—Letter from the Union to Management No. 1 requesting for payment of overtime wages to the clerks and watchmen. (True copy)

Ex W-15/1-11-72—Letter from Management No. 1 to the Assistant Labour Commissioner (C), Madras in reply to the representation dated 11-10-72 of the casual clarks and watchmen. (True copy)

Ex W-16/23-10-72—Letter from the Assistant Labour Commissioner (C), I, Madras to the Management-1 sending the representation dated 11-10-72 of the casual clerks and watchmen for comments. (True copy)

For Managements :

Ex M-1/21-6-73—Conciliation notice issued to the Union and Management No. 2 by the Assistant Labour Commissioner (C), Madras-1. (True copy)

Ex. M-2/30-6-73—Letter from Madras Dock Labour Board to the Madras Steamer Agents' Association. (True copy)

Ex M-3/3-3-69—Memorandum of settlement u/s. 12(3) of the I.D Act, 1947 between the management No. 2 and the Madras Port and Dock Workers Progressive Union, Madras. (copy)

Ex M-4/26-5-81—Letter from Management No. 2 to the Government of India regarding non-inclusion of the views of Management in the conciliation report. (copy)

T. SUDARSANAM DANIEL, Industrial Tribunal

[No. L-33011(3)/81-D IV(A)]

T. B. SITARAMAN, Desk Officer

S.O. 3126.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta, in the indsutrial dispute between the employers in relation to the management of United Bank of India, Calcutta and their workman, which was received by the Central Government on the 10-8-82.

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL : CALCUTTA

Reference No. 38 of 1978

PARTIES :

Employers in relation to the management of the United Bank of India, Calcutta

AND

Their Workmen

APPEARANCES :

On behalf of Employers—Mr. C. L. Ganguly, Advocate

On behalf of Workmen—Mr. S. Das Sharma, General Secretary of the Union

STATE : West Bengal INDUSTRY : Banking

AWARD

Government of India, Ministry of Labour by Order No. F. No L-12011/48/77-D.II.A dated 5th April, 1978, referred an industrial dispute existing between the employers in relation to the management of the United Bank of India, Calcutta and their workmen, to this Tribunal for adjudication. The Schedule to the Order of reference reads :

"Whether the action of the management of the United Bank of India, 16, Old Court House Street, Calcutta-1, in refusing to declare S/Shri Jahar Kanti Sen and Baburam Pal their representatives at the Clearing House, Calcutta as permanent incumbents is justified ? If not, to what relief are these workment entitled ?"

2. The case as pleaded on behalf of the concerned workmen may be briefly indicated. Sri Jahar Kanti Sen and Sri Baburam Pal were appointed in the services of the United Bank of India on 6th May, 1971 and 8th September, 1972 in the clerical cadre. They were allotted the duties of clearing house representative of Reserve Bank of India building, 15-Netaji Subhas Road, Calcutta on regular assignment on 1-8-71 and 28-3-1973 respectively. The above duties of clearing house attracted a special allowance of Rs. 91 per month along with usual dearness allowance by vrtue of para 5.2 and para 5.6 of the Bipartite Settlement dated 19-10-66. The concerned workmen made a claim to the Bank for payment of the special allowance and "letters of permanency" on the posts. The management paid the arrears of special allowance but did not concede the other demand.

3. The claims of the concerned workmen were based on the decision of the Central Government Labour Court, Calcutta in Srinivasan vs First National City Bank in 1967 which was confirmed in the dispute between the Bank managements vs Workmen in a consolidated case in 1969 contested by the representatives of the Banks Association. In appeal to the Supreme Court by the Central Bank of India, the decision of the Labour Court was upheld by the judgment of the Supreme Court delivered on 8th October, 1975.

4. That the management failed to treat the concerned workmen as permanent incumbents of the above posts and although the management has been paying the full special allowance of Rs. 91 plus usual dearness allowance per month to the concerned workmen, the management has not made them permanent. A dispute was raised before the Assistant Labour Commissioner (Central). The conciliation failed and resulted in the present reference. That the management acted in violation of the provisions of the Bipartite Settlement dated 19-10-66. The payment of special allowance to the concerned workmen is being made from May, 1978 by separate vouchers and not by salary sheets, so long as they are in the clearing house without confirming them as permanent special assistants and withdrawing their previous letter dated 5-1-78 under which the management confirmed them as Special Assistants. The conduct of the management is mala fide. It is further said that by virtue of their regular posting at the clearing house as representatives of the Bank and having regard to their long tenure of service at the clearing house the concerned workmen ought to have been designated as Special Assistant-cum-clerks by the management. The action of the management in not treating them as permanent incumbents is in violation of the provisions of Settlement dated 19-10-1966. In conclusion it was submitted on behalf of the concerned workmen that the management should be directed to treat them as permanent Special Assistants on regular assignment at the Clearing House.

5. The Bank has contested the claim of the workmen. Short of verbiage the case of the Bank is that the clerks concerned have no right to be made permanent incumbents and as per clauses 5.8 and 5.9 of the Bipartite Settlement dated 19th October, 1966 they are entitled to special allowance only so long as they perform the job in the Clearing House and not if they are withdrawn by the Bank from the clearing house and cease to work. It is said that these two clerks are doing the job in the clearing house and they are getting the special allowance payable to Special Assistants. It is also pleaded by the Bank that seniority is taken into consideration as the criterion to designate special assistants from amongst the existing clerical staff, that the two concerned workmen are junior clerks and there are many clerks who are senior to them. The Bank submits that these two concerned workmen are not special Assistant. It is said, however, that the Bank has decided to give special allowance and not to discontinue it in the case of these two workmen even if they are withdrawn from the clearing house.

6. Firstly it is contended by the workmen that the two concerned workmen used to draw special allowance while on leave and as admitted by the bank in its written statement and this can be done only if they are permanent incumbents. My attention has been drawn to clause 5.10 of the Bipartite Settlement which provides : "The Special allowance would continue to be drawn by permanent incumbent while on leave". It is true that this clause contemplates the existence of permanent incumbent but it does not say that if any clerk permanent or temporary does the work of clearing house he will automatically be permanent incumbent. No rule or any clause in the Settlement has ben shown to me as to how a clerk is made permanent incumbent. There is also on rule that if a person draws up special allowance while on leave he will automatically become permanent incumbent. In Rohtas Industries Ltd v Brij Nandan Pandey, AIR 1957 CS 38 it has been observed that a circumstances that a worker enjoys some benefits of permanent employees will not make them permanent. The contention, therefore, must be repelled.

7. It is next contended that it is a case of victimisation because the bank with a mala fide motive wants to deprive the concerned workmen of the special allowance after the decision of the Supreme Court in Central Bank of India Ltd. v Sisir Kumar Shaw (1976) II LJ 90. The argument has no substance. It appears that the Bank has already decided to pay special allowance even if the two concerned workmen are transferred. Moreover it is to be noted that whatever be the motive of the bank if it has right to transfer and if transfer is made in exercise of that right in the interest of the bank, the motive is of no significance. In Oil & National Gas Commission v Md S Iskandar Ali AIR 1980 SC 1242 (1980 Lab. IC 698) it was held : "The short history of the service of the respondent clearly shows that his work had never been satisfactory and he was not found suitable for being retained in service and that is why even

though some sort of an enquiry was started, it was not proceeded with and no punishment was inflicted on him. In these circumstances, therefore, if the appointing authority considered is expedient to terminate the services of the respondent, a prabtioner, it cannot be said that the order of termination attracted the provision of Art. 311 of the Constitution. "Their Lordships added that in such a case, even if misconduct, negligence inefficiency might be the motive of the induing factor which influenced the employer to terminated the services of the employee, a power which the employer possessed; even so under the term of appointment of the employee such a power flowed from the contract of srvice, the termination of service could not be termed as penalty or punishment." In my opinion the principles laid down by the Supreme Court will apply to the present case. So the point has no force and it fails.

8. The third contention advanced on behalf of the workmen is that caluse 5.13 of the Bipartite Settlement has been violated. I do not agree. That claue runs as follows :

> "5.13. The standardization of nomenclatures as aforesaid should not by itself lead to withdrawal of special allowance from persons already drawing them except where specifically provided in this Settlement. Subject to this, banks will be free to reallocate the duties of any workman to bring them in conformity with the duties specified in the Appendix 'B' hereto. Where for the first time a special allowance provided for in this Settlement is introduced in an office, in reallocating the duties, preference will be given from among those who are already performing the appropriate duties. In specifying the duties it is not the intention that in each office/branch posts should be created in each category for which special allowance has been agreed to."

On a perusal of the above it is clear that the clause nowhere says that a clerk doing the job in the clearing house will become permanent incumbent. The contention is, therefore, rejected.

The fourth contention argued by the workmen is that the bank has conceded in the written statement that the two concerned workmen are permanent incumbents. I have read the written statement. The bank has not admitted this fact Therefore no question of passing any order in favour of the workmen on admission arises. The contention is rejected.

10. The fifth contention of the workmen is that each of the two clerks is discharging additional duties and functions requiring greater skill or responsibilities in the clearing house for a pretty long time, both having record of splendid work and therefore they should be made permanent incumbents. It is argued that Sri Jahar Kanti Sen is discharging that duty with effect from 1st August 1971 and Sri Baburam Pal from 29th March 1973 and for that reason they should be made permanent incumbents. I am not inclined to agree with this contention. Mere performance of the job for a number of years will not entitle a clerk to become permanent incumbent unless there is a rule or contract to that effect. There is therefore on force in this submission.

11. It will not be out of place to mention here that similar point arose recently before my predecessor in office Mr. Justice R. Bhattacharya in Reference 49 of 1978 which was decided on 25th March 1981. It was held in that case that the bank has the right to withdraw the concerned clerk from the clearing house and place him for doing usual duties of his own cadre for which he cannot claim special allowance which he was getting for work in the clearing house and that such cessation of special allowance does not attract Sec. 9A of the Industrial Disputes Act. 1947. In that case one Asoke Kumar Mukherjee was performing the job of the clearing house. He was withdrawn by the bank. Mr. Justice Bhattacharya the then Presiding Officer held that the action of the bank was legal and justified. The union leader appearing for the two concerned workmen placed reliance on Central Bank of India v Sisir Kumar Shaw's case (1976) LLJ90 but that case is of no assistance to him. In that case it was held that paragraph 5 6 of the Bipartite Settlement did not refer to a special assistant only being entitled to special allowance and that other workmen though not special assistance were also entitled to special allowance provided they discharge certain additional duties and functions requiring greater skill or responsibility over and above their routine duty and functions It was emphasised that the fact that the claimant was not called a special assistant did not make any difference in the situation. There is nothing in that decision to show as to how a clerk could become permanent incumbent. No rule or any agreement has been placed before me to show that the two concerned workmen are entitled to be made permanent incumbents.

12. My award, therefore, is that the concerned workmen have acquired no right to be declared as permanent incumbents in the clearing house and they have no right to be kept or posted at the clearing house permanently or to be allowed to discharge the clearing house work. It follows that the bank has every right to withdraw them at any time and to place them in any branch of the bank in its own interest unless there is a contract or rule to the contrary. The two concerned workmen are not, therefore, entitled to any relief. Their claim is disallowed.

Dated, Calcutta,

The 31st July, 1982.

M. P. SINGH, Presiding Officer

[No. L-12011(48)/77-D.II(A)]

S.O. 3127.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal Calcutta, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of United Bank of India, Calcutta, and their workman, which was received by the Central Government on the 10-8-1982.

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL AT CALCUTTA

Reference No. 99 of 1980

PARTIES :

Employers in relation to the management of United Bank of India

AND

Their workmen.

APPEARANCES :

On behalf of Employers—Sri Anjan Chatterjee, Asstt. Chief Officer of the Bank.

On behalf of Workmen—Shri Sudhir Das Sharma, General Secretary of the Union.

STATE : West Bengal INDUSTRY : Banking

AWARD

By Order No. L-12012/190/79-D.IIA dated 16th December, 1980 the Government of India, Ministry of Labour, sent an industrial dispute existing between the employers in relation to the management of United Bank of India and their workmen, to this Tribunal for adjudication. The dispute as mentioned in the Schedule to the order of reference reads as :

> "Whether the action of the management of United Bank of India, 16 Old Court House Street, Calcutta-1 in re-designating Shri Alok Kumar Sinha, Telephone operator of the Head office of the Bank as Telephone Operator-cum-Receptionist without providing special allowance or adequate financial benefits is justified? If not, to what relief is the workman concerned entitled?"

2. The short facts are that Alok Kumar Sinha, the workman concerned was appointed as a Telephone Operator, clerical cadre through Bank's letted dated 7/8 June 1972. He was entrusted with the duties of Telephone Operator and he got special allowance for that as per provisions of the Bipartite Settlement dated 19 October 1966. His services were confirmed with effect from 18 December 1972 and thereafter he was posted in the 5th floor of the Head office at Calcutta relieving Sunil Kumar Monda, another Telephone Operator. By the Bank's letter dated 17/18 August

1978 he was redesignated as Telephone Operator-cum-Receptionist with effect from 18th August 1978. It was stated in that letter that Sri Sinha would not be entitled to any special allowance for the change of designation. Sri Sinhan claims additional allowance for working as a receiptionst also in addition to his duties as Telephone Operator The Bank has refused to provide special allowance or any adequate financial benefits for re-designating him. The question is whether the action of the Bank is justified. I think the answer should be "yes".

3. Firstly, Sri Sinha relied on clause (5) of the terms of appointment dated 7/8 June, 1972 which runs as below : "Your duty will include all work of Telephone operating as may be allotted to you from time to time". On the basis of this clause it is argued that the only job (technical in nature) which Sri Sinha was required to perform was telephone operating and that after about six years the Manager of the Bank was not competent to ask him to do additional job of Receptionist without providing special allowance for the same. The contention is not correct. In the said clause (5) the duties are inclusive and not exhaustive. His duty includes work of telephone operating. It cannot be construed to mean that the only job to be performed was one of telephone operator. His duty rather includes the work of telephone operator. He did that work as being in the clerical cadre and he cannot refuse to perform the routine duty of clerical cadre in addition to his duty of telephone operator if called upon by the Bank to do so. It seems from a letter dated 19th February 1981 filed before this Tribunal by the Union that Sri Sinha was doing such job since the very date of his posting in the 5th floor though he had not been redesignated as such in the beginning. The point thus has no force.

4. So far as redesignation as "Telephone Operator-cum-Receptionist" from 18th August, 1978 is concerned, the same is not in violation of any rule or any provision of any award or settlement. It rather appears to be a long practice of the Bank in view of the provisions contained in clause 20(1) and (2) of the Bipartite Settlement dated 19th October, 1966 of giving double designation to clerks from time to time. As for example, Cashier-cum-General clerk, Typist-cum-clerk, Telephone Operator-cum-clerk etc. in clerical cadre and Dafty-cum-peon, Driver-cum-cash peon, Bill collector-cum-cash peon, Liftman-cum-peon and Armed guard-cum peon in subordinate cadre. These facts have been stated in the written statement of the management and have not been shown to be wrong by the workmen. In fact this fact has not been challenged. Thus, there has not been any material change in respect of his duties. Moreover, the nature of work of Receptionist is simple one. At most he is to be courteous to an outsider and if any enquiry is made by the outsider he is to point out the proper place or proper person Sri Sinha has to work only for four to four-half hours a day with intermittent rest, although as Telephone Operator he was to work for 6 1|2 hours a day He has already got special allowance for operating the telephone. His salary in December 1980 was as follows :

Basic pay	..Rs. 515/-
D. A.	. Rs. 398.71
Special Allowance	. .Rs. 31.00
H. A.	.Rs. 40.04
C C A	..Rs. 46.35
Total	..Rs 1031.10

In my opinion, he is not entitled to double allowance simply because he has been asked by the employer to do the work of Receptionist also.

5. It was next urged on behalf of Sri Sinha that technical hand can be asked only to perform particular job and not any other additional job and reference was made to Para 5.292 of Desai Award and Para 163 of Sastry Award and also to clause 14.5 of the Bipartite Settlement. Being an industrial court it will not be right to generalise any proposition of law. Suffice it to say that the work of telephone operator is not of such a type that the clerk concerned cannot be asked to do the duty of Receptionist.

6. The third submission on behalf of Sri Sinha is that the provisions of clause 20(1) and (2) of the Bipartite settlement apply only to general clerks and not to technical hands

It is not necessary to go into the validity of this general argument in the facts and circumstances of this case. In the instant case Sri Sinha was appointed as a clerk and it was made known to him by the term of appointment that his duty will include all the work of telephone operator. So the above provisions apply to his case also.

7. It was lastly argued that the duties and functions of a Receptionist are of higher responsibility and require greater skill and so special allowance should be paid to Sri Sinha on the principles laid down in the case of Central Bank of India Ltd. v Sisir Kumar Shaw, (1976) I LLJ 90. The argument is misconceived because that was a case of performing the job at the Clearing House and undoubtedly that duty requires greater skill and higher responsibility. Special allowance was, therefore, ordered to be given. That case therefore is of no assistance to Sri Sinha.

8. In the result, I hold that the action of the management in re designating Alok Kumar Sinha, Telephone Operator as Telephone-Operator-cum-Receptionist without providing special allowance or adequate financial benefits is justified. Sri Sinha is, therefore, not entitled to any relief.

This is my award.

M. P. SINGH, Presiding Officer.

Date, Calcutta.
The 2nd August, 1982.

[No. L-12012(190)/79-D.II(A)]
N. K. VERMA, Desk Officer.

New Delhi, the 21st August, 1982

S.O. 3128.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of All India Radio, Chhatarpur (M.P.) and their workman, which was received by the Central Government on the 11th August, 1982.

BEFORE JUSTICE SHRI S. R. VYAS (RETD.) PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, JABALPUR (M.P).

CASE NO. CGIT/LC(R)(51)|1981.

PARTIES :

Employers in relation to the management of All India Radio, Chhatarpur (M.P.) and their workman Shri Santosh Kumar Gupta S/o Shri Shobhalal, Clerk, Hithayai Marg, 285, Sabnigar Muhalla, Chhatarpur (M.P.)

APPEARANCES :

For Workman—Shri R. K. Gupta, Advocate.
For Management—Shri G. P. Chaube, Advocate.

INDUSTRY : A.I.R. DISTRICT : Chhatarpur (M.P.)

Dated : August 2, 1982

AWARD

This is a reference made by the Government of India in the Ministry of Labour vide Notification No. L-42012(38)/81-D. II. B Dated 15th December, 1981, for the adjudication of the following dispute by this Tribunal :—

"Whether the action of the management of of All India Radio, Chhatarpur (M.P.) in terminating the services of Shri Santosh Kumar Gupta S|o Shobhalal, Clerk, with effect from 31-12-1980 without assigning any reason is justified ? If not, to what relief the workman is entitled ?"

2. Facts which are not in dispute giving rise to this reference are these. On 4-5-1979 Shri Santosh Kumar Gupta, hereinafter referred to as the workman, was appointed by the Station Director, All India Radio, Chhatarpur, hereinafter referred to as the management, as a Grade II clerk in

temporary capacity and on an adhoc basis. The vacancy was notified to the Local Employment Exchange and the workman was referred to the management through it. The workman joined his duties on 14-5-1979 and continued to work in the aforesaid capacity till 31-12-80 without any break. During this period he was granted one annual increment also. After 31-12-1980 the employment was not continued.

3. The workman contends that he was appointed against a clear vacancy; that when he worked continuously from 14-5-1979 to 31-12-1980 he had acquired the status of a continuous workman that both on the facts as well as in law the termination amounts to retenchment; that such a retrenchment without proper compliance of Sec. 25F was illegal and void and that he is entitled to be reinstated with all benefits of back wages etc. etc.

4. As against this claim made by the workman, the first objection by the management is that All India Radio is not an industry as its main functions are to educate, to broadcast information, creation programmes, etc. etc.; that any dispute between the management and its employees cannot be said to be dispute relating to industry and that for this reason this Tribunal has no jurisdiction to adjudicate upon the dispute referred to it by the Government.

5. The second contention is that the appointment of the workman was on an adhoc basis; that grant of annual increment during the period of employment does not confer any right on the workman; that as this appointment was on an adhoc basis the management was within its rights to terminate it without any liability either for reinstatement or for future payment of wages. It is also contended that the claim made by the workman is not tenable.

6. Rejoinder was filed only by the workman in which he made the same claim as was made in the statement of claim.

7. The first contention of the management is that the All India Radio is not an industry within the meaning of the Industrial Disputes Act, hereinafter referred to as the Act. This contention cannot, in the light of the decision of their Lordship of the Supreme Court in the matter of Bangalore Water Supply Works Vs. A. Rajappa and others (A.I.R. 1978 SC. p. 548) be accepted. The contention of the management therefore must at the outset be rejected.

8. On the aforesaid rival contentions of both the parties on merits the following issues were framed :—

ISSUES

1. Whether the termination of the service of Shri Santosh Kumar Gupta by the management of All India Radio, Chhatarpur was justified ?

2. To what relief are the parties entitled to ?

9. My findings on the aforesaid issues are that :

(1) the termination of the services of the workman, Shri S. K. Gupta, by the management of All India Radio was not justified; and

(2) the workman, Shri S. K. Gupta, is entitled to the relief of reinstatement, back wages and other consequential benefits.

Reasons for the aforesaid findings :

10. Before proceeding further it may be stated that in this case neither party led any oral or documentary evidence. The reference was, therefore, heard only on the facts as they are admitted in the respective claims and rejoinder of the parties.

11. It is an admitted fact that from 14-5-1979 to 31-12-1980 the workman was in the employment of the management continuously without any break. After completion of one year of service the management granted one increment also to the workman. Calculated backward from 31-12-1980 it is evident that the workman had completed more than 240 days' employment under the management when his services were terminated after 31-12-1980.

12. Industrial Disputes Act, 1947 in Clause 2(oo) defines "retrementchment" as under :—

"(oo) "retrenchment" means the termination by the employer of the service of a workman for any reason whatsoever, otherwise than as a punishment inflicted by way of disciplinary action, but does not include —

(i) voluntary retirement of the workman; or

(ii) retirement of the workman on reaching the age of superannuation if the contract of employment between the employer and the workman concerned constains a stipulation in that behalf; or

(iii) termination of the service of a workman on the ground of continued ill-health."

13. When the services of the workman are terminated it has to be seen as to whether he has been retrenched or not within the meaning of the aforesaid provisions of the Act. It is not alleged that the workman voluntarily retired or that retired on reaching the age of superannuation or that his services were terminated on the ground of continued ill health. In the decisions of the Supreme Court (1) State Bank of India Vs. N. Sundermony (AIR 1976 SC p. 1111); Santosh Gupta Vs. Bank of Patiala (AIR 1980 SC p. 1219); and Mohan Lal Vs. Bharat Electronics (AIR 1981 SC. p. 1255) it has been repeatedly held by the Supreme Court that if the termination of a workman does not fall into any of the three exceptions specified in the aforesaid Section 2(oo) then any retrenchment without proper compliance of the Sec. 25F of the Act would be illegal and void. In the instant case, it has not even alleged that there was even a formal compliance of the provisions of Sec. 25F of the Act. Consequently, it must be held that the termination of the services of the workman, Shri S. K. Gupta, was not justified either on facts or in law. The workman having completed 240 days of employment under the management from 14-5-1979 to 31-12-1980 could not have had terminated in the manner in which it has been done in this case. Accordingly it is held that the termination of the services of the workman, Shri S. K. Gupta, by the management of the All India Radio, Chhatarpur, was unjustified both on facts as well as in law. Issue No. 1 is decided in favour of the workman.

14. Issue No. 2 :—In the light of the view taken and the reasons given above the workman is entitled to reinstatement with full back wages, annual increments etc. from 1-1-1981 and all other consequential benefits to which he would have become entitled had he remained in service upto the date of reinstatement.

ORDER :

15. The management of the All India Radio, Chhatarpur shall reinstate the workman, Shri S. K. Gupta, on the post from which his services were terminated on 31-12-1980. The management shall further pay him all the back wages with annual increments and such other benefits to which the workman would have become entitled had his services been not terminated. In the circumstances of the case, both the parties are directed to bear their own costs as incurred in these proceedings.

S. R. VYAS, Presiding Officer
[No. L-42012(38)/81-D. II(D)]
S. S. PRASHER, Desk Officer

नई दिल्ली, 17 अगस्त, 1982

का०आ० 3129:—मैसर्स महेन्द्र एंड महेन्द्र लिमिटेड, मेटेल बिल्डिंग, आपोलो बंदर, मुम्बई–400039 (एम०एच०/4435) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, महाराष्ट्र को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसा लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4 नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, महाराष्ट्र के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते है, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते है, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[सं० एस-35014/155/82-प०नि०-2]

New Delhi, the 17th August, 1982

S.O. 3129.—Whereas Messrs Mahindra and Mahindra Limited, Gateway Building, Appollo Bundera, Bombay-400039 (MH/4435), (hereinafter referred to as the said establishment) have been applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and maintain such accounts and provide for such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges, etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the notice board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended along with a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Where the employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said scheme are enhanced so that the benefits available

under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving him approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where for any reason the employees of the establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the establishment or the benefits to the employees under this Scheme are reduced to any manner, the exemption shall be liable to the cancelled.

10. Where, for any reason the employer fails to pay the premium within the due date as fixed by the Life Insurance Corporation of India and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any, made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme, the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S. 35014(155)/82-PF. II]

का०आ० 3130—मैसर्स धर्मपुरी डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव सुगर मिल्स लिमिटेड पालाकोडे—636808 (तमि/8058) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम, कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है,

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे है और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, तमिलनाडु को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, निरीक्षण प्रभारों ऐसे का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय समय पर निर्दिष्ट करे।

3 सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन मे, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4 नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा मे उसकी मुख्य बातो का अनुवाद, स्थापन के सूचनापट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5 यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सदत्त करेगा।

6 यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदो मे समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदो से अधिक अनुकूल हो, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है।

7 सामूहिक बीमा स्कीम मे किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप मे दोनों रकमो के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8 सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धो में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, तमिलनाडु के पूर्व अनुमोदन के बिना नही किया जाएगा और जहा किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहा, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9 यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नही रह जाते है, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10 यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने मे असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय मे किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदो के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध मे नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक

धारियों को बीमाकृत रकम का सदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[सं० एस-35014/160/82-भ०नि०-2]

S.O. 3130.—Whereas Messrs Dharmapuri District Cooperative Sugar Mills Limited, Palacod-636808 (TN/8058), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu maintain such accounts and provide for such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges, etc, shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the notice board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended along with a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Where the employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted, under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving him approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where for any reason the employees of the establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the establishment or the benefits to the employees under this Scheme are reduced to any manner, the exemption shall be liable to the cancelled.

10. Where, for any reason the employer fails to pay the premium within the due date as fixed by the Life Insurance Corporation of India and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme, the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(160)/82-PF-II]

का०आ० 3131—मैसर्स एम०जी० शाहानी एंड कम्पनी (दिल्ली) प्राइवेट लिमिटेड, 34, बी कनाट प्लेस, नई दिल्ली-110001 (दि०/741) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे है और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल है जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त दिल्ली को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5 यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियो को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि हो जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियो के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हो, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7 सामूहिक बीमा स्कीम मे किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशित को प्रतिकर के रूप मे दोनो रकमो के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों मे कोई भी, संशोधन, प्रादेशिक भविष्य आयुक्त, दिल्ली के पूर्व अनुमोदन के बिना नही किया जाएगा और जहा कहीं संशोधन के कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहा, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियो को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नही रह जाते है, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियो को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते है, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का सदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सदाय मे किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा मे, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के सबध मे नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसो को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा मे भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[सं० एस० 35014(166)/82-पी एफ-II]

S.O. 3131.—Whereas Messrs M. G. Shahani and Company (Delhi) Private Limited 34-B, Connaught Place New Delhi-110001, (DL/741), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi maintain such accounts and provide for such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges, etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the notice board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended along with a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Where the employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi, and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving him approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where for any reason the employees of the establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the establishment or the benefits to the employees under this Scheme are reduced to any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason the employer fails to pay the premium within the due date as fixed by the Life Insurance Corporation of India and the policy allowed to lapse the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme, the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S. 35014(166)/82-PF. II]

का०आ० 3132—मैसर्स एसोसिएटिड सीमेंट कम्पनी लिमिटेड, सीमेंट हाउस, महर्षि कार्वे रोड, मुम्बई-400020 (एम०एच०/4095) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और [प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फ़ायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिये ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं,

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त मुम्बई को ऐसा विवरणिया भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक वर्ष की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंकेक्षण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों को बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ा दिए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, मुम्बई के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन पूंजी सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अधीन होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर इसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने से सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[सं० एस०-35014/17/82-पी०एफ० (II)]

S.O. 3132.—Whereas Messrs Associated Cement Company Limited, Cement House, Maharshi Karve Road, Bombay-400020 (MH/4095) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said scheme for a period of three years

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Bombay maintain such accounts and provide for such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme including maintenance of accounts submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges, etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the notice board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended along with a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Where the employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi, and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving him approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where for any reason the employees of the establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the establishment or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason the employer fails to pay the premium within the due date as fixed by the Life Insurance Corporation of India and the policy allowed to lapse the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme, the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(177)/82-PF. II]

का०आ० 3133.—मैसर्स टिन बाक्स कम्पनी बी-68, रेवाड़ी लाइन्स, मायापुरी फेज-1, नई दिल्ली-110064 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है,

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है,

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, दिल्ली को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अंतर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, दिल्ली के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9 यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उक्त सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते है, तो इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते है तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10 यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों का जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12 उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[सं० एस०-35014/180/82-पी०एफ०(II)]

S.O. 3133.—Whereas Messrs Tin Box Company, B-68 Rewari Lines, Mayapuri Phase I, New Delhi-110064 (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi maintain such accounts and provide for such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2 The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme including maintenance of accounts submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges, etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the notice board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended along with a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees

5. Where the employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi, and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving him approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where for any reason the employees of the establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the establishment or the benefits to the employees under this Scheme are reduced to any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason the employer fails to pay the premium within the due date as fixed by the Life Insurance Corporation of India and the policy is allowed to lapse the exemption is liable to be cancelled

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer

12. Upon the death of the member covered under the Scheme, the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S. 35014(180)/82-PF. II]

का० आ० 3134—मैसर्स मौर्य शेरेटन, डिप्लोमेटिक एन्क्लेव, नई दिल्ली-110021 (दि०/4123) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे है और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल है जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है;

अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध

अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त दिल्ली को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन से, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का, रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप में वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अंतर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, दिल्ली के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उस मृत सदस्य के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[सं० एस०-35014/186/82-स० नि०-II]

S.O. 3134.—Whereas Messrs Maurya Sheraton, Diplomatic Enclave, New Delhi-110021 (DL/4123) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi and maintain such accounts and provide for such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme including maintenance of accounts submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges, etc., shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the notice board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended along with a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Where the employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the

said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where for any reason the employees of the establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the establishment or the benefits to the employees under this Scheme are reduced to any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason the employer fails to pay the premium within the due date as fixed by the Life Insurance Corporation of India and the policy is allowed to lapse the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme, the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominees/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S. 35014(186)/82-PF. II]

का० आ० 3135—मैसर्स कंट्रोल्स एंड स्विचगियर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड 222, ओखला एस्टेट, नई दिल्ली-110020 (दि०/2689) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19), जिसे इसमें इसके पश्चात अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है,

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल है जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें उनुज्ञेय है,

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1 उक्त स्थापन के सबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, दिल्ली को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2 नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3 सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंकेक्षण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4 नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5 यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भावष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है, तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सदत्त करेगा।

6 यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बंद किए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप में वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे, उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है।

7 सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिसों/नामनिर्देशितियों को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, दिल्ली के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9 यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति में कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी का व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11 नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12 उक्त स्थापन के संबन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[सं० एस-35014/187/82-पी० एफ०-II]

S.O. 3135.—Whereas Messrs Controls and Switchgear Company Private Limited, 222, Okhla Industrial Estate, New Delhi-11002 (DL/2689) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi and maintain such accounts and provide for such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme including maintenance of accounts, submission of returns, payment of Insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges, etc., shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the notice board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended along with a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Where the employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where for any reason the employees of the establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the establishment of the benefits to the employees under this Scheme are reduced to any manner, the exemption shall be liable to the cancelled.

10. Where for any reason the employer fails to pay the premium within the due date as fixed by the Life Insurance Corporation of India and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme, the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S. 35014 (187)/82-PF-II]

का०आ० 3136.—मैसर्स कंपर्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, ए-138, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-II, नई दिल्ली-110020 (डी एल/4080) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल है जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है,

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, दिल्ली को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर, निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त दिल्ली के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[सं० एस०-35014/193/82-पी० एफ०-II]

S.O. 3136.—Whereas Messrs Kapil International Private Limited, A 138, Okhla Industrial Area, Phase II, New Delhi-110020 (DL/4080) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insuarnce Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit linked Insurance Scheme 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now therefore in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi and maintain such accounts and provide for such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the notice board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended along with a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Where the employee, who is already a member of the Employees Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits avaialble to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where for any reason the employees of the establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the establishment or the benefit, to the employees under this Scheme are reduced to any manner the exemption shall be liable to the cancelled.

10. Where for any reason the employer fails to pay the premium within the due date as fixed by the Life Insurance Corporation of India and the policy is allowed to lapse the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the

said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme, the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S 35014 (193)/82-PF-II]

का० आ० 3137.—मैसर्स नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, 29, कम्युनिटी सेंटर, ईस्ट आफ कैलाश, नई दिल्ली-110024 (डी एल/3657) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं,

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, दिल्ली, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि, आयुक्त, दिल्ली के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[एस०-35014/193/82-भ०नि०-2]

S.O. 3137.—Whereas Messrs National Fertilizers Limited, 29, Community Centre, East of Kailash, New Delhi-110024 (DL/3657), (hereinafter referred to as the said establishment) have been applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi maintain such accounts and provide

for such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges, etc shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the notice board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended along with a translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Where the employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6 The employer shall arrange to enchance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insusurance Scheme, if on the death of any employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regioal Provident Fund Commissioner shall before giving him approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where for any reason the employees of the establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the establishment or the benefits to the employees under this Scheme are reduced to any manner, the exemption shall be liable to the cancelled.

10 Where for any reason the employer fails to pay the premium within the due date as fixed by the Life Insurance Corporation of India and the policy is allowed to lapse the exemption shall be liable to be cancelled

11. In case of default, if any mad eby the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer

12. Upon the death of the member covered under the Scheme, the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S. 35014 194 82-PF-II]

का० आ० 3138.—मैसर्स फूड स्पेशिलिटीज लिमिटेड, (एम-50) कनाट सर्कस, नई दिल्ली-110001 (डी० एल/1918) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार को समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक् अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए किये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1967 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है ;

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इसके उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, दिल्ली को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उसमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति नए कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय हो तो जब वह उक्त स्कीम के अधीन होगा तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त दिल्ली के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[सं० एस० 35014(196)/82-पी एफ-II]

S.O. 3138.—Whereas Messrs Food Specialities Limited, M-5A, Cannaugh Circus, New Delhi-110001 (DL/4398), (hereinafter referred to as the said establishment) have been applied for exemption under sub section (2A) of Section 17 of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi and maintain such accounts and provide for such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges, etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the notice board of the establishment a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended along with a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Where the employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving him approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where for any reason the employees of the establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the establishment or the benefits to the employees under this Scheme are reduced to any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason the employer fails to pay the premium within the due date as fixed by the Life Insurance Corporation of India and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme, employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No S. 35014 (196)/82-PF-II]

का० आ० 3139.—मैसर्स पुरोलेटर इंडिया लिमिटेड, श्री अरविन्दो मार्ग, नई दिल्ली-110016 (डी०एल०/2538) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है,

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम

स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है,

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त दिल्ली को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियो को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियो के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदो से अधिक अनुकूल हो, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है।

7 सामूहिक बीमा स्कीम मे किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अंतर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8 सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धो में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, दिल्ली के पूर्व अनुमोदन के बिना नही किया जाएगा और जहा किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियो को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नही रह जाते है, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते है, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

690 GI/82—14

10 यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध मे नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसो को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[स०एम०-35014(199)/82-पी०एफ-II]

S.O. 3139.—Whereas Messrs Pulorator India Limited, Sri Aurobindo Marg, New Delhi-110016 (DL/2538), (hereinafter referred to as the said establishment) have been applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nautre of Life Insurance which are more favourable to such employees Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi and maintain such accounts and provide for such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges, etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the notice board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended along with a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Where the employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said scheme are enhanced so that the benefits available

under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving him approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where for any reason the employees of the establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the establishment or the benefits to the employees under this Scheme are reduced to any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason the employer fails to pay the premium within the due date as fixed by the Life Insurance Corporation of India and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme, the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(199)/82-PF.II]

का० आ० 3140.—मैसर्स डियोर इंटरनेशनल (प्राइवेट) लिमिटेड, ए० 138 ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-II, नई दिल्ली-110020 (डी०एल० 4856) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है,

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं:—

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, दिल्ली को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले, सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अंतर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, दिल्ली के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[सं०एस० 35014(201)/82-पी० एफ-II]

S.O. 3140.—Whereas Messrs Dior Internatoinal (Private) Limited, A-138, Okhla Industrial Area Phase II, New Delhi-110020 (DL/4856), (hereinafter referred to as the said establishment) have been applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi and maintain such accounts and provide for such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges, etc, shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the notice board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended along with a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Where the employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving him approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where for any reason the employees of the establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurasce Corporation of India as already adopted by the establishment or the benefits to the employees under this Scheme are reduced to any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason the employer fails to pay the premium within the due date as fixed by the Life Insurance Corporation of India and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme, the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S. 35014(201)/82-PF.II]

का० आ० 3141—मैसर्स इंडियन कार्ड क्लोथिंग कंपनी लिमिटेड, मुम्बई पुणे रोड, पिम्परी, पुणे-411018 (महा०/3762) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदे से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, दिल्ली को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक,

सामूहिक बीमा स्कीम के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं, तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, महाराष्ट्र के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11 नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों का जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12 उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[सं० एस०-35014/203/82-भ०नि०-II]

S.O. 3141.—Whereas Messrs The Indian Card Clothing Company Limited, Bombay Pune Road, Pimpri, Pune-411018 (MH/3762), (hereinafter referred to as the said establishment) have been applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and maintain such accounts and provide for such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges, etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the notice board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended along with a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Where the employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving him approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where for any reason the employees of the establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the establishment or the benefits to the employees under this Scheme are reduced to any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason the employer fails to pay the premium within the due date as fixed by the Life Insurance Corporation of India and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme, the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S. 35014(203)/82-PF-II]

का० आ० 3142—मैसर्स जय हिन्द इंडस्ट्रीज लिमिटेड, अकुर्डी, पुणे-111035 (एम० एच०/7319) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है,

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, महाराष्ट्र को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, प्रीमियम प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, महाराष्ट्र के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसमें स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होने बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[सं० एस० 35014(205)/82-पीएफII]

S.O. 3142.—Whereas Messrs Jai Hind Industries Limtied, Akurdi, Pune-411035 (MH/7319), (hereinafter referred to as the said establishment) have been applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said scheme for a preiod of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and maintain such accounts and provide for such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges, etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the notice board of the establishment a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended along with a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas the employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Comissioner shall before giving him approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view

9. Where for any reason the employees of the establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the establishment or the benefits to the employees under this Scheme are reduced to any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason the employer fails to pay the premium within the due date as fixed by the Life Insurance Corporation of India and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but of grant of this exemption, shall be that of the employer

12. Upon the death of the member covered under the Scheme, the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S. 35014 (205)/82-PF. II]

का० आ० 3143—मैसर्स कलर केम लिमिटेड, रवीन्द्र अनेक्सी, बीनशाह रोड, 199, चर्च गेट रेक्लेमेशन, मुम्बाई-400020 (एम एच)/4094 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है,

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल है जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1 उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, महाराष्ट्र को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय समय पर निर्दिष्ट करे ।

2 नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय समय पर निर्दिष्ट करे ।

3 सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4 नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहु संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6 यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है।

7 सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अंतर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, महाराष्ट्र के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9 यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपनाचुका है अधीन नहीं रह जाते है, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते है, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में

असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

11 नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होने वाले बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12 उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[सं० एस० 35014(211)/82-पी एफ-II]

S.O. 3143.—Whereas Messrs Colour Chem Limited Ravindra Annexe, Dinshaw Vachha Road, 194, Churchgate Reclamation, Bombay-400020 (MH/4094), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act),

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nautre of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Comissioner, Maharashtra and maintain such accounts and provide for such facilities for inspection as the Central Government any direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under caluse (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges, etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the notice board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended along with a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Where the employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employe in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving him approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where for any reason the employees of the establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the establishment or the benefits to the employees under this Scheme are reduced to any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason the employer fails to pay the premium within the due date as fixed by the Life Insurance Corporation of India and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme, the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S. 35014 (211)/82-PF-II]

का० आ० 3144.—मैसर्स केडमच मशीनरी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, पोस्ट बोक्स सं० 9037, मणिनगर, अहमदाबाद (जी जे/6087) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है।

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिये ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1 उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अहमदाबाद को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4 नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पटट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन का, भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6 यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8 सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अहमदाबाद के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपनाया है अधीन नहीं रह जाते है, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते है, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10 यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11 नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[सं० एम० 35014/213/82-स्०नि०(II)]

S.O. 3144.—Whereas Messrs Cadmach Machinery Company Private Limited, P.B. No. 9007, Maninagar, Ahmedabad-380008 (GJ/6087), (hereinafter referred to as the said establishment) have been applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act;

And whereas the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits usder the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nautre of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-linked Issurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Ahmedabad and maintain such accounts and provide for such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accouts, payment of inspection charges, etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the notice board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended along with a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Where the employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissoiner, Ahmedabad and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving him aproval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where for any reason the employees of the establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already

adopted by the establishment or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason the employer fails to pay the premium within the due date as fixed by the Life Insurance Corporation of India and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased memebers who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme, the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(213)/82-PF. II]

नई दिल्ली, 19 अगस्त, 1982

का० आ० 3145—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 91क के साथ पठित धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 1531, तारीख 2 मई 1981, के अनुक्रम में मैसर्स सेन्ट्रल इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड साहिबाबाद जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन एक पब्लिक सेक्टर उपक्रम है को उक्त अधिनियम के प्रवर्तन से 1 जुलाई, 1981 से 30 जून, 1982 तक जिस में वह तारीख भी सम्मिलित है, की एक वर्ष की अवधि के लिए छूट देती है।

2. उक्त छूट की शर्तें निम्नलिखित हैं अर्थात्—

(1) उक्त कारखाने का नियोजक उस अवधि की बाबत जिसके दौरान उस कारखाने पर उक्त अधिनियम प्रवर्तमान था (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त "अवधि" कहा गया है) ऐसी विवरणियां ऐसे प्ररूप में और ऐसी विशिष्टियों सहित देगा जो कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के अधीन उस उक्त अवधि की बाबत देनी थीं,

(2) निगम द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किया गया कोई निरीक्षक या निगम का इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य पदधारी,—

(1) धारा 44 की उपधारा (1) के अधीन, उक्त अवधि की बाबत दी गई किसी विवरणी की विशिष्टियों को सत्यापित करने के प्रयोजनार्थ, या

(2) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 द्वारा यथा अपेक्षित रजिस्टर और अभिलेख उक्त अवधि के लिए रखे गए थे या नहीं, या

(3) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी नियोजक द्वारा दिए गए उन फायदों को, जिसके प्रतिफलस्वरूप इस अधिसूचना हकदार बने हुए है या नहीं, या

(4) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि उस अवधि के दौरान जब उक्त कारखाने के संबंध में अधिनियम के उपबंध प्रवृत्त थे, ऐसे किन्हीं उपबन्धों का अनुपालन किया गया था या नहीं

निम्नलिखित कार्य करने के लिए सशक्त होगा—

(क) प्रधान या अव्यवहित नियोजक से अपेक्षा करना कि वह उसे जानकारी दे जो उपरोक्त निरीक्षक आवश्यक समझे या

(ख) ऐसे प्रधान या अव्यवहित नियोजक के अधिभोगाधीन किसी कारखाने स्थापन कार्यालय या अन्य परिसर में किसी भी युक्तियुक्त समय पर प्रवेश करना और उसके भारसाधक व्यक्ति से अपेक्षा करना कि वह व्यक्तियों के नियोजन और मजदूरी के संदाय से संबंधित ऐसी लेखा बहियां और अन्य दस्तावेज, ऐसे निरीक्षक या अन्य पदधारी के समक्ष प्रस्तुत करे और उनकी परीक्षा करने दे या उन्हें ऐसी जानकारी दे जो वह आवश्यक समझे या

(ग) प्रधान अव्यवहित नियोजक की, उसके अभिकर्ता या सेवक की या ऐसे किसी व्यक्ति की जो ऐसे कारखाने स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में पाया जाए, या ऐसे किसी व्यक्ति की जिसके बारे में उक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी के पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि वह कर्मचारी रहा है, परीक्षा करना;

(घ) ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में रखे गए किसी रजिस्टर लेखाबही या अन्य दस्तावेज की नकल तैयार करना या उससे उद्धरण लेना।

(सं० एस०-38014/18/81-एच० आई०)

स्पष्टीकरण ज्ञापन

इस मामले में, छूट को भूतलक्षी प्रभाव देना आवश्यक हो गया है क्योंकि छूट के लिए आवेदन के प्रक्रमण में विलम्ब हो गया है। तथापि यह प्रमाणित किया जाता है कि भूतलक्षी प्रभाव से छूट दिए जाने से किसी के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

New Delhi, the 19th August, 1982

S.O. 3145.—In exercise of the powers conferred by section 87 read with section 91A of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour S.O. 1531 dated the 2nd May, 1981, the Central Government hereby exempts M/s. Central Electronics Limited, Sahibabad, a public sector undertaking under the Department of Science and Technology, from the operation of the said Act, for a further period of one year with effect from 1st July, 1981 upto and inclusive of the 30th June, 1982.

2. The above exemption is subject to the following conditions, namely :—

(1) The employer of the said factory shall submit in respect of the period during which that factory was subject to the operation of the said Act (hereinafter referred to as the said period), such returns in such form and containing such particulars as were due from it in respect of the said period under the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 ;

(2) Any inspector appointed by the Corporation under sub section (1) of section 45 of the said Act or other official of the Corporation authorised in this behalf shall, for the purposes of—

(i) verifying the particulars contained in any return submitted under sub-section (1) of section 44 for the said period ; or

(ii) ascertaining whether registers and records were maintained as required by the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 for the said period ; or

(iii) ascertaining whether the employees continue to be entitled to benefits provided by the employer in cash and kind being benefits in consideration of which exemption is being granted under this notification ; or

(iv) ascertaining whether any of the provisions of the Act has been complied with during the period when such provisions were in force in relation to the said factory ;

be empowered to—

(a) require the principal or immediate employer to furnish to him such information as he may consider necessary ; or

(b) enter any factory, establishment, office or other premises occupied by such principal or immediate employer at any reasonable time and require any person found incharge thereof to produce to such inspector or other official and allow him to examine such accounts, books and other documents relating to the employment of persons and payment of wages or to furnish to him such information as he may consider necessary ; or

(c) examine the principal or immediate employer, his agent or servant, or any person found in such factory, establishment, office or other premises or any person whom the said inspector or other official has reasonable cause to believe to have been an employee ; or

(d) make copies of or take extracts from any register, account book or other document maintained in such factory, establishment, office or other premises

[No. S-38014/18 81-HI]

EXPLANATORY MEMORANDUM

It has become necessary to give retrospective effect to the exemption in this case, as the processing of the application for exemption took time. However, it is certified that the grant of exemption with retrospective effect will not affect the interest of anybody adversely.

का०आ० 3146,—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 91क के साथ पठित धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं० का०आ० 2695 तारीख 14 सितम्बर, 1981 के अनुक्रम में भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड, गाजियाबाद, जो रक्षा मंत्रालय के अधीन एक पब्लिक सेक्टर उपक्रम है, को उक्त अधिनियम के प्रवर्तन से, 1 जुलाई, 1981 से 30 जून, 1982 तक, जिसमें वह तारीख भी सम्मिलित है, की एक वर्ष की अवधि के लिए छूट देती है ।

2 उक्त छूट की शर्तें निम्नलिखित हैं, अर्थात्:—

(1) पूर्वोक्त कारखाना, जिसमें कर्मचारी नियोजित है, एक रजिस्टर रखेगा, जिसमें छूट प्राप्त कर्मचारियों के नाम और पदाभिधान दिखाए जाएंगे ,

(2) इस छूट के होते हुए भी कर्मचारी उक्त अधिनियम के अधीन ऐसी सुविधाएं प्राप्त करने रहेंगे, जिनको पाने के लिए वे इस अधिसूचना द्वारा दी गई छूट के प्रवृत्त होने की तारीख से पूर्व संदत्त अभिदायों के आधार पर हकदार हो जाते ,

(3) छूट प्राप्त अवधि के लिए यदि कोई अभिदाय पहले ही किए जा चुके हों तो वे वापस नहीं किए जाएंगे ,

(4) उक्त कारखाने का नियोजक, उस अवधि की बाबत जिसके दौरान उस कारखाने पर उक्त अधिनियम प्रवर्तमान था (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त अवधि" कहा गया है), ऐसी विवरणियां ऐसे प्ररूप में और ऐसी विशिष्टियों सहित देगा जो कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के अधीन उसे उक्त अवधि की बाबत देय था ,

(5) निगम द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किया गया कोई निरीक्षक या निगम या इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य पदधारी—

(1) उक्त अवधि की बाबत धारा 44 की उपधारा (1) के अधीन दी गई किसी विवरणी की विशिष्टियों को सत्यापित करने के प्रयोजनार्थ; या

(2) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 द्वारा यथा-अपेक्षित रजिस्टर और अभिलेख उक्त अवधि के लिए रखे गए थे या नहीं ; या

(3) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी नियोजक द्वारा किए गए उन फायदों को, जिसके प्रतिफलस्वरूप इस अधिसूचना के अधीन छूट दी जा रही है, नकद और वस्तु रूप में पाने का हकदार बना हुआ है या नहीं , या

(4) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि उस अवधि के दौरान, जब उक्त कारखाने के संबन्ध में अधिनियम के उपबन्ध प्रवृत्त थे, ऐसे किन्हीं उपबन्धों का अनुपालन किया गया था या नहीं ;

निम्नलिखित कार्य करने के लिए सशक्त होगा :—

(क) प्रधान या अव्यवहित नियोजक से अपेक्षा करना कि वह उसे ऐसी जानकारी दे जिसे उपरोक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी आवश्यक समझता है ,

(ख) ऐसे प्रधान या अव्यवहित नियोजक के अधिभोगाधीन किसी कारखाने स्थापन कार्यालय या अन्य परिसर में किसी भी उचित समय पर प्रवेश करना और उसके प्रभारी से यह अपेक्षा करना कि वह व्यक्तियों के नियोजन और मजदूरी के संदाय से संबन्धित ऐसे लेखा, बहियां और अन्य दस्तावेज ऐसे निरीक्षक या अन्य पदधारी के समक्ष प्रस्तुत करे और उसे उनकी परीक्षा करने दे, या उसे ऐसी जानकारी दे जिसे वह आवश्यक समझता है; या

(ग) प्रधान या अव्यवहित नियोजक की उसके अभिकर्ता या सेवक की, या ऐसे किसी व्यक्ति की जो ऐसे कारखाने स्थापन कार्यालय या अन्य परिसर में पाया जाए, या ऐसे किसी व्यक्ति की जिसके बारे में उक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी के पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि वह कर्मचारी है, परीक्षा करना ; या

(घ) ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में रखे गए किसी रजिस्टर लेखाबही या अन्य दस्तावेज की नकल तैयार करना या उसमें से उद्धरण लेना ।

[सं० एस-38014/30/81-एच०आई०]

स्पष्टीकारक ज्ञापन

इस मामले में छूट को भूतलक्षी प्रभाव देना आवश्यक हो गया है क्योंकि छूट के लिए आवेदन में प्रक्रमण में विलम्बित हो गया है ? तथापि यह प्रमाणित किया जाता है कि भूतलक्षी प्रभाव से छूट दिए जाने से किसी के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

S.O. 3146.—In exercise of the powers conferred by section 87 read with section 91A of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 2695 dated the 14th September, 1981 the Central Government hereby exempts Bharat Electronics Limited, Ghaziabad, a public Sector Undertaking under the Ministry

of Defence from the operation of the said Act for a further period of one year with effect from the 1st July, 1981 upto and inclusive of the 30th June, 1982.

2. The above exemption is subject to the following conditions, namely :—

(1) The employer of the said factory shall submit in respect of the period during which that factory was subject to the operation of the said Act (hereinafter referred to as the said period), such returns in such form and containing such particulars as were due from it in respect of the said period under the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 ;

(2) Any inspector appointed by the Corporation under sub section (1) of section 45 of the said Act or other official of the Corporation authorised in this behalf shall, for the purposes of—

(i) verifying the particulars contained in any return submitted under sub-section (1) of section 44 for the said period ; or

(ii) ascertaining whether registers and records were maintained as required by the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 for the said period ; or

(iii) ascertaining whether the employees continue to be entitled to benefits provided by the employer in cash and kind being benefits in consideration of which exemption is being granted under this notification ; or

(iv) ascertaining whether any of the provisions of the Act has been complied with during the period when such provisions were in force in relation to the said factory ;

be empowered to —

(a) require the principal or immediate employer to furnish to him such information as he may consider necessary ; or

(b) enter any factory, establishment, office or other premises occupied by such principal or immediate employer at any reasonable time and require any person found incharge thereof to produce to such inspector or other official and allow him to examine such accounts, books and other documents relating to the employment of persons and payment of wages or to furnish to him such information as he may consider necessary ; or

(c) examine the principal or immediate employer, his agent or servant, or any person found in such factory, establishment, office or other premises or any person whom the said inspector or other official has reasonable cause to believe to have been an employee ; or

(d) make copies of or take extracts from any register, account book or other document maintained in such factory, establishment, office or other premises.

[No. S-38014/30/81-HI]

EXPLANATORY MEMORANDUM

It has become necessary to give retrospective effect to the exemption in this case, as the processing of the application for exemption took time. However, it is certified that the grant of exemption with retrospective effect will not affect the interest of anybody adversely.

का०आ० 3147.—मैसर्स कोयम्बतूर वायनियर मिलस लिमिटेड, बी मिल्स कोयम्बतूर-19 (तमिलनाडु 1038) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल है जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है,

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1 उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, तमिलनाडु को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय समय पर निर्दिष्ट करे।

2 नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय समय पर निर्दिष्ट करे।

3 सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन, में जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4 नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किए जाएं, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5 यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है, तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6 यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है।

7 सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8 सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, तमिलनाडु के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त,

अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9 यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते है, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते है, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10 यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि वह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के संबन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[सं० एस-35014(42)/82-पी० एफ०-II]

S.O. 3147.—Whereas Messrs Coimbatore Poineer Mills Limited, 'B' Mills, Coimbatore-19 (TN/1038) (hereinafter referred to as the said establishment) have been applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) ;

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Schme) ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and maintain such accounts and provide for such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All exepnses involved in the administration of the Group Insurance Scheme including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges, etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the notice board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended along with a translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees

5. Where the employee, who is already a member of the Employees Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving him approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where for any reason the employees of the establishment do not remain covered under the Group Insurance scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the establishment or the benefits to the employees under this Scheme are reduced to any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason the employer fails to pay the premium within the due date as fixed by the Life Insurance Corporation of India and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assuranee benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme, the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(42)/82-PF-II]

का०आ० 3148.— मैसर्स कोईबील स्पिनिंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड 59-सी, वेंकटस्वामी रोड वेस्ट, आर एस० पुरम-कोयम्बतूर-641002 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है,

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे है और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल है जो कर्मचारी निक्षेप संलग्न बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है ,

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष

की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देता है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, तमिलनाडु को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखे रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय समय पर निदिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय समय पर निदिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उसमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी यथोचित आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिदेशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अंतर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, तमिलनाडु के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के जिसमें स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन वे लाभ जो प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो ये छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन पूत सदस्यों के नामनिदेशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि पर, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिदेशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[सं० एस०-35014(43)/82-पी० एफ० II]

S.O. 3148.—Whereas Messrs Cordweel Spinning Mills Private Limited, 59-B, Venkataswamy Road West, R. S. Puram, Coimbatore-641002, (hereinafter referred to as the said establishment) have been applied for exemption under sub-section 2A) of Section 17 of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) ;

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Schme) ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and maintain such accounts and provide for such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges, etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the notice board of the establishment a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended along with a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Where the employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Gorup insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less, than the amount that

would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving him approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view

9 Where for any reason the employees of the establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the establishment or the benefits to the employees under this Scheme are reduced to any manner, the exemption shall be liable to be cancelled

10 Where for any reason the employer fails to pay the premium within the due date as fixed by the Life Insurance Corporation of India and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled

11 In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12 Upon the death of the member covered under the Scheme, the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(43)/82-PF-II]

का०आ० 3149—मैसर्स शिवकामी मिल्स लिमिटेड, थेनूर, भदर्स (तमिलनाडु) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ,

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पेंशन अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिये ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल है जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1 उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, तमिलनाडु को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसा लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2 नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3 सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4 नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5 यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6 यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बंद किए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7 सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों स्कीमों के अंतर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8 सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, तमिलनाडु के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने में पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9 यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति में कम हो जाते हैं, या यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10 यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11 नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12 उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[सं०एस-35014/44/82-पी०एफ०-I

S.O. 3149.—Whereas Messrs Sivakami Mills Limited, Thenur, Madurai (Tamil Nadu), (hereinafter referred to as the said establishment) have been applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) ;

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) ,

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section(2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and maintain such accounts and provide for such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer

4. The employer shall display on the notice board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended along with a translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Where the employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving him approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view

9. Where for any reason the employees of the establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the establishment or the benefits to the employees under this Scheme are reduced to any manner, the exemption shall be liable to be cancelled

10. Where for any reason the employer fails to pay the premium within the due date as fixed by the Life Insurance Corporation of India and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme, the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(44)/82-PF-II]

का० आ० 3150—मैसर्स डेज मेडिकल स्टोर्स (मैन्युफैक्चरिंग) लिमिटेड, 6/डी लिंडसे स्ट्रीट कलकत्ता-700016 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 (1952 का 19 जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है कि धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे है और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल है जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976(जिसे इसमें पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है,

अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस पर उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सब उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1 उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त पश्चिम बंगाल को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2 नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत अपेक्षित प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस / नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, पश्चिम बंगाल के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते है, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते है तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[सं० एस-35014/55/82-भा० नि०-2]

S.O. 3150.—Whereas Messrs Dey's Medical Stores (Manufacturing) Limited, 6-D, Lindsay Street Calcutta-700016 (hereinafter referred to as the said establishment) have been applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) ;

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section(2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner West Bengal and maintain such accounts and provide for such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the asid Act, within 15 days from the close of every month.

3. All exepnses involved in the administration of the Group Insurance Scheme including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges, etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the notice board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended along with a translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees

5. Where the employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Gorup Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Schme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, West Bengal and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving him approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where for any reason the employees of the establishment do not remain covered under the Group Insurance Schme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the establishment or the benefits to the employees under this Scheme are reduced to any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason the employer fails to pay the premium within the due date as fixed by the Life Insurance Corporation of India and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the

nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(55)/82-PF-II]

का० आ० 3151.—मैसर्स मैसूर सेल्स इन्टरनैशनल लिमिटेड, एम० आई० एस० स० हाउस 36, कनिंगम रोड, बंगलौर-560052 (फ० एन० /3964) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है)। के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1 उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, कर्नाटक को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय समय पर निर्दिष्ट करे।

2 नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है।

609 GI/82—16.

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अंतर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त कर्नाटक के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमा कृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[सं० एस० 35014/115/82-पी० एफ-2]

S.O. 3151.—Whereas Messrs Mysore Sales International Limited, MISL House, 36, Cunningham Road, Bangalore-560052 (KN/3964), (hereinafter referred to as the said establishment) have been applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka and maintain such accounts and provide for such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges, etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the notice board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended along with a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Where the employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the Provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving him approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where for any reason the employees of the establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the establishment or the benefits to the employees under this Scheme are reduced to any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason the employer fails to pay the premium within the due date as fixed by the Life Insurance Corporation of India and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benets to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exmption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme, the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(115)/82-PF. II]

का०आ० 3152.—मैसर्स आई जी ई (इंडिया) लिमिटेड निर्मल 17वीं मंजिल, नारिमन पाइंट, बम्बई-400021/एम०एच०/4043, (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल है जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापना को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, महाराष्ट्र को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा। जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अंतर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन , प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, महाराष्ट्र के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका

से अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[सं० एस-35014/117/82-पी०एफ०-2]

S.O. 3152.—Whereas Messrs I. G. E. (India) Limited, Nirmal 17th Floor, Nariman Point, Bombay-400021 (MH/4043), (hereinafter referred to as the said establishment) have been applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nautre of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17, of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and maintain such accounts and provide for such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges, etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the notice board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended along with a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Where the employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving him approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where for any reason the employees of the establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the establishment or the benefits to the employees under this Scheme are reduced to any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason the employer fails to pay the premium within the due date as fixed by the Life Insurance Corporation of India and the Policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme, the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S 35014(147)/82-PF. II]

का० आ० 3153.—मैसर्स के० एल० राठी स्टील लिमिटेड, 3-ग, वंदना, 11, टालस्टाय मार्ग, नई दिल्ली-110001 (दि०/3365) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापना कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, दिल्ली को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधायें प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अंतर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि, आयुक्त दिल्ली के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते है, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते है, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[सं० एस०-35014/188/82-पी०एफ० (ii)]

S.O. 3153.—Whereas Messrs **K. L. Rathi Steels Limited**, 3-A, Vandhna, 11, Tolstoy Marg, New Delhi-110001 (DL / 3365), (hereinafter referred to as the said establishment) have been applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi and maintain such accounts and provide for such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges, etc shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the notice board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amendment along with a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Where the employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall borne giving him approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where for any reason the employees of the establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the establishment or the benefits to the employees under this Scheme are reduced to any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason the employer fails to pay the premium within the due date as fiixed by the Life Insurance Coropration of India and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemptions, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt o fthe sum assured from the Life Insurance Coropration of India.

[No. S-35014(188)/82-PF. II]

नई दिल्ली, 21 अगस्त, 1982

का०आ० 3154.—मैसर्स महेश्वरी मिल्स लिमिटेड, शाहीबाग मार्ग, अहमदाबाद-380004 (जी०जे०/309), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदा उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है,

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अहमदाबाद को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन का भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अहमदाबाद के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[सं० एस-35014/146/82-पी०एफ०-2]

New Delhi, the 21st August, 1982

S.O. 3154.—Whereas Messrs Maheshwari Mills Limited, Shahibagh Road, Ahmedabad-380004 (GJ/309), (hereinafter referred to as the said establishment) have been applied for

exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any, separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Ahmadabad and maintain such accounts and provide for such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges, etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the notice board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended along with a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Where the employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Ahmedabad and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving him approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where for any reason the employees of the establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the establishment or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason the employer fails to pay the premium within the due date as fixed by the Life Insurance Corporation of India and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by thte employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(146)/82-PF. II]

का० आ० 3155—मैसर्स उड़ड इण्डिया लिमिटेड, अरकाडिया, 14वीं मंजिल, नारिमन पाइंट, बम्बई-400021 (एम०एच०/14765) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है,

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं।

अत: केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, महाराष्ट्र को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है।

7 सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी की उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अंतर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, महाराष्ट्र के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12 उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर एकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[सं० एस०-35014/148/82-पी०एफ० (ii)]

S.O. 3155.—Whereas Messrs Uhde India Limited, Areadia 13th Floor, Nariman Point, Bombay-400021 (MH/14765) (hereinafter referred to as the said establishment) have been applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of he said establishmtnt are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Governmen hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and maintain such accounts and provide for such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges, etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the notice board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended along with a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Where the employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/ nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving him approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9 Where for any reason the employees of the establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the establishment or the benefits to the employees under this Scheme are reduced to any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason the employer fails to pay the premium within the due date as fixed by the Life Insurance Corporation of India and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme, the employer in relation to said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominees/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India

[No. S-35014(148)/82-PF. II]

का० आ० 3156.—मैसर्स गीडी एसोसिएट्स, गोपाल बाग, 35, अविनाशी रोड, कोयम्बटूर-18 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है, और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं,

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त तमिलनाडु को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अंतर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त तमिलनाडु के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[सं०एस०-35014/21/82-भ०नि० II]

ए० के० भट्टाराई, अवर सचिव

S.O. 3156.—Whereas Messrs Geede Associates, Gopal Bagh, 315, Avanashi Road, Coimbatore-18, (hereinafter referred to as the said establishment) have been applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the *Central Government* hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and maintain such accounts and provide for such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges, etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the notice board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended along with a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees

5. Where the employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an estableshment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisinos of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving him approval give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where for any reason the employees of the establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the establishment or the benefits to the employees under this Scheme are reduced to any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reaon the employer fails to pay the premium within the due date as fixed by the Life Insurance Corporation of India and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme, the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S. 35014(21)/82-PF-II]

A. K. BHATTARAI, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1982.